बी.एड. द्वितीय वर्ष

व्यावसायिक शिक्षा

(VOCATIONAL / WORK EDUCATION)

GEDE-19

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय – भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY - BHOPAL

Reviewer Committee

1. Dr. Vandana Chaturvedi
   Assistant Professor
   RKDF University, Bhopal (M.P.)

2. Dr. Meena Barse
   Assistant Professor
   Sant Hirdaram Girls College, Bhopal (M.P.)

3. Dr. Pravini Pandaagle
   Professor
   NRI Group of Institutions, Bhopal (M.P.)

Advisory Committee

1. Dr. Jayant Sonwalkar
   Hon'ble Vice Chancellor
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)

2. Dr. L.S. Solanki
   Registrar
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)

3. Dr. Hemlata Dinkar
   HOD, DME
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)

4. Dr. Vandana Chaturvedi
   Assistant Professor
   RKDF University, Bhopal (M.P.)

5. Dr. Meena Barse
   Assistant Professor
   Sant Hirdaram Girls College, Bhopal (M.P.)

6. Dr. Pravini Pandaagle
   Professor
   NRI Group of Institutions, Bhopal (M.P.)

COURSE WRITERS

Dr. Jagtap Manisha Vasantrao, Asst. Prof., Department of External Education and Learning (DEEL), Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University (KBCNMU), JALGAON
Units (1-2)

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

व्यावसायिक शिक्षा

Syllabi	Mapping in Book
इकाई–1 अवधारणा, दर्शन, आवश्यकता, भूमिका और ऐतिहासिक विकास– व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा : अर्थ, परिभाषा और महत्व, व्यावसायिक शिक्षा का दर्शन, ऐतिहासिक विकास, मानव संसाधन विकास के साधन के रूप में व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य और समस्याएं; व्यावसायिक शिक्षा का विकास– ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा का विकास, आयोगों और समितियों की सिफारिशें, व्यावसायिक शिक्षा : समस्याओं और गैर–कार्यान्वयन के कारण, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष समूहों का रोजगार; प्रणाली, मॉडल, प्रगति और वर्तमान स्थिति– भारत में माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यावसायिक शिक्षा का स्थान, व्यावसायिक शिक्षा के मॉडल, विभिन्न राज्यों में प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति और वर्तमान स्थिति; व्यावसायिक शिक्षा के मुद्दे/समस्याएं और रुझान– भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे, समस्याएं और चुनौतियां, व्यावसायिक शिक्षा में नए रुझान और विकास – (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता प्रणाली, आजीवन और सतत शिक्षा, सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा), जनसंख्या वृद्धि, मूल्य शिक्षा, मानवाधिकार, आरटीई –2009 आदि जैसी उभरती हुई चिंताएं और व्यावसायिक शिक्षा के साथ उनका संबंध, सामुदायिक कॉलेजों के माध्यम से कौशल सीखने की अवधारणा	**इकाई 1** : व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना **(पृष्ठ 3–110)**
इकाई–2 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और कार्यान्वयन– राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना और रूप (क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम), व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन लिए रणनीतियां; संगठन और प्रबंधन– राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत स्तरों पर प्रबंधन संरचना, विद्यालय संगठन और प्रबंधन योजना, निष्पादन और निर्देशन, कक्षा, कार्यशाला (शॉप फ्लोर) और नौकरी प्रशिक्षण प्रबंधन, खरीद, भंडारण, अभिलेख (रिकॉर्डिंग), सामग्री और उपकरण का रखरखाव; पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान– पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान : कई क्षेत्रों के कार्य कौशल के संयोजन की संभावना, वास्तविक जीवन में ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका; व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अभिकरण/एजेंसियां– माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के विशेष संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका, गैर–औपचारिक क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थानों की भूमिका, व्यावसायिक संस्थानों के शिक्षक और प्रमुख की भूमिका, कर्तव्य और गुण, भोपाल में केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की भूमिका	**इकाई 2** : व्यावसायिक शिक्षा : पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन, प्रबंधन और अभिकरण (एजेंसियां) **(पृष्ठ 111–210)**

विषय–सूची

परिचय **1–2**

इकाई 1 व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना **3–110**

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 अवधारणा, दर्शन, आवश्यकता, भूमिका और ऐतिहासिक विकास
  1.2.1 व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा : अर्थ, परिभाषा और महत्व
  1.2.2 व्यावसायिक शिक्षा का दर्शन
  1.2.3 ऐतिहासिक विकास
  1.2.4 मानव संसाधन विकास के साधन के रूप में व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य और समस्याएं
1.3 व्यावसायिक शिक्षा का विकास
  1.3.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा का विकास
  1.3.2 आयोगों और समितियों की सिफारिशें
  1.3.3 व्यावसायिक शिक्षा : समस्याओं और गैर–कार्यान्वयन के कारण
  1.3.4 व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष समूहों का रोजगार
1.4 प्रणाली, मॉडल, प्रगति और वर्तमान स्थिति
  1.4.1 भारत में माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यावसायिक शिक्षा का स्थान
  1.4.2 व्यावसायिक शिक्षा के मॉडल
  1.4.3 विभिन्न राज्यों में प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति और वर्तमान स्थिति
1.5 व्यावसायिक शिक्षा के मुद्दे/समस्याएं और रुझान
  1.5.1 भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे, समस्याएं और चुनौतियां
  1.5.2 व्यावसायिक शिक्षा में नए रुझान और विकास – (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता प्रणाली, आजीवन और सतत शिक्षा, सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा)
  1.5.3 जनसंख्या वृद्धि, मूल्य शिक्षा, मानवाधिकार, आरटीई –2009 आदि जैसी उभरती हुई चिंताएं और व्यावसायिक शिक्षा के साथ उनका संबंध
  1.5.4 सामुदायिक कॉलेजों के माध्यम से कौशल सीखने की अवधारणा
1.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
1.7 सारांश
1.8 मुख्य शब्दावली
1.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.10 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 2 व्यावसायिक शिक्षा : पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन, प्रबंधन और अभिकरण (एजेंसियां) **111–210**

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और कार्यान्वयन
  2.2.1 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना और रूप (क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम)
  2.2.2 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन लिए रणनीतियां
2.3 संगठन और प्रबंधन
  2.3.1 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत स्तरों पर प्रबंधन संरचना
  2.3.2 विद्यालय संगठन और प्रबंधन योजना, निष्पादन और निर्देशन, कक्षा, कार्यशाला (शॉप फ्लोर) और नौकरी प्रशिक्षण प्रबंधन
  2.3.3 खरीद, भंडारण, अभिलेख (रिकॉर्डिंग), सामग्री और उपकरण का रखरखाव

2.4 पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान
2.4.1 पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान : कई क्षेत्रों के कार्य कौशल के संयोजन की संभावना
2.4.2 वास्तविक जीवन में ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका
2.5 व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अभिकरण (एजेंसियां)
2.5.1 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के विशेष संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका
2.5.2 गैर–औपचारिक क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थानों की भूमिका
2.5.3 व्यावसायिक संस्थानों के शिक्षक और प्रमुख की भूमिका, कर्तव्य और गुण
2.5.4 भोपाल में केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की भूमिका
2.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर
2.7 सारांश
2.8 मुख्य शब्दावली
2.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.10 सहायक पाठ्य सामग्री

परिचय

टिप्पणी

प्रस्तुत पुस्तक 'व्यावसायिक शिक्षा' का लेखन विश्वविद्यालय के बी.एड. द्वितीय वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया है।

भारत में प्राचीन काल से ही व्यावसायिक शिक्षा के प्रमाण मिलते रहे हैं, परंतु इसकी संगठित शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही हुई। कंपनी ने अंग्रेजी सरकार की आवश्यकता के अनुरूप कार्मिक तैयार करने के लिए व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने शुरू किए।

शिक्षा का लक्ष्य नागरिकों में जनतांत्रिकता, उत्तरदायित्व, कार्यकुशलता, निर्णय लेने की क्षमता, आधुनिकता और वैज्ञानिकता पैदा करना होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की व्यावसायिक कुशलता का विकास है। देश को कुशल कारीगरों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, प्राध्यापकों और प्रशासकों की आवश्यकता होती है और इसके लिए विशेष विद्यालयों एवं संस्थानों की जरूरत पड़ती है। शिक्षा में प्रबंधन का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है ताकि संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

इस पुस्तक में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सभी अहम पहलुओं का सांगोपांग अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक इकाई के आरंभ में संदर्भित विषय का परिचय एवं उद्देश्य स्पष्ट कर दिए गए हैं। इकाई के बीच–बीच में शिक्षार्थियों के स्व–मूल्यांकन के लिए 'अपनी प्रगति जांचिए' शीर्षक के तहत वैकल्पिक प्रश्न भी दिए गए हैं।

अध्ययन की सुविधा के लिए समूचे पाठ्यक्रम को दो इकाइयों में समायोजित किया गया है। इन इकाइयों का विवरण इस प्रकार है–

पहली इकाई व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना पर आधारित है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा, भूमिका, व्यावसायिक शिक्षा का विकास, व्यावसायिक शिक्षा के मॉडल, भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के मुद्दे एवं समस्याओं को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

दूसरी इकाई व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, प्रबंधन और एजेंसियों पर आधारित है। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, कार्यान्वयन, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संगठन व प्रबंधन की संरचना, पाठ्यक्रम में कार्य की भूमिका तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अभिकरणों (एजेंसियों) का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं का विश्लेषण सरल एवं रोचक रूप से किया गया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक अध्येताओं का ज्ञानवर्द्धन कर उनके मार्गदर्शन में सहायक सिद्ध होगी।

इकाई 1 व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना

संरचना

1.0 परिचय

1.1 उद्देश्य

1.2 अवधारणा, दर्शन, आवश्यकता, भूमिका और ऐतिहासिक विकास

- 1.2.1 व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा : अर्थ, परिभाषा और महत्व
- 1.2.2 व्यावसायिक शिक्षा का दर्शन
- 1.2.3 ऐतिहासिक विकास
- 1.2.4 मानव संसाधन विकास के साधन के रूप में व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य और समस्याएं

1.3 व्यावसायिक शिक्षा का विकास

- 1.3.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा का विकास
- 1.3.2 आयोगों और समितियों की सिफारिशें
- 1.3.3 व्यावसायिक शिक्षा : समस्याओं और गैर–कार्यान्वयन के कारण
- 1.3.4 व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष समूहों का रोजगार

1.4 प्रणाली, मॉडल, प्रगति और वर्तमान स्थिति

- 1.4.1 भारत में माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यावसायिक शिक्षा का स्थान
- 1.4.2 व्यावसायिक शिक्षा के मॉडल
- 1.4.3 विभिन्न राज्यों में प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति और वर्तमान स्थिति

1.5 व्यावसायिक शिक्षा के मुद्दे/समस्याएं और रुझान

- 1.5.1 भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे, समस्याएं और चुनौतियां
- 1.5.2 व्यावसायिक शिक्षा में नए रुझान और विकास – (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता प्रणाली, आजीवन और सतत शिक्षा, सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा)
- 1.5.3 जनसंख्या वृद्धि, मूल्य शिक्षा, मानवाधिकार, आरटीई –2009 आदि जैसी उभरती हुई चिंताएं और व्यावसायिक शिक्षा के साथ उनका संबंध
- 1.5.4 सामुदायिक कॉलेजों के माध्यम से कौशल सीखने की अवधारणा

1.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1.7 सारांश

1.8 मुख्य शब्दावली

1.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

1.10 सहायक पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

1.0 परिचय

शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कार्य बच्चों के लिए सीखने का क्षेत्र भी होता है चाहे वह घर में हो, स्कूल में या समाज में। कार्य करने के स्थान पर बच्चे कार्य की अवधारणा को 2 वर्ष की उम्र से ही समझने लगते हैं। बच्चे अपने अभिभावकों की नकल करते हैं। कार्य मानव जीवन को समृद्ध बनाता है क्योंकि यह सम्मान तथा आनंद के लिए नए आयाम सामने रखता है। कार्य व्यवसाय शिक्षण हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में लगातार वृद्धि हो रही थी। यह महसूस किया गया है कि यदि देश का आर्थिक

विकास होना है और जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए। भारत की जनशक्ति के विशाल संसाधन केवल आधुनिक दुनिया में एक संपत्ति बन सकते हैं जब यह प्रशिक्षित और शिक्षित हो।

टिप्पणी

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी जुटाकर, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल का आकलन करते हुए, स्कूलों, पॉलिटेक्निक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने, निजी को प्रोत्साहित करते हुए आकांक्षात्मक बनाया जा रहा है।

सभी भारतीयों के लिए सतत, समावेशी विकास करने के लिए कौशल प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता है। स्किलिंग वर्तमान उद्योग मानकों के प्रशिक्षण, व्यावहारिक, सैद्धांतिक और सॉफ्ट कौशल ज्ञान को संदर्भित करता है। इसमें युवाओं की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करना और उन्हें वर्तमान रोजगार बाजार के लिए प्रासंगिक कौशल के साथ रोजगारपरक बनाना शामिल है। समस्या इस तथ्य में निहित है कि हमारे पास दुनिया में प्रशिक्षित युवाओं का अनुपात सबसे कम है।

प्रस्तुत इकाई में व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा, भूमिका का विकास, व्यावसायिक शिक्षा के मॉडल, भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के मुद्दे एवं समस्याओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया है।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा को जान पाएंगे;
- व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका और विकास को समझ पाएंगे;
- भारत में आयोगों और समितियों की सिफारिशों से परिचित हो पाएंगे;
- व्यावसायिक शिक्षा के मॉडलों के बारे में जान पाएंगे;
- भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दों एवं समस्याओं से अवगत हो पाएंगे;
- व्यावसायिक शिक्षा में नए रुझानों और विकास को समझ पाएंगे।

1.2 अवधारणा, दर्शन, आवश्यकता, भूमिका और ऐतिहासिक विकास

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह सामाजिक मानदंडों के अनुसार जीवन जीता है। मनुष्य और पशुओं में मुख्य अंतर यह है कि मनुष्य अपनी संस्कृति और चारों ओर के वातावरण के अनुसार स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करता है, जो पशु नहीं कर पाता। वह यह सब अपने शिक्षक से सीखता है। उसके जीवन में पहला शिक्षक उसकी मां होती है, उसके बाद परिवार के सदस्य और अंत में समाज। हर मनुष्य सुबह से उठकर शाम तक, रात में सोने तक बहुत सारे काम में व्यस्त रहता है क्योंकि कार्य करना ही जीवन की आवश्यकता है। कार्य करने से मनुष्य के जीवन में बहुत सी

उपलब्धियां आ जाती हैं। कार्य और आजीविका का आपस में घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक एवं व्यवसाय हर पहलू से शारीरिक श्रम की परिधि से बाहर नहीं है अर्थात माननीय जीवन का संचालन शारीरिक श्रम पर ही निर्भर है। उसका बड़ा बहुत महत्व है।

टिप्पणी

काम का महत्व क्या है यह बच्चों को पाठशाला में ही पढ़ाया जाता है। उसके लिए अनेक गतिविधियां शिक्षकों द्वारा की जाती हैं। शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण और सार्थक शारीरिक माननीय श्रम माना गया है, उसे ही कार्य शिक्षा कहते हैं। कार्य शिक्षण प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जाता है। इसका परिणाम सामग्री के उत्पादन और समुदाय की सेवा के रूप में प्रकट होता है जिसमें आत्म संतोष तथा आनंद का अनुभव होता है।

1.2.1 व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा : अर्थ, परिभाषा और महत्व

शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। अंग्रेजी में शिक्षा का पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है। यह शब्द लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है जो समानार्थी समझे जाते हैं। एक शब्द है एजुकेटम, एजुसीयर एंड एजुकेयर। इन शब्दों का अर्थ, अंदर से बाहर लाना है, आगे बढ़ाना या आगे ले जाना है। एजुकेटम का अर्थ Act of teaching (सिखाने की क्रिया) भी लगाया जाता है। शिक्षा का अर्थ है– सिखाना, निर्देशन देना, बढ़ाना, आगे ले जाना।

महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ 'रघुवंश' में शिक्षा शब्द का प्रयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया के रूप में किया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, शिक्षा निःसंदेह एक प्रक्रिया है और ज्ञान केवल उसकी उपलब्धि। शिक्षा के अतिरिक्त जीवन संबंधी मान्यताओं, मूल्यों और आदर्शों से भी संबंधित है। यह एक कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास द्वारा ही प्राप्त कर सकता है।

'रूसो' के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य बालक की विभिन्न शक्तियों का विकास करना है, जो बालक की स्वाभाविक क्रिया में सहायता प्रदान करके ही किया जा सकता है।

'जॉन ड्यूवी' के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य बालक की समस्त शक्तियों का विकास है। बालक की योग्यता, मूल्य, शक्तियों इत्यादि का विकास शिक्षा द्वारा संभव है।

शिक्षा के विकास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। आज जो शिक्षा विद्यालयों में प्रदान की जा रही है उसका आधार यही तीनों माने जाते हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, इसमें स्वाभाविक प्रवाह होता है, यह जड़ नहीं अपितु चेतन है। इसका संबंध जीवन से होने का कारण इसमें गति और ग्रहण करने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में शिक्षा एक जीवित प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को जीवन के संचित अनुभव से परिचित कराया जाता है। यह अनुभव व्यक्ति की जीवन समस्याओं के लिए उचित समाधान प्रस्तुत करते हैं। परंतु इन अनुभवों की मात्रा इतनी अधिक है कि कोई भी जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम करके भी इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है।

शिक्षा शास्त्र का विकास आज भी हो रहा है। इसमें उन सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है जिनमें सामान्य शिक्षा दी जाती है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जन्म और विकास की स्थिति में शिक्षा के महत्व को सदन में प्रकाशित किया है। शिक्षा जीवन के इन संबंधों को और महत्वपूर्ण और प्रभावी बनाती है, इसी दृष्टि से

बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। हर देश में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना होता है जो अपने नागरिकों को उनकी प्रतिभा दिखाने और विकास का मौका दें जिसकी जरूरत उन्हें जीवन भर रहती है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि शारीरिक श्रम को शिक्षा से जोड़ा जाए।

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा : अवधारणा, अर्थ और परिभाषा

व्यावसायिक शिक्षा आधुनिक युग की नई मांग है। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 (NCF 2005) में भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में उसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्थान दिया जाता है जो छात्रों को जीविकोपार्जन करने योग्य बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का प्रथम प्रयास कोठारी आयोग 1964 ने किया। इस आयोग ने सरकार को माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का सुझाव दिया।

सामान्यतः शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना ही व्यवसायिक शिक्षा कहलाती है परन्तु वास्तव में इसका अर्थ इससे अधिक व्यापक है। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को व्यवसाय चुनने एवं व्यवसाय संबंधित योग्यता प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करती है। व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964–66 के सुझावों द्वारा हुई। जिस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अपनी मंजूरी प्रदान की और यह शिक्षा का एक माध्यम बन गई। इसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने 1995 तक +2 कक्षा के 25% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु इसे दूरस्थ शिक्षा में भी सम्मिलित किया गया।

भारत देश में छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक परिषद के निर्माण की बात कही गई जो व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन एवं नीति निर्माण की योजना बनाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद (JCVE) की स्थापना की गई। यह परिषद व्यावसायिक पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु नीति का निर्माण करती है और उसके क्रियान्वयन हेतु विद्यालयों को मंजूरी प्रदान करती है।

व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा को क्रमशः इस प्रकार समझा जा सकता है–

- **अवधारणा**

1. व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा वास्तव में उस समय से शुरू हुई है जब माता–पिता ने अपने बच्चों को आदिम लोगों के सता और सभा बैंड में जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल सिखाया। व्यावसायिक शिक्षा वास्तव में एक कौशल विकास शिक्षा है और इसका उद्देश्य कौशल और ज्ञान का एक वांछित स्तर विकसित करना है। यह इस प्रकार रोजगार का मार्ग प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्रों को स्वतंत्र होने के लिए और एक ही समय में, एक उत्पादक समुदाय बनाने का अवसर प्रदान करता है।
2. व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा मूल रूप से वैदिक काल से चली आ रही है जब बच्चा आश्रमों में रहता था और हर तरह के काम करता था जो चेतन और

विकासशील दिमाग के लिए आवश्यक होता है। व्यक्ति को माल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा एक प्रभावी हथियार और शक्तिशाली संचार माध्यम है।

3. शिक्षा के व्यावसायीकरण पर भारतीय कार्यसमूह (1996) ने भी व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर (ड्रॉपआउट) को कम करने के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रचलित कार्यक्रम की योजना बनाई जानी चाहिए।

टिप्पणी

4. व्यावसायिक शिक्षा शब्द एक सामान्य शब्द है और इसका उपयोग उस क्षेत्र के कुछ संकेतों के बिना नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए संदर्भ बनाया जा रहा है, उदाहरण के लिए– कृषि व्यावसायिक शिक्षा, व्यापार और औद्योगिक व्यावसायिक शिक्षा।

5. व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा की शिक्षा के रूप में व्याख्या की जा सकती है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को उदार शिक्षा के साथ विपरीत माना जाता है। व्यावसायिक शिक्षा एक व्यक्ति को एक कुशल निर्माता बनाने के लिए डिजाइन की गई है और उदार शिक्षा को एक कुशल उपभोक्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सख्त उपयोगितावादी अर्थ में, "व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण किसी दिए गए रोजगार के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शिक्षित या प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए गए संगठित और नियंत्रित सीखने के अनुभवों की एक शृंखला का अर्थ।" व्यावसायिक शिक्षा को परिभाषित करने के लिए कई अवधारणाएं विकसित की गईं जो कभी–कभी इसे कुछ विशिष्ट विषयों में एक पूरक के रूप में शिक्षा के रूप में मानती हैं। सामान्य शिक्षा का घटक, कभी–कभी इसे उत्पादक उद्देश्यों या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्यों और इतने पर शिक्षा के रूप में मानता है।

6. एनसीईआरटी (2000) द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने पहले के नाम कार्य अनुभव के बजाय एक नया कार्यकाल कार्य शिक्षा दिया है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) ने कार्य अनुभव को सार्थक कार्य के रूप में संपन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं को लोगों के लिए फायदेमंद है। कार्य शिक्षा में स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बच्चों के मानसिक स्तर और कौशल के अनुसार सेवाओं, भोजन, कपड़े, सामाजिक सेवाओं और मनोरंजन से युक्त गतिविधियां शामिल हैं। समाज के कल्याण के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करना। व्यावसायिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका हस्त कार्य चरित्र है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करेंगे जबकि वे सीखेंगे। इसके द्वारा वे व्यक्तिगत, सामाजिक गुणों, कौशल, कार्य से संबंधित मूल्यों का विकास करते हैं।

7. व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल सिलेबस में स्थान प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता के साधन के रूप में और भावी जीवन के लिए एक प्रशिक्षण के रूप में एक आत्म–महत्व की आवश्यकता होती है। स्कूल एक ऐसी जगह है जो बच्चे और समुदाय के बीच मध्यस्थ का काम करती है। स्कूल न केवल हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हैं बल्कि एक ही समय में पोषण और प्रगति भी करते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से हम समाज में बदलाव ला सकते

हैं। स्कूलों में कार्य शिक्षा का एक ईमानदार निष्पादन छात्र को समुदाय/समाज के करीब ला सकता है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बना सकता है।

8. मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह शिक्षा के व्यावहारिक और बौद्धिक भाग को संतुलित करेगा। यह काम के लिए कौशल, मूल्यों और गरिमा को विकसित करने में मदद करेगा और दूसरी तरफ बच्चा अपने दिमाग और बुद्धिमत्ता को कुछ रचनात्मक/उत्पादक कार्यों के लिए लागू कर सकता है जो बच्चे के लिए और समाज के लिए भी अच्छा है। रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था एक बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह है जो हम करते हैं इसमें लिखें। शब्द या ज्ञान को बच्चे द्वारा स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा, इसलिए यदि इस प्रौद्योगिकी उन्मुख समाज में हम बच्चे के मस्तिष्क को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ेंगे, वे आसानी से ज्ञान को समझेंगे और समाज को विकसित करने में मदद करेंगे जो तकनीकी रूप से पूरा होता है। कार्य शिक्षा रचनात्मकता को संरक्षित करने या पोषण करने में मदद करती है, दूसरे के लिए मदद उन्हें लोकतांत्रिक देश का उपयोगी हिस्सा बनाती है।

9. कई दशकों से व्यावसायिक शिक्षा की अहम भूमिका है। कुशल श्रमिकों के लिए राष्ट्र की मांग को पूरा करना ऐतिहासिक रूप से, व्यावसायिक शिक्षा को उन संघीय व्यावसायिक शिक्षा अधिनियमों द्वारा समर्थित गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के विकास के लिए प्रदान करते हैं। हालांकि, व्यापक या सामान्य अर्थों में, व्यावसायिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति के व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

टिप्पणी

• अर्थ और परिभाषा

अर्थ : 'शब्द' वोकेशनल एजुकेशन का मतलब व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण या रिट्रेनिंग है जो स्कूल या कक्षाओं में सार्वजनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत या किसी राज्य बोर्ड या स्थानीय शैक्षिक एजेंसी के साथ अनुबंध के तहत दिया जाता है और इसे एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है, जो व्यक्तियों के लिए तैयार किया जाता है।

मान्यताप्राप्त व्यवसायों में अर्ध–कुशल या कुशल श्रमिकों या तकनीशियन या उप–पेशेवर के रूप में रोजगार और नए और उभरते व्यवसायों में जो आयुक्त निर्धारित करता है, विनियमन द्वारा मध्य निर्दिष्ट करता है, जिसे आमतौर पर पेशेवर माना जाता है या जिसके लिए एक स्नातक या उच्चतर डिग्री की आवश्यकता होती है, और इस तरह के शब्द में व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकल्पों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श शामिल हैं।

1963 में शब्द 'मान्यताप्राप्त व्यवसाय' व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषा का एक हिस्सा था। मुख्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए व्यापक संदर्भ पाते हैं जो व्यावसायिक शिक्षा को निर्दिष्ट करता है जिसमें व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श शामिल हैं।

व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ है– लोगों को तैयार करना और उन्हें हमारी जरूरत के प्रकारों के लिए तैयार रखना। इस तरह की आवश्यक सेवाओं के प्रकार या स्तर

के रूप में शब्द की कोई सीमा नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा अच्छी शिक्षा, अच्छा समाजशास्त्र, अच्छा अर्थशास्त्र और अच्छा लोकतंत्र है।

परिभाषा

व्यावसायिक शिक्षा शब्द को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग–अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं–

टिप्पणी

- वास्तविक पर्यवेक्षण 1944 और 1945 के ग्रीष्मकाल के दौरान फ्लोरिडा के डेटोना बीच में आयोजित दक्षिणी राज्यों के कार्य सम्मेलन ने व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषा तैयार की, सरल शब्दों में, व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा का वह पहलू है जो ज्ञान के संदर्भ में मानव क्षमताओं के विकास का उद्देश्य है। कौशल और समझ ताकि व्यक्ति अपनी पसंद के व्यावसायिक दृष्टिकोण में गतिविधियों को पूरा करने में खुशी और कुशलता से सेवा कर सके।
- 1954 में अमेरिकन वोकेशनल एसोसिएशन के अनुसंधान और प्रकाशन पर समिति ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन की गई शिक्षा है। क्षमता, समझ, दृष्टिकोण, काम करने की आदतें और प्रशंसा एक उपयोगी और उत्पादक आधार पर रोजगार में प्रवेश करने और प्रगति करने के लिए श्रमिकों द्वारा आवश्यक ज्ञान और जानकारी शामिल है। यह कुल शैक्षणिक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है और अच्छे नागरिकों के विकास में योगदान देता है।
- जॉन एफ. थॉम्पसन व्यावसायिक शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित करते हैं– "व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो अनुभव, दृश्य उत्तेजना, स्नेह जागरूकता, संज्ञानात्मक जानकारी प्रदान करती है, या मनो–मोटर कौशल और जो व्यावसायिक विकास को बढ़ाता है, काम की दुनिया में खुद को तलाशने, स्थापित करने और बनाए रखने की प्रक्रियाएं।"
- आर. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स के अनुसार, "व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अतिरिक्त कौशल और जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के अवसरों को उपलब्ध कराकर आधुनिक उद्योग की दक्षता में वृद्धि करते हैं।" रोजगार के क्षेत्र में उभरते अवसरों और चुनौतियों का जवाब देने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा प्राथमिकता के साथ उभरी। कुशल रोजगार, स्व–रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल, इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य बन गया।
- कुलंदिस्वामी ने 'व्यावसायिक शिक्षा' शब्द की एक कार्यशील परिभाषा पर जोर दिया। परंपरागत रूप से 'व्यावसायिक शिक्षा' को कुशल कर्मियों को तैयार करने के लिए डिजाइन की गई शिक्षा के रूप में समझा जाता हैं।
- एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया (1985) में कहा गया है कि "व्यावसायिक शिक्षा औद्योगिक या व्यावसायिक व्यवसाय के लिए व्यक्तियों को लैस करने के लिए निर्देश है। यह औपचारिक रूप से व्यापार, स्कूलों और तकनीकी माध्यमिक विद्यालयों में या नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में या अनौपचारिक रूप से बिना नौकरी के आवश्यक कौशल उठाकर प्राप्त किया जा सकता है।"
- कार्टर वी. डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन निम्नानुसार व्यावसायिक शिक्षा को परिभाषित करता है– "कॉलेज ग्रेड के नीचे शिक्षा का एक कार्यक्रम एक विशेष रूप से चुने

गए व्यवसाय में प्रवेश के लिए सीखने या ग्रेड कार्यरत श्रमिकों को तैयार करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें व्यापार और औद्योगिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, वितरण शिक्षा और गृह अर्थशास्त्र शिक्षा जैसे विभाग शामिल हैं।"

टिप्पणी

- शैक्षिक अनुसंधान के विश्वकोश ने व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन इस प्रकार किया है– "व्यावसायिक शिक्षा किसी भी तरह के काम के लिए शिक्षा है जिसे व्यक्ति जन्मजात पाता है और जिसके लिए समाज की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से अलग शिक्षा के रूप में जाना जाता है।"
- अमेरिकन वोकेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन ने व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन कौशल, क्षमता, समझ, दृष्टिकोण, कार्य की आदतों, और श्रमिकों द्वारा उपयोगी और उत्पादक आधार पर रोजगार में प्रगति करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन की गई शिक्षा के रूप में किया है।
- वाशिंगटन, डीसी स्कूल प्रणाली के लिए शैक्षिक सलाहकारों का समूह अपनी रिपोर्ट में 'व्यावसायिक शिक्षा' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है– "एक व्यापक अर्थ में, सभी शिक्षा, औपचारिक या अनौपचारिक व्यावसायिक क्षमता में योगदान करती हैं। कुछ व्यवसायों के लिए, पर्याप्त तैयारी के लिए कोलेजिएट की तैयारी की आवश्यकता होती है। एक अर्थ में ज्ञान या कौशल के बाद का उपयोग एक बड़े माप में इसके वर्गीकरण को निर्धारित करता है।"
- यूनेस्को भाषा के अनुसार व्यावसायिक विस्तार (स्पेक्ट्रम) यह है कि "शैक्षिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में सामान्य शिक्षा के अलावा, प्रौद्योगिकियों और संबंधित विज्ञानों का अध्ययन और व्यावहारिक कौशल, योग्यता, समझ और विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों से संबंधित ज्ञान का अधिग्रहण शामिल है।"
- महात्मा गांधी की शिक्षा के अनुसार, "लड़कों और लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रशिक्षण, जहां तक संभव हो, लाभ देने वाले व्यवसाय के माध्यम से दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वोकेशन को दोहरे उद्देश्य से काम करना चाहिए। स्कूल में सीखे वोकेशन के माध्यम से पूरे पुरुष या महिला को उसके विकास के लिए तैयार कर सके। दूसरे शब्दों में वह स्वावलंबी शिक्षा चाहते हैं।"

व्यावसायिक शिक्षा की विशेषताएं

व्यावसायिक शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. यह छात्रों को समाज से जोड़ने और सामाजिक कार्यों में योगदान देने हेतु तैयार करती है।
2. यह छात्रों को जीविकोपार्जन बनाने हेतु उनमें व्यावसायिक कौशल की प्रवृत्ति का विकास करती है।
3. इसके द्वारा छात्रों को विद्यालयों में क्रियाशील रखा जाता है और इससे उनका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है।
4. इससे वह अपने सामाजिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों से परिचित हो जाते हैं।
5. व्यावसायिक शिक्षा द्वारा शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यो को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य

व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- छात्रों को व्यवसायपरख बनाना जिससे वह समाज में सम्मानपूर्वक रहने योग्य बन सकें।
- छात्रों में जीविकोपार्जन करने की दक्षता का विकास करना जिससे वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भली–भांति निर्वहन कर सकें।
- राष्ट्र का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना।
- राष्ट्रीय आर्थिक संरचना को मजबूती प्रदान करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।
- शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा देना।

टिप्पणी

शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व

किसी देश के विकास में उस देश की शैक्षिक व्यवस्था का बहुत अत्यधिक महत्व होता है और अगर उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय दिलाना और उनको जीविकोपार्जन योग्य बनाना हो तो उस देश का विकास निश्चित होता है। शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर सकती है जब वह शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा हो। वर्तमान में शिक्षा की घटती गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि शिक्षा को पूर्णतः व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित किया जाए।

व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को व्यवसाय चुनने में ही सहायक नहीं हैं अपितु इसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास भी किया जाता है। आधुनिक युग में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षा को छात्रों के अनुरूप बनाया जाए जिससे वह अपने वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें।

1.2.2 व्यावसायिक शिक्षा का दर्शन

अदिशेशिया रिपोर्ट, 1978 ने व्यावसायिक शिक्षा के दर्शन को निम्नानुसार बताया–

"ऐसे देश में जहां औद्योगिक और कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग गतिविधि के विविध क्षेत्रों को खोलते हैं, जहां वाणिज्य और व्यापार और सार्वजनिक सेवाओं की एक बड़ी विविधता तेजी से विस्तार कर रही है, पर्याप्त होना चाहिए।"

भारत में, हालांकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार दशकों से बनी हुई है, लेकिन हम अतीत में मुख्य रूप से उद्योग व व्यवसायों के साथ जुड़े रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगिताएं और सेवाएं आम तौर पर पिछड़ी हुई हैं ताकि शहर में प्रशिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर और यहां तक कि तकनीशियन ग्रामीण क्षेत्रों में बसने और सेवा करने के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक नहीं लगते हैं। इसलिए, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जीवन की गुणवत्ता और ग्रामीण क्षेत्र, जो विशेष रूप से उन व्यवसायों के विकास का अर्थ है, जो सर्विसिंग से ग्रामीण कृषि संसाधनों के बेहतर उपयोग की क्षमता रखते हैं। ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों या अन्य मशीनरी के लिए जो वैरिएफेल्टल वनस्पति / बागवानी /

चिकित्सा संयंत्र/उत्पादों पर आधारित हैं, या ग्रामीण स्वास्थ्य, शैक्षणिक/सांस्कृतिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए हैं। इसलिए, एक अर्थ में, व्यावसायिक शिक्षा हमें आर्थिक विकास के लाभों को सामाजिक न्याय और सामाजिकता की ओर समान रूप से साझा करने की दिशा में सक्षम बनाने की क्षमता रखती है।

टिप्पणी

बुनियादी शिक्षा (बेसिक एजुकेशन), शिल्प शिक्षा (क्राफ्ट एजुकेशन), सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्यों को सीखना (लर्निंग टू डू, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क), व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनलिसेशन ऑफ एजुकेशन), कार्यानुभव (वर्क एक्सपीरियंस), कामकाजी दुनिया (वर्ल्ड ऑफ वर्क)–इन सभी बड़ी अवधारणाओं और एक ही विचार को प्रयोग (कंज्यूम) करते हैं यानी शिक्षा उत्पादकता (एजुकेशन प्रोडक्टिविटी) से संबंधित होनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का मूल कारण मैकाले है जो ब्रिटिश शासकों के लिए दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए क्लर्कों की एक सेना का उत्पादन करना चाहता था। अब यह महसूस किया गया है कि समय की बड़ी जरूरत हमारी 'सिंगल ट्रैक' शिक्षा को मोड़ना है।

शैक्षणिक प्रकार एक 'डबल ट्रैक' में, या वास्तव में उच्च माध्यमिक छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने के लिए, हमारी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी और उत्पादक बनाते हैं। देश की शिक्षा प्रणाली को नौकरी–उन्मुखीकरण, कार्य अनुभव और कौशल और दृष्टिकोण के विकास के संदर्भ में पुनर्गठित किया जाना है जो नौकरी की तलाश में एक व्यक्ति को लगाने के बजाय स्व–रोजगार में मदद करेगा। जैसा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है, "एक व्यक्ति पुस्तक–विद्या में प्रतिष्ठित हो सकता है लेकिन उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहती है जब तक कि उसने अच्छे और कुशल उद्देश्य के लिए हाथ न लगाना सीख लिया हो।" महात्मा गांधी ने सिर और हाथ से काम करने के महत्व पर भी बल दिया।

व्यावसायिक शिक्षा व्यवसाय संचालन संबंधी है। व्यावसायिक शिक्षा कुल शिक्षा प्रक्रिया का एक हिस्सा है। व्यापक अर्थों में व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का वह हिस्सा है जो एक व्यक्ति को दूसरे की तुलना में व्यवसायों के एक समूह में अधिक रोजगारपरक बनाता है। तो कोई भी प्रशिक्षण, जो रोजगार के लिए योगदान देता है या काम के लिए तैयारी, व्यावसायिक शिक्षा है। व्यावसायिक शिक्षा काम के साथ शिक्षा को एकीकृत करने की एक विधि है। व्यावसायिक कार्यक्रमों में सभी व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए अपने कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त स्तर पर सभी युवाओं और वयस्कों के लिए एक मंच प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।

आज व्यावसायिक शिक्षा को मनुष्य के रचनात्मक और प्रगतिशील विकास की नींव के रूप में माना जाता है। व्यावसायिक शिक्षा देश के उचित मानव संसाधन को विकसित करने, औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में व्यावसायिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों को शामिल करती है जैसे– पर्यटन, साधन रखरखाव, फैशन डिजाइनिंग, कला और शिल्प, फूलों की खेती (फ्लोरीकल्चर), बागवानी, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, संचार कौशल, होटल प्रबंधन, और कई और। यह उल्लेखनीय है कि भारत की तकनीकी और विशिष्ट जनशक्ति अब व्यावसायिक रूप से बेहतर हो गई है जो इसे प्रस्तुत करती है।

देश के भीतर और बाहर व्यवसाय और ज्ञान उद्योगों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति उत्पन्न करना संभव है। यह तथ्य बताता है कि देश में एक

सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए, नियमित शिक्षा के व्यावसायीकरण और तकनीकी शिक्षा के सुधार पर भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए। डी.आर. दुआ ने सही टिप्पणी की है, "शिक्षा के व्यावसायीकरण का प्रमुख उद्देश्य, यह मुखर हो सकता है, यह व्यक्तित्व के अभिन्न विकास को सुनिश्चित करने के लिए है, न कि केवल तकनीशियन या मैकेनिक के विकास के लिए।"

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद और वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो कार्य करने की खुशी के अलावा समाज के लिए उपयोगी होती हैं। यह शिक्षा के सभी वर्गों यानी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा अच्छी तरह से विकसित, चैनल और संरचित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। इसमें बुनियादी जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, विभिन्न जीवन कौशल, अवलोकन और नैतिक मूल्य शामिल होने चाहिए।

आवश्यकता

जैसा कि मनुष्य की बुद्धि और पेट है, उसके पास अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों की देखभाल के लिए धन होना चाहिए। नौकरी पाने के लिए व्यक्ति के पास विपणन योग्य कौशल होना चाहिए। एक व्यक्ति के पास अच्छा विपणन कौशल हो सकता है यदि उसके पास ज्ञान, कौशल और कार्य करने के लिए उचित रवैया है। जीवन में उद्देश्यहीनता को समाप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति को एक प्राणिक्य नौकरी या पेशे के बारे में उचित शिक्षा है।

व्यवसाय की अनुपस्थिति एक परजीवी की तरह दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। यदि उनके विचार, अवलोकन और सरलता को उत्तेजित किया जाता है तो रुचि और दृष्टिकोण उत्तेजित होते हैं। इस प्रकार शिक्षा का महत्व व्यक्ति की सामाजिक दक्षता के लिए एक उचित आधार तैयार करता है यदि उसके पास सही व्यावसायिक उद्देश्य है। संपूर्ण जीवन शैली को निर्धारित करने और अपने जीवन को अर्जित करने के लिए, व्यक्ति का व्यवसाय सबसे बड़ा कारक है। कौशल व्यक्ति को अपने कामकाजी जीवन में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। नौकरी से संतुष्टि जीवन की सबसे बड़ी चीज है। डॉ (मिस) एम. डी. बेंगाली निम्नलिखित शब्दों में वर्णन करते हैं– "प्रत्येक सुबह उठना और उस काम में शामिल होना एक महान आशीर्वाद है जो जीवन के उद्देश्यों की पूरी तरह से संतुष्टि और पूर्ति देता है। यह सभी की गतिविधियों में नया जोश और रंग भरता है और यह समाज को अधिक उपयोगी बनाता है।"

अपनी मर्जी से काम करने पर परिश्रम खो जाता है और क्योंकि इससे संतुष्टि मिलती है। इसे खेलने के लिए एक आनंददायक गतिविधि के रूप में तब्दील किया जाता है। संक्षेप में, काम खेल बन जाता है और व्यक्ति को वही आनंद मिलता है और वही लाभ जो उसे खेल गतिविधियों के माध्यम से मिलता है। जब वह अपने कामकाजी जीवन में इस मुकाम पर पहुंचता है, तो वह एक खुश, संतुष्ट व्यक्ति होता है जो अधिक घंटे काम करता है। ऊर्जा और उत्साह के साथ निर्धारित समय की तुलना में जो कभी समाप्त नहीं होता है। वह अपने काम के साथ अच्छी तरह से समायोजित है और एक

टिप्पणी

कामकाजी अनुसूची में उसके साथ काम करना हल्का करता है और सभी की संतुष्टि के लिए आसानी और दक्षता के साथ पूरा किया जाता है।

कार्ल मार्क्स के अनुसार, "भविष्य की शिक्षा, एक निश्चित आयु से अधिक के प्रत्येक बच्चे के मामले में, शिक्षा और खेलकूद (एथलेटिक्स) के साथ उत्पादक श्रम को न केवल सामाजिक उत्पादन बढ़ाने के तरीकों में से एक है, बल्कि पूरी तरह से विकसित मानवों के उत्पादन की एकमात्र विधि के रूप में है। व्यावसायिक शिक्षा भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक है। विस्तारित अर्थव्यवस्था को पर्याप्त श्रम आपूर्ति की आवश्यकता है।" इसलिए आर. डब्ल्यू. रॉबर्ट्स ने सही टिप्पणी की– "व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अतिरिक्त कौशल और जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के अवसरों को उपलब्ध कराकर मॉडेम उद्योग की दक्षता में वृद्धि करते हैं।"

व्यावसायिक शिक्षा का मार्गदर्शन नए कार्यकर्ता को रोजगार के लिए सही समय पर तैयार करता है जब उद्योग को उसकी आवश्यकता होती है। व्यावसायिक शिक्षा और नई तकनीक कार्यकर्ता के कौशल को उन्नत करने में मदद करती है। व्यावसायिक शिक्षा पर्याप्त श्रम आपूर्ति और वर्तमान कार्यकर्ता के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रेरित करती है। व्यावसायिक शिक्षा आर्थिक शिक्षा है और नौकरी बाजार की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। व्यावसायिक शिक्षा स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में योगदान करती है।

व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका

व्यावसायिक शिक्षा की निम्न भूमिका है–

1. स्वरोजगार की जरूरतों का आकलन करने के लिए समुदाय और कार्य कुशलता को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की स्थिति की जांच करना।
2. कार्य अनुभव छात्रों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करना।
3. व्यावहारिक स्तर पर कार्यस्थल की खोज के लिए साख (क्रेडिट) अर्जित करना।
4. कार्यस्थल की यथार्थवादी समझ के आधार गुणों और कौशलों का विकास करें, जो रोजगार और कैरियर के विकास में सफलता के लिए हस्तांतरणीय हैं, और योगदान करना।
5. भविष्य के नियोक्ताओं के लिए संदर्भ रुचियों और योग्यता के बारे में जागरूकता, आत्मविश्वास का विकास करना।
6. कार्य–संबंधित नेटवर्क/संपर्क विकसित करना।
7. स्कूल से कार्य या आगे की शिक्षा के लिए संक्रमण का समर्थन करना।

1.2.3 ऐतिहासिक विकास

शिक्षा की वर्धा योजना, जिसे 'बुनियादी शिक्षा' (बेसिक शिक्षा) के रूप में जाना जाता है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यह योजना हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी द्वारा भारत में शिक्षा की एक स्वदेशी योजना विकसित करने का पहला प्रयास था। एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उन्होंने पूरी तरह से महसूस किया कि शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली देश की सामाजिक–आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती।

लंदन में गोलमेज सम्मेलन (1931) में उन्होंने भारत में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की अप्रभाविता और भारतीय लोगों के बीच साक्षरता के कम प्रतिशत का संकेत दिया। उन्होंने सामूहिक शिक्षा के क्षेत्र में इस दर्दनाक स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया। गांधीजी ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली न केवल बेकार है बल्कि सकारात्मक रूप से हानिकारक है।' इस संदर्भ में गांधीजी के दिमाग में बेसिक शिक्षा की अवधारणा उभरकर आई।

टिप्पणी

1937 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 लागू हुआ। अधिनियम के अनुसार, भारत में सात प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों का गठन किया गया था। गांधीजी ने प्रस्ताव रखा कि धन की चाह के लिए सामूहिक शिक्षा की योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक उपयोगी और उत्पादक शिल्प के माध्यम से शिक्षा प्रदान करके स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया को स्वावलंबी बनाया जा सकता है तो हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है।

गांधीजी ने 1937 में वर्धा सम्मेलन में अपनी बेसिक शिक्षा प्रणाली को राष्ट्र के सामने रखा। तब सम्मेलन ने उपरोक्त प्रस्तावों की तर्ज पर एक विस्तृत शिक्षा योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। जैसा कि एक विस्तृत शिक्षा योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले उल्लेख किया गया था। इसने अपनी रिपोर्टें दिसंबर, 1937 में और दूसरी अप्रैल, 1938 को प्रस्तुत कीं। यह रिपोर्ट तब से मूल योजना का मूल दस्तावेज बन गई है और इस योजना को शिक्षा की वर्धा योजना के रूप में जाना जाने लगा है।

महात्मा गांधी द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था और मार्च, 1938 में आयोजित इसके हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष रखा गया था।

1. पहली रिपोर्ट में शिक्षा की वर्धा योजना, उसके उद्देश्य, शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण, स्कूलों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण और शिल्प केंद्रित शिक्षा जैसे कताई, बुनाई आदि के बारे में बुनियादी सिद्धांतों को शामिल किया गया था।
2. दूसरी रिपोर्ट कृषि से संबंधित थी, धातु का काम, लकड़ी के शिल्प और अन्य बुनियादी हस्तकला। उन सभी विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम और अन्य विषयों के साथ उनके सहसंबंध स्थापित करने के तरीके और साधन भी सुझाए गए थे।

1945 के सम्मेलन ने 'जीवन के लिए शिक्षा' के रूप में बुनियादी शिक्षा की विशेषता बताई। सम्मेलन ने इसे भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना में एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में माना, अर्थात, जीवन का एक नया तरीका बनाया। तब से बेसिक शिक्षा को 'नई तालीम' के नाम से जाना जाने लगा।

शिल्प/हस्तकौशल शिक्षा की अवधारणाओं में परिवर्तन

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से कला और शिल्प आंदोलन के बाद से, 'Craft' शब्द को सौंदर्य की दृष्टि से स्वीकार किया गया (ग्रीनहल्ग इन फिलिस, 2008, पृष्ठ 135) में उद्धृत किया गया है। और शिल्प उद्योग की एक परिभाषा पर विचार किया गया, खासकर शिल्प और कला के बीच एक अंतर बनाने में। शिल्प और कला दोनों

टिप्पणी

का सौंदर्यशास्त्रीय मूल्य है, हालांकि सौंदर्य मूल्य की डिग्री अलग है। शिल्प आमतौर पर अधिक सजावटी, अधिक समृद्ध दृश्य, सामग्री और प्रक्रिया का अधिक सम्मानजनक है, लेकिन कला के इतिहास के साथ–साथ कला के मुद्दों (मेटकाफ, 1993) के साथ कम संज्ञानात्मक है। हालांकि, बेकर ने पहचान की कि शिल्पकार कलाकार–शिल्पकार और सामान्य शिल्पकार में प्रतिष्ठित हैं। सौंदर्यवादी चिंतन को बढ़ावा देने के रूप में कलाकार वस्तुओं की अभिव्यक्ति या प्रभावशीलता पर जोर देते हैं; कलाकार–शिल्पकार सुंदरता के साथ–साथ उपयोगिता पर विचार करते हैं, जबकि सामान्य शिल्पकार सुंदरता पर जोर नहीं देते हैं बल्कि ग्राहक की मांग पर प्रतिक्रिया देते हैं।

गांधीजी की शिक्षा की परिभाषा उनके शिक्षा के दर्शन में एक अंतर्दृष्टि देती है। अब, गांधीजी के अनुसार शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा से उनका अभिप्राय है कि बच्चे और मनुष्य, शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ से हटकर एक सर्वांगीण चित्र। गांधी के लिए साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है, शुरुआत भी नहीं है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और महिला को शिक्षित किया जा सकता है। इसलिए, वह अपनी शिक्षा की योजना में साक्षरता को बहुत कम महत्व देता है।

शिल्प के माध्यम से शिक्षा

इस योजना का मूल विचार कुछ शिल्प या उत्पादक कार्यों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। शिल्प का काम बच्चे को संवेदक और मोटर समन्वय का अधिग्रहण करने और ईमानदार श्रम के मूल्य की सराहना करने में मदद करता है। गांधी जी का विचार था कि गांव की हस्तकला के माध्यम से मन को प्रशिक्षित करने का तरीका शुरू से ही केंद्रीय ध्यान से मन के वास्तविक, अनुशासित विकास को बढ़ावा देगा।

"शैक्षिक दृष्टिकोण से, शिल्प के माध्यम से बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान के लिए अधिक संक्षिप्तता और वास्तविकता दी जा सकती है क्योंकि ज्ञान जीवन से संबंधित होगा।" शिल्प–केंद्रित शिक्षा रचनात्मक उत्तेजना और आत्म–अभिव्यक्ति के माध्यम से सिद्धांत और सीखने के बीच एक संतुलन बनाती है। यह हस्त (मैनुअल) और बौद्धिक कौशल के बीच भेदभाव को कम करने और शहरी और ग्रामीण भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने वाले सामाजिक रूप से सार्थक कार्यों के संबंध में पूर्वाग्रहों पर काबू पाने में मदद करता है। यह आय और समुदाय की पहल के स्थायी स्रोतों के माध्यम से एक सभ्य आजीविका अर्जित करने पर गर्व महसूस करता है जिसके परिणामस्वरूप सहकारी समितियों और सूक्ष्म उद्यमों का परिणाम होता है।

कौशल अधिगम, कार्य अनुभव

चौतरफा व्यावसायिक शिक्षा के अद्वितीय महत्व को देखते हुए बच्चे का विकास और देश की भलाई विचारणीय है। शिक्षा पर लगभग सभी महत्वपूर्ण योजनाओं, रिपोर्टों और दस्तावेजों में इसे महत्व दिया गया है जो पिछले पचास वर्षों में सामने आए हैं। उदाहरण– गांधीजी की बेसिक शिक्षा की योजना, कोठारी आयोग की रिपोर्ट, एनसीईआरटी के दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम, ईश्वर भाई पटेल समिति की रिपोर्ट, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 और हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। शिक्षा और उत्पादकता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में एक स्वावलंबी और उत्पादक नागरिक के रूप में और सामाजिक पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय विकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में बच्चे की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।

इसे अलग–अलग समय पर और देश के विभिन्न हिस्सों में शिल्प शिक्षा (क्राफ्ट एजुकेशन) (1937), कार्यानुभव (वर्क एक्सपीरियंस) (1967), सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क) (1977) जैसे अलग–अलग नामों से शुरू और लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) ने सभी चरणों में स्कूली पाठ्यक्रम में शिक्षा का काम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया है।

टिप्पणी

कोठारी आयोग द्वारा कल्पना के रूप में स्कूल के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) ने कार्य अनुभव की अवधारणा पर फिर से जोर दिया। एनपीई कहता है– "कार्य अनुभव जिसे उद्देश्यपूर्ण, सार्थक, मैनुअल कार्य के रूप में देखा जाता है। कार्य अनुभव में छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और जरूरतों, कौशल के स्तर और ज्ञान को शिक्षा के चरणों के साथ उन्नत करने के अनुसार गतिविधियां शामिल होंगी। यह अनुभव एक छात्र को कार्यबल में प्रवेश करने पर मददगार होगा।"

सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और व्यावसायिक शिक्षा

ईश्वर भाई पटेल समिति– (1977) : इस समिति ने कार्यानुभव को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का नाम देते हुए, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया। इस समिति ने छह आधारभूत आवश्यक क्षेत्रों की पहचान की यथा– भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संस्कृति और मनोरंजन तथा सामुदायिक कार्य व समाज सेवा। कार्यानुभव के क्रियाकलाप इन्हीं क्षेत्रों के इर्द–गिर्द विकसित किए जाने का सुझाव दिया। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW), जहां तक संभव हो, मुख्यतः मैनुअल होना चाहिए। बच्चों और समुदाय की आवश्यकताओं से संबंधित उद्देश्यपूर्ण, उत्पादक कार्य और सेवाएं शिक्षार्थी के लिए सार्थक सिद्ध होंगी। इस तरह के काम को यांत्रिक रूप से नहीं किया 10जाना चाहिए, लेकिन इसमें हर स्तर पर योजना, विश्लेषण और विस्तृत तैयारी शामिल होनी चाहिए, ताकि यह शैक्षिक रूप से सार हो। उन्नत उपकरण और सामग्री को अपनाना, जहां उपलब्ध हो और आधुनिक तकनीकों को अपनाने से प्रौद्योगिकी के आधार पर एक प्रगतिशील समाज की जरूरतों की सराहना होगी।

पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम

भारत में व्यावसायिक शिक्षा को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कौशल विकास के वर्तमान परिदृश्य और स्कूल व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

- **परिचयात्मक सत्र**– प्राचीन शिक्षा पद्धति महान विचारकों, दार्शनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए विचारों का वर्णन करती है, जो व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर आधारित हैं। यह व्यक्तिगत रोजगार और राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व पर एक नींव भी बनाता है, जिसे समय–समय पर भारत सरकार द्वारा गठित शिक्षा पर विभिन्न आयोगों द्वारा जोर दिया गया था।
- **दूसरा सत्र**– यह सत्र अपनी प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से भारत में कौशल विकास के परिदृश्य का वर्णन करता है, जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच

समन्वित कार्रवाई, सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक कौशल का एकीकरण, कौशल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन।

- **तीसरा सत्र**– यह सत्र कक्षा IX और X में कार्य अनुभव कार्यक्रम, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम और कक्षा XA और XIA में माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिक शिक्षा की पूर्ववर्ती योजना से संबंधित है। यह प्रशिक्षुओं को स्कूली शिक्षा का व्यावसायिक विकास, प्रगति और मुद्दों को समझने में मदद करेगा। कक्षा आठवीं तक के कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया गया।
- **चौथा सत्र**– चौथा सत्र पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करता है। कक्षा IX से XIA तक कक्षा छठी से आठवीं और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से शुरू किया जाएगा। यह कक्षा IX से XIA तक स्कूल व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का वर्णन करता है जो स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रत्येक घटक के महत्व की समझ प्रदान करते हैं।

टिप्पणी

अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की परिकल्पना की जा रही है। छठी से आठवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा का व्यावसायीकरण समदर्शी शिक्षा के तहत (स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना) सामान्य शैक्षणिक विषयों के साथ कौशल आधारित गतिविधियों को जोड़ने के लिए विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान, आदि यह उपलब्ध कराने में उपयोगी होगा। बहु–कौशल गतिविधियों, अन्य बातों के साथ होगा, सौन्दर्य कौशल जैसे सौंदर्य मूल्यों के विकास को बढ़ावा देना, सहयोग, टीम–वर्क, कच्चे माल का विवेकपूर्ण उपयोग, रचनात्मकता, गुणवत्ता, चेतना आदि। छात्र संगठन, अलग–अलग व्यवसायों में संलग्न लोग, आनंदमय ज्ञान के लिए और भविष्य के रोजगार के संभावित क्षेत्रों से संबंधित कौशल। भाषाओं, गणित, विज्ञान के सामान्य शिक्षा शिक्षक, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत और कार्य अनुभव शामिल होंगे। विषयों से संबंधित कौशल–आधारित गतिविधियों के संगठन में वे सिखा रहे हैं।

डिजाइन, शिल्प और प्रौद्योगिकी सामान्य शिक्षा का हिस्सा बन जाएगी, जो कि करियर में छात्रों की अधिक संख्या और विविधता को आकर्षित करने में मदद करती है। मुलायम और कठिन कौशल पर व्यावसायिक अनुखंड (मॉड्यूल) बच्चों को मदद करेगा। काम की दुनिया के आवश्यक पहलुओं का पता लगाएं और उन्हें तैयार करें। व्यावसायिक विषय या करियर विकल्प चुनने के लिए व्यावसायिक कौशल घटकों के लिए, गतिविधियों के आधार पर सामान्य शिक्षा विषयों के लिए पाठ्यक्रम में दिए गए विषय होंगे।

आधुनिक औद्योगिक विकास के साथ पारंपरिक शिल्प

शिल्प उत्पादन के लिए औद्योगिक क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया। क्रांति के बाद, निर्माताओं ने कुछ शिल्प उत्पादों का उत्पादन किया जो पहले हाथ से बनाए गए थे। कुछ मामलों में, यह पहचानना मुश्किल है कि कुछ उत्पाद उत्पादकों (मैन्युफैक्चरर्स) द्वारा बनाए गए या हाथ से। उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी के कारण लगभग सभी हस्तनिर्मित उत्पाद निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। कुछ उद्योगों को शिल्प उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में विचार किया गया

है। इन परिस्थितियों में, कुछ विद्वानों का तर्क है कि शिल्प को मुख्य रूप से हाथ से बनाया जाना चाहिए (चाट्रैंड, 1989; दोंटो, 1964; फिलिस, 2008; लीके, 1994; मेटकाफ, 1993)। हाथ से बनाई गई कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। कूपर एंड लाइब्रांड (1994) ने सुझाव दिया कि शिल्प उद्योग को दो प्रकारों में विभेदित किया गया है–

1. हस्तशिल्प (हैंडिक्राफ्ट) उद्योग और
2. शिल्प (क्राफ्ट) आधारित उद्योग (कूपर एंड लाइब्रांड जैसा कि फिलिस, 2008, पृष्ठ 137) में उद्धृत है।

टिप्पणी

शिल्प को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया किया गया है–

1. औद्योगिक शिल्प और
2. हस्तकला (फिलिस, 2008)।

हस्तकला उद्योग के उत्पाद मुख्य रूप से हाथ से बनाए जाते हैं, जबकि क्राफ्ट आधारित उद्योग के उत्पाद मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग में मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। अतीत के साथ संबंध समकालीन शिल्प और पारंपरिक शिल्प को अलग करता है। समकालीन शिल्प में आमतौर पर अतीत का कोई संदर्भ नहीं होता है जबकि पारंपरिक शिल्प तकनीक, दृश्य संकेतों, अर्थों और विचारों के लिए अतीत को देखता है। कुछ शिल्प उद्योग, दोनों समकालीन और पारंपरिक शिल्प आधुनिकतावादी सिद्धांतों का पालन करते हैं। पारंपरिक शिल्प उद्योग समृद्ध संभावनाएं प्रदान करते हैं। उन्हें सामाजिक परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक होने के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है।

पिछले दशक में सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के द्वारा, कई संचार प्रदाताओं द्वारा प्रदान किया गया कवरेज क्षेत्र अब इंडोनेशिया में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। यह सुविधा शिल्पकारों और उनके रिश्तेदारों, जैसे खरीदारों, पूंजी या सामग्री प्रदाताओं, सरकार और अन्य संस्थानों के बीच लेनदेन और बातचीत की प्रक्रिया को सुचारू करती है।

निष्कर्ष में, शिल्प उद्योग का अपना सौंदर्य मूल्य है, जो सामग्री, श्रमिकों के कौशल और उसके ऐतिहासिक मूल्य पर निर्भर करता है। जैसा कि पारंपरिक शिल्प की विशिष्ट विशेषता हाथ से निर्मित उत्पादन है, नवाचार रणनीति को इस विशेष शिल्प कौशल पर प्रतिबिंबित करना चाहिए। अंत में, शिल्प उद्योग अपने उत्पादों को विकसित करने में व्यक्त सौंदर्यवादी मूल्य के बजाय उपयोगितावादी मूल्य पर विचार करते हैं।

1.2.4 मानव संसाधन विकास के साधन के रूप में व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य और समस्याएं

व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों, उद्देश्यों और समस्याओं को क्रमशः इस प्रकार समझा जा सकता है–

• **लक्ष्य** – अब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विकसित हो रहा है। यह सामग्री और मानव संसाधनों की उपलब्धता के कारण संभव हुआ है। हमारा देश इन दोनों संसाधनों से बहुत समृद्ध है। जरूरत है उनके समुचित उपयोग की। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार और विकास की आवश्यकता है।

"तकनीकी जानकारी" के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए समय की आवश्यकता व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है।

1. व्यवसाय की दुनिया में एक पुरस्कृत जगह में प्रवेश करने और खोजने में मदद करना।
2. उनकी क्षमताओं के आधार पर आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाना।
3. अव्यक्त रचनात्मक आवेगों की रिहाई और व्यवसाय के माध्यम से व्यक्तिगत पर्याप्तता की भावना को बढ़ाना।
4. ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करना और बेरोजगारी और विनाश को दूर करना।
5. उत्पादकता और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना।
6. अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों के लिए मध्यम स्तर की शक्ति को प्रशिक्षित करना।
7. मध्यम स्तर की नौकरियों के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना जो उद्योग और सेवा क्षेत्र में प्रत्याशित हो सकते हैं।
8. कृषि, लघु उद्योगों, सेवा जैसे मरम्मत आदि में स्व–रोजगार के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना।
9. व्यक्तिगत रोजगार को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए जो न तो बहुत संकीर्ण हैं और न ही बहुत विशिष्ट हैं।
10. कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच गलत मिलान को कम करना और रोजगार के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना।
11. देश के व्यक्तियों और सामाजिक–आर्थिक विकास के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों के बौद्धिक क्षितिज को आत्मनिर्भरता और आत्म–साक्षात्कार के माध्यम से उच्च स्तर की प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना।

टिप्पणी

• **उद्देश्य** – शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने स्पष्ट दिशा दी है कि कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक हस्त (मैनुअल) कार्य के रूप में देखा जाता है, जिसे सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग के रूप में आयोजन किया जाता है और जिसके परिणामस्वरूप समुदाय के लिए उपयोगी वस्तुओं या सेवाओं को आवश्यक घटक माना जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों को उचित दिशा देने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा के समग्र उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को ज्ञान और समझ विकसित करने में मदद करती है–

1. भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कपड़े, आश्रय, मनोरंजन और सामाजिक सेवा के संबंध में उसकी जरूरतों और उसके परिवार और समुदाय की पहचान करें।
2. समुदाय में उत्पादक गतिविधियों से खुद को परिचित कराएं।
3. कच्चे माल के स्रोतों को जानें और माल और सेवाओं के उत्पादन में उपकरणों और उपकरणों के उपयोग को समझें।
4. विभिन्न प्रकार के काम में शामिल वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों को समझें।

5. उत्पादक कार्य की योजना और आयोजन की प्रक्रिया को समझें।
6. उत्पादक स्थितियों में उनकी भूमिका को समझें।
7. उत्पादक प्रक्रियाओं और कौशल के मामले में तकनीकी रूप से आगे बढ़ने वाले समाज की जरूरतों को समझें।

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को कौशल विकसित करने में मदद करती है–

1. उत्पादक कार्यों के विभिन्न रूपों के लिए उपकरणों और सामग्रियों के चयन, खरीद, व्यवस्था और उपयोग के लिए कौशल विकसित करना।
2. उत्पादक कार्य और सामाजिक सेवा स्थितियों में समस्या निवारण विधियों के अनुप्रयोग के लिए कौशल विकसित करना।
3. अधिक उत्पादक दक्षता के लिए कौशल विकसित करना।
4. नवीन तरीकों और सामग्रियों को तैयार करने के लिए अपने रचनात्मक संकायों का उपयोग करना।

व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है–

1. हस्त (मैनुअल) काम के लिए और श्रमिकों के लिए सम्मान विकसित करना।
2. सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों जैसे आत्मनिर्भरता, सहायकता, सहकारिता, टीम–वर्क, दृढ़ता, सहिष्णुता आदि को बढ़ाना।
3. उचित कार्य आदतों और मूल्यों जैसे नियमितता, समय की पाबंदी, अनुशासन, ईमानदारी, दक्षता, उत्कृष्टता के प्रति प्रेम और कर्तव्य के प्रति समर्पण का विकास करना।
4. उत्पादक कार्यों और सेवाओं में उपलब्धियों के माध्यम से आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास का विकास करना।
5. पर्यावरण के लिए एक गहरी चिंता और समाज से संबंधित, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना का विकास करना।
6. समाज की सामाजिक–आर्थिक समस्याओं के बारे में जागरूकता विकसित करना।
7. समुदाय को उत्पादक कार्यों और सेवाओं की उपयोगिता की सराहना करना।

- **कार्य**

1. व्यावसायिक शिक्षा द्वारा लोगों को अपने काम के बेहतर प्रदर्शन में मदद करना।
2. अपने कौशल को सुधारने का मौका देना।
3. व्यक्ति को एक जिम्मेदार और स्वतंत्र बनाना।
4. अपनी पसंद का कैरियर बनाना एवं इस शिक्षा के प्रमुख लाभों की पहचान करना।
5. व्यावसायिक शिक्षा से प्राप्त कुछ व्यावसायिक कौशलों का निर्माण करना एवं छात्रों को मैनुअल काम के महत्व के बारे में बताना।
6. रोजगार के अवसर पैदा करना।

7. तकनीकी कार्यक्रम अत्यधिक कुशल श्रमिकों के साथ मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करके अर्थव्यवस्था का विकास करना।

टिप्पणी

• **व्यावसायिक शिक्षा–कार्यान्वयन की समस्याएं** : व्यावसायिक शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन और रोजगार के बीच एक संबंध बनाती है, फिर भी यह पाया गया कि शैक्षणिक विषयों को व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया था। व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति बहुत खराब पाई गई और बड़े पैमाने पर उपेक्षा की गई।

1. **समाज की धारणा :** व्यावसायिक शिक्षा के प्रति समाज की सामान्य धारणा बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है। व्यावसायिक प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने में बहुत कम सक्षम रही है क्योंकि इसे राष्ट्र के विकास में प्राथमिकता के रूप में नहीं देखा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के लिए माता–पिता का असहयोगात्मक रवैया भी एक मुख्य समस्या थी क्योंकि वे सोचते हैं; यह समय और धन का अपव्यय है।
2. **अपर्याप्त धन :** आमतौर पर शिक्षा क्षेत्र को कम करके आंका गया है और तकनीकी पहलू को बहुत कम आंका गया है। भले ही सरकार के पास व्यावसायिक शिक्षा को विकसित करने के बारे में बहुत अच्छे विचार हों, लेकिन पर्याप्त धन की कमी इसके विकास में बाधा बनती है।
3. **अपर्याप्त सुविधाएं** : अधिकांश सार्वजनिक व्यावसायिक स्कूलों में कार्यशाला उपकरणों जैसी सुविधाओं का गंभीर अभाव है। यहां तक कि उन जगहों पर जहां सुविधाएं हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं और ज्यादातर खराब परिस्थितियों में हैं, खराब रखरखाव का संकेत है।
4. **शिक्षण सामग्री और सीखने की सामग्री की कमी** : इस तथ्य के अलावा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी है, छात्रों की सीखने में सहायता करने के लिए विशेष रूप से पाठ्य पुस्तकों की कमी है।
5. **योग्य और उचित प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी** : आमतौर पर व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षण पाठ्यक्रम और भी बदतर है। स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों में व्यावसायिक शिक्षा को संभालने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की कमी है। प्रशिक्षकों के लिए सेवा की खराब स्थिति का मतलब यह भी है कि उनमें से अधिकांश को तकनीकी शिक्षा से दूर दूसरे क्षेत्रों में जाने की संभावना है जहां बेहतर वेतन और समर्थन की गारंटी है।
6. **तकनीकी विकास की धीमी गति** : विकसित राष्ट्रों की तुलना में विज्ञान और तकनीकी नवाचार और विकास के क्षेत्र में धीमी वृद्धि दर्ज की है। व्यावसायिक शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर टिकी हुई है और चूंकि वैज्ञानिक नवाचारों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हम व्यावसायिक शिक्षा के स्नातकों का उत्पादन करते हैं जो दुनिया के मानकों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं हैं।
7. **भारत में प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन** : इसके अंतर्गत निम्नलिखित समस्या क्षेत्रों की पहचान की गई है–

- माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉप–आउट दर है।
- व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान में ग्रेड 11, 12 वीं में दी जाती है।
- निजी और उद्योग भागीदारी की कमी है।
- देश में व्यावसायिक संस्थानों की संख्या कम है।
- प्रशिक्षित संकायों की पर्याप्त संख्या नहीं है।
- सभी स्तरों पर व्यावसायिकता सफल नहीं हुई है।
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के नए क्षेत्रों का अभाव।
- देश में कुशल प्रशिक्षकों और शिक्षकों की तीव्र कमी।
- निरंतर कौशल उन्नयन के लिए अवसरों की कमी।
- निगरानी समिति की अनुपस्थिति।
- व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता का अभाव।
- प्रशासनिक अधिकारियों के अनियमित रवैये की समस्या।
- प्रशासनिक अधिकारियों से प्रेरणा की कमी और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के चयन में उचित योजना की समस्या।
- छात्रों के सामर्थ्य के अनुसार व्यावहारिक व्यावसायिक के लिए अपर्याप्त समय और स्थान की समस्या।
- प्रयोगशालाओं और उपकरणों की स्थिति संतोषजनक नहीं।
- व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की तुलना में छात्रों को अपने सैद्धांतिक विषयों पर अन्य विषय के शिक्षकों के दबाव की समस्या।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

1. "व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो अनुभव, दृश्य, उत्तेजना, स्नेहपूर्ण जागरुकता, रूढ़िवादी जानकारी या साइकोमोटर कौशल प्रदान करती है।" यह किसका कथन है?

   (क) जॉर्ज–दीन (ख) जॉन एफ. थाम्पसन

   (ग) महात्मा गांधी (घ) यूनेस्को

2. कौन सी शिक्षा लोगों को अपने काम के बेहतर प्रदर्शन में मदद करती है?

   (क) व्यावसायिक (ख) अव्यावसायिक

   (ग) वर्तमान (घ) विश्वविद्यालयी

1.3 व्यावसायिक शिक्षा का विकास

बच्चे के सर्वांगीण विकास और देश की भलाई के लिए व्यावसायिक शिक्षा के अनूठे महत्व को देखते हुए, लगभग सभी महत्वपूर्ण योजनाओं, शिक्षा और रिपोर्ट पर दस्तावेजों को महत्व दिया गया है जो अंतिम रूप में सामने आए हैं। गांधीजी की

बेसिक शिक्षा की योजना, कोठारी आयोग की रिपोर्ट, एनसीईआरटी का दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम, ईश्वर भाई पटेल समिति की रिपोर्ट, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 और हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। नतीजतन, व्यावसायिक शिक्षा को देखा जाना चाहिए।

टिप्पणी

शिक्षा और उत्पादकता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, एक स्वावलंबी और उत्पादक नागरिक के रूप में और सामाजिक पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय विकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में बच्चे की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे अलग–अलग समय पर और देश के अलग–अलग हिस्सों में क्राफ्ट एजुकेशन (1937), वर्क एक्सपीरियंस (1967), सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क (SUPW 1977) जैसे अलग–अलग नामों से पेश और लागू किया गया है।

1.3.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा का विकास

भारतीय शिक्षा प्रणाली ने प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करने और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने में मदद की और सामाजिक मूल्यों की भावना को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद (1863–1902), रवींद्रनाथ टैगोर (1861–1941), श्री अरबिंदो घोष (1872–1950), मोहनदास करमचंद गांधी (1869–1948), भीमराव रामजी अंबेडकर (1891–1956) और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान भारतीय दार्शनिक और विचारकों (1888–1975) ने शिक्षा प्रणाली पर अपने विचार दिए।

हमारे देश में पिछले पचास वर्षों में और विशेष रूप से पिछले बीस वर्षों में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम को शामिल करने की आवश्यकता महसूस हुई है। व्यावसायिक शिक्षा की धारणाओं में इसकी जड़ें हैं–

- सभी प्रकार के शारीरिक (मैनुअल) काम को सम्मान और प्रतिष्ठा बहाल करने के एक शक्तिशाली साधन के रूप में।
- मैनुअल श्रमिकों और सफेद कॉलर श्रमिकों के बीच के अंतर को दूर करना, किसी की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- उचित व्यावसायिक कौशल और मूल्यों के विकास के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना, छात्रों द्वारा सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्य के माध्यम से देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना।
- विशेष रूप से, व्यावसायिक शिक्षा के अनुकूल कार्य मूल्यों और आदतों को विकसित करने, काम से संबंधित आवश्यक ज्ञान प्रदान करने और उचित कार्य कौशल विकसित करने की दिशा में उचित दृष्टिकोण के निर्माण का आधार प्रदान करना।
- बच्चों को उत्पादक और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके, दिन–प्रतिदिन की जरूरतें और उनके परिवार और समुदाय को व्यावसायिक शिक्षा माध्यम से आगे चलकर बच्चों को उनके वास्तविक हितों और अभिरुचियों की खोज करने में सक्षम बना सकती है जो बाद में अध्ययन और व्यवसायों के उपयुक्त पाठ्यक्रमों का चयन करने में उनके लिए सहायक होंगे।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा का एक लंबा इतिहास रहा है। एक संक्षिप्त विवरण व्यावसायिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास के बारे में नीचे दिया गया है–

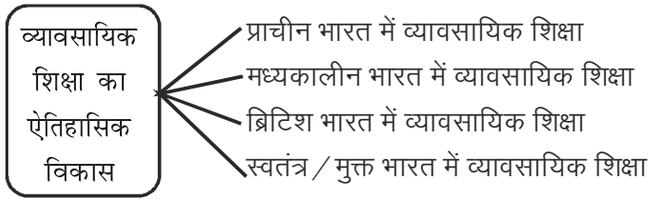

टिप्पणी

प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा

शिक्षा को व्यावसायिक आधार प्रदान करने के लिए समय–समय पर प्रयास किए गए हैं। प्राचीन भारत (वैदिक काल) में भी शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यावसायिक तरीके से सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग था क्योंकि शिष्य गुरुकुल प्रणाली में थे, जहां वे शिक्षकों के साथ रहते थे और दोनों के लिए सभी प्रकार के मैनुअल काम करते थे। काम की दुनिया और काम के जीवन के बीच कोई अलगाव नहीं था।

समय बीतता गया और जाति के रूप में नया सामाजिक स्तरीकरण विकसित हुआ और भारतीय समाज के व्यावसायिक क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाई। बच्चों ने अपने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपने माता–पिता से अलग–अलग व्यावसायिक कौशल सीखे, इसलिए इस तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण पीढ़ी–दर–पीढ़ी पारगमन के लिए तथाकथित पारंपरिक काम के लिए उपयुक्त हो गया। बौद्ध काल के दौरान, व्यावसायिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा में अपना स्थान था, जिससे छात्रों को कमाई करने में मदद मिलती थी। भिक्षुओं को गृह निर्माण, सिलाई, कताई और बुनाई, मूर्तिकला, ड्राइंग आदि के विज्ञान से परिचित होना आवश्यक था।

हमारे प्राचीन काल में प्रदर्शित 'संघ', 'गिल्ड्स', 'महाजनी स्कूल' जैसे शब्द बहुत उपस्थिति दर्शाते हैं। बौद्ध समाज में व्यावसायिक शिक्षा। इस अवधि के दौरान यह माना जाता था कि व्यापार वाला व्यक्ति समाज का एक उपयोगी सदस्य था और व्यक्तिगत काम को सभी व्यक्तियों के लिए एक कर्तव्य माना जाता था। सैन्य कला, उद्योग, चिकित्सा, पशु चिकित्सा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्राचीन भारत में, उद्योगों की योजना, निर्माण, उत्पादन और वितरण आमतौर पर औद्योगिक संस्थाओं द्वारा प्रबंधित किए जाते थे।

चिकित्सा शिक्षा का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय चिकित्सा के पिता चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर किताबें लिखी थीं। कई पशु शल्य चिकित्सकों ने अशोक के शासनकाल में राज्य के पशु चिकित्सालयों में काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन भारत में व्यवस्थित व्यावसायिक शिक्षा का कुछ रूप लंबे समय तक प्रदान किया गया था, अन्य बुद्धिमान, पुराने समय के भारतीय समाज ने इतनी व्यावसायिक दक्षता और आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं की होगी।

मध्यकालीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा

मध्ययुगीन काल में, मुस्लिम शासकों में से कई ने व्यावसायिक शिक्षा को जारी रखा। अकबर की अवधि के दौरान, व्यावसायिक शिक्षा को एक महान प्रेरणा मिली। कला और शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई। उनके काल

टिप्पणी

में लोक निर्माण विभाग बनाए गए। इसके अलावा, फिरोज शाह तुगलक ने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत उद्योगों का एक नियमित विभाग बनाए रखा और कुछ कार्यशालाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में बदल दिया।

जहांगीर और शाहजहां के समय में कला और शिल्प संपन्न थे। युद्ध–वस्तुओं के उत्पादन ने हस्तशिल्प के विकास में भी मदद की। नावों, जहाजों और रथों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। कला के लिए कला का अस्तित्व नहीं था, बल्कि आजीविका और साधन प्रदान करने के लिए भी था। इस तरह के हस्तशिल्प का प्रशिक्षण युवाओं को पारंपरिक पारिवारिक संस्थानों में दिया जाता था।

ब्रिटिश भारत में व्यावसायिक शिक्षा

अंग्रेजों के आगमन के साथ, व्यावसायिक शिक्षा और भारत में तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई और इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और शिक्षा की व्यवस्था को चलाने के लिए केवल सक्षम और वफादार क्लर्कों को प्रशासन चलाने और ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करना था जो रक्त और रंग में भारतीय थे लेकिन स्वाद और शिष्टाचार में ब्रिटिश थे। इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार ने एक संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ पूरी प्रणाली विकसित की। हालांकि, ब्रिटिश शासन के बाद के हिस्से में पहले की नीति से थोड़ा विचलन हुआ और व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए कुछ प्रयास किए गए।

स्वतंत्र भारत में व्यावसायिक शिक्षा

स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यावसायिक शिक्षा का विकास इसके प्रचार के लिए विशेष रूप से स्थापित किए गए विभिन्न आयोगों द्वारा जोर देने के लिए चिह्नित किया गया है, जैसे– 1948 का राधाकृष्णन आयोग, 1952 का मुदलियार आयोग, 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग। शिक्षा के व्यावसायीकरण की जोरदार सिफारिश की गई थी। 1964–66 के कोठारी आयोग द्वारा और उसके बाद आदिशैय्या समिति (1978 में करना सीखना), शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 और कार्ययोजना, 1992 आदि। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में कहा गया है कि "व्यवस्थित, अच्छी तरह से नियोजन की शुरुआत और व्यावसायिक शिक्षा का सख्ती से लागू किया गया कार्यक्रम अशिक्षित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है।"

व्यावसायीकरण के माध्यम से मानव जीवन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था, क्योंकि यह बुनियादी ज्ञान, कौशल को सशक्त बनाता है और बढ़ाता है। क्षमता, योग्यता, रुचियां और निपटान। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा ने उचित ध्यान दिया लेकिन बदलते श्रम बाजार के रुझान के अनुरूप हमेशा नए सिरे से जोर देने की जरूरत है। आज तक भारतीय छात्रों में व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता कई कारणों से काफी हतोत्साहित करने वाली है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा 'माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिकता' योजना के तहत माध्यमिक स्तर पर पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को संदर्भित करती है।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम 1976–77 में सामान्य शिक्षा संस्थानों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। देश में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा के बाद 1985 में गठित नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन (कुलानंदीस्वामी समिति) ने प्रोग्रामों के विस्तार के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किए। इसके बाद, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) विकसित की गई थी जो 1988 से लागू की गई थी। सिफारिशों को बाजार की

मांग के आधार पर व्यक्तिगत रोजगार और कुशल जनशक्ति के उत्पादन में वृद्धि पर अनुमान लगाया गया था और इस प्रकार विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा का पीछा करने वालों के लिए एक विकल्प के रूप में दिखाई दिया।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा 1989 में स्कूल स्तर पर प्रासंगिक सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड के माध्यम से पूर्वगामी स्तर तक थी। इसकी गतिविधि मूल रूप से 1992 में शुरू हुई थी और इसके संचालन क्षेत्र को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर और कृषि, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, गृह विज्ञान और आतिथ्य, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी बढ़ाया गया था। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के व्यापक उद्देश्य के साथ भी कार्य करता है।

टिप्पणी

भारत में व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से वोकेशनलिसेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 'नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्कूल ग्रेड 11 और 12 में पेश किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संदर्भित करती है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (VEP) 1976–77 में सामान्य शिक्षा संस्थानों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनलिसेशन ऑफ एजुकेशन (कुलानंदीस्वामी समिति, 1985) ने देश में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा की और कार्यक्रम के विस्तार के लिए दिशानिर्देश विकसित किए। इसकी सिफारिशों ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण (वोकेशनलाइजेशन) पर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के विकास का नेतृत्व किया, जो 1988 से लागू होना शुरू हुआ।

1.3.2 आयोगों और समितियों की सिफारिशें

टिप्पणी

स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर आयोगों, समितियों, योजना, नीति के सुझाव एव सिफारिशें

• **वुड्स डिस्पैच (1854)**: वुड्स डिस्पैच 1854 में इंगित की गई थी और सरकार ने व्यावहारिक की ओर ध्यान दिया लेकिन व्यावहारिक रूप से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यावसायिक शिक्षा की एक औपचारिक प्रणाली की आवश्यकता का पता 1854 में लगाया जा सकता है, जब लॉर्ड चार्ल्स वुड ने भारत की शैक्षणिक व्यवस्था पर 'वुड्स डिस्पैच' के रूप में लोकप्रिय एक डिस्पैच तैयार किया, जिसे 'मैग्ना कार्टा' के रूप में जाना जाता है। वुड्स डिस्पैच द्वारा सामान्य शिक्षा के विविधीकरण के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता का सुझाव दिया।

• **हंटर कमीशन (1882)**: हंटर कमीशन (1882) ने शिक्षा की समस्याओं की जांच की और सिफारिश की कि उच्च विद्यालय के स्तर पर शिक्षा की दो विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए – एक उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए और दूसरी व्यावहारिक व्यवसायों के लिए। दूसरे शब्दों में, इसने हाई स्कूल के उच्च कक्षाओं में पाठ्यक्रमों के द्विभाजन पर जोर दिया – एक विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा (मैट्रिक) और दूसरा व्यावहारिक जीवन के लिए युवाओं को व्यावसायिक या गैर–साहित्यिक के लिए तैयार करना। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और संस्था की परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक परीक्षा हर प्रांत में आयोजित की जाने लगी। लेकिन यह योजना अलोकप्रिय रही।

• **राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (1905–1921)**: राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ने एक नए युग और शिक्षा को जोड़ा। भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा को जन्म दिया। यह महसूस किया गया कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए। कलकत्ता कांग्रेस (1906) के संकल्प के साथ इस आंदोलन को बल मिला कि देश भर के लोगों के लिए समय आ गया है कि वे लड़के और लड़कियों दोनों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का सवाल उठाएं और शिक्षा, साहित्यिक वैज्ञानिक और तकनीकी की व्यवस्था करें।

• **हार्टोग कमेटी (1929)**: इस कमेटी ने मिडिल स्कूल चरण के अंत में विविध पाठ्यक्रमों की सिफारिश की ताकि छात्रों को औद्योगिक और वाणिज्यिक करियर के लिए तैयार किया जा सके। हार्टोग कमेटी (1929) ने पाठ्यक्रम और छात्रों के औद्योगिक और वाणिज्यिक करियर में विविधता लाने का सुझाव दिया। इस सिफारिश का नतीजा यह हुआ कि प्रांतीय सरकारों ने तकनीकी, वाणिज्यिक या कृषि हाई स्कूल शुरू किए और गैर–साहित्यिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले स्कूलों की सहायता के लिए बड़े अनुदान देने शुरू कर दिए। इस विकास ने माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक व्यावसायिक या प्रचलित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कुछ प्रभावी उपायों की शुरुआत में मदद की।

• **वुड और एबट आयोग (1937)**: वुड एंड एबट रिपोर्ट (1937) ने छात्रों की आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा में मैन्युअल गतिविधियों के महत्व पर बल दिया। शिक्षा में मैनुअल काम के महत्व पर जोर दिया और सुझाव दिया कि–

(1) व्यावसायिक शिक्षा को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए और किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र को कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।

(2) व्यावसायिक शिक्षा साहित्यिक और विज्ञान शिक्षा के बराबर मानी जाती है और इसके मानक को उठाया जाना चाहिए।

टिप्पणी

(3) व्यावसायिक शिक्षा को अन्य प्रकार की शिक्षा का पूरक माना जाना चाहिए।

(4) छोटे उद्योगों में लगे कुशल श्रमिकों को भी उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(5) व्यावसायिक शिक्षा के लिए दो प्रकार के विद्यालय होने चाहिए– पहला जूनियर वोकेशनल स्कूल और दूसरा सीनियर वोकेशनल स्कूल होना चाहिए। ग्रेड VIII के बाद जूनियर स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा के लिए तीन साल का कोर्स होना चाहिए। सीनियर स्कूल में, ग्रेड XI के बाद दो साल का व्यावसायिक शिक्षण होना चाहिए। जूनियर वोकेशनल स्कूल को एक हाई स्कूल के बराबर माना जाना चाहिए और वरिष्ठ को एक इंटरमीडिएट कॉलेज के बराबर होना चाहिए।

(6) व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद सम्मानित किया गया प्रमाणपत्र, उम्मीदवार द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

(7) व्यावसायिक स्कूल व्यावसायिक केंद्रों के पास स्थापित किए जाने चाहिए।

(8) अंशकालिक कक्षाएं विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के लिए खोली जानी चाहिए।

(9) श्रमिकों को व्यावसायिक स्कूलों में 2–1 के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रति सप्ताह 2 दिन और उन्हें इन 2–1/2 दिनों के लिए पूर्ण वेतन दिया जाना चाहिए।

(10) अंशकालिक स्कूलों में, दिन के समय प्रशिक्षण के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

• **सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (1938)**: महात्मा गांधी (1937) ने जोर देकर कहा कि मैनुअल और उत्पादक कार्यों को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए।1938 में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने वर्धा एजुकेशन स्कीम (Nai Taleem of Mahatma Gandhi) पर श्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी प्रांतीय सरकारों में नैटलेबी को लागू करने की सिफारिश की। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को जाकिर हुसैन समिति और 'बेसिक शिक्षा' (बुनियादी शिक्षा) द्वारा व्यावहारिक रूप दिया गया था।

1938 में प्रारंभिक चरण के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न के रूप में स्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी, जिन्होंने पहली बार स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में न केवल मैनुअल और उत्पादक कार्य पर जोर दिया, बल्कि एक कार्य उन्मुख शिक्षा भी पेश की। 22–23 अक्टूबर, 1937 को वर्धा राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन में उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को ठोस रूप दिया, जिसे भारतीय शिक्षा के इतिहास में बुनियादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद काम करने की शिक्षा के लिए कई वैचारिक संस्करण दिए गए हैं।

टिप्पणी

• **सार्जेंट प्लान (1944):** सार्जेंट प्लान ने उच्च विद्यालयों को दो प्रकार के विद्यालयों में फिर से बनाने की सिफारिश की– शैक्षणिक उच्च विद्यालयों को कला और शुद्ध विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के रूप में कल्पना की गई, जबकि तकनीकी उच्च विद्यालयों में प्रशिक्षण देने के लिए संस्थानों के रूप में कल्पना की गई थी। विज्ञानों के साथ–साथ औद्योगिक और वाणिज्य विषय, ग्रामीण पाठ्यक्रम, लड़कियों की शिक्षा में घरेलू विज्ञान एक विकल्प के रूप में प्रमुख सिफारिशों पर जोर दिया।

उन्नीस सौ चालीस के दशक में नियमित स्कूल प्रणाली के बाहर, शिल्प शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक और सचिवीय अभ्यास की तैयारी के अवसरों के प्रावधान में कुछ स्वस्थ विकास थे। इससे माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इनमें से कुछ सुविधाएं थीं–

1. प्रशिक्षण–तकनीशियनों के लिए पॉलिटेक्निक।
2. कुशल और अर्ध–कुशल श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक संस्थान।
3. सचिवीय और वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों का परिचय।
4. पैरा–मेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण के वित्तपोषण के लिए प्रावधान।
5. कृषि में मध्यम स्तर के श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम।

स्वतंत्रता के बाद भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर आयोगों, समितियों, योजना, नीति के सुझाव एवं सिफारिशें

• **राधाकृष्णन/विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49):** विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य शिक्षा की एक प्रणाली में छात्रों को व्यावसायिक आधार देने के लिए दसवीं कक्षा के अंत में बड़ी संख्या में इंटरमीडिएट कॉलेज खोलने की सिफारिश की गई। आयोग ने भी सिफारिश की थी, उसने मध्यवर्ती चरण को जोड़ने, माध्यमिक शिक्षा की अवधि को एक वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय के चरण में तीन साल के डिग्री कोर्स की योजना बनाने की मांग की थी। प्रचलित दो वर्षीय प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम। इसने पाठ्यक्रम के विविधीकरण की भी सिफारिश की।

बहुउद्देशीय विद्यालयों को माना जाता था कि वे प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कला और गृह विज्ञान में आवधिक (टर्मिनल) पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और छात्रों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाने में मदद करते हैं और विश्वविद्यालय के प्रवेश पर दबाव कम करते हैं।

इसने ग्रामीण विद्वानों के साथ–साथ बागवानी, पशुपालन और कुटीर उद्योगों में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में कृषि का सुझाव दिया। इसने सिफारिश की कि सह–शैक्षिक या मिश्रित विद्यालयों में लड़कियों को गृह विज्ञान, सुई काम, ड्राइंग, पेंटिंग और संगीत जैसे विषय पढ़ाए जाएं।

• **माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53):** माध्यमिक शिक्षा आयोग जो मुख्य रूप से माध्यमिक और शिक्षक शिक्षा पर केंद्रित था, ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप बहुउद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना हुई। इन स्कूलों ने कृषि, गृह विज्ञान, व्यवसाय और वाणिज्य, ललित कला और मानविकी में एक या अधिक व्यावहारिक पाठ्यक्रम पेश किए। और यह भी घोषित किया कि प्रत्येक हाई स्कूल के छात्र को शिल्प की सुझाव सूची से एक शिल्प चुनना होगा।

टिप्पणी

• **कोठारी आयोग (1964–66)**: प्रो. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग (1964–66) देश में संपूर्ण शैक्षिक दृश्य का व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास करने वाला शायद पहला आयोग था। कोठारी आयोग ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। आयोग ने कार्य अनुभव की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है क्योंकि यह महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा के अपने दर्शन में परिभाषित किया गया है और इसे सड़क औद्योगीकरण पर शुरू किए गए समाज के संदर्भ में उनके विचारों के पुनर्वितरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

आयोग ने शिक्षा का एक राष्ट्रीय प्रतिमान विकसित किया जो उस समय तक अस्तित्व में नहीं था। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षा के विकास और विकास के लिए शिक्षा को जोड़ने के लिए प्रमुख और महत्वपूर्ण उपकरण होने पर इसका स्पष्ट अवलोकन था।

मुख्य सिफारिशें

(1) शिक्षा की 10 + 2 + 3 प्रणाली का एक राष्ट्रीय पैटर्न।

(2) सामान्य शिक्षा के दस वर्षों में कार्य अनुभव।

(3) नामांकन के 50% के संभावित कवरेज के साथ 2 चरण में व्यावसायीकरण।

यह सुनिश्चित करने के लिए–

- स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से प्रतिभाशाली बच्चे के लिए पर्याप्त अवसर के साथ चरित्र में टर्मिनल होना चाहिए, मुख्य धारा में फिर से शामिल होने और आगे के अध्ययन के माध्यम से उच्चतर होने के लिए माध्यमिक शिक्षा तेजी से और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक होनी चाहिए और उच्च शिक्षा में, कृषि और तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों और लड़कियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न अंशकालिक और पूर्णकालिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में स्थित उन सभी प्राथमिक स्कूलों को अपने कार्यक्रम के लिए एक कृषि उन्मुखीकरण देना चाहिए।
- कार्य अनुभव कार्यक्रम एक कार्यशाला में, घर में, स्कूल में उत्पादक कार्य, एक कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक स्थिति में। यह अनुशंसित कार्य अनुभव, जिसमें सार्थक मैनुअल काम, एक अनिवार्य घटक होना चाहिए। इसे सीखने वालों के लिए सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए। मैनुअल वर्क, आत्मनिर्भरता, सहकारिता, दृढ़ता के मूल्य, सहायकता, कार्य नैतिकता, दृष्टिकोण और इससे संबंधित मूल्य समुदाय के उपयोगी होना चाहिए– यह सिफारिशें कीं।

• **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)**: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय एकीकरण और अधिक से अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए 'कट्टरपंथी पुनर्गठन' और शैक्षिक अवसरों के समीकरण के लिए नीति प्रदान की। ऐसी पहली नीति 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के अधीन आई थी। इस नीति से पहले, 1964 में कांग्रेस के सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिन्होंने

शिक्षा और केंद्र पर पर्याप्त ध्यान न देने के लिए सरकार की आलोचना की थी और शिक्षा के लिए एक समान दृष्टि और निश्चित दर्शन का अभाव था।

सरकार इस बात पर सहमत थी कि शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय और समन्वित नीति होनी चाहिए। सरकार ने तब यूजीसी के चेयरपर्सन डीएस कोठारी (कोठारी आयोग) के तहत 17 सदस्यीय शिक्षा आयोग का गठन किया। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जारी की गई थी। इस नीति ने एक राष्ट्रीय स्कूल प्रणाली का आह्वान किया था, जिसका अर्थ था कि सभी छात्र, जाति, पंथ और लिंग के बावजूद, एक तुलनात्मक शिक्षा तक पहुंच बना सकते हैं।

टिप्पणी

मुख्य सिफारिशें

- शिक्षा के सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 6% तक बढ़ाएं।
- शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता प्रदान करें।
- तीन–भाषा सूत्र– राज्य सरकारों को एक आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन को लागू करना चाहिए, अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, और गैर में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी– हिंदी भाषी राज्य। सभी भारतीयों के लिए एक समान भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को समान रूप से प्रोत्साहित किया गया।
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (TVE) के लिए सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- इसके अलावा, इसने एक सामान्य शैक्षिक संरचना (10 + 2 + 3) की परिकल्पना की, जिसे देश भर में स्वीकार किया गया था और हम में से अधिकांश ने उस प्रणाली के तहत अध्ययन किया है।
- अनुभव और राष्ट्रीय सेवा– स्कूल और समुदाय को आपसी सेवा और सहायता के उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से करीब लाया जाना चाहिए। कार्य–अनुभव और राष्ट्रीय सेवा,सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सार्थक और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों में भागीदारी के अनुसार शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। स्व–सहायता, चरित्र निर्माण और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना विकसित करने पर होना चाहिए।
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं के प्रावधान मोटे तौर पर आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए, इन कार्यक्रमों में जोर दिया।
- विकासशील अर्थव्यवस्था और वास्तविक रोजगार के अवसर, कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, गृह प्रबंधन, कला और शिल्प, सचिवीय प्रशिक्षण, आदि जैसे क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं में विविधता लानी चाहिए। यह सिफारिशें कीं।

• **केंद्रीय शिक्षा बोर्ड (1975)**: एनसीईआरटी को विविध पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा और कार्यक्रम को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद की। तदनुसार, 'उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और इसके व्यावसायीकरण' नामक एक दस्तावेज 1976 में NCERT द्वारा तैयार किया गया था। दस्तावेज में पाया गया कि पिछले दो वर्षों की स्कूली शिक्षा (जिसे उच्चतर माध्यमिक

कहा जाता है) की विशेषता विविधता है, जिसका उद्देश्य बचना है। छात्रों को अकेले अकादमिक चैनल के लिए मजबूर करना और उन्हें उनके रोजगार बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ, उनके दृष्टिकोण, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के बहुत व्यापक क्षेत्र में विषयों और अध्ययन के कार्यक्रमों को चुनने के अवसर प्रदान करना।

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने और बड़ी संख्या में विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में स्वरोजगार कौशल विकसित करने के लिए विविध पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुशल जनशक्ति विकसित करना है। यह देखते हुए कि केवल 7 से 10 प्रतिशत आबादी ही अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में लगी हुई है, व्यावसायिक शिक्षा का विकास अनौपचारिक क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति प्रदान करेगा जो उत्पादकता को और बढ़ाएगा।

• **ईश्वर भाई पटेल समिति (1977)**: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सितंबर 1976 में 'उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और इसके व्यावसायिक' शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। दस्तावेज में व्यावसायिक आधार पर कौशल की आवश्यकताओं का निर्धारण करते हुए, वृत्ति (वोकेशन) के विकल्प में लचीलापन लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। ईश्वर भाई पटेल समिति (1977) ने तदनुसार, इस योजना को देश के लगभग सभी माध्यमिक स्कूलों में शुरू किया था और इस उद्देश्य के लिए समय–सारणी में एक अवधि आवंटित की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों, श्रम की गरिमा के लिए पसंद और प्यार को विकसित करना था। शुरू करने के लिए, SUPW के कार्यान्वयन के लिए बहुत उत्साह था। लेकिन, जैसे–जैसे समय आगे बढ़ा, पहल और उत्साह धीरे–धीरे कम होता गया। वास्तव में, मूर्त परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था।

• **आदिशेशैया समिति (1978)**: वर्ष 1978 में, +2 चरण के लिए मैकलम एस. अदिशेशैया की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त की गई और रिपोर्ट को हाथों से काम करके सीखना (लर्निंग टू डू), 'समाज के लिए कार्य करना सीखना' (लर्निंग एंड वर्किंग सोशल) की ओर रखा गया। इस समिति को विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। इसने स्कूल स्तर पर SUPW और उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए भी सिफारिश की। इसने उत्पादकता से संबंधित शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वाक्पटुता प्रदान की। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) के अनिवार्य परिचय के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिफारिश की।

समिति की प्रमुख सिफारिशें थीं–

(1) सीखना सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य पर या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से होना चाहिए।

(2) व्यावसायिक पाठ्यक्रम कृषि और संबंधित ग्रामीण व्यावसायिक क्षेत्रों में होना चाहिए।

(3) सामान्य और व्यावसायिक शैक्षिक स्पेक्ट्रम में पाठ्यक्रमों की कठोर स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। सुविधाओं की उपलब्धता और क्षेत्र की मांग के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को इस तरह के सामान्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

टिप्पणी

(4) उच्चतर माध्यमिक चरण में एक सामान्य शिक्षा विस्तार (स्पेक्ट्रम) और एक व्यावसायिक विस्तार (स्पेक्ट्रम) शामिल होना चाहिए।

(5) पाठ्यक्रम इतना संरचित होना चाहिए कि पाठ्यक्रम अच्छी तरह से जुड़े अनुखंड (मॉड्यूल) के निर्देश प्रशिक्षुओं को प्रदान करने के लिए और छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें चुनने और गठबंधन करने में सक्षम बनाया जा सके।

(6) प्राथमिकता के आधार पर पुस्तकों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निर्देश प्रदान करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लिखा जाना चाहिए।

(7) सेमेस्टर स्वरूप (पैटर्न) और आकलन प्रणाली (क्रेडिट सिस्टम) को ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में पेश किया जाना चाहिए।

(8) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 3 या 4 स्कूलों के समूहों में परामर्श (काउंसलिंग) और नौकरी दिलाने वाले (प्लेसमेंट) अधिकारियों के साथ शुरू करने के लिए।

(9) ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं जिन्हें नौकरी पर वास्तविक अनुभव है, उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए उपयोगी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। वहां भी आवश्यक अंशकालिक शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के संबंध में स्नातकोत्तर योग्यता पर जोर नहीं होना चाहिए।

(10) शिक्षा के इस स्तर पर प्रस्तावित परिवर्तनों को लाने के लिए पूर्व–सेवा और इन–सर्विस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम दोनों को ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

• **शिक्षा पर मसौदा राष्ट्रीय नीति (1979):** इसमें में कहा गया है, "माध्यमिक शिक्षा में दोनों धाराओं के पास पाठ्यक्रम में एक मजबूत व्यावसायिक घटक होना चाहिए और उनकी संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविधता होनी चाहिए। जाहिर है, आवधिक (टर्मिनल) माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यावसायिकता अन्य धाराओं की तुलना में बहुत बड़ा घटक होगा। इस प्रक्रिया को पहले भी सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्यों के माध्यम से शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें व्यावहारिक कार्य प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का अंतरग्रहीय घटक होता है।

1979 की राष्ट्रीय नीति तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रताप चंद्र चंदर ने कुछ शिक्षाविदों और संसद के सदस्यों की मदद से एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार की और अप्रैल 1979 में इसकी घोषणा की। जिसमें उच्च शिक्षा के विकास के लिए ये बातें थीं–

1. **उच्च शिक्षा को बढ़ावा और उन्नत बनाया जाएगा**– उच्च शिक्षा का लाभ मुख्य रूप से उच्च वर्ग का युवा उठा रहा है, इसे कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए भी सुलभ बनाया जाएगा। सभी को उच्च शिक्षा के लिए समान अवसर मिलेंगे। इसी समय, शिक्षा के इस स्तर में गुणात्मक सुधार किया जाएगा, पाठ्यक्रमों को उपयोगी बनाया जाएगा। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. **व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाएगा**– सभी प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को अद्यतन

किया जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थानों में सुधार किया जाएगा, उनकी प्रयोगशाला और कार्यशालाओं को उन्नत किया जाएगा, उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

3. **शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा**– शिक्षकों के पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यावहारिक बनाया जाएगा और सेवा में शिक्षकों को अद्यतन शिक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए सेवा से संबंधित कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा।

टिप्पणी

• **कार्य समिति रिपोर्ट (1985)**: कार्यवाहक समूह, जिसकी स्थापना 1985 में प्रो. कुलानंदीस्वामी की अध्यक्षता में की गई थी, ने विभिन्न शीषर्कों के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के वर्गीकरण की सिफारिश की–

1. कृषि
2. व्यापार और वाणिज्य,
3. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी,
4. स्वास्थ्य और पैरा–मेडिकल,
5. गृह विज्ञान,
6. मानविकी और अन्य।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कल्पना की गई लक्षित जनसंख्या थी दसवीं कक्षा तक के छात्र, उच्चतर माध्यमिक छात्र, स्कूल से बाहर के समूह तृतीयक स्तर के छात्र कार्य अनुभव को पाठ्यक्रम के कुल समय का 20 प्रतिशत आवंटित किया गया था। परिकल्पना की दुनिया में काम करने का लक्ष्य क्रमशः 1990 तक 10 प्रतिशत और 1995 तक 25 प्रतिशत था।

• **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1986)**: 1986 की नीति प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जारी की गई थी। एनपीई ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण थी। 1985 के कार्य समूह द्वारा सुझाए गए मूल लक्ष्य वही थे। NPE'86 में व्यावसायिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है।

विभिन्न प्रावधान निम्नानुसार हैं–

- o व्यावसायिक शिक्षा एक दूर की धारा होगी जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों के लिए बच्चों को तैयार करने का इरादा रखती है।
- o व्यावसायिक पाठ्यक्रम +2 चरणों से शुरू किए जाएंगे। लेकिन, ये आठवीं कक्षा के बाद भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- o प्रभावी स्वास्थ्य योजना और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- o अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी कृषि, विपणन, सामाजिक सेवाओं, आदि पर आधारित होंगे।
- o स्वरोजगार पर जोर दिया जाना है।

टिप्पणी

- o वंचित वर्ग, महिलाओं, विकलांगों और ग्रामीण छात्रों को न्याय देने के प्रावधान के साथ व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
- o पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेशेवर विकास, कैरियर में सुधार, सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पार्श्व प्रविष्टि के लिए देखभाल की जाएगी।
- o नव–साक्षर, लचीले और आवश्यकता–आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम भी नव–साक्षरों, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले युवाओं, स्कूल छोड़ने वालों (ड्रॉप–आउट) और काम में लगे व्यक्तियों और बेरोजगार या आंशिक रूप से नियोजित व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- o उन युवाओं के लिए तृतीयक स्तर के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो शैक्षणिक स्ट्रीम के उच्चतर माध्यमिक चरण को पूरा करते हैं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता हो सकती है।
- o यह प्रस्तावित है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम 1990 तक उच्च माध्यमिक छात्रों के 10 प्रतिशत और 1995 तक 25 प्रतिशत को कवर करेंगे। पाठ्यक्रमों के उत्पादों के रोजगार के लिए पर्याप्त रूप से कदम उठाए जाएंगे। पाठ्यक्रमों की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी।
- o व्यावसायिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता के लिए, एक प्रभावी, समय–परीक्षण प्रबंधन प्रणाली को व्यवस्थित करना काफी आवश्यक है।

• **राममूर्ति समिति (1990)**: इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) की अपनी समीक्षा में प्रस्तावित किया कि, व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए और यह सभी स्तरों पर शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिए। व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच कोई द्वंद्वात्मकता का अभ्यास नहीं किया जाना है। यह आवश्यक है क्योंकि सामान्य शिक्षा में भी, छात्रों को कुछ क्षमता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपनी रोजी–रोटी कमा सकें।

व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को श्रम की गरिमा की भावना भी प्रदान करती है जो भारतीय समाज में सामंजस्य प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है, जो कुलीन वर्ग और श्रमिक वर्ग के आधार पर खंडित है। इस प्रकार, सभी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा तथाकथित 'ब्लू–कॉलर' व्यवसायों के लिए सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करेगी। इसके अलावा, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को रोजगार के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में निर्देशित किया जाना चाहिए।

• **शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के कार्यक्रम (1992)**: शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (NPE), 1986 (1992 में संशोधित) और 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री थे तब इसे अद्यतन किया गया था। राष्ट्रीय नीति ने जोर दिया कि–

- o शिक्षा कार्यक्रम के व्यावसायीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि माध्यमिक स्तर पर, छात्रों को कैरियर चुनने के लिए तैयार किया जाता है।
- o इसने व्यावसायिक हितों और अभिरुचियों के विकास पर बल दिया ताकि व्यावसायिक प्राथमिकताओं की आत्म–खोज की जा सके और उत्पादकता और काम में भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

- o इस नीति ने शिक्षा में आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया।
- o अध्यापक शिक्षा के पुनर्गठन, बचपन की देखभाल।
- o महिला सशक्तीकरण और वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया गया था।
- o विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्वायत्तता को भी स्वीकार किया, जिसका अतीत में विरोध किया गया था।
- o 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में 'व्यवस्थित, अच्छी तरह से योजनाबद्ध और सख्ती से लागू किए गए कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है।' स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, नीति दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि "व्यावसायिक शिक्षा एक अलग स्ट्रीम होगी, जिसका उद्देश्य छात्रों को गतिविधि के कई क्षेत्रों में फैले हुए पहचानों के लिए तैयार करना है।"
- o ये पाठ्यक्रम सामान्य रूप से माध्यमिक चरण के बाद प्रदान किए जाएंगे, लेकिन योजना को लचीला बनाए रखते हुए, इन्हें कक्षा V के बाद भी उपलब्ध कराया जा सकता है...।
- o नीतिगत अनिवार्यता को ठोस कार्यक्रमों में तब्दील करने के लिए 1986 में एक कार्ययोजना बनाई गई। यह सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के तहत एक व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (CIVE) का गठन अनुसंधान और विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यों को करने के लिए किया जाना चाहिए।
- o तृतीयक स्तर के कार्यक्रमों जैसे डिप्लोमा इन व्यावसायिक विषयों, एडवांस डिप्लोमा कार्यक्रमों और डिग्री कार्यक्रमों को चयनित पॉलिटेक्निक, संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, साथ ही विशेष संस्थानों में इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की।
- o हालांकि, कार्यान्वयन में अनुभव की गई बाधाओं के मद्देनजर, एनपीई के 1992 के संशोधित संस्करण ने व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को संशोधित किया। इस उद्देश्य के लिए नया टाइम–केस 1995 तक 10 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत और 25 प्रतिशत 2000 तक लाना था।

टिप्पणी

एन.सी.ई.आर.टी. जुलाई 1993 को एमएचआरडी द्वारा शुरू की गई पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना के लिए कार्यान्वयन रणनीति तैयार करना। पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा की योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

(1) कार्य–अनुभव के बदले पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश की जा सकती है।

(2) प्रति सप्ताह न्यूनतम छह अवधि आवंटित की जाएगी।

(3) यह केवल उन्हीं स्कूलों में शुरू किया जाएगा जहां पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम +2 चरण की पेशकश की जा रही है और नियमित बुनियादी सुविधाएं उपलध हैं।

टिप्पणी

• **स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेम वर्क (2000)**: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने भी व्यावसायिक शिक्षा (वर्क एजुकेशन) की अवधारणा और दर्शन पर जोर दिया है और इस बात पर भी जोर दिया है कि व्यावसायिक शिक्षा (वर्क एजुकेशन) से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जैसे कि सम्मान के शिक्षार्थियों के बीच झुकाव मैनुअल कार्य, आत्म–विश्वास, सहकारिता, दृढ़ता, सहायकता, सहिष्णुता और कार्य नैतिकता के अलावा व्यवहार और मूल्यों का निर्माण–उत्पादक कार्य और समुदाय के लिए चिंता से संबंधित है।

तकनीकी रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करना और उत्पादक स्थितियों में उनकी भूमिका की अवधारणा करना। कार्यक्रम शिक्षार्थियों के बीच नवीन तरीकों की पहचान, चयन, व्यवस्था और विकास के लिए कौशल विकसित करना चाहिए और कार्य प्रथाओं में अवलोकन करना, हेरफेर करना और भाग लेना और इस तरह उत्पादक दक्षता को बढ़ाना चाहिए।

NCERT (2000) द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने कार्य अनुभव के पहले नामकरण के स्थान पर एक अधिक व्यापक शब्द 'कार्य शिक्षा' का सुझाव दिया। कार्य शिक्षा की अवधारणा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक हस्त (मैनुअल) कार्य के रूप में माना है जिसके परिणामस्वरूप उन वस्तुओं या सेवाओं का परिणाम होता है जो समाज के लिए उपयोगी हैं।

कार्य शिक्षा में मानव की जरूरतों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता, भोजन, कपड़े, मनोरंजन और सामाजिक सेवा के साथ–साथ मानसिक क्षमताओं और शिक्षा के विभिन्न चरणों में बच्चों की मानसिक दक्षता और उपलब्धता के अनुसार सामाजिक विकास की गतिविधियां शामिल हैं। इसने बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय या समाज के कल्याण, विकास के लिए सामाजिक जागरूकता और चिंता पैदा करने के लिए सामुदायिक कार्य/सामाजिक सेवा को समान महत्व दिया।

• **केंद्रीय शिक्षा बोर्ड (सीएबीई) समिति रिपोर्ट, (2005)**: शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर भी निम्न सुधारों का प्रस्ताव किया है–

1. यह सुनिश्चित करना कि व्यावसायिक शिक्षा एक मृत अंत नहीं है और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की अनुमति देता है उच्च शिक्षा पर यह सुनिश्चित होगा कि व्यावसायिक स्ट्रीम को भावी छात्रों द्वारा अंतिम उपाय के विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
2. संस्थानों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्नातकों के लिए श्रम बाजार से सीधा संबंध सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन, और संगठनात्मक और उत्पादक नवाचारों को लाने के लिए एक प्रभावी माध्यम है।
3. मानविकी और विज्ञान में बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए इन कार्यक्रमों के सामान्य शिक्षा घटक को मजबूत करना, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में काम करने के लिए तैयार करना, उन्हें समस्याओं को हल करने के लिए सिखाना और उन्हें सीखने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

4. वित्त पोषण और बजट आवंटन को एक ऐसी प्रणाली से जानना जो विशेष रूप से सरकार द्वारा एक प्रणाली के लिए वित्तपोषित है जो निजी क्षेत्र द्वारा और उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने वाले छात्रों द्वारा तेजी से वित्तपोषित है। निजी क्षेत्र केवल तभी योगदान करने को तैयार होगा जब वे देखेंगे कि सिस्टम प्रासंगिक स्नातकों का उत्पादन कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा से श्रम बाजार के लाभ को देखते हुए छात्रों के योगदान की संभावना है।

टिप्पणी

• **राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 (NSD)**: राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में प्रत्येक वर्ष लगभग 12–15 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस नीति के तहत निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (भारत के माननीय प्रधान मंत्री के तत्वावधान में), समन्वय समिति और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की है। अन्य बातों के बीच यह नीति राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना का प्रस्ताव करती है।

यह नीति निम्नलिखित विशेषताओं का प्रस्ताव करती है–

1. राष्ट्रीय रूप से सहमत मानकों और मानदंडों के आधार पर योग्यता आधारित योग्यता और प्रमाणन।
2. सीखने की उपलब्धि और योग्यता के लिए प्रमाणन।
3. राष्ट्रीय योग्यता स्तरों की एक श्रेणी – सम्मान के साथ मानदंडों के आधार पर जिम्मेदारी, गतिविधियों की जटिलता और दक्षताओं का हस्तांतरण।
4. सभी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को शामिल करने का आश्वासन देते हुए दोहराव से बचने और योग्यता के अतिरेक।
5. अनुकूलित स्वरूप जहां उपलब्धि को छोटे चरणों में बनाया जा सकता है और पहचानने योग्य योग्यता प्राप्त करने के लिए संचित किया जाता है।
6. गुणवत्ता आश्वासन शासन जो कौशल और श्रम बाजार की गतिशीलता की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) को बढ़ावा देगा।
7. एक बेहतर कौशल मान्यता प्रणाली के माध्यम से आजीवन सीखने, औपचारिक सीखने की मान्यता औपचारिक, गैर–औपचारिक या अनौपचारिक व्यवस्था में है।
8. खुली और लचीली प्रणाली जो सक्षम व्यक्तियों को उच्च डिप्लोमा और डिग्री में परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को जमा करने की अनुमति देगी।
9. विभिन्न शिक्षण मार्ग – शैक्षणिक और व्यावसायिक – जो औपचारिक और गैर–औपचारिक सीखने को एकीकृत करते हैं, के लिए व्यावसायिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अपनी पसंद में व्यक्तियों के लिए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान करता है।
10. एकाधिक प्रमाणीकरण एजेंसियों/संस्थानों NVQF के भीतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी

- **राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं में व्यावसायिक शिक्षा (1951–2017)**:
  - o पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56): सामाजिक सह विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव और बुनियादी शिक्षा की इकाई के साथ सामुदायिक केंद्र।
  - o दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61): स्कूल्स में कार्यशाला और फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव।
  - o तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66): एकीकृत करने पर जोर दिया और व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति में सुधार।
  - o पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–78): "शिक्षा का मौलिक पुनर्निर्माण और लोगों का जीवन" से संबंधित परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।
  - o छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980–85): बिना शैक्षणिक मुद्दों पर जोर दिए अनुभवी शिल्पकार और कला के व्यवसायी को शामिल करने का प्रस्ताव।
  - o आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97): शिक्षा के व्यावसायीकरण की पहचान आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में की गई थी। संशोधित नीति निर्माण, जो NPE में संशोधन को आगे बढ़ाते हैं, हालांकि, लक्ष्य को 1995 तक उच्च माध्यमिक छात्रों के 10 प्रतिशत और वर्ष 2000 तक 25 प्रतिशत को संशोधित करने के लिए संशोधित किया गया था।
  - o नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002): इस योजना में ध्यान असमानताओं को कम करने, व्यावसायिक और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम विस्तार पर जोर देने के साथ पाठ्यक्रम के नवीकरण पर था। और मुक्त अधिगम प्रणाली (ओपन लर्निंग सिस्टम) का विविधीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण का पुनर्गठन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग पर था।
  - o दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07): शिक्षा को काम की दुनिया से जोड़ने के लिए कहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की पहचान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच निरंतरता है। दसवीं योजना में व्यावसायिक शिक्षा मिशन के लिए 650 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने 2000 में दसवीं योजना के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर एक अलग कार्यदल का गठन किया। कार्यसमूह की सिफारिशों के अनुरूप, केंद्र प्रायोजित योजना को दसवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था।
  - o ग्यारहवीं (2007–12) और बारहवीं (2012–17) पंचवर्षीय योजना : शिक्षा से संबद्ध केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) भी व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं और मुख्य–धारा शिक्षा प्रणाली के भीतर व्यावसायिक शिक्षा के लचीलेपन की सिफारिश करते हैं। सरकार ने 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया है।

• **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2019–20)**: इस नीति का उद्देश्य 2025 तक सभी शिक्षार्थियों को कम से कम 50% व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। व्यावसायिक शिक्षा उदार शिक्षा की वृहद दृष्टि का एक अभिन्न अंग है। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षा संस्थानों में एकीकृत व्यावसायिक शिक्षा को कौशल अंतराल विश्लेषण, स्थानीय अवसरों की मैपिंग के आधार पर चुना गया है। शिक्षक तैयारी की क्षमता और गुणवत्ता राष्ट्रीय कौशल योग्यता के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति को संबोधित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता आधार (फ्रेमवर्क) को आगे बढ़ाएगी, जो कि प्रत्येक विषय व्यवसाय/पेशे 'लोक विद्या' के लिए विस्तृत है, भारत में विकसित ज्ञान को सुलभ बनाया गया है। व्यावसायिक शिक्षा सभी शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए इस पर जोर दिया है।

टिप्पणी

1.3.3 व्यावसायिक शिक्षा : समस्याओं और गैर–कार्यान्वयन के कारण

व्यावसायिक शिक्षा की विफलता के प्रमुख कारण निम्न हैं–

1. बुनियादी शिक्षा को शहरी मध्यम वर्ग द्वारा माना जाता था कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रामीण बच्चों के लिए उपयुक्त है लेकिन अपने लिए नहीं।
2. वर्तमान शिक्षा प्रणाली की प्रमुख कमजोरी है।
3. शिक्षा और दुनिया के बीच दुविधापूर्ण संबंध।
4. सामान्य शिक्षा का अप्रतिबंधित विस्तार।
5. अपर्याप्त रोजगार के अवसर और नौकरी उत्साहजनक नहीं रही है।
6. नौकरी के पर्याप्त अवसरों की अनुपस्थिति।
7. छात्रों को मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान का अभाव।
8. अपर्याप्त वित्तीय संसाधन।
9. उपयुक्त मूल्यांकन उपकरण की कमी।
10. अनुसंधान के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कार्यशाला।
11. प्रयोगशाला की अनुपलब्धता।
12. छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लाने के लिए।
13. किए गए प्रयासों में कमी।
14. राज्य सरकारों और अन्य गैर–सरकारी एजेंसियों के सहयोग में कमी।
15. प्रतिकूल वेतन नीतियां।

समस्याएं और कठिनाइयां

1. वर्ष 1947 में आजादी के समय, भारत को शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली विरासत में मिली जो न केवल मात्रात्मक रूप से छोटी थी, बल्कि बड़े अंतर और अंतर–क्षेत्रीय के साथ–साथ संरचनात्मक असंतुलन की दृढ़ता की विशेषता थी। केवल 14 प्रतिशत आबादी ही साक्षर थी, और तीन में से एक बच्चे का नामांकन प्राथमिक विद्यालय में हुआ था।

टिप्पणी

2. 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच और सार्वभौमिक भागीदारी के लिए जब तक वे शैक्षिक कार्यक्रमों के प्राथमिक चरण को पूरा नहीं कर लेते।

3. 1950 से 1968 के बीच प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1967–68 में प्रतिधारण दर घटकर 35% रह गई। इससे पता चलता है कि नीति विवरण को कार्यान्वयन की एक विस्तृत रणनीति में अनुवादित नहीं किया गया था। नतीजतन, बड़े पैमाने पर अनुपात तक पहुंचने के लिए उपयोग, गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता और वित्तीय परिव्यय की समस्याएं वर्षों से जमा हुई हैं।

4. एनपीई, 1968 ने शैक्षिक प्रणाली में असमानताओं के उन्मूलन और स्कूल की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया। केवल नामांकन पर जोर देने के बजाय प्रतिधारण पर अधिक जोर दिया गया।

5. 1968 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई), 1986 में एनपीई, कार्यक्रम अनुयोजन (पीओए) 1986 के एनपीई में विस्तृत और 1992 में एनपीई के अद्यतन रूप ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) कार्यक्रम के लिए एक अयोग्य प्राथमिकता दी।

6. 1968 की नीति या NEP-I बहुत सफल नहीं थी। इसके बहुत से कारण थे–
   - उस समय, कार्रवाई का एक उचित कार्यक्रम नहीं लाया गया था।
   - धन की कमी थी, भारत की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी।
   - उस समय, शिक्षा राज्य सूची में थी, इसलिए केंद्र की भूमिका इस बात पर कम थी कि राज्य इस योजना को कैसे लागू करेंगे।

7. पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण– 1986 में उल्लेख किया गया है कि, नामांकन में असमानता अभी भी प्राथमिक स्तर पर राज्यों के बीच बनी हुई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए, भारत में 1986 में एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई। इस नीति में, 14 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौमिक पहुंच, नामांकन और सार्वभौमिक अवधारणा के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार पर जोर दिया गया। इस नीति ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की समस्या को हल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यह नीति में गैर–औपचारिक शिक्षा पर दिए गए जोर से स्पष्ट है।

8. दुर्भाग्य से, भारत में नीति निर्माता मुख्यधारा की शैक्षिक प्रणाली के भीतर व्यावसायिकता की निरर्थकता का एहसास करने में विफल हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति–1986 (भारत का शासन, 1986) 1995 तक भारत में माध्यमिक शिक्षा के 25 प्रतिशत व्यावसायीकरण की मांग करता है। नीति निर्माताओं ने उच्च शिक्षा की मांग को कम करने की उम्मीद में इस निरर्थक अभ्यास का नेतृत्व किया है जो वास्तव में, शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए भारत की नीतियों का एक उद्देश्य रहा है। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा की मांग को कम करने में विफल रही है। इसके अलावा, इस तरह के उद्देश्य में वैधता का अभाव है।

टिप्पणी

9. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषय की पेशकश करके, उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में संभावित प्रवेशकों को दौड़ से बाहर रखने की मांग की जाती है क्योंकि उच्च शिक्षा में प्रवेश विशेष रूप से शैक्षणिक विषय से स्कूल के स्नातकों के लिए होता है। जो लोग व्यावसायिक विषय का विकल्प चुनते हैं, वे मुख्य रूप से निचले सामाजिक समूहों से खींचे जाते हैं। इस तरीके से, माध्यमिक स्तर पर विषय वर्गीकरण के कारण उच्च शिक्षा की मांग में कमी इसके असमानताओं के कारण एक संदिग्ध उपलब्धि होगी।
10. आईटीआई के रूप में एक समानांतर ढांचे (सेट–अप) के मामले में माता–पिता को पहले से पता है कि उनके बच्चों को हस्त कार्यों (मैनुअल) वाली नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। लेकिन मुख्यधारा की शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक विषय के मामले में, माता–पिता अनजान पाए जाते हैं, उनके बच्चे उच्च शिक्षा की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। एक बड़े आकार के असंगठित क्षेत्र के कारण, एक सटीक अनुमान देना बहुत मुश्किल है। हालांकि, हम संगठित क्षेत्र की कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पा सकते हैं जिसमें कुशल कारीगर विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं; परिवहन में एक–चौथाई और बिजली, गैस और पानी में एक तिहाई (राव, 1982)। तदनुसार, कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकताएं (1985) में लगभग 10 मिलियन हो जाती हैं।
11. हालांकि, उद्योग क्षेत्र स्तर पर कई समस्याओं को देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता का उपयोग किया गया है। कई राज्यों में प्रबंधन संरचना और कमजोर उद्योग के साथ संबंध कमजोर हुए हैं। औद्योगिक विकास के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देने की कमी है।
12. शिक्षा की गुणवत्ता– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुद्दा न केवल इसलिए उपयुक्त है क्योंकि भारत सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंच रहा है, बल्कि इसलिए भी है कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन कौशल प्रदान करना चाहता है। अब तक, प्राथमिक ग्रेड के छात्रों के लिए अपेक्षित उपलब्धि स्तर की तुलना में, सीखने की उपलब्धियां, एएसईआर 2009 के अनुसार काफी असंतोषजनक हैं।
13. अधिक स्कूल छोड़ने (ड्रॉप–आउट) की दर– पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। रूढ़िवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण लड़कियों को स्कूलों में जाने से रोकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद मध्याह्न भोजन, मुफ्त किताबें और वर्दी, लड़कियों की उपस्थिति खराब है। हालांकि शादी के लिए न्यूनतम उम्र अठारह वर्ष है, लेकिन कई लड़कियों की शादी बहुत पहले हो जाती है। इसलिए, माध्यमिक स्तर पर, महिला ड्रॉप–आउट दर अधिक है।
14. सुविधाओं की कमी– 2016 की वार्षिक सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 3.5% स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं थी, जबकि केवल 68.7% स्कूलों में शौचालय की सुविधा थी। 2016 में सर्वेक्षण में शामिल 75.5% स्कूलों में पुस्तकालय था, जो कि 2017.14 में 78.1% की कमी थी। अलग–अलग लड़कियों के शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत 2010 में 32.9% से बढ़कर

2016 में 74.1% से 61.9% हो गया है और स्कूलों में 64.5% स्कूलों में खेल का मैदान था।

15. पाठ्यक्रम के मुद्दे– पाठ्यक्रमों की अप्रासंगिकता हैं। कई अलग–अलग पाठ्यक्रम प्रणालियां हैं जो छात्रों को भ्रमित करती हैं जो इंजीनियरिंग, चिकित्सा और व्यवसाय प्रशासन जैसे एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर, समान कार्यक्रम के लिए पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम (सिलेबस) में एकरूपता नहीं है। पाठ्यक्रम बिना पुनरीक्षण (रिवीजन) अक्सर किया जाता है। उद्योगों की समकालीन आवश्यकताओं पर विचार करना। कॉलेजों में विषयों में विविधता का अभाव है। विषय वर्गों को पार करने के लचीलेपन में भी कमी है।

टिप्पणी

16. प्रचलित सामाजिक स्थिति और सामाजिक दृष्टिकोण– प्रचलित सामाजिक स्थिति और सामाजिक दृष्टिकोण से संकेत मिलता है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। योजना की प्रगति को हतोत्साहित करने के लिए कई कारक बताए जा सकते हैं।

1.3.4 व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष समूहों का रोजगार

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा विशेष फोकस समूहों से जुड़े बच्चों यानी एससी, एसटी, ओबीसी, गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग और विशेष जरूरतों वाले बच्चों, इन समूहों से संबंधित लड़कियों पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया। चिह्नित अल्पसंख्यक/एससी/एसटी केंद्रित जिलों/ब्लॉकों में व्यावसायिक स्कूलों/मॉडल व्यावसायिक स्कूलों को खोलने/मजबूत करने के लिए विशेष प्राथमिकता दी।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी भागीदारी के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन का विकास करेंगे जिसके लिए योजना में धन का प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा पर एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की NIOS, IGNOU जैसे संस्थानों में विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और देश भर में शिक्षा के सुदूर मोड में शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे अन्य संस्थानों को बढ़ावा दिया।

श्रम और रोजगार के क्षेत्र में, श्रम मंत्रालय एससी के लिए विशेष प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रमों को लागू कर रहा है ताकि उन्हें कौशल उन्नयन में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके और इस प्रकार, उनके रोजगार के अवसरों में सुधार हो सके। 'कोचिंग–कम–गाइडेंस सेंटर फॉर एससी/एसटी' की योजना विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 22 केंद्रों के माध्यम से लागू की गई ताकि व्यावसायिक जानकारी के साथ–साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके और एससी/एसटी की नौकरी के लाभ के लिए आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जा सकें।

विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती की सुविधा के लिए, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGET) ने एक और योजना शुरू की है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण लड़कियों को नौकरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में आमतौर पर तकनीकी क्षमता, उद्यमशीलता और व्यावसायिक कौशल का विकास शामिल होता है। आदर्श रूप से, व्यावसायिक प्रशिक्षण

मांग–उन्मुख है और भावी नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट कौशल का निर्माण करता है। अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लड़कियों को व्यावहारिक कौशल के व्यापक सेट बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि संघर्ष समाधान, समूह निर्माण, और संचार, जो वे विभिन्न प्रकार की नौकरियों में उपयोग कर सकते हैं।

हालांकि व्यावहारिक कौशल मांग उन्मुख प्रशिक्षण हेतु अनुपूरक हो सकती है। अनुसंधान दर्शाता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की सफलता मुख्य रूप से नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक वास्तविक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को विकसित करने और लड़कियों को लक्षित करने में मदद करने के कार्यक्रमों की क्षमता पर निर्भर करती है।

टिप्पणी

लड़कियों का आर्थिक सशक्तीकरण न केवल नौकरियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, बल्कि कार्यस्थल में उनके प्रवेश के लिए सुरक्षात्मक नीति वातावरण और समुदाय–आधारित समर्थन पर भी निर्भर करता है। अधिवक्ताओं और नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं और नियोक्ताओं को लड़की के अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

कौशल की शक्ति एक नए दशक की पूर्व संध्या पर प्रासंगिक प्रशिक्षण और कौशल पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है जो युवाओं को कार्यबल में प्रवेश करने और जीवित रहने और पनपने में मदद करेगा। जैसा कि हम भूमंडलीकरण, डिजिटलीकरण, प्रवास और हरित संक्रमण के प्रमुख अवसरों और चुनौतियों का सामना करते हैं, कौशल की शक्ति को मान्यता दी जानी चाहिए।

अपनी प्रगति जांचिए

3. किस काल के दौरान व्यावसायिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा में अपना स्थान था?

   (क) प्राचीन काल (ख) मध्य काल

   (ग) बौद्ध काल (घ) वर्तमान काल

4. किस आयोग द्वारा शिक्षा में हस्त कार्य युक्त (मैन्युअल) गतिविधियों के महत्व पर बल दिया गया?

   (क) हंटर कमीशन (ख) वुड एवं एबट

   (ग) हार्टोग कमेटी (घ) सार्जेंट प्लान

1.4 प्रणाली, मॉडल, प्रगति और वर्तमान स्थिति

शिक्षा न केवल दक्षता बढ़ाने का एक उपकरण है, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी को व्यापक और संवर्धित करने का एक प्रभावी उपकरण भी है और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की समग्र गुणवत्ता को उन्नत करता है। माध्यमिक शिक्षा, शायद, एक व्यक्ति की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इन वर्षों के दौरान एक छात्र यह तय करता है कि वह आगे की शिक्षा के लिए क्या लेने जा रहा है और कैसे वह अपनी दैनिक रोटी कमाने जा रहा है। एक छात्र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में जो वर्ष बिताता है, उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसके भविष्य के जीवन का पाठ्यक्रम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिक प्रायोजित योजना शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण के लिए प्रदान करता है ताकि व्यक्तिगत रोजगार में वृद्धि हो, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम किया जा सके और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान किया जा सके।

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति की व्यावसायिक और संबंधित शैक्षणिक आवश्यकताओं को विकसित करने के लिए शैक्षिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। कार्य अनुभव के रूप में सभी चरणों में स्कूल में व्यावसायिक अभिविन्यास की पेशकश की जानी चाहिए। यह व्यावसायिक तैयारी के लिए चुनने वाले छात्रों के बीच रोजगार के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। युवाओं के विभिन्न हितों और अभिरुचिओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक विषयों के विविधीकरण का आह्वान किया जाता है।

1.4.1 भारत में माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यावसायिक शिक्षा का स्थान

एक लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों की आवश्यकता और मांग को पूरा करना और देश को स्थायी प्रगति की ओर ले जाना है। इस संदर्भ में, एक लोकतांत्रिक देश की शिक्षा का उद्देश्य है–

(1) आत्मनिर्भरता और स्वदेशीवाद का विकास।

(2) सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मूल्यों का विकास।

(3) शरीर और मन का विकास और आर्थिक विकास।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में, छात्र एकल शैक्षणिक विषय प्राथमिक शिक्षा (मानक 8) पर शिक्षा जारी रखते हैं। जैसे ही वे माध्यमिक शिक्षा चरण (मानकों 9 और 10) में प्रवेश करते हैं, उन्हें पूर्व–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से कार्य शिक्षा के लिए एक जोखिम प्रदान किया जाता है। जब वे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा चरण (मानकों 11 और 12) में प्रवेश करते हैं, तो उनके पास शिक्षा का एक अकादमिक (तकनीकी) विषय या उन्हें काम करने के लिए तैयार करने वाले व्यावसायिक विषय को अपनाने का विकल्प होता है। शैक्षणिक विषय का उद्देश्य एक व्यक्ति को एक पेशेवर कैरियर के लिए तैयार करना है, जबकि व्यावसायिक विषय का उद्देश्य छात्र को उसकी शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद काम के लिए तैयार करना है।

माध्यमिक शिक्षा में व्यावहारिक विषयों को शुरू करने से लेकर उत्पादकता से संबंधित सामान्य शिक्षा का नेतृत्व करने और छात्रों में प्रवेश के लिए छात्रों में व्यवहारिक समायोजन करने के लिए शिक्षा का व्यावसायिक तर्क प्रस्तुत करता है। यूनेस्को ने 1974 की सिफारिश में व्यावसायिक शिक्षा लागू करने को कहा। सामान्य शिक्षा, प्रौद्योगिकियों और संबंधित विज्ञान के अध्ययन और आर्थिक व सामाजिक विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यावहारिक कौशल, व्यवहार, उपक्रम और ज्ञान के अधिग्रहण के अलावा, शैक्षिक प्रक्रिया के उन पहलुओं को गले लगाते हुए जिंदगी में उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर दोनों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है।

महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा की वकालत की एक ही बात का उच्चारण किया कि शिक्षा जीवन का एक सामंजस्यपूर्ण विकास करेगी। इसका कारण यह है कि उत्पादक कार्य की अनुपस्थिति एक छात्र को शारीरिक रूप से कमजोर और वस्तुतः जीवन के लिए अयोग्य बनाती है। ईश्वरभाई पटेल समिति (1977) ने सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) की जोरदार सिफारिश की, जिसने स्कूली पाठ्यक्रम में केंद्रीय स्थान पर कब्जा कर लिया।

टिप्पणी

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक स्तर पर केंद्र प्रायोजित योजना +2 स्तर पर 1988 से लागू की जा रही है। संशोधित योजना 1992–93 से चालू है। यह योजना राज्यों को प्रशासनिक संरचना, क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक पाठ्यक्रम गाइड, प्रशिक्षण नियमावली, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता आदि प्रदान करती है।

व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और विशेष रूप से अगले उद्देश्य के लिए सीधे और अन्य सभी उद्देश्यों के लिए सीधे काम कर रहा है। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्‌गम लॉर्ड मैकॉले से है, जो ब्रिटिश शासकों के लिए नियमित रूप से आज–कल प्रशासनिक कार्य करने के लिए क्लर्कों की एक सेना का निर्माण करना चाहते थे। अब यह महसूस किया गया है कि यह 'एकल विषय' (सिंगल ट्रैक) शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक पर्याप्त नहीं है। वर्तमान पीढ़ियों की मांग का सामना करने के लिए इसे बहु–विषय किया जाना चाहिए और उत्पादकता से संबंधित होना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य

- हस्त (मैनुअल) कार्य के प्रति छात्रों में व्यवहार परिवर्तन लाना।
- बच्चों को काम की दुनिया से परिचित कराना।
- उन्हें सामाजिक समस्याओं और सामुदायिक सेवा से अवगत कराना।
- रचनात्मक आत्म–अभिव्यक्ति के लिए उन्हें सक्षम कराना।
- कम बुद्धिमान छात्रों के लिए आशा की किरण लाना। कम बुद्धि के छात्र अगर आगे की शिक्षा जारी रखने में असफल रहे, तो कम से कम कुछ उत्पादक काम करने के लिए मिल सकते हैं और इसके साथ एकीकृत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से स्कूल छोड़ने वालों (ड्रॉप आउट) को नियंत्रित किया जा सकता है।
- समाज में मौजूद खाई को पाटने के लिए, उदारवादी शिक्षा अभिजात्य वर्ग और बाकी वर्गों के बीच सामाजिक दूरी को बढ़ाती है जबकि शिक्षा का व्यावसायीकरण इसे कम से कम करने की कोशिश करता है।
- उन्हें सामाजिक समस्याओं और सामुदायिक सेवा से अवगत कराना।
- छात्रों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- माध्यमिक स्तर पर अन्य उद्देश्यों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

टिप्पणी

- लिंग, सामाजिक–आर्थिक और विकलांगता की बाधाओं को दूर करना।
- माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक अर्थात सार्वभौमिक अवधारणा प्राप्त करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना।
- लंबवत संबंध (वर्टिकल लिंकेज) के माध्यम से स्कूल और व्यावसायिक स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुनने के अवसरों में वृद्धि करना।

माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यावसायिक शिक्षा

एनपीई 86 से पहले पाठ्यक्रम से राज्य के भीतर और एक ही राज्य से पाठ्यक्रम के भीतर पाठ्यक्रम डिजाइन में अत्यधिक विविधताएं थीं। लेकिन सभी राज्यों को जिन्हें 1987 के बाद केंद्रीय सहायता मिली है, मोटे तौर पर केवल मामूली बदलाव के साथ एक सामान्य पाठ्यक्रम ढांचे के अनुरूप हैं। इसमें एक या दो भाषाओं का अध्ययन, कुल समय के सत्तर प्रतिशत के साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम और एक नींव पाठ्यक्रम शामिल है। इस ढांचे के भीतर सिखाई जाने वाली भाषाओं, सामान्य आधार पाठ्यक्रमों और संबंधित विषयों के संबंध में भिन्नता हो सकती है।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम स्वरूप (पैटर्न) के कई पुराने संस्करण अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। इसमें तमिलनाडु पैटर्न (कुल समय का व्यावसायिक पाठ्यक्रम–40%), महाराष्ट्र पैटर्न (कुल समय का व्यावसायिक पाठ्यक्रम) और उत्तर प्रदेश और असम पैटर्न (वैकल्पिक का अपरिभाषित और परिवर्तनीय मिश्रण) शामिल हैं। इन राज्यों की ओर से पहले के पैटर्न को समाप्त करने और एक व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप (पैटर्न) के भीतर वांछनीय लचीलेपन के लिए कुछ प्रयास देखा गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 (NCF 2005) National curriculum framework 2005 (NCF 2005)-NCERT 2005, NCERT द्वारा लाया गया, प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में काम और शिक्षा पर जोर दिया गया है। ज्ञान अर्जन, विकासशील मूल्यों और कई कौशल निर्माण में काम की शैक्षणिक क्षमता पर जोर देते हुए, यह कहता है कि,शिक्षा के सभी चरणों में काम से संबंधित सामान्य दक्षताओं (बुनियादी, पारस्परिक, और प्रणालीगत) का एक सेट किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता, संचार कौशल, सौंदर्यशास्त्र, कार्य प्रेरणा, सहयोगी कामकाज की नैतिकता और उद्यमशीलता सह सामाजिक जवाबदेही शामिल हैं।

NCF (2005) VET कार्यक्रम को एक मिशन मोड में लागू करने के लिए मानता है, जिसमें अलग–अलग VET केंद्र और संस्थानों की स्थापना शामिल है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कृषि विज्ञान केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे मौजूदा संस्थानों के दायरे के साथ एकीकरण और विस्तार, कृषि महाविद्यालय और सहकारी आदि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख नीचे दिया गया है–

- वीईटी को टर्मिनल या अंतिम विकल्प के बजाय एक गरिमामय सेवा के रूप में काम करना है।

- कैरियर मनोविज्ञान के लिए कार्यक्रम पर तनाव माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरणों में बच्चों के लिए एक विकास उपकरण के रूप में परामर्श करना ताकि वे अपने कैरियर की योजना बना सकें।
- व्यावसायिक क्षेत्र में अलग–अलग अवधि के लचीले, अनुकूलित (मॉड्यूलर) प्रमाणपत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश करना।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कई प्रवेश निकास बिंदु हैं।
- व्यावसायिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों के साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संबंध रखने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
- पाठ्यचर्या लचीली होनी चाहिए।

टिप्पणी

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF–2005) की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यक्रम और विशेष रूप से आरटीई अधिनियम 2009 के बाद NCF–2005 के क्रियान्वयन के संदर्भ में, NCERT द्वारा नए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और अन्य संबंधित सामग्री केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में लाई गई हैं और कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ आदि के माध्यमिक विद्यालय (अनुबंध–XI) केवीएस/एनवी/तिब्बती स्कूलों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए कई अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीएफ–2005 पर परिप्रेक्ष्य निर्माण के लिए आयोजित किए गए और आमने–सामने और दूर संवाद विधि (टेलीकांफ्रेंसिंग मोड) के माध्यम से नई पाठ्यपुस्तकों को लागू करने के लिए भी आयोजित किए गए।

अब, पाठ्यक्रम के नवीनीकरण की दिशा में एक नई दिशा प्रदान करने और आगे की नीति निर्माण के लिए आगत (इनपुट) प्रदान करने और माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर भविष्य की स्कूल शिक्षा के लिए योजनाएं शुरू करने के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं जैसे कि पाठ्य सामग्री, शैक्षणिक प्रक्रियाओं, मूल्यांकन स्कूल के वातावरण और शिक्षक के व्यावसायिक विकास को सक्षम करने में NCF–2005 के कार्यान्वयन की स्थिति को समझना अपरिहार्य है।

- **एनसीएफ–2005 के उद्देश्य**

1. माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पाठ्यक्रम सामग्री, शैक्षणिक प्रक्रिया, मूल्यांकन, स्कूल को सक्षम करने में NCF–2005 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में पर्यावरण और शिक्षक का व्यावसायिक विकास करना।
3. उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिन पर राज्य के पदाधिकारियों को समर्थन की आवश्यकता होती है और अपनी क्षमता का निर्माण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य पदाधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करने वाले तंत्र का विकास करना।
4. शिक्षकों के लिए एनसीईआरटी संकाय के साथ संलग्नक कार्यक्रमों के संचालन के लिए उन्हें पाठ्यक्रम और क्षेत्र में सहायता प्रदान करना।

टिप्पणी

NCTE ने संरचना और पाठ्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप देते हुए दो मानदंडों का पालन किया। शिक्षकों की गतिशीलता के लिए एक मंच से दूसरे तक लचीलापन और एकीकरण, एक अनुशासन से दूसरे में गतिशीलता और पूर्व–सेवा से सेवा में एकीकरण का मतलब एक कुल कार्यक्रम के साथ सिद्धांत घटक को एकीकृत करना है। प्रत्येक चरण में 3 मुख्य क्षेत्र शामिल होते हैं–

(1) शैक्षणिक सिद्धांत

(2) सामुदायिक

(3) साथ काम करना।

शिक्षाशास्त्र के मुख्य पत्रों में शिक्षकों को उनके विषय, क्षेत्र या स्तर की परवाह किए बिना शिक्षकों के कौशल विकास पर केंद्रित मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सिखाया गया था। वास्तविक स्थिति पर सिद्धांत लागू करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ समुदाय के साथ काम करना शुरू किया गया था।

• माध्यमिक चरण में इन 3 क्षेत्रों को दिए जाने वाला भार शिक्षाशास्त्र पर है – 20% समुदाय के साथ कार्य करना – 20% सामग्री सह कार्यप्रणाली – उच्चतर माध्यमिक चरण में 60% भार शिक्षा है – 30% समुदाय के साथ कार्य करना – 20% सामग्री सह कार्यप्रणाली – 50% माध्यमिक स्तर पर प्रवेश की योग्यता न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्कूल के विषयों में 3 पेजर्स के साथ स्नातक है। अवधि 1 वर्ष है।

• उच्चतर माध्यमिक चरण के लिए प्रवेश योग्यता स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% के साथ 2 विषयों में से 1 में स्नातकोत्तर है। दो तरह के कोर्स यानी अकादमिक और व्यावसायिक को डिजाइन किया गया है। अकादमिक धारा के पाठ्यक्रमों की विशेषताएं हैं : विभेदित, सीमांकित और विशिष्ट सामग्री विषय के विनिर्देश के लिए विषय और विशिष्ट पाठ्यक्रम के साथ विशिष्ट और विषय उन्मुखीकरण की तैयारी अनिवार्य और सार और रचनात्मक सोच पर जटिल और वैकल्पिक में विषयों पर जोर देना और जटिल से निपटने के लिए उच्च मानसिक संकायों पर विचार और जटिल अवधारणाएं उच्च अध्ययनों के लिए निर्देशित और केंद्रित हैं।

• माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा

माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है–

सैद्धांतिक अनिवार्य

- भारत में माध्यमिक शिक्षा के सिद्धांत, स्थिति, समस्याएं और मुद्दे और संबंधित क्षेत्र।
- उभरते भारतीय समाज (एकता, विविधता और क्षेत्रीय विशिष्टता पर जोर) और माध्यमिक शिक्षा।
- माध्यमिक शिक्षा का दर्शन : भारतीय और पश्चिमी (केवल रुझान और शैक्षिक निहितार्थ)।

- समाजशास्त्र शिक्षा और सांस्कृतिक नृविज्ञान (एकता – विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति के अध्ययन को उचित भार दिया जाता है)।
- माध्यमिक विद्यालय स्तर के छात्रों के सीखने और प्रेरणा का मनोविज्ञान (क्षेत्रीय और समूह की विशिष्टताएं दी गई हैं (वेटेज)।
- माध्यमिक विद्यालय स्तर के लिए पाठ्यक्रम और अनुदेशात्मक डिजाइन।
- पर्यावरण शिक्षा – एक्शन रिसर्च और इनोवेटिव प्रैक्टिस।
- शांति शिक्षा और सामाजिक सद्भाव।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता और शारीरिक शिक्षा।
- मूल्यांकन और मापन।
- सुरक्षा और आपदा प्रबंधन।
- प्रबंधन, योजना और वित्त।
- मार्गदर्शन और परामर्श।
- माध्यमिक शिक्षा में आईसीटी और इसका उपयोग।
- समावेशी शिक्षा।
- क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार कोई अन्य।

टिप्पणी

व्यावहारिक गतिविधियां

- माध्यमिक विद्यालय में एक।
- सप्ताह के लिए इंटर्नशिप।
- दो विषयों का शिक्षण और शैक्षणिक विश्लेषण जैसा कि स्कूलों में आम है या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।
- संचार कौशल।
- पर्यावरण संरक्षण।
- पारिस्थितिकी तंत्र।
- संरचना और कार्य।
- वृक्षारोपण और जल संचयन।
- ऊर्जा संचयन।
- काम का अनुभव।
- स्कूलों का सौंदर्यीकरण।
- खेल और खेल का संगठन।
- साहित्यिक गतिविधियों का संगठन।
- पर्यटन और भ्रमण का संगठन।
- फील्ड वर्क का संगठन।
- शारीरिक शिक्षा।

- सामुदायिक कार्य / सहभागिता छात्रों की स्वच्छता।
- क्रिया–शोध (एक्शन रिसर्च), केस अध्ययन (स्टडीज) और कार्य–क्षेत्र (फील्ड वर्क) का कार्यान्वयन क्षमताओं को मापने के लिए परीक्षणों की तैयारी।
- उत्तर लिपियों का मूल्यांकन।

टिप्पणी

- व्यावसायिक कार्य और उसका मूल्यांकन।
- मानचित्र, चार्ट, आरेख तैयार करना।
- कानून की लागत में सुधार और शिक्षण लागत में कोई कमी नहीं।
- शैक्षिक खेल।
- नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण।
- किसी भी अन्य जरूरत आधारित गतिविधियां।

वरिष्ठ माध्यमिक चरण में शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य : व्यावसायिक विषयों के लिए शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम, छात्र शिक्षकों की दक्षता के क्षेत्र में निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करना है–

- समृद्ध व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना जो प्रतिस्पर्धी और खुली बाजार अर्थव्यवस्था में सफलता के लिए आवश्यक है।
- पारंपरिक व्यवसायों की प्रकृति को बदलने और उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बनाने के लिए।
- उन्हें विपणन, बाजार सर्वेक्षण, बिक्री कौशल और विज्ञापन के कौशल प्रदान करने के लिए।
- उन्हें सक्षम बनाने के लिए भावी शिक्षकों के बीच उच्च और बेहतर व्यावसायिक कौशल और दक्षताओं और उन्हें अपने छात्रों के बीच बढ़ावा देने की क्षमता विकसित करने के लिए।
- उन्हें स्व–रोजगार के लिए आवश्यक पाठ्यक्रमों और दक्षताओं को डिजाइन करने में सक्षम बनाने के लिए।
- संकीर्ण विशेषज्ञ और शैक्षिक रूप से हीन व्यक्ति बनने के खिलाफ सावधानी बरतने और भावी शिक्षकों को काम की गरिमा और नैतिकता को विकसित करने और अपने छात्रों के बीच कार्य संस्कृति का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए।

शिक्षाशास्त्र में कोर पेपर को उनके विषय, क्षेत्र या स्तर की परवाह किए बिना शिक्षकों के लिए कौशल के विकास पर केंद्रित मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सिखाया जाता था। प्रत्येक चरण में शिक्षण के लिए विशिष्ट कौशल विकसित करना भी होगा। वास्तविक स्थिति पर सिद्धांत लागू करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ समुदाय के साथ काम करना शुरू किया गया था।

दो तरह के कोर्स यानी अकादमिक और व्यावसायिक को डिजाइन किया गया है। अकादमिक धारा के पाठ्यक्रमों की विशेषताएं हैं– विभेदित, सीमांकित और विशिष्ट सामग्री, विषय और विनिर्देश के लिए विषय उन्मुखीकरण की तैयारी, विचारों की जटिल अवधारणाएं उच्च अध्ययनों के लिए निर्देशित और केंद्रित हैं।

• वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक) के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम की संरचना

सैद्धांतिक अध्ययन का पाठ्यक्रम

- उभरते हुए भारतीय समाज (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यापार, वाणिज्य, औद्योगीकरण और अर्थव्यवस्था आदि पर जोर)।
- दर्शन, समाजशास्त्र, सांस्कृतिक नृविज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा पर उनका प्रभाव।
- व्यावसायिक और औद्योगिक मनोविज्ञान।
- आर्थिक और वाणिज्यिक भूगोल।
- उद्यमिता और प्रबंधन।
- शांति शिक्षा और सामाजिक सद्भाव।
- वित्तीय संसाधनों, कच्चे माल और मशीनरी का प्रबंधन।
- विपणन, बिक्री, विज्ञापन और बाजार सर्वेक्षण।
- मूल्य निर्धारण, लाभ, बीमा आदि।
- प्राथमिक श्रम कानून, श्रम कल्याण और श्रम समस्याएं।
- स्थिति, समस्याएं, मुद्दे और व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियां।
- एक व्यापार या व्यवसाय का सैद्धांतिक ज्ञान।
- पर्यावरण शिक्षा।
- किशोरावस्था शिक्षा।
- मूल्यांकन।
- आईसीटी।
- कोई अन्य क्षेत्र विशिष्ट विषय।

विशेषज्ञता

- सिद्धांत और अभ्यास– एक अथवा दो
- फैशन डिजाइन
- खानपान और खाना पकाने
- सिलाई और बुनाई
- होटल प्रबंधन
- कताई और बुनाई
- कालीन बुनाई
- बढ़ईगीरी
- ब्लॉक स्मिथ जहाज
- कृषि आधारित उत्पाद

टिप्पणी

- खाद्य और फल संरक्षण
- ऑटो मैकेनिक
- मशीनों और इंजनों की मरम्मत
- बिजली मिस्त्री

टिप्पणी

- रेडियो और टेलीविजन
- ट्रैक्टर मैकेनिक
- मिट्टी का काम / चित्रकारी
- वॉल हैंगर / पेंटिंग
- आंतरिक सजावट
- खिलौना बनाना
- चित्र
- विज्ञापन
- कम्प्यूटर के वो भाग जिसे छूकर महसूस किया जा सके
- अन्य व्यावसायिक गतिविधियां।

व्यावहारिक

- एक सेमेस्टर की शिक्षुता,
- कार्यशाला तकनीक,
- व्यावहारिक लेखा,
- शिक्षण और सीखने के लिए व्यावसायिक स्कूल, आईटीआई, टीटीआई आदि में इंटर्नशिप,
- सेल्समैन के रूप में इंटर्नशिप,
- बाजार सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग,
- किसी उत्पाद की सामाजिक मांग और आपूर्ति का सर्वेक्षण,
- समुदाय की जरूरतों का आकलन,
- माल और उसके प्रबंधन का परिवहन,
- कच्चे माल की खरीद,
- विभिन्न कर रजिस्टरों और भुगतान प्रक्रियाओं का रखरखाव,
- पर्यावरण संरक्षण,
- जल और ऊर्जा की कटाई,
- आपदा प्रबंधन और सुरक्षा शिक्षा,
- किसी भी अन्य जरूरत आधारित गतिविधियां।

• **बी. एड. के लिए पाठ्यक्रम संरचना, व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञता** : अभिनव शिक्षक तैयारी के तरीके अब दूरस्थ शिक्षा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की दक्षताओं को अपडेट करने के लिए। "मुक्त शिक्षण प्रणाली का स्वरूप अनुकूलित होता है" विचार को आधार मानकर (ओपन लर्निंग सिस्टम कैरी ए मॉड्यूलर पैटर्न) व्यावसायिक शिक्षकों के लिए समय–समय पर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इन पर आधारित सुनियोजित प्रशिक्षण रणनीतिकार की आवश्यकता है। भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए बड़ी संख्या में नवाचारों और वृत्त अध्ययन (केस स्टडीज)/सफलता गाथाएं (सक्सेस स्टोरीज) के विकास की मांग की जाएगी जो लचीले वितरण माध्यम (डिलीवरी मोड) से शिक्षक तैयारी के लिए संशोधित पाठ्यक्रम है।

टिप्पणी

सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रम को सतत और आजीवन सीखने के लिए बहु–प्रवेश और बहु–निकास प्रणाली को उजागर करना चाहिए। यह पूर्व सीखने और नौकरी की आवश्यकता पर विचार करने के लिए भी पेशकश करनी चाहिए। कार्यक्रम को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि यह शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया के लिए एक सुविधा के रूप में तैयार करता है न कि ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित करने के लिए एक अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में। व्यावसायिक शिक्षा की नींव के संबंध ा में कुछ योग्यताएं– उदाहरण– स्कूलों/संस्थानों में उत्पादन–सह–प्रशिक्षण–सह सेवा गतिविधियों का आयोजन व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में शामिल लोगों के लिए आवश्यक माना जाता है।

1. **व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नई सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय** : सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली–संचार, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ऐसे अन्य लोगों के विविध पहलुओं को समाहित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन के हर पहलू– संचार, सेवाएं, विनिर्माण, व्यापार, सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, अनुसंधान, राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक सुरक्षा को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

   सूचना प्रौद्योगिकी पुराने अवरोधों को तोड़ रही है और देशों, समुदायों/समाजों और व्यक्तियों के बीच नए पुल बना रही है। इसका एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी देश का मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाना। यह तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की प्रक्रियाओं में क्रांति के अवसर भी प्रदान करता है। दूरस्थ शिक्षा, टेली–कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग कुछ उदाहरण हैं। इन सभी को देखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और इसे प्रभावी और आसानी से उपलब्ध, सुलभ बनाने में किया जाना चाहिए।

2. **विदेशी भाषा और संस्कृति का परिचय** : निर्यात–आयात व्यवसाय और उच्च शिक्षा के लिए विदेशी भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होगी। यह उन लोगों के लिए भी आवश्यक होगा, जिनके पास उपयुक्त नौकरियों की तलाश में दूसरे देशों में पलायन करना है। जो लोग अपने कौशल के साथ पलायन करना चाहते हैं, उनके लिए विदेशी भाषा सीखना अनिवार्य हो सकता है। इसे देखते

हुए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को इस तरह से पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी भाषा कुछ पहलुओं को जहां भी आवश्यक हो, शामिल किया जा सके।

सार– पूर्व शिक्षा का आकलन, कार्य अनुभव और प्रमाणन मानकों की मान्यता इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह औपचारिक प्रणाली और अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रणाली और शिक्षा के बीच अंतर–निर्भरता के साथ बड़ी विरासत के लिए महत्वपूर्ण होगा। कई देशों में, एक तंत्र मौजूद है, जिसमें राष्ट्रीय कौशल को उनके कौशल और योग्यता के लिए कार्यबल को दिया जाता है। कुछ देशों में तंत्र/प्रणाली को 'राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता फ्रेमवर्क' के रूप में जाना जाता है। यह ढांचा किसी भी उम्र में नए कौशल और योग्यता हासिल करने के लिए और स्कूल में अपने करियर–आजीवन सीखने के लिए किसी भी स्तर पर लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रवेश बिंदु और रास्ते प्रदान करता है।

टिप्पणी

शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण में नई दिशाओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि शिक्षक कई भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार हों और शिक्षण–अधिगम परिवेश में अपने उचित पदों को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण कर सकें। हम केवल अपने छात्रों के लिए दुनिया भर में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं यदि हम अपने शिक्षकों को आवश्यक कौशल, ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं। जो कि 21वीं शताब्दी में शिक्षार्थियों की एक शिक्षाप्रद प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के एक दृष्टिकोण के रूप में अध्यापन के हकदार हैं।

21 वीं सदी के शिक्षक की क्षमता है कक्षा जो शिक्षक के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करना असंभव बना देती है और यहां तक कि कुछ मामलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों की सुरक्षा को खतरे में डालती है। इस तरह की प्रकृति की समस्याएं 21 वीं सदी में स्कूलों में बढ़ सकती हैं और इस कारण से, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को प्रबंधन को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए ताकि इस तरह की समस्याओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से संबोधित किया जा सके।

शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम समावेशी होना चाहिए और छात्रों को लाभान्वित करने के लिए व्यवहार्य विकल्पों की योजना बनाने के लिए जीवन भर सीखने, प्रौद्योगिकी के विकास और इसके अनुप्रयोगों और रणनीतियों पर जोर देना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र के संस्थागतकरण से शिक्षकों को स्कूलों की भूमिका और वैश्विक परिप्रेक्ष्य से लोकतांत्रिक मूल्यों, कौशल और व्यवहार के विकास में योगदान मिलेगा।

1.4.2 व्यावसायिक शिक्षा के मॉडल

वीईटी कार्यक्रमों के बहुमत ने उद्योगों और व्यापार में कुशल मानव संसाधनों के लिए उभरते रोजगार के अवसरों की जरूरतों के संबंध में, विशेष रूप से पहुंच, इक्विटी के मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। यह वीईटी में उद्योग की भागीदारी की कमी, उद्योग आधारित कौशल मानकों की कमी, अप्रशिक्षित और अनुभवहीन व्यावसायिक शिक्षकों की तैनाती के कारण था। वीईटी के संदर्भ में 'उद्योग' शब्द में ऐसे सभी संगठन और उद्यम शामिल हैं जिनमें वीईटी प्रणाली से स्नातक शिक्षकों की क्षमता है। सर्व

शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के लिए सकल नामांकन में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, बड़ी अक्षमता शिक्षा प्रणाली में बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा से उच्च संख्या में ड्रॉपआउट हो गए हैं।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच सीमित है, क्योंकि अधिकांश कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्र व्यावसायिक शिक्षा धाराओं में अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रकार इक्विटी चिंताओं को बढ़ाते हैं। वित्त और प्रशिक्षण की जिम्मेदारियों के लिए उद्योग और उद्यमों की अधिक भागीदारी वीईटी में कमी है। नामांकन दर, छात्र–शिक्षक अनुपात, पाठ्यक्रमों की अवधि, प्रशिक्षण के मानक, प्रशिक्षण शुल्क, शिक्षक प्रशिक्षकों के वेतन और योग्यता आदि के संदर्भ में सार्वजनिक और निजी प्रावधान के बीच महत्वपूर्ण अंतर सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।

टिप्पणी

बढ़ते ज्ञान के कारण रोजगार का परिदृश्य बदल रहा है। आधारित और तकनीकी रूप से संचालित रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रौद्योगिकी की जगह श्रम के साथ, अधिक व्यक्तियों को स्व–रोजगार में स्थानांतरित करना होगा, इस प्रकार उद्यमशीलता की क्षमता और कौशल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, भारत में वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप होने वाले तकनीकी विज्ञापन, वेतन वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है।

वीईटी में अच्छे व्यवहार और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (गुड प्रैक्टिसेज एंड पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी)) के मॉडल हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत कम है। पीपीटी मोड में वीईटी के सफल प्रारंभिक (पायलट) कार्यक्रमों की बड़े पैमाने पर प्रतिकृति की आवश्यकता है ताकि बड़े पैमाने पर गुणवत्ता वीईटी प्रदान करने के मुद्दे को संबोधित किया जा सके। समाज, उद्योग, छोटे और मध्यम उद्यमों और व्यवसाय के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में मॉडल के महत्व और भूमिका का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

मौजूदा / वर्तमान मॉडल (Existing models of delivery of VET)

संस्था आधारित उद्योग–आधारित सहयोगी मॉडल मल्टी–चैनल मॉडल

1. **संस्था आधारित मॉडल** (Institution Based Model)– संस्था आधारित मॉडल में संस्थान में ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण सहित सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों निर्देश दिए जाते हैं। प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं पूरी तरह से आवश्यक उपकरणों और मशीनों से सुसज्जित हैं। व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने और उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के लिए जहां भी संभव हो, उत्पादन–सह–प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) स्थापित किए जाते हैं।

   भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पॉलिटेक्निक संस्थान–आधारित मॉडल के उदाहरण हैं। भारत के अलावा, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई अन्य देशों में यह काफी लोकप्रिय है। इसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस में अपनाया गया है। ग्रीस, नीदरलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, स्पेन और स्वीडन तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) के वितरण के लिए स्थापित किए हैं।

टिप्पणी

2. **उद्योग आधारित मॉडल** (Industry Based Model)– उद्योग आधारित मॉडल में, वास्तविक कार्य स्थान या 'उद्योग' में सैद्धांतिक और व्यावहारिक निर्देश दिए जाते हैं। यहां उद्योग को एक विशेष उद्योग समूह के भीतर संगठनों या नियोक्ताओं के रूप में लिया जाता है। मॉडल उन मामलों में अपनाया जाता है जहां बुनियादी ढांचे के विकास की लागत अधिक होती है या प्रशिक्षकों को किसी कारण से संस्थान में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। यह मॉडल उन मामलों में भी अपनाया जाता है जहां उद्यम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी संस्था स्थापित करते हैं।

3. **सहयोगात्मक मॉडल** (Collaborative Model)– सहयोगी मॉडल में, बुनियादी कौशल में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ सैद्धांतिक निर्देशन VET संस्था में प्रदान किया जाता है, जबकि विशेष कौशल प्रशिक्षण उद्योग में प्रदान किया जाता है। शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग की डिग्री पाठ्यक्रम से भिन्न हो सकती है, उद्योग द्वारा विस्तारित सहयोग की सीमा के आधार पर मेल–जोल, उद्योग में विशेष प्रशिक्षण की अवधि भी भिन्न हो सकती है।

   सहयोगी मॉडल में जर्मनी में TVET के वितरण की 'दोहरी प्रणाली' की विशेषताएं हैं, जहां पाठ्यक्रम को ब्लॉक में विभाजित किया गया है, और वैकल्पिक संस्थागत निर्देश शामिल हैं।

   व्यावसायिक शिक्षा में हालिया रुझान और उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण (टिम्मरमैन, 1995)। हालांकि, प्रत्येक ब्लॉक की अवधि भिन्न होती है। छात्रों को एक या दो दिन के लिए संस्थान में भाग लेने की आवश्यकता होती है, और सप्ताह में 3–4 दिन वे उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वे प्रयोगशाला में ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं और औद्योगिक स्थितियों में समान होते हैं। जर्मनी के अलावा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड आदि देशों में दोहरे मॉडल को अपनाया गया है।

4. **मल्टी–चैनल मॉडल** (Multy Channal Model)– मल्टी–चैनल मॉडल, शिक्षण संस्थानों में कक्षा निर्देश के माध्यम से बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण के वितरण पर आधारित है, जो मुक्त विगम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम) द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के माध्यम से पूरक और/या पूरक है, उदाहरण के लिए, ओपन स्कूलों द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों, इंटरनेट, कंप्यूटर–सहायक अनुदेशात्मक सामग्री, आदि)। यह मॉडल सीखने की औपचारिक और गैर–औपचारिक प्रणाली का एक संकर है और वीईटी के लिए एक मल्टी–चैनल दृष्टिकोण के लिए प्रदान करता है। यह मॉडल मांग पर और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए वीईटी की पेशकश के लिए नए विकल्प प्रदान करता है, इस प्रकार शैक्षिक अवसर और शैक्षणिक संसाधनों के किफायती उपयोग की अधिक समानता सुनिश्चित करता है।

'लियोनार्ड प्रोजेक्ट' ने GSE और TVET के बीच 'सम्मान की समानता' को बढ़ावा देने के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रणाली (यूनेस्को, 2005) के निम्नलिखित चार मॉडल की पहचान की है–

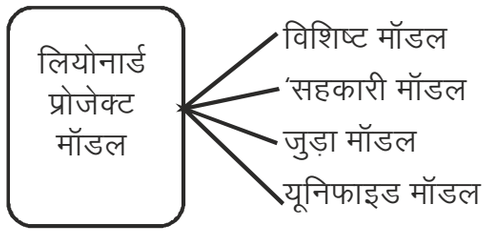

टिप्पणी

1. **विशिष्ट मॉडल** (Distinctive Model)– यह मॉडल जर्मनी और ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, अपने पाठ्यक्रम और नियोक्ताओं के साथ लिंक की विशेषता सामग्री पर जोर देकर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है।
2. **सहकारी मॉडल** (Cooperative Model)– फिनलैंड और नॉर्वे में इसका सबूत है। 'विशिष्ट संवर्धन' के साथ–साथ 'पारस्परिक संवर्धन' और व्यावसायिक और सामान्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना चाहता है।
3. **जुड़ा मॉडल** (Linked Model)– यह मॉडल एक सामान्य योग्यता संरचना के माध्यम से व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच अधिक औपचारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। यह फ्रांस और इंग्लैंड में बदलती समाज और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप खोजा जा रहा मार्ग है।
4. **यूनिफाइड मॉडल** (Unified Model)– यह एकल पोस्ट शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें सभी छात्रों को कुछ सामान्य विषयों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण– स्वीडन और स्कॉटलैंड में पाए जा सकते हैं।

विभिन्न मॉडल जिन्हें स्कूलों और बाहर आजमाया जा सकता है

मौजूदा प्रणाली के तहत यह योजना कुछ समस्याओं का सामना कर रही है, जो योजना के स्थान के मुद्दे को जन्म देती हैं। विभिन्न मॉडल जिन्हें स्कूलों और बाहर आजमाया जा सकता है, नीचे चर्चा की गई है–

1. **स्वतंत्र व्यावसायिक स्कूल मॉडल** (Independent Vocational School Model)– पूरे देश में, केवल हरियाणा ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए स्वतंत्र व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की है। ये संस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं। व्यवसायिक छात्रों की परीक्षा और प्रमाणीकरण राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है।

   कुछ राज्य सरकारों ने केवल व्यावसायिक स्ट्रीम के लिए हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करके व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ मामलों में मौजूदा तकनीकी उच्च विद्यालयों को केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से +2 व्यावसायिक संस्थानों में अपग्रेड किया गया है। यह देखा जाता है कि यह मॉडल उन परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है, जहां उद्योग स्थित नहीं हैं। सतत राष्ट्रीय विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा आसपास और नौकरी पर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में संस्थान में बुनियादी ढांचा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

टिप्पणी

2. **स्कूल–उद्योग दोहरे मॉडल** (School-Industry Dual Model)– व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक बड़ी संख्या में उद्योगों और अन्य पेशेवर और अर्ध–पेशेवर संस्थानों के साथ नेटवर्किंग और गहन सहयोग की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से व्यावहारिक प्रशिक्षण के आयोजन में दिन–प्रतिदिन निर्देश प्रदान करने के लिए इन पाठ्यक्रमों में से अधिकांश स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और कृषि क्षेत्रों से संबंधित हैं। यह मॉडल कुछ राज्यों में परिचालन में है। इसकी सफलता का एक अच्छा उदाहरण चंडीगढ़ में पाया गया है।

3. **सामान्य स्कूल मॉडल** (Common School Model)– +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्कूलों में शुरू किए गए हैं। हालांकि, पाठ्यक्रमों का चयन अग्रिम रूप से जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण आयोजित किए बिना किया गया था, हालांकि 27 राज्यों में से 11 ने इस तरह के सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। पाठ्यक्रम का चयन मांग, नौकरी की संभावना और उद्योग के साथ जुड़ाव के आधार पर किया जाना चाहिए। वाणिज्य, गृह–विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के पाठ्यक्रम स्कूलों में परिचय और लेनदेन के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

स्कूल–उद्योग साझेदारी के मॉडल (Models of School-Industry Partnerships)

यद्यपि विभिन्न मॉडलों ने स्कूल–उद्योग साझेदारी के विकास में आकार लिया है: स्टोक्स एट अल (2006) ने अपने अध्ययन के माध्यम से तीन मॉडल सुझाए हैं।

1. **क्षेत्रीय क्लस्टर मॉडल** (Regional Cluster Model)– एक क्षेत्रीय क्लस्टर मॉडल में, क्षेत्र के भीतर स्कूल एक औपचारिक समझौता करते हैं और एक केंद्रीय वीईटी समन्वयकारी निकाय द्वारा इसकी सेवा ली जाती है। वह निकाय, जो अपने उद्योग और विद्यालय के प्रतिनिधित्व की विविधता और अपने नेटवर्क की व्यापकता के माध्यम से, स्थानीय उद्योग और छात्र की रुचि और क्षमताओं की पहचान और समन्वय के लिए अच्छी तरह से रखा गया है।

   यह सभी भाग लेने वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के वीईटी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानीय समुदायों के भीतर और व्यापक क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक पूंजी को आकर्षित करने और मजबूत करने में सक्षम है। क्षेत्रीय क्लस्टर मॉडल वीईटी के प्रति साझा मूल्य और प्रतिबद्धता पर निर्भर है, और इसके परिणामस्वरूप, पारस्परिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूल संसाधनों की इच्छा पूरे क्षेत्र में एक ठोस संरचना, आकर्षक व्यवसाय और उद्योग का निर्माण, और VET को अंतर्संबंधों की एक प्रणाली के भीतर एम्बेड करना संक्रमण काल के माध्यम से साझेदारी को बनाए रखने में मदद करता है।

2. **विशिष्ट कार्यक्रम मॉडल** (Specialized Programme Model)– एक विशेष कार्यक्रम मॉडल में एक स्थानीय क्षेत्र के भीतर लक्षित आबादी और उद्योग फोकस होता है। हालांकि, विशिष्ट फोकस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकते हैं। यह उन युवाओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक समर्पित प्रयास करता है जिनके लिए मौजूदा शैक्षिक विकल्प काम नहीं करते हैं–वे नियमित रूप से स्कूली शिक्षा या वीईटी विकल्प हैं–और जो एक समुदाय की मौजूदा सामाजिक प्रणालियों (और इसलिए, पूंजी) से बाहर रखा गया है। पहल का नेतृत्व स्कूल या किसी अन्य समुदाय द्वारा किया जा सकता है।

3. **संपूर्ण–समुदाय मॉडल** (Whole-of-community model)– पूरे समुदाय के मॉडल में, जहां तक संभव हो, युवा लोगों की जरूरतों की व्यापक श्रेणी का जवाब देने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण में सामुदायिक सदस्यों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम संलग्न करने का एक सक्रिय और लगातार प्रयास है। मॉडल उन युवाओं के लिए विकल्पों पर विचार करके सभी को शामिल करना चाहता है, जो स्कूल से अलग हो गए हैं या जो स्कूल छोड़ चुके हैं, और जो स्कूल में रहेंगे, लेकिन जिनके लिए वैकल्पिक अनुभवों का उपयोग करना उनकी भविष्य की शिक्षा के लिए फायदेमंद होगा।

   यह मॉडल आमतौर पर एक स्कूल बेस से संचालित होता है, जिसमें सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव और समर्थन होता है। इसे युवाओं के लिए कार्यक्रम विकल्प बनाने के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों संसाधनों पर आकर्षित करने की आवश्यकता है।

टिप्पणी

भागीदारी मॉडल (Partnership Model)

यह मॉडल स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान तैयार करना और स्थानीय हितों के लिए लगातार प्रयास करता है। व्यापार के लिए विशिष्ट लाभ भी हैं (Figgis, 2000)–

(1) मौजूदा कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि छात्र योगदान के माध्यम से।

(2) प्रशिक्षण के माध्यम से कंपनी के कौशल आधार की वृद्धि जो कि कर्मचारियों को लाभ या पुनर्विचार उनकी भूमिका और मौजूदा कार्य प्रथाओं में।

(3) अधिक सामान्य और प्रभावी भर्ती।

(4) उनके योगदान के लिए सामुदायिक मान्यता।

(5) बेहतर सार्वजनिक छवि।

(6) नियोक्ता और कर्मचारियों की व्यक्तिगत संतुष्टि, जो दृष्टिकोण और प्रेरणा पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।

(7) इन सब बातों का सकारात्मक प्रभाव उनकी 'नीचे की रेखा' पर पड़ता है।

वीईटी संस्थान और उद्योग के बीच साझेदारी उद्योग के लिए यह मॉडल फायदेमंद है।

राष्ट्रीय मॉडल (The National Model)

TVET कार्यक्रम, जो विभिन्न प्रणालियों द्वारा पेश किए जा रहे हैं, सामग्री के विकास के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों, संरचना और तौर–तरीकों को निर्धारित करते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा श्रम मंत्रालय के तहत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम किसी विशेष व्यापार के लिए कौशल के व्यावहारिक और विकास पर बहुत जोर देते हैं और सामान्य शिक्षा का घटक केवल 5 से 10 प्रतिशत है। तकनीकी शिक्षा के तहत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में सिद्धांत पर अधिक जोर दिया जाता है जहां अभ्यास घटक केवल 30 से 40 प्रतिशत है। +2 स्तर पर पेश व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक डिजाइन का अनुसरण करते हैं।

टिप्पणी

व्यावसायिक मॉडल (Professional Model)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) व्यावसायिक मॉडल–राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से 14 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। यह विभिन्न प्रकार के लक्ष्य समूहों को पूरा करता है। किसान, बढ़ई, निर्माण श्रमिक, प्रसाधक (ड्रेसर), सेवा क्षेत्र के कार्यकर्ता आदि, जो नवीनतम रोजगार कौशल प्राप्त करने के लिए कुछ अवसर की तलाश में हैं और उन लोगों के लिए भी जिनके लिए कुछ व्यावसायिक गतिविधियां शौक की तरह हैं।

ये व्यावसायिक शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों (एवीआई) के माध्यम से पेश किए जाते हैं। एनआईओएस द्वारा तैयार की गई शिक्षण सामग्री शिक्षार्थियों को एवीआई के माध्यम से दी जाती है। व्यावहारिक हाथों को एक अनुभव देने के लिए संपर्क कार्यक्रम की व्यवस्था करता है। छात्र एकल आधारित पाठ्यक्रम (स्टैंडअलोन कोर्स) के रूप में एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं और प्रमाणित हो सकते हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम भी प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति अन्य गैर–कौशल शैक्षणिक विषयों के संयोजन में एक कोर्स चुन सकता है। हालांकि, यदि कोई सभी व्यावसायिक विषयों को लेना चाहता है, तो वह एक भाषा पाठ्यक्रम के संयोजन में ऐसा कर सकता है। खुले शिक्षण के माध्यम से NIOS व्यावसायिक मॉडल में बहुत अधिक लचीलापन है और यह आर्थिक गतिविधियों के बड़े क्षेत्र को कवर करता है।

इसी तरह आधुनिक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में, जिसमें नौकरियों की वैचारिक सामग्री तेजी से बढ़ रही है और इसी तरह के मैनुअल कौशल कम महत्वपूर्ण हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली शैक्षणिक माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त व्यापक दक्षताएं महत्वपूर्ण हैं, न केवल तत्काल उत्पादकता के लिए, बल्कि श्रमिकों की क्षमता के लिए, कैरियर के दौरान नए कौशल सीखने के लिए, कौशल, रचनात्मक सोचने की क्षमता, निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने, कारण, विश्लेषण, व्याख्या, और जानने के लिए विभिन्न मॉडलों ने अर्थव्यवस्था के लिए मानव संसाधन विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1.4.3 विभिन्न राज्यों में प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति और वर्तमान स्थिति

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास श्रमिकों की उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए राष्ट्रीय विकास का विस्तार होता है। विकास, उच्च उत्पादकता और बेरोजगारी में कमी, किसी देश के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कार्यबल के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। 16–29 वर्षों के बीच भारत में 70% आबादी है। एलपीजी युग के आगमन के साथ, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने होंगे और प्रशिक्षण देना होगा ताकि लोगों की रोजगार क्षमता दुनिया भर में बढ़े। भारत सरकार ने वीईटी को प्रमुख प्राथमिकता माना है। लेकिन भारत में कुल कार्यबल का केवल 2% ही कौशल प्रशिक्षण से गुजरा है।

भारत में दुनिया में काम करने की आयु (15–59 वर्ष) के व्यक्तियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इस जनसंख्या समूह का कौशल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जरूरी है कि इस आयु वर्ग के लिए पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण उन्हें उत्पादक बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। भारत को बड़ी मांग–आपूर्ति के अंतराल के कारण कौशल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित शिक्षार्थियों का एक बड़ा पूल है।

टिप्पणी

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई), 1986 (1992 में संशोधित) यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा प्रणाली को देश के आर्थिक विकास के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। भारत सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा के सार और भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE), 1986 (1992 में संशोधित) ने माना है कि शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जनशक्ति का विकास करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) ने व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, बेहतर और सख्ती से लागू किए गए कार्यक्रमों की परिकल्पना की है, जो रोजगार बढ़ाने के लिए सख्ती से लागू किए जा सकते हैं, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच गलत मिलान को कम कर सकते हैं और तृतीयक शिक्षा का पीछा करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान कर सकते हैं, विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना। नीति में परिकल्पना की गई है कि उच्च व्यावसायिक स्तर पर बच्चों को सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, जो कई व्यावसायिक क्षेत्रों में कटौती करते हैं और जो व्यवसाय विशिष्ट नहीं हैं।

विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली का विकास– व्यावसायिक शिक्षा (वीई) और व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटी) के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, जो इस संबंध में नीति ओवरलैप को हटाने में उपयोगी होगा।

- वोकेशन एजुकेशन–व्यावसायिक शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के दायरे में आती है। MHRD के तहत अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद (AICVE), राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की योजना, मार्गदर्शन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन (SCVEs) राज्य स्तर पर समान कार्य करता है।

यह औपचारिक शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, जिसमें 'माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 11 वीं और 12 वीं कक्षाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। यह संरचित पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिसमें छात्र अपने समय के एक छोटे हिस्से को व्यावसायिक या व्यावहारिक विषयों के लिए समर्पित करते हैं। यह व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली लंबे समय से विवादों में रही है और इसका कार्यान्वयन पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। यह कार्यक्रम 1976–77 में शुरू किया गया था और 1979 में बंद कर दिया गया था, और इसे फिर से 1988 से शुरू किया गया था। इस योजना को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (लक्षद्वीप को छोड़कर) द्वारा लागू किया गया है।

टिप्पणी

व्यवसायिक शिक्षा (Vocational Education) के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों (16–17 वर्ष के बच्चों के लिए, अर्थात कक्षा 11–12 में) के लिए संशोधित कार्यक्रम की विशेषताएं राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NVEQF) के लिए प्रस्तावित वीई के डिजाइन के समान हैं (मेहरोत्रा एटल), 2012। NVEQF में माध्यमिक विद्यालय प्रणाली के साथ–साथ देश में VET प्रणाली में एक प्रमुख प्रतिमान शामिल है। यह पहले से ही केंद्र सरकार के कैबिनेट द्वारा स्वीकार किया गया है और राज्य सरकारों, शिक्षा मंत्रियों द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित है।

• **माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण**– व्यवसायिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर तृतीयक शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा और कौशल विकास को कवर करता है – औपचारिक और गैर–औपचारिक प्रोग्राम दोनों के माध्यम से। व्यावसायिक शिक्षा 2 स्टेज पर, जिसे उच्चतर माध्यमिक चरण के रूप में भी जाना जाता है, विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से, विशेष रूप से आत्म–बेरोजगारी के लिए काम की दुनिया के लिए शिष्य तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर एक केंद्र प्रायोजित योजना, शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण के लिए प्रदान करती है ताकि व्यक्तिगत रोजगार में वृद्धि हो, कुशल मानव शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम किया जा सके और उच्च शिक्षा का पीछा करने वालों के लिए एक विकल्प हो।

यह योजना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशासनिक संरचना, क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तक पाठ्यक्रम मार्गदर्शिकाएं, प्रशिक्षण नियमावली, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुनरुत्थान विकास, प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मजबूत बनाने और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

• **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)**– सीटीएस का मुख्य उद्देश्य कुशल कारीगरों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उद्योगों को प्रदान करना है और शिक्षित युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। सीटीएस के तहत कार्यक्रम औद्योगिक ट्रेडों पर केंद्रित है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (निजी आईटीआई) द्वारा संचालित किया जाता है।

इस योजना के तहत प्रशासित कार्यक्रम दो मुख्य प्रकार के संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं–

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीटी)– ये संस्थान राज्य श्रम मंत्रालयों द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित किए जाते हैं। 2005–6 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत में 500 आईटीआई के उन्नयन का ऐलान किया। इस उद्देश्य के लिए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के तहत विश्व बैंक सहायता के माध्यम से घरेलू संसाधनों से 100 आईटीआई और 400 आईटीसी का उन्नयन किया। इसका उद्देश्य विश्व मानक के बहु कुशल कर्मचारियों के उत्पादन के लिए आईटीआई को 'उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)' में अपग्रेड करना था। उत्कृष्टता के ये केंद्र एक विशिष्ट व्यापार के विशेषज्ञ हैं और उसी के लिए अलग से धन प्राप्त करते हैं।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (निजी आईटीआई), जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2011 के रूप में निजी आईटीआई का नाम दिया गया था, निजी संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों के स्वामित्व, वित्तपोषित और प्रबंधित हैं। निजी आईटीआई उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां औद्योगिक क्लस्टर हैं जो कुछ कौशल की मांग करते हैं।

टिप्पणी

श्रम और रोजगार मंत्रालय में डीजीई एंड टी स्कूल लीवर्स के लिए 114 ट्रेडों में 8,306 आईटीआई/आईटीसी (2140 सरकारी आईटीआई और 6166 प्राइवेट आईटीसी) के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि 6 महीने से 3 वर्ष तक भिन्न होती है और कक्षा 8 से 12 पास योग्यता वाले छात्र इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।

आईटीआई खोलने और आईटीआई में ट्रेडों को शुरू करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों के साथ रहती है। DGE – T द्वारा नियमित रूप से उद्योग और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के परामर्श से पाठ्यक्रमों की अद्यतन/संशोधित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण बाजार की जरूरतों और रोजगार उन्मुख से जुड़ा हो। उपरोक्त योजना के तहत कवर किए गए प्रत्येक उन्नत आईटीआई को प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में संबंधित उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ एक औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

• **केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड** (CBSE)– सीबीएसई अपने देश में लगभग 500 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 107 विषयों से संबंधित 34 व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेश कर रहा है। शैक्षणिक सत्र 2007–08 के दौरान, वित्तीय बाजार प्रबंधन को 11 वीं कक्षा में व्यावसायिक पैकेज के रूप में पेश किया गया था। सीबीएसई ने 'आतिथ्य और पर्यटन', 'मास मीडिया स्टडीज एंड मीडिया प्रोडक्शन' और 'जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी' नामक तीन नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए। शैक्षणिक सत्र 2010–11 सीबीएसई संबंधित उद्योग/संगठन के सहयोग से ऐसे और पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास कर रहा है, और संयुक्त प्रमाणन के लिए सुविधाएं हैं।

• **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** (RMSA) को 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसे राष्ट्रीय संसाधनों (केंद्र सरकार, राज्य सरकार) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था और अब विकास साझेदारों (DP)– वर्ल्ड बैंक इंटरनेशन द्वारा बाह्य वित्त पोषण के लिए करार किया गया है। डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA), यूनाइटेड किंगडम– डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) और यूरोपियन यूनियन (EU)। डीपी से बाहरी सहायता के लिए समझौते के हिस्से के रूप में, जो नवंबर, 2012 में प्रभावी हुआ।

राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (RMSA) मार्च 2009 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और अकादमिक वर्ष 2009/10 में कार्यान्वयन शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाना, लिंग, सामाजिक–आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करना, 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण प्राप्त करना है।

टिप्पणी

अप्रैल 2013 से, भारत सरकार (जीओआई) ने आरएमएसए के कुछ पहलुओं को संशोधित किया। इन संशोधनों ने आरएमएसए के दायरे को शिक्षा की अन्य केंद्र–प्रायोजित योजनाओं को शामिल करने के लिए व्यापक कर दिया, जिसमें 'माध्यमिक शिक्षा का प्रसार' भी शामिल है, जो 1988 में शुरू किया गया था। 2012 तक, 10,000 स्कूलों ने उस योजना में लगभग 1 मिलियन छात्रों की सेवन क्षमता के साथ भाग लिया था। हालांकि, कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों ने इसके सफल कार्यान्वयन में बाधाओं की एक श्रृंखला की पहचान की।

इनमें शामिल थे– नियमित शिक्षकों की कमी या अनुपस्थिति और उनका प्रशिक्षण/पुनः प्रशिक्षण, अपर्याप्त वित्तीय आवंटन, राज्यों की ओर से उच्च वित्तीय निहितार्थ, अनम्य अवधि और पाठ्यक्रमों की डिलीवरी, जो कभी–कभी जरूरत–आधारित नहीं होती थीं, भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं; उद्योग के साथ खराब संबंध, खराब ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अलग प्रबंधन संरचनाओं की अनुपस्थिति, परिणामस्वरूप और कुशल जनशक्ति के लिए भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता के मद्देनजर, इस योजना को सितंबर 2011 में संशोधित किया गया और फिर फरवरी 2014 में फिर से संशोधित किया गया ताकि पहले इसे 11 वीं पंचवर्षीय योजना के शेष के लिए जारी रखा जा सके और दूसरा, आगे बढ़ने के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना। स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के अलावा, संशोधित योजना को व्यावसायिक शिक्षा शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण का काम सौंपा गया था।

• **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)**– NIOS अपने मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से 82 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिसमें सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संगठन और पंजीकृत सोसायटी शामिल हैं। 1063 मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान (AVI) पूर्व स्तर के स्तर तक नव साक्षरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

• **जन शिक्षण संस्थान (JSS)**– JSS शहरी और ग्रामीण भारत में निरक्षर और नव साक्षर वयस्कों और युवाओं के शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती श्रमिक विद्यापीठों से विकसित हुआ है। जन शिक्षण संस्थान स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जो अनपढ़ और नव–साक्षर व्यक्तियों, सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, वंचित समूहों, अकुशल और बेरोजगार युवाओं से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

• **राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता ढांचा (NVEQF)**– राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ), जिसे एआईसीटीई द्वारा लॉन्च किया गया है और एचआरडी मंत्रालय मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा में सामान्य शिक्षा तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके विपरीत यह स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम लाता है जो छात्रों को नए कैरियर विकल्प प्रदान करेगा और उन्हें काम की दुनिया के लिए बेहतर तैयार करेगा। NVEQF के माध्यम से, मंत्रालय का उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के कौशल और दक्षता को विकसित करना है।

• **कौशल भारत (Skill India)**– स्किल इंडिया 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत में विभिन्न

कौशलों में 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसमें सरकार की विभिन्न पहल जैसे 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन', 'राष्ट्रीय नीति कौशल विकास और उद्यमिता, 2015', 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' (पीएमकेवीवाई) और 'कौशल ऋण योजना'।

• **उदान** (UDDAN)– भारत के कॉरपोरेट्स और गृह मंत्रालय के बीच साझेदारी की प्रकृति और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रकृति में जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष उद्योग पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है और जम्मू–कश्मीर के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना में स्नातक, स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक शामिल हैं। इसके दो उद्देश्य हैं– (1) बेरोजगार स्नातकों को कॉरपोरेट इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए और (2) कॉरपोरेट इंडिया को उपलब्ध कराने के लिए, राज्य में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा पूल के लिए एक जोखिम।

टिप्पणी

विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी के तुरंत बाद, शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें शिक्षा और गुणवत्ता दोनों की पहुंच बढ़ाने का जनादेश था, जिससे 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति बनी। शिक्षा क्षेत्र का प्रारंभिक विस्तार भारत की आर्थिक वृद्धि द्वारा सीमित था लेकिन 20 वीं शताब्दी के अंत तक लगातार जारी रहा। 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद, भारत ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में बहुत प्रगति की है। विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि 2000 से 2017 के बीच प्राथमिक विद्यालय में 33 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई– 2000–01 में 156.6 मिलियन से बढ़कर 2017–18 में 189.9 मिलियन हो गई।

29 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों, इनमें से दो–तिहाई ने सार्वभौमिक प्राथमिक नामांकन हासिल करने का दावा किया है। 2001 में भारत सरकार की दो प्रमुख पहलें, सर्व शिक्षा अभियान (SSA – 'शिक्षा के लिए सभी अभियान' हिंदी में) और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 तक पहुंच के मुद्दों पर अधिक व्यापकता को बढ़ावा दिया है। शिक्षा में समावेश और गुणवत्ता। कामकाजी आबादी (25 वर्ष से अधिक आयु वाले) की स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 4.19 वर्ष से बढ़ गए।

2017 में 2000 से 6.4 वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध किया है, जिसमें कई और बड़े पैमाने पर और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है।

(Source–An Integrated Scheme for School Education Framework for implementation draft-april-2018-Ministry of Human Resource Development Department of School Education and Literacy)

• राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 22 सितंबर, 2015 को भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के 68 वें दौर के आंकड़ों को जारी किया। 15–59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से लगभग 2.2 प्रतिशत ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त

टिप्पणी

किया और 8.6 प्रतिशत ने गैर–औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना दी। व्यावसायिक शिक्षा पर डेटा चिंताजनक है।

1. **2019 से पहले और भारत में शिक्षा के बाद की 2019 की प्रस्तावित संरचना**

आयु (विशिष्ट) Age (typical)	वर्तमान Current (2019)	ग्रेड Grade	प्रस्तावित संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में (Proposed in revised National Education Policy
17-18	उच्च माध्यमिक(Higher secondary)	12	ऊँचा चरण (High stage)
16-17		11	
15-16	माध्यमिक(secondary)	10	
14-15		9	
13-14	उच्च प्राथमिक(Upper primary)	8	मध्य चरण (Middle stage)
12-13		7	
11-12		6	
10-11	प्राथमिक (primary)	5	प्रारंभिक चरण (Preparatory stage)
09-10		4	
08-09		3	
07-08		2	मूलभूत अवस्था (Foundational stage)
06-07		1	
05-06	पूर्व प्राथमिक (Pre-primary)		
04-05			
03-04			

(Source– Ministry of Human Resource Development (2019: 75), Based on Draft NEP–2019)

● भारत में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के व्यावसायीकरण के तहत मंजूर/अनुमोदित स्कूल

क्र सं.	राज्य	मंजूर/अनुमोदित विद्यालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश–Andhra Pradesh	46
2	अरुणाचल प्रदेश–Arunachal Pradesh	21
3	असम–Assam	60
4	बिहार–Bihar	38
5	चंडीगढ़–Chandigarh	06
6	छत्तीसगढ़–Chhattisgarh	25
7	दिल्ली–Delhi	22
8	गोवा–Goa	38
9	हरियाणा–Haryana	240
10	हिमाचल प्रदेश–Himachal Pradesh	200
11	जम्मू और कश्मीर–Jammu and Kashmir	132

12	झारखंड–Jharkhand	24
13	कर्नाटक–Karnataka	250
14	मध्य प्रदेश–Madhya Pradesh	50
15	महाराष्ट्र–Maharashtra	350
16	मणिपुर–Manipur	39
17	नागालैंड–Nagaland	05
18	ओडिशा–Odisha	30
19	पंजाब–Punjab	100
20	राजस्थान –Rajasthan	70
21	सिक्किम–Sikkim	52
22	उत्तर प्रदेश–Uttar Pradesh	100
23	उत्तराखंड–Uttarakhand	44
24	पश्चिम बंगाल–West Bengal	93
	टोटल (Total)	2035

(Source– Vocational Education International Experience–World Bank Report– 2015, RMSA India website on 27th November 2014)

टिप्पणी

• एमएचआरडी द्वारा अनुमोदित स्कूलों की संख्या और समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) के तहत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (Vocational Education programme) को लागू करने वाले स्कूलों की संख्या

क्र सं.	राज्य	मंजूर/अनुमोदित विद्यालय की संख्या	VEP कार्यान्वित विद्यालयों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37	31
2	आंध्र प्रदेश	437	256
3	अरुणाचल प्रदेश	101	99
4	असम	340	251
5	बिहार	38	00
6	चंडीगढ़	22	16
7	छत्तीसगढ़	546	546
8	दादर और नगर हवेली	4	0
9	दमन और दीव	5	0
10	दिल्ली	65	22
11	गोवा	132	97
12	गुजरात	122	20
13	हरियाणा	1065	1051
14	हिमाचल प्रदेश	953	873

टिप्पणी

15	जम्मू और कश्मीर	657	352
16	झारखंड	388	260
17	कर्नाटक	150	150
18	केरल	93	00
19	लक्षद्वीप	05	00
20	मध्य प्रदेश	1200	626
21	महाराष्ट्र	644	508
22	मणिपुर	78	42
23	मेघालय	25	23
24	मिजोरम	29	27
25	नागालैंड	26	18
26	ओडिशा	576	434
27	पुडुचेरी	09	00
28	पंजाब	955	780
29	राजस्थान	905	905
30	सिक्किम	194	184
31	तमिलनाडु	120	67
32	तेलंगना	307	192
33	त्रिपुरा	80	24
34	उत्तर प्रदेश	200	200
35	उत्तराखंड	200	00
36	पश्चिम बंगाल	726	600
	टोटल	11434	8654

Source: (Framework on Vocational Pedagogy, PSSCIV, Bhopal, 2020)

शिक्षा प्रणाली की संरचना

1. **प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य शिक्षा**– कक्षा एक से आठवीं तक की कार्य शिक्षा की कल्पना की गई है। कार्य शिक्षा की आवश्यक विशेषता इसका मैनुअल चरित्र है, जिसका अर्थ है कि बच्चों को अपने हाथों से काम करना चाहिए और इस तरह श्रम और कड़ी मेहनत की गरिमा का विकास होता है। मैनुअल काम उद्देश्यपूर्ण और शिक्षाप्रद होना चाहिए। इसमें ज्ञान, समझ, दृष्टिकोण, व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों और कार्य की दुनिया से संबंधित कौशल विकसित करने में मदद करनी चाहिए। कार्य शिक्षा का कार्यक्रम सभी राज्यों में चल रहा है।

टिप्पणी

2. **पूर्व व्यावसायिक शिक्षा**– पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा पर एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) वर्ष 1993–94 में चयनित स्कूलों में नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों को सरल विपणन योग्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसने व्यावसायिक हितों और योग्यता के विकास पर जोर दिया। व्यावसायिक प्राथमिकताओं की स्व–अन्वेषण और काम में उत्पादकता और भागीदारी को बढ़ाना। यह एक जन्मजात कार्य संस्कृति को प्रभावित करने के लिए शैक्षणिक शिक्षा का एक वांछित आयाम है। पूर्व–व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण उस स्तर का नहीं होगा जिसे व्यावसायिक कहा जा सकता है, फिर भी यह छात्रों को काम की दुनिया के एक नाभि क्षेत्र का पता लगाने के लिए पर्याप्त अंतर्दृष्टि देता है।

   पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम आम तौर पर ऐसे संस्थानों में शुरू किया गया है, जहां व्यावसायिक स्ट्रीम पहले से ही +2 स्तर पर शुरू की गई है और आवश्यक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छी तरह से नियोजित और कठोरता से पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने से छात्रों को एक तरफ अपनी प्रतिभा, रुचियों और योग्यता का पता लगाने और दूसरी ओर काम की दुनिया में अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। कुछ राज्यों ने कक्षा IX और X में कुछ पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान की है और उन्हें लागू किया है। देश में पर्याप्त धन के प्रावधान के साथ सभी स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का एक सुनियोजित व्यापक कार्यक्रम है।

3. **जेनेरिक वोकेशनल कोर्स**– जेनेरिक वोकेशनल कोर्स (जीवीसी) विभिन्न व्यवसायों में शैक्षिक स्ट्रीम में कटौती के छात्रों के लिए है और इसका उद्देश्य रोजगार से संबंधित सामान्य कौशल विकसित करना है, जो एक शिक्षित कार्य बल द्वारा आवश्यक है, भले ही वह व्यवसाय हो। यह प्रौद्योगिकी उन्मुख समाज के लिए महत्वपूर्ण दक्षताओं और हस्तांतरणीय कौशल विकसित करके सामान्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है।

4. **व्यावसायिक पाठ्यक्रम**– कृषि, व्यावसायिक और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, होम के क्षेत्रों में +2 स्तर पर रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। विज्ञान, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की मांग संचालित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण/संसर्ग (एक्सपोजर) पर एक संरचित कार्यस्थल के साथ किया जाएगा। मुख्य जोर व्यवहार कुशलता (सॉफ्ट स्किल्स) और कम्प्यूटर साक्षरता, निश्चित समय के न होने (फ्लेक्सी–टाइम) के साथ सेवा क्षेत्र पर होगा। अन्य विशेषताओं में नियोक्ताओं के साथ अनिवार्य भागीदारी शामिल है जो प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) प्रदान करते हैं, पाठ्यक्रम पर सलाह, मूल्यांकन और प्रमाणन में भाग लेते हैं। कार्यक्रम व्यावसायिक, सामान्य और तकनीकी शिक्षा और कई प्रवेश निकास विकल्पों के बीच गतिशीलता सुनिश्चित करेगा। 11 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्रों के पास देश के 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 6,000 स्कूलों में पेश किए गए लगभग 160 व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं।

देश में लागू राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के +2 चरण में छह प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में 160 से अधिक विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। उक्त विद्यालयों में 9.72 लाख छात्रों की क्षमता के विरुद्ध विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले लगभग 4.5 लाख छात्र हैं।

टिप्पणी

निम्नलिखित क्षेत्रों में लगभग 160 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं–

1. कृषि
2. व्यापार और वाणिज्य
3. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी
4. स्वास्थ्य और पैरा–मेडिकल
5. गृह विज्ञान
6. मानविकी, विज्ञान और शिक्षा

दो साल के पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, एक साल के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का प्रावधान है। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को 1986 में संशोधित किया गया था ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के पास–आउट को 2 स्तर पर शामिल किया जा सके। अधिनियम के तहत शामिल व्यावसायिक पाठ्यक्रम की संख्या 94 है और प्रत्येक छात्र को दिए जाने वाले वजीफे की राशि रु. 1090 प्रति माह। अपरेंटिस एक्ट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर में स्थित 4 रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (BOATS) के माध्यम से लागू किया गया है। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण एक वर्ष की अवधि का है और अनिवार्य नहीं है।

• प्रत्येक क्षेत्र में अपरेंटिस अधिनियम 1961 के तहत आने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं–

- **कृषि**

  1. मुर्गी पालन; 2. मत्स्य पालन प्रसंस्करण; 3. डेयरी; 4. फसल संवर्धन/उत्पादन; 5. सेरीकल्चर; 6. एपिकल्चर; 7. फूलों की खेती; 8. पादप संरक्षण; 9. कृषि रसायन; 10. अंतर्देशीय मत्स्य; 11. वृक्षारोपण फसलें और प्रबंधन; 12. बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी; 13. सूअर का उत्पादन; 14. सब्जी बीज उत्पादन; 15. औषधीय और सुगंधित पादप उद्योग; 16. भेड़ और बकरी पालन; 17. पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट सह कृत्रिम गर्भाधान; 18. कृषि आधारित खाद्य उद्योग पशु आधारित; 19. कृषि आधारित खाद्य उद्योग फसल आधारित; 20. कृषि आधारित उद्योग फीड आधारित; 21. पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी; 22. मछली बीज उत्पादन; 23. मछली पकड़ने की तकनीक; 24. विद्युत चालित फार्म मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव।

- **व्यापार और वाणिज्य**

  1. लेखा और लेखा परीक्षा, 2. बैंकिंग, 3. विपणन और बिक्री कौशल, 4. कार्यालय सचिव, 5. सहयोग, 6. निर्यात–आयात अभ्यास और प्रलेखन, 7. बीमा, 8. क्रय और भण्डारण, 9. कराधान, 10. पर्यटन और यात्रा तकनीक।

टिप्पणी

- **इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी**

  1. सिविल : कंस्ट्रक्शनइंबेनेशन, 2. मैकेनिकल सर्विसेज, 3. ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन, 4 मेंटीनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक।

- **स्वास्थ्य और पैरा–मेडिकल**

  1. चिकित्सा : प्रयोगशाला / प्रौद्योगिकी सहायक, 2. स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 3. नर्सिंग, 4. स्वास्थ्य संचित निरीक्षक, 5. अस्पताल का दस्तावेजीकरण, 6. अस्पताल का घर का रख–रखाव, 7. ऑप्थेल्मिक तकनीशियन, 8 फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा, 9. एक्स– रे तकनीशियन, 10. बहु पुनर्वास कार्यकर्ता।

- **गृह विज्ञान**

  1. खाद्य संरक्षण, 2. कपड़ा डिजाइनिंग, 3. खानपान और रेस्तरां प्रबंधन, 4. संस्थागत हाउस कीपिंग, 5. कमर्शियल गारमेंट्स डिजाइनिंग और मेकिंग, 6. प्री–स्कूल और क्रेच मैनेजमेंट, 7. इंटीरियर डिजाइन, 8. चाइल्ड केयर पोषण।

- **विज्ञान और मानविकी**

  1. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, 2. वाद्य संगीत (टक्कर तबला)। 3. शास्त्रीय नृत्य कथक, 4. भारतीय संगीत (हिंदुस्तानी गायन संगीत)।

व्यावसायिक शिक्षा को कैरियर और तकनीकी शिक्षा (सीटीई) या तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) के रूप में भी जाना जाता है। यह व्यावसायिक स्कूलों के भीतर शिक्षा है जो छात्रों को जीवन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट ट्रेडों, शिल्प और करियर के लिए तैयार करती है। इसमें विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियां शामिल हैं। इसे कभी–कभी तकनीकी शिक्षा के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि प्रशिक्षु व्यापार के सभी पहलुओं को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और वैज्ञानिक तकनीक से संबंधित तकनीकों के एक विशेष समूह में सीधे विशेषज्ञता विकसित करता है।

ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, एमएचआरडी द्वारा देश में शिक्षा के व्यवसायिक विकास की योजना के मूल्यांकन के लिए नियुक्त एक स्वतंत्र शोध संगठन, लगभग 28% व्यावसायिक पास आउट कार्य–रोजगार या स्वयं की दुनिया में शामिल हो रहे थे। रोजगार, उनके पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद यह अपने आप में योजना की सफलता के बारे में बताता है।

व्यावसायिक विषय वर्ग के लगभग 40% उत्तीर्ण व्यक्ति अकादमिक विषय वर्ग में उच्च अध्ययन में शामिल हो रहे थे। उच्चतर माध्यमिक संस्थानों में एक अलग व्यावसायिक शिक्षा विषय वर्ग शुरू किया गया है। व्यवसायिक पाठ्यक्रम (वोकेशनल कोर्स) को स्व–निहित अनुखंड (मॉड्यूल) के रूप में डिजाइन किया गया है जो सैद्धांतिक पहलुओं या बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यावहारिक परिचालन का विवरण निर्दिष्ट करता है। स्कूलों को छात्रों की पेशकश करने से पहले पाठ्यक्रमों की आवश्यकता, प्रासंगिकता और क्षमता का आकलन करना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि उनकी प्रकृति और कौशल की आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती है। औपचारिक स्कूल प्रणाली में ये पाठ्यक्रम काम की दुनिया में शामिल होने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।

टिप्पणी

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी जुटाकर, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल का आकलन करते हुए, स्कूलों, पॉलिटेक्निक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने, निजी को प्रोत्साहित करते हुए आकांक्षात्मक बनाया जा रहा है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से भागीदारी, मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से कुशल श्रमिकों की पूर्व शिक्षा को पहचानना, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पेश किए गए कौशल विकास पाठ्यक्रमों का चयन करने के लिए श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी और 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक कौशल भारत मिशन की स्थापना की गई थी। राज्य कौशल विकास मिशनों (एसडीएम) को विभिन्न लोगों द्वारा स्थापित किया गया है। राज्य कौशल विकास के लिए एक एकीकृत रणनीति बनाने और राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए काम करते हैं।

कौशल विकास निगम (NSDC) के नेतृत्व में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल, जो 2009 में स्थापित किया गया था, अब नीति नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों के विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन में कौशल विकास गतिविधियों को चला रहा है। NSDC के पास भारत सरकार द्वारा पहचाने जाने वाले 20 उच्च विकास क्षेत्रों में 2022 तक 150 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का जनादेश है।

समग्र शिक्षा के तहत जॉब रोल्स के अनुसार राज्यवार व्यावसायिक विषय (State wise Vocational Subjects as per the Job Roles under Samagra Shiksha)

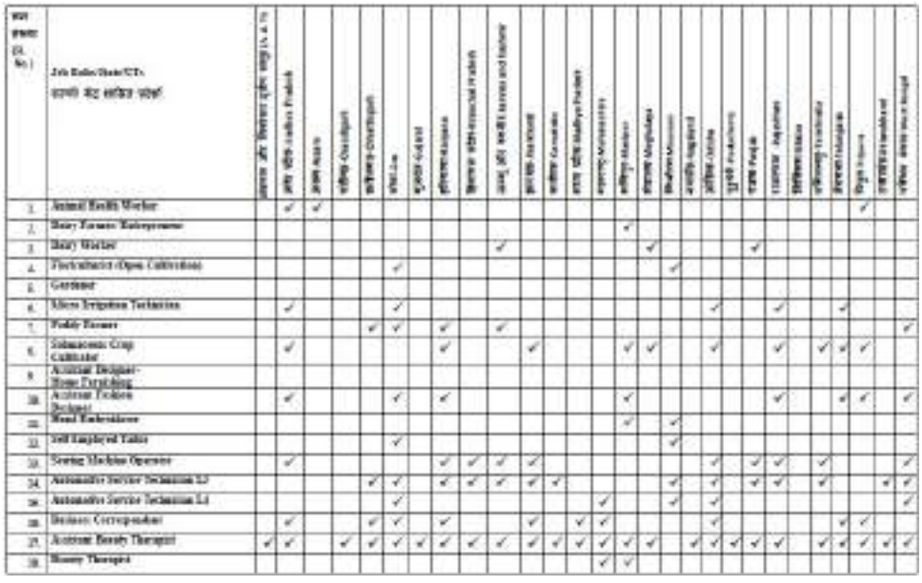

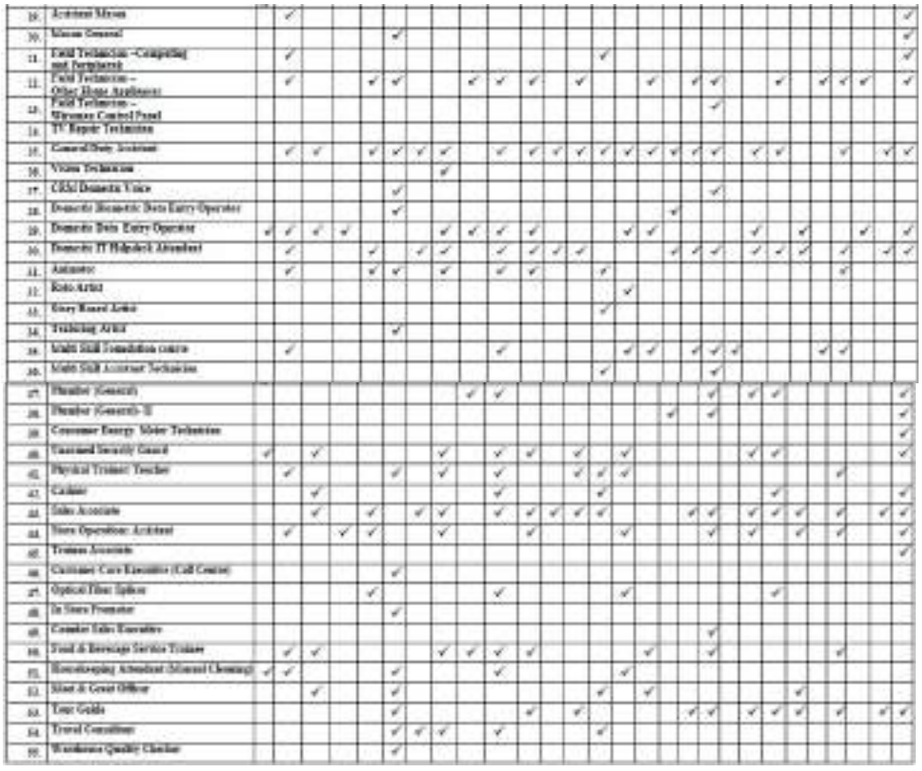

(Source: Framework on Vocational Pedagogy, PSSCIV, Bhopal, 2020)

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

5. माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक स्तर पर केंद्र प्रायोजित योजना +2 स्तर पर कब से लागू की गई?

   (क) 1988 (ख) 1989

   (ग) 1992 (घ) 1998

6. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 किसके द्वारा लाया गया?

   (क) SCERT (ख) NCERT

   (ग) NCTE (घ) NIOS

1.5 व्यावसायिक शिक्षा के मुद्दे/समस्याएं और रुझान

जब हम भारत के बारे में सोचते हैं, तो हम विविधता और संस्कृति के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अतिपिछड़ों के बारे में भी सोचते हैं। 1.2 बिलियन की एक बर्बर आबादी का मतलब है कि देश में औसत आयु 29 है और हमारी आधी आबादी 25 वर्ष से कम है। हमारे पास भारत के विकास के लिए यह प्रतीत होता है कि नकारात्मक कारक को एक वरदान में बदलने का अवसर है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा संभावित कार्यबल है। इसके अतिरिक्त, अधिक विकसित देशों में उम्र बढ़ने की आबादी भी 2022 तक लगभग 56.5 मिलियन की वैश्विक कुशल श्रम शक्ति की कमी का संकेत देती है।

कई सामाजिक असमानताएं हैं जो अभी भी समग्र विकास को प्रभावित करती हैं क्योंकि कई भारतीयों को अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए अवसरों और उपकरणों की पहुंच की कमी का सामना करना पड़ता है।

1.5.1 भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे, समस्याएं और चुनौतियां

टिप्पणी

शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम के परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। अधिकांश अभिभावक और छात्र व्यावसायिक शिक्षा को हीन मानते हैं, न कि सामान्य शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के बराबर। वास्तव में, शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का विषय कई समस्याओं, मुद्दों और चिंताओं से ग्रस्त है, जिन पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में कुछ निहित अड़चनें हैं। विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के साथ रहता है, जो ज्यादातर मामलों में, शिक्षा के राज्य विभागों के माध्यम से काम करते हैं। कर्नाटक और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा के अलग निदेशालय बनाए गए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से होता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शैक्षणिक समर्थन PSSCIVE, NCERT द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे पाठ्यक्रम के विकास, अनुदेशात्मक सामग्री, कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, अनुसंधान और मूल्यांकन कार्यक्रम और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

• व्यावसायिक शिक्षा के कुछ सकारात्मक पहलू

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम इतने तैयार हैं कि जब वे छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने या उन्हें स्व–रोजगार में मदद करने के लिए विशिष्ट कार्य उन्मुख कौशल विकसित करने में मदद करते हैं, तो वे उच्च शिक्षा के लिए अपने शैक्षणिक कैरियर में बाधा नहीं डालते हैं। इन कार्यक्रमों के कुछ सकारात्मक पहलू निम्नलिखित हैं–

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दो भाषाओं और तीन वैकल्पिक विषयों की उपस्थिति छात्रों को डिग्री स्तर पर उच्च अध्ययन के लिए चयन करने में सक्षम बनाती है, अगर उच्च शिक्षा के लिए गुंजाइश उनके लिए बढ़ा दी जाती है।
2. उद्यमिता कौशल के साथ व्यावसायिक क्षेत्रों को दिया जाने वाला अधिक वेटेज छात्रों को अपने स्वयं के विषयों में स्व–रोजगार के क्षेत्रों में अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से लागू करने में सक्षम बनाता है।
3. मौजूदा सामाजिक–आर्थिक संरचना में, विषय और समाज की निकटता के कारण व्यावसायिक क्षेत्रों की पसंद पर अत्यधिक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, यदि पाठ्यक्रम को नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।
4. व्यावसायिक शिक्षा में स्वरोजगार और गैर–संगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर गुंजाइश है।

व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे, समस्याएं और चुनौतियां

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे और समस्याएं इस प्रकार हैं–

1. भारत में वर्तमान वीईटी प्रणाली कुछ गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है जिनमें पुराने पाठ्यक्रम, कम धन और नीतिगत योजना और शासन के कई स्तर शामिल हैं।
2. i kBî Øe VET प्रशिक्षण प्रणाली का मुख्य स्तंभ है। अगर वीईटी प्रावधानों को विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, एजेंसियों और संगठनों द्वारा लागू किया जाता है, चाहे सरकारी या निजी, प्रमाणीकरण, मानकों और पाठ्यक्रम की बहुलता के साथ, यह पाठ्यक्रम और संस्थानों के अतिव्यापी होने के साथ–साथ छात्रों और नियोक्ताओं के लिए भ्रम पैदा करेगा।
3. वर्तमान वीईटी कार्यक्रम काफी हद तक सप्लाई–संचालित हैं और अभी भी उपलब्ध नौकरियों के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण का अभाव है। इस बेमेल को कम करने के लिए स्कूलों और उद्योग के बीच संबंध सुधारने की आवश्यकता है।
4. कौशल के बीच एक विचलन जो आबादी के पास है और उद्योग के लिए आवश्यक कौशल भारतीय युवाओं में कम रोजगार का एक प्रमुख कारण है।
5. भारत मुख्य रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था रहा है और इसकी अधिकांश जनसंख्या अभी भी पारंपरिक गतिविधियों पर निर्भर है, भारत की 90% से अधिक श्रम शक्ति अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में कम उत्पादकता और कौशल के साथ काम करती है। असंगठित क्षेत्र तक सीमित कौशल और अनुभव के साथ, ये श्रमिक उद्योग में बेरोजगार हैं।
6. नई तकनीकों के उद्भव के कारण स्टेनोग्राफी जैसे कई कौशल पुराने हो गए हैं। इससे उद्योग की जरूरत और जनशक्ति आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ता है।
7. भारत जैसे देशों में VET को हमेशा जनता और अभिभावकों द्वारा कम शैक्षणिक–योग्यता के लिए कैरियर की पसंद के रूप में माना जाता है, इस बात के साथ कि VET स्कूल छोड़ने वालों (स्कूली ड्रॉप आउट) के लिए है। कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में व्यावसायिक शिक्षा के बजाय 'अकादमिक' पर बहुत अधिक ध्यान और संसाधन दिए जाते हैं।
8. अपर्याप्त अकादमिक–उद्योग संबंध (लिंकेज) कारण रोजगार की कम दरों का कारण यह है कि नौकरी प्रदाताओं के लिए क्या चाह रहे हैं, प्रशिक्षण क्षेत्र के साथ संचार नहीं किया जाता है। इसके अलावा यह रोजगार नियोजन (प्लेसमेंट) को भी प्रभावित करता है।
9. अद्यतन पाठ्यक्रम जो उद्योग की वर्तमान आवश्यकता के लिए प्रासंगिक है, एक प्रमुख आवश्यकता है। पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकता के लिए प्रासंगिक होना चाहिए।
10. अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों और प्रशिक्षकों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण समस्या है।
11. अंशकालिक आधार पर अप्रशिक्षित और अनुभवहीन शिक्षकों की नियुक्ति।

टिप्पणी

12. प्रशिक्षण के दौरान निर्माण, आधुनिक उपकरण और कच्चे माल, सीखने में बाधा है। इसे धन की अनुचित रिलीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
13. प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही का अभाव एक और नुकसान है। यदि इन संस्थानों को स्वायत्तता का अच्छा सौदा दिया जाता है, तो वे वर्तमान बाजार की जरूरतों के बदलते परिदृश्य में उन्हें बदलने और समायोजित करने में बेहतर होंगे।
14. सक्षम संकाय शिक्षण, आदानों, अपर्याप्त धन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाओं और उपकरणों के संदर्भ में अवस्थापना सुविधाओं की अनुपलब्धता, शिक्षाविदों और प्रशासनों को प्रभावित करने वाले नौकरशाही निर्णयों में गैर–लचीले प्रबंधन और गैर–लचीलेपन, पाठ्यक्रम की अवधि, पार्श्व की कमी है।
15. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के मॉडल, और संबद्ध व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न मॉडल जैसे कि स्कूल आधारित मॉडल, उद्योग आधारित मॉडल, सहयोगी मॉडल और बहु–चैनल मॉडल को विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया है।
16. सहयोगी मॉडल को लागू करने में समस्या है। कई मामलों में नौकरी पर प्रशिक्षण प्रभावी नहीं है। चूंकि इस क्षेत्र में ऐसे छात्रों की कमी है और उद्योग की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
17. अलग और विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली का अभाव।
18. स्कूलों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाओं की अनुपस्थिति।
19. अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण।
20. उद्योगों में प्लेसमेंट की अनुपलब्धता।
21. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के बीच समन्वय का अभाव है। भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण MSDE के अंतर्गत है जबकि व्यावसायिक शिक्षा MHRD के अंतर्गत है। विभिन्न संस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
22. श्रम बाजार की जरूरतों और प्रशिक्षण कौशल के बीच एक बेमेल के लिए अग्रणी पाठ्यक्रमों की अप्रासंगिकता।
23. एकीकृत, अंतः संयंत्र प्रशिक्षुता (इन–प्लांट अप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण की अनुपस्थिति।
24. निजी और उद्योग की भागीदारी की कमी है।
25. देश में व्यावसायिक संस्थानों की कम संख्या।
26. वीईटी प्रणाली का अपर्याप्त वित्तपोषण।
27. औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की अनुपस्थिति में कई लोगों को औपचारिक रूप से कुशल होने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन वे अनौपचारिक प्रशिक्षुओं के रूप में काम करते हुए दक्षता हासिल करते हैं।
28. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) को स्टार और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत शुरू

किया लेकिन उन्होंने आरपीएल के सार और भावना का पालन नहीं किया। 2–3 घंटे के प्रशिक्षण के बाद मौजूदा कार्यरत संविदाकर्मियों को प्रमाणित करके संख्याओं को बढ़ाने के लिए अवधारणा का दुरुपयोग किया गया था।

29. राष्ट्रीय मानकों के स्वामित्व की अनुपस्थिति में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कौशल विकास के लिए नोडल मंत्रालय है। हालांकि, MSDE के अलावा, अन्य मंत्रालय/विभाग हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं।

टिप्पणी

30. भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण हमेशा प्रवेश स्तर की नौकरियों के बारे में होता है और इसे कभी भी आकांक्षात्मक नहीं माना जाता है।
31. सामाजिक स्वीकार्यता में कमी।
32. व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम प्राथमिकता।
33. बुनियादी सुविधाओं का अभाव (भवन, आधुनिक उपकरण और कच्चे माल)।
34. सेवा में ट्रेडों की अपर्याप्त या गैर–कवरेज जिस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं।
35. रोजगार के उद्देश्यों के लिए तुल्यता का अभाव।
36. विभिन्न एजेंसियों के बीच अभिसरण की कमी।
37. समग्र सामाजिक मान्यता का अभाव।
38. सार्वजनिक संस्थानों में VET के रोजगार आदान–प्रदान या सुधार के प्रावधान को स्थापित करना उच्च प्रभाव वाले हस्तक्षेप हैं।
39. व्यावसायिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अन्य प्रमुख बाधाएं– हाल के वर्षों में PSS केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (NCERT) ने हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, असम और महाराष्ट्र में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया है। इससे पहले गोवा, कर्नाटक, म.प्र., महाराष्ट्र और दिल्ली राज्यों के लिए भी इस तरह के अध्ययन किए गए थे। इनमें से प्रत्येक राज्य की शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन किया गया है। व्यावसायिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आधारित कुछ सामान्य समस्याएं निम्नानुसार दी गई हैं–
    - कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थित स्कूल–उद्योग लिंकेज का अभाव।
    - केंद्र और राज्य सरकारें भर्ती नियमों को संशोधित नहीं कर रही हैं।
    - पर्याप्त अनुदेशात्मक सामग्रियों की अनुपलब्धता, विशेष रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जरूरतों के लिए विकसित की गई।
    - प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक सुविधाओं के लिए अपर्याप्त सुविधाएं।
    - कार्यक्रम की सामग्री, अवधि और वितरण में अनम्यता।
    - समान या संबंधित ट्रेडों में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अवसरों की कमी।
    - पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विकास, कैरियर में सुधार और पार्श्व प्रवेश के लिए। लेकिन

तथ्य यह है कि व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों (+2 स्तर) में छात्रों में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं होती है।

आज वीईटी की पहचान इसके विकास के लिए किसी भी देश की सिद्ध आवश्यकता के रूप में की गई है। भारत जैसे देशों में इसका बहुत महत्व है जहां कुल जनसंख्या में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है और कौशल के साथ इस आबादी को बढ़ाने के लिए भारत को अत्यधिक कुशल श्रमशक्ति वाले देशों की सूची में लाया जाएगा, जो देश के लिए काफी आवश्यक कारक है।

टिप्पणी

शिक्षा में वीईटी से संबंधित कैरियर मार्गदर्शन शुरू करने जैसे आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, तो यह कौशल और रोजगार बढ़ाने पर उच्च प्रभाव डालेगा। विभिन्न हितधारकों–सरकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र, सामाजिक व्यवसायों और गैर–लाभकारी संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों–को वीईटी में क्षमता, गुणवत्ता और उपयोग की चुनौतियों को दूर करने के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र में काम करने की आवश्यकता है। वीईटी में सुधार करके रोजगार में वृद्धि करना एक जटिल मुद्दा है जिसमें पिछड़े सामाजिक समूहों के लिए जनसांख्यिकीय रुझान, आर्थिक और श्रम बाजार में सुधार, शिक्षा प्रणाली, उद्योग की भागीदारी और ऊपर की गतिशीलता शामिल है।

1.5.2 व्यावसायिक शिक्षा में नए रुझान और विकास – (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता प्रणाली, आजीवन और सतत शिक्षा, सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा)

व्यावसायिक शिक्षा को व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवसाय और रोजगार पर आधारित है। व्यावसायिक शिक्षा को कैरियर और तकनीकी शिक्षा (सीटीई) या तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली शिक्षा की भूमिका और विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा को मान्यता देती है। भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्णकालिक और साथ ही अंशकालिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

- **व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का संक्षिप्त इतिहास**
  - **1945:** रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी) की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागरिक जीवन में युद्धरत डिबार किए गए रक्षा सेवा कर्मियों को फिर से बसाने के लिए की गई थी।
  - **1950:** शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) स्थापित किए गए।
  - **1964:** कोठारी समिति द्वारा अनुशंसित माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए पहल की गई।
  - **1986:** उच्चतर माध्यमिक चरण में व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदान की गई।
  - **2013:** राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना (स्टार)।
  - **2015:** कौशल भारत मिशन–स्किल इंडिया 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य 2022 तक

विभिन्न कौशल में भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसमें सरकार की विभिन्न पहल शामिल हैं।

- **2016:** पीएम–यूयूवीए योजना (प्रधानमंत्री युवा विकास योजना)– पांच साल की अवधि के लिए चुनिंदा उच्च शिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (ITI) और उद्यमिता विकास केंद्र (EDCs) के चुनिंदा संस्थानों में उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए है।
- **2018–19:** आकांक्षापूर्ण कौशल (एस्पिरेशनल स्किलिंग) अभियान– इसमें कौशल विकास के लिए चुनौतियों की पहचान करना और इन चुनौतियों से उबरने में जिलों की सहायता के लिए अनुकूलित समाधान तैयार करना शामिल है।
- **2019:** आजीविका के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP) में स्वीकृत यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका कुल आकार यूएस डॉलर 675 मिलियन है, जिसमें यूएस डॉलर 500 मिलियन की विश्व बैंक सहायता भी शामिल है। सभी कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना वंचित वर्गों को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना। उद्योग का नेतृत्व करना और संचालित कौशल प्रशिक्षण क्षमता की मांग करना।

टिप्पणी

• व्यावसायिक शिक्षा में हालिया रुझान

रोजगार योग्यता, सामान्य कौशल; अभिवृत्ति एवं व्यवहार (एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जेनेरिक स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर) हैं जो नियोक्ता नई भर्तियों में तलाशते हैं और वे वर्तमान कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित होते हैं। रोजगार कौशल उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो कार्यस्थल की साक्षरता मांगों को प्रभावी ढंग से जवाब देने और नौकरी पर सफलतापूर्वक काम करने, सीखने और लागू करने के लिए व्यक्तियों द्वारा आवश्यक कौशल का उल्लेख करते हैं (गौएन, 1992)। फुगते एट अल के अनुसार– (2004) रोजगार योग्यता एक मनो–समाजिक निर्माण (एम्प्लॉयबिलिटी ए साइको–सोशल कंस्ट्रक्शन) है जो व्यक्तिगत विशेषताओं को अपनाता है जो अनुकूल अनुभूति, व्यवहार को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत–कार्य इंटरफेस को प्रभावित करके बढ़ाता है।

यह कार्य विशिष्ट सक्रिय अनुकूलनशीलता के रूप में संकल्पित है जो श्रमिकों को कैरियर के अवसरों को पहचानने और महसूस करने में सक्षम बनाता है। यह दोनों संगठनों के भीतर और नौकरियों के बीच आंदोलन को सुविधाजनक बनाता है। यह रोजगार प्राप्त करने की किसी व्यक्ति की संभावना को भी बढ़ाता है। नियोजनीयता या 'सॉफ्ट स्किल्स', जिसे नियोक्ता कर्मचारी से अपेक्षा करता है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

1. **मौखिक संचार कौशल** : सुनने का कौशल, प्रस्तुति कौशल, समूहों में भागीदारी, आवाज, स्वर, हावभाव, शैली, टेलीफोन पर बातचीत आदि।
2. **लिखित संचार कौशल** : स्पष्ट और छोटे संदेश, व्याकरण का सही उपयोग, वाक्य तैयार करना आदि।
3. **स्व–प्रेरणा कौशल** : स्व–सक्रियकर्ता।

टिप्पणी

4. **कार्य नैतिकता** : दूसरों के लिए सम्मान, मूल्य, समयनिष्ठ आदि।
5. **महत्वपूर्ण सोच** : व्यवस्थित रूप से जानकारी का उपयोग करें, अनुभवों को साझा करना, अवलोकन करना और तर्क करना, स्वयं के निर्णय लेने के लिए कौशल, क्रिया और विश्वास।
6. **बहु–कार्य (मल्टी–टास्किंग) कौशल** : नए कार्यों के लिए अनुकूलन, विभिन्न प्रकार के कार्य करना, आदि।
7. **नेतृत्व कौशल** : कुछ पूरा करने के लिए दूसरों का मार्गदर्शन करना और उनका समर्थन करना।
8. **अंतर्वैयक्तिक कौशल** : अन्य लोगों के साथ संबंध और रोजमर्रा की बातचीत में उनके साथ संवाद करना।
9. **संगठन कौशल** : संगठित और व्यवस्थित।
10. **समस्या–समाधान कौशल** : समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण करना और समाधान के साथ आना।
11. **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल** : कंप्यूटर आदि का उपयोग करके कम समय और ऊर्जा के साथ कुशलतापूर्वक कार्य करना।
12. **समय प्रबंधन कौशल (टाइम मैनेजमेंट स्किल्स)** : समय का समझदारी से और लगातार इस्तेमाल करना, शेड्यूल और मीटिंग पर बने रहना, डेडलाइन। इसमें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, प्रभावी समय–निर्धारण, गतिविधि लॉग को बनाए रखना, शामिल है।

माध्यमिक व्यावसायिक स्कूलों और श्रम प्रशिक्षण केंद्रों में कुशल श्रमिकों का सार्वजनिक पूर्व–रोजगार प्रशिक्षण भी उचित हो सकता है जब नियोक्ता और निजी प्रशिक्षण क्षमता कमजोर होती है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों को प्रभावी और कुशल दोनों होना चाहिए, और कई मामलों में बाजार की शक्तियों के प्रति जवाबदेही में सुधार के लिए संस्थागत प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी।

औद्योगिक देशों में अनुभव से पता चलता है कि प्रशिक्षण से असंतुष्ट श्रमिकों को रोजगार पाने में मदद मिल सकती है यदि अन्य पूरक तत्व काम में हों, जिनमें रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्व–रोजगार और छोटे व्यवसाय के विकास के लिए सहायता, प्रभावी श्रम बाजार में व्यवस्था और श्रम प्लेसमेंट संस्थान, सब्सिडी शामिल हैं।

सामान्य शिक्षा की तुलना में अच्छे प्रशिक्षण की लागत अधिक है, और इस प्रकार कुशलता से लागतों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम लेन–देन की प्रक्रिया को प्रभावी और कुशल बनाया जाना चाहिए। अन्य संसाधन संस्थानों और उद्योगों के साथ नेटवर्किंग करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NVEQF)

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NVEQF) देश के विकास की प्रक्रिया में है। एनवीईक्यूएफ का कार्य एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता प्रणाली के लिए सामान्य सिद्धांतों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना है, स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों को माध्यमिक से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक की योग्यता के साथ राष्ट्रीय मानकों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए अग्रणी बनाना।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय समकक्षता के लिए अग्रणी,
- व्यावसायिक शिक्षा (VE) सामान्य शिक्षा और नौकरी बाजार के बीच कई प्रवेश और निकास,
- व्यावसायिक शिक्षा के भीतर प्रगति,
- व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच स्थानांतरण, और उद्योग/नियोक्ताओं के साथ साझेदारी

टिप्पणी

प्रमुख विशेषताएं

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

(1) सीखने और काम का घनिष्ठ एकीकरण प्रदान करता है।

(2) सामान्य शैक्षणिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करता है।

(3) ज्ञान और कौशल के निरंतर उन्नयन को प्रोत्साहित करता है।

(4) क्षेत्रों और उस पार के बीच लचीले शैक्षिक मार्गों का समर्थन करता है।

(5) शैक्षणिक और व्यावसायिक के बीच सम्मान की समानता को प्रोत्साहित करता है।

(6) सामाजिक भागीदारों की अधिक और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है।

(7) सभी को VET की समान पहुंच प्रदान करके समावेशी विकास का समर्थन करता है।

व्यापकता (Scope)

व्यावसायिक शिक्षा तैयार करने के लिए एक अलग स्ट्रीम होगी। कई क्षेत्रों में उभरती अर्थव्यवस्था, उद्योग/नियोक्ता की मांग के अनुसार पहचान किए गए व्यवसाय/ट्रेडों के लिए कुशल व्यक्ति, जिसमें संगठित और गैर–संगठित दोनों क्षेत्र शामिल होंगे। इसके अलावा, मॉड्यूल के रूप में व्यावसायिक ऐच्छिक अपने शैक्षिक विषयों के अलावा शैक्षणिक स्ट्रीम के छात्रों के लिए भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें प्राप्ति प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा और एक मॉड्यूल के पूरा होने पर क्रेडिट मांग संचालित मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान की जाएगी। उद्योग/नियोक्ताओं के सहयोग से इन पाठ्यक्रमों को उच्च माध्यमिक सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के माध्यम से NVEQF प्रणाली के अनुरूप पेश किया जाएगा।

- **योजना का स्वरूप** (Nature of the Scheme)

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) होगी जिसके तहत वित्तीय अनुमोदित उद्देश्यों के लिए ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर सरकारी संगठनों/वीओ को सहायता दी जाएगी। इस योजना में नए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना शामिल होगी, मौजूदा व्यावसायिक स्कूलों को मजबूत बनाना, व्यावसायिक शिक्षा शिक्षकों की क्षमता निर्माण, योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का विकास को बढ़ावा देता है।

टिप्पणी

- **आवश्यकता**

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NVEQF) के विकास की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। एनवीईक्यूएफ एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता प्रणाली के लिए सामान्य सिद्धांत और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा, जिसमें स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को माध्यमिक से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक की योग्यता के साथ कवर किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय मानकों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी।
2. छात्रों को कई प्रवेश और निकास के साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता की गुंजाइश होगी। विशेष जरूरतों वाले बच्चों सहित हर बच्चे की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी होगा।
3. पाठ्यक्रम, सामग्री विकास, प्रशिक्षण और संसाधन व्यक्तियों की पहचान, मूल्यांकन, मान्यता, प्रमाणीकरण और नियुक्ति से शुरू होने वाले सभी चरणों में उद्योग/संभावित नियोक्ताओं के साथ निकट भागीदारी और सहयोग होगा।

- **संरचना**

Framework options for astudent

Certification Level	General Education Qualifications	TVET qualification	Proposed Certificate Awarding Bodies
1	Class IX (Pre-vocational	National Certificate for Work Preparation (NCWP-1)	Jointly by Institution and SSC*
2	Class X (Pre-vocational	NCWP-2	Jointly by Institution and SSC*
3	Class XI (General Academic/ Vocational Education)	National Competence Certificate (NCC 1)	Jointly by Institution and SSC*
4	Class XII (General Academic/ Vocational Education)	NCC 2	Jointly by CBSE/ State Boards /NIOS /State Open Schools and SSC
5	Diplomas	NCC 3	Jointly by Colleges / Polytechnics /Universities /IGNOU/State Open Universities and SSC*
6	Graduate Certificates/ Advanced Diplomas	NCC 4	Jointly by Colleges / Polytechnics /Universities /IGNOU/State Open Universities and SSC*
7	Bachelor Degrees and Graduate Diplomas	NCC 5	Jointly by Colleges / Polytechnics /Universities /IGNOU/State Open Universities and SSC*
8	Post Graduate Certificates, Post Graduate Diplomas and Bachelor Degrees (Honours)	NCC 6	Jointly by Colleges / Polytechnics /Universities /IGNOU/State Open Universities and SSC*
9	Masters	NCC 7	Jointly by Universities / IGNOU/ State Open Universities and SSC
10	Doctorates	NCC 8	Universities and SSC

• **प्रमाणीकरण** (Certification)

औपचारिक मोड में, राष्ट्रीय योग्यता प्रमाणपत्र 1 (एनसीसी 1) और एनसीसी 2 को क्रमशः कक्षा XI और XII में योग्यता के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, उन छात्रों को प्राप्ति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे जो छोटी अवधि के चयनित मॉड्यूल ले रहे हैं। उन्हें क्रेडिट संचय सुविधा के साथ मल्टी–एंट्री और मल्टीएक्सिट की एक प्रणाली के माध्यम से पेशकश की जाती है। उन नियमित छात्रों को भी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो सभी आवश्यक मॉड्यूल लेते हुए कक्षा XI / XII में दाखिला लेंगे लेकिन उनमें से केवल एक या कुछ को पूरा करेंगे। एक क्रेडिट संचय और स्थानांतरण (कैट) प्रणाली शिक्षार्थियों को संचित क्रेडिट को एक मान्यता प्राप्त योग्यता में बदलने के लिए विभिन्न मॉड्यूल से सीखने के कुछ क्रेडिट जमा करने में सक्षम बनाएगी। गैर–औपचारिक मोड में, मॉड्यूलर पाठ्यक्रम छोटी अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जो क्रेडिट संचय और बहु प्रवेश–निकास लचीलेपन के प्रावधान के साथ प्राप्ति/योग्यता प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा।

टिप्पणी

NVEQF को तैयार करने के लिए 12 राज्यों के राज्य शिक्षा मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था। एक समन्वय समिति द्वारा तैयार NVEQF पर कार्यरत दस्तावेज 30 वें 2011 को राज्य शिक्षा मंत्रियों के समूह को प्रस्तुत किया गया था। राज्यों के परिप्रेक्ष्य से मुद्दों और चिंताओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी। 7 जून, 2011 को हुई 58 वीं बैठक में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) द्वारा विकसित किए जा रहे फ्रेमवर्क का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया।

आजीवन और सतत शिक्षा (Life&long and Continuing Education)

भारत में कई शैक्षिक नीति दस्तावेजों और प्रवचनों में आजीवन सीखने/शिक्षा के महत्व पर बार–बार जोर दिया गया है। जबकि शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964–66) में कहा गया है कि शिक्षा स्कूली शिक्षा के साथ नहीं बल्कि आजीवन समाप्त होती है। भारत में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति – 1986 (1992 में संशोधित) को आजीवन शिक्षा को शैक्षिक प्रक्रिया का पोषित लक्ष्य माना जाता है, जो सार्वभौमिक साक्षरता, युवाओं, गृहिणियों, कृषि और उद्योग के लिए अवसरों का प्रावधान करता है।

पिछले तीन दशकों के दौरान देश में सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों द्वारा कई आजीवन सीखने के कार्यक्रमों को लागू किया गया था, लेकिन अधिकांश कार्यक्रमों में मुख्य रूप से वयस्क साक्षरता और सतत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। गैर साहित्यकारों की बड़ी संख्या और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम–साक्षरता तथ्य एट ए ग्लॉस्ट, 2007) के अनुसार नव साक्षरों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–20012) के निर्माण के साथ, भारत सरकार ने दायरे का विस्तार करने का विचार रखा।

भारत में आजीवन सीखने की भूमिका और महत्व कई सामाजिक व आर्थिक कारकों के कारण हाल के दिनों में बढ़ा है। प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में आजीवन सीखने का परिदृश्य भारत में तेजी से बदल रहा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान दृष्टिकोण न केवल पहली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए होगा, बल्कि उन्हें समेकित करने और नए विश्वविद्यालयों को कवर करने और कॉलेजों का चयन करने के लिए विस्तारित करने के लिए भी होगा।

आजीवन सीखना एक व्यापक सामान्य शब्द है। यह अन्य निकट संबंधी अवधारणाओं जैसे कि सतत शिक्षा, वयस्क शिक्षा आदि के साथ ओवरलैप करता है। आजीवन सीखने की अवधारणा नए विचारों जैसे 'सीखने वाले समाज' और 'शिक्षण संगठन' के विकास के साथ मजबूत होती है।

टिप्पणी

खुले विश्वविद्यालयों में लगातार बढ़ता नामांकन आजीवन सीखने के लिए लोगों की आवश्यकता का एक संकेतक है। कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों (विशेषकर तकनीकी संस्थानों) में जारी शिक्षा और 'दूरस्थ शिक्षा' के केंद्र अलग–अलग लक्ष्य समूहों की आजीवन सीखने की जरूरत को पूरा करने के लिए थे। इनमें जोर उन लोगों को आगे की शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने पर था जिनके पास पहले से ही योग्यता थी और वे विभिन्न संस्थानों/संगठनात्मक सेट–अप में काम कर रहे थे।

मुक्त विद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय खोलने के साथ, इस प्रवृत्ति में बदलाव आया है जिससे शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर बड़े पैमाने पर लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। उम्र, लिंग, पिछली योग्यता, आदि के बावजूद, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के संबंध में, आजीवन सीखने की अवधारणा ने अभी तक समग्र शैक्षिक विकास प्रतिमान में अपनी जड़ें नहीं पाई हैं।

• आजीवन और सतत शिक्षा के लक्षण

मानव विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अनिवार्य रूप से, मानव मस्तिष्क जीवन भर सक्रिय रहता है जब तक कि तंत्रिका कोशिकाएं जीवित हैं, जीवन है। मानव शरीर सोचने और काम करने के लिए है। यही कारण है कि, मनुष्य के लिए आजीवन सीखने की विशेषताएं अजीब हैं। यद्यपि स्तर में भिन्नता हो सकती है, सीखने के लिए प्रकार, पसंद और कारण व्यक्तिगत से अलग–अलग और सामाजिक–आर्थिक कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। व्यक्ति के जीवन की संक्षिप्त गुणवत्ता का सीधा संबंध आजीवन शिक्षा से है। नीचे दिए गए आजीवन सीखने के कुछ आयाम हैं।

1. यदि आजीवन शिक्षा प्रणाली में है, तो सभी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।
2. आजीवन शिक्षा और इसके लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के लिए पहुंच, अवसर और प्रेरणा आवश्यक है।
3. आजीवन सीखने की प्रकृति और डिजाइन लचीला होना चाहिए, और सामग्री, संदर्भों, समय और शिक्षाशास्त्र के संबंध में विविध होना चाहिए।
4. आजीवन शिक्षा योग्यता का अधिग्रहण करती है और चुने हुए क्षेत्र में अनुदैर्ध्य और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए एक व्यक्ति को योग्य बनाती है।

• व्यावसायिक शिक्षा और आजीवन और सतत शिक्षा

रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा एक पासपोर्ट है। यह जापान और पूर्व एशियाई औद्योगिकीकरण बाघों का अनुभव है, जहां बेरोजगारी दर काफी कम बनी हुई है। आजीवन वीईटी की मांग को पूरा करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, अर्थशास्त्र और समाजों के वैश्वीकरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग और श्रम बाजार संरचनाओं में परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है।

हमें यह मानना चाहिए कि अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों के आधार पर मानव संसाधन विकास के लिए निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसका वे सामना कर

रहे हैं। इसमें मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाने के तरीकों और रणनीतियों को खोजने के लिए नीति निर्देश, शोध और पिछले अनुभव शामिल हैं। यह एकल, बहु, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रणाली प्रदान करने के लिए VET कार्यक्रमों के अभिसरण को लंबी अवधि के लिए लचीले पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

- **आजीवन और सतत शिक्षा और प्रशिक्षण के उद्देश्य**

टिप्पणी

1. जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि,
2. बहु–कुशल मानव संसाधन विकसित करना,
3. इसके आधुनिकीकरण के मद्देनजर व्यवसाय की मांग को पूरा करना,
4. कम समय की जरूरतों के अनुरूप कर्मचारियों के विशिष्ट कौशल को अनुकूलित करना।

आजीवन सीखने के लिए वीईटी प्रणाली की गतिशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली विभेदित और परस्पर मार्गों का प्रस्ताव करती हैं, जिनमें से प्रत्येक को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए कई प्रकार के संकटों की एक शृंखला के लिए तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार, शिक्षार्थी केंद्रित और लचीली मल्टी एंट्री और मल्टी एक्जिट वीईटी सिस्टम एक विविध और बड़े लक्ष्य समूहों को समायोजित करने में सक्षम होंगे।

यह वीईटी कार्यक्रम एक व्यापक कौशल विकास प्रणाली प्रदान करेगा। व्यावसायिक शिक्षा को निचले स्तर पर कुशल कर्मियों को तैयार करने के लिए डिजाइन की गई शिक्षा के रूप में समझा गया है, जो व्यवसायों या नौकरियों के एक या अधिक समूहों के लिए योग्य है। हाई–टेक क्षेत्रों में भी उच्च कुशल कर्मियों की आवश्यकता के साथ अवधारणा बदल गई है।

भारतीय जीवन पद्धति में मानव संसाधन के विकास की अंतर्निहित प्रणाली है, जिसके माध्यम से हमारे किसान, शिल्पकार, कुम्हार, बुनकर, राजमिस्त्री, कालीन निर्माता, खिलौना बनाने वाले, सुनार, लुहार, मोची, लोक संगीतकार, लोक चित्रकार, लोक चित्रकार मंच के कलाकार, सज्जाकार, रसोइया, आदिवासी चिकित्सा पुरुष, आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसायी और अन्य लोग अपने शिल्प को उनके विज्ञान और तकनीकी और कौशल सहित सीखते हैं (गुरु 1999)। ये संभावित शिक्षार्थी बहु–प्रवेश और बहु–निकास प्रणाली के माध्यम से अपने व्यवसाय को उन्नत करने के लिए उन्नत कौशल प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे। यह प्रणाली मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न अवधि में मॉड्यूल के क्लस्टर की पेशकश करने के लिए एक मानदंड दृष्टिकोण पर आधारित है।

विभिन्न शब्दावली के तहत पहले शुरू किए गए सभी अलग–अलग कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, विस्तार, जनसंख्या शिक्षा, छात्र परामर्श, प्लेसमेंट सेवाएं और ई–लर्निंग का सुधार और जीवन स्तर कार्यक्रम के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि तेजी से बढ़ते वैश्विक ज्ञान परिदृश्य के अनुरूप उन्हें लाएं। आजीवन सीखना हाल की शैक्षिक नीतियों का एक मूल लक्ष्य बन गया है, जिसे अक्सर सामाजिक–आर्थिक विकास और ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में वकालत की जाती है।

सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education forAll)

महात्मा गांधी ने शिक्षा को 'समाज की चेतना और पुनर्निर्माण के बुनियादी उपकरण' के रूप में महत्व दिया। आधुनिक संदर्भ में यह भी व्यापक रूप से मान्यता दी गई है

टिप्पणी

कि सभी देशों की आकांक्षाओं और विकास लक्ष्यों को शिक्षा के आश्वासन से ही पूरा किया जा सकता है। सभी लोगों ने, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में और अधिकांश देशों के संविधान और कानून में एक अधिकार का वादा किया। लेकिन शिक्षा का मतलब केवल साक्षरता नहीं है। इसका मतलब एक कार्यात्मक क्षमता है जो जीवन में काम और सशक्तीकरण में उत्कृष्टता लाती है, जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध और बेहतर बनाती है।

आगे की सोच में, शिक्षा के चार स्तम्भों को जानना सीखना, करना सीखना, साथ रहना सीखना और बनना सीखना है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) को अनिवार्य रूप से संबोधित करना 'सीखना'। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक अनिवार्यता बन गया है। जनादेश सभी तक पहुंचना चाहिए और उभरते वैश्विक समाज के भीतर सभी क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन का निर्माण करना चाहिए, जिससे राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़े।

1951 के बाद से, भारत प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस दिशा में और इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए, कदमों की योजना बनाई गई है – बच्चों के लिए आसान पैदल दूरी के भीतर शैक्षिक सुविधाएं, स्कूलों में बच्चों के अनिवार्य नामांकन के लिए माता–पिता को प्रोत्साहित करना, बच्चों के बीच ड्रॉप–आउट पर ध्यान देना और इस तरह से बचना सबसे बेहतर तरीके से स्थिति और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बच्चे को स्कूल आने के लिए आकर्षित करने के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाना।

सभी मोर्चों पर सबसे बड़ी समस्या हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में और विशेष रूप से वहां की बालिकाओं के मामले में महसूस की गई है।

लेकिन पूरी योजना केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्तर पर भड़की हुई लगती है। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच लड़कियों के मामले में स्थिति अभी भी बदतर है।

ऐसे समूहों के बच्चों को सभी प्रयासों और सभी प्रोत्साहनों की नामांकित प्रेरणा नहीं मिलती है। घर के कामों में और छोटे भाई–बहनों की देखरेख में लड़की को मां के लिए एक दासी माना जाता है। देश के कुछ हिस्सों में, सामाजिक निषेध के कारण लड़की को सह–शिक्षा विद्यालय में नहीं भेजा जाता है। इस खाते में लड़कियां तब ही शामिल होती हैं, जब वे पहले से कम उम्र के समूह में शामिल हो जाती हैं, जैसे ही वे थोड़ी बड़ी हो जाती हैं।

विश्व बैंक के तहत 'सभी के लिए शिक्षा' परियोजना में भी शैक्षिक किट निःशुल्क वितरित की गई है; शिक्षा, अन्यथा निःशुल्क है, लेकिन परिणाम अभी भी उत्साहजनक नहीं हैं। ड्रॉपआउट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। 8 वर्ष या 10 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के बच्चे का इलाज ग्रामीण परिवारों में किया जाता है, क्योंकि उसे एक आय का पूरक माना जाता है, इसलिए उसके लिए और परिवार के लिए शिक्षा एक अनुचित विलासिता है। इस प्रकार ड्रॉपआउट की स्थिति 60% तक हो जाती है।

इस स्थिति को पूरा करने के लिए अंशकालिक लघु अवधि कक्षाएं, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में विकसित की गई

हैं। इस गैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख कार्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में किया गया है।

बच्चों के नामांकन में उत्साहजनक परिणाम दिखाने के लिए और गैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पंचायत स्तर पर कर्मचारियों को पुरस्कृत करने और मनोरंजक शो के माध्यम से बच्चों को आकर्षित करने से लेकर हर तरह के प्रयास किए गए हैं। यहां तक कि सभी कार्यक्रमों के लिए इस शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और स्टेशनरी, लड़कियों को मुफ्त पोशाक, दोपहर का भोजन और ऐसे अन्य अलाउंस दिए गए हैं।

टिप्पणी

1986 में, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने 21 वीं सदी से पहले 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की कसम खाई थी। भारत में दुनिया में निरक्षरों की सबसे बड़ी संख्या है। लाखों बच्चों के लिए, जो नहीं जानते कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा। सभी राज्य सरकारों ने उच्च प्राथमिक स्तर तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षण शुल्क समाप्त कर दिया है। 25 राज्यों में से, 15 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाले विधायी कार्य किए हैं। हालांकि प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच, छात्रों की अवधारण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे पहली बार 1990 में 'प्रत्येक समाज के प्रत्येक नागरिक' को शिक्षा का लाभ देने के लिए शुरू किया गया था। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए, राष्ट्रीय सरकारों, नागरिक समाज समूहों और यूनेस्को और विश्व बैंक समूह जैसी विकास एजेंसियों के एक व्यापक गठबंधन ने छह विशिष्ट शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है–

बचपन की व्यापक देखभाल और शिक्षा का विस्तार और सुधार करें, खासकर सबसे कमजोर और वंचित बच्चों के लिए। यह सुनिश्चित करें कि 2015 तक सभी बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां, जो कठिन परिस्थितियों में हैं, और जो जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, उनके पास अच्छी गुणवत्ता के पूर्ण और मुफ्त, और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच है।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को चिह्नित करते हुए कई मील के पत्थर हैं। 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया। "देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। सरकार ने संसद में 83 वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया, जिससे 6–14 वर्षों से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। लेकिन जो बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजा गया था, वह एक स्वाभाविक मौत हो सकती है, यह असंगत है। लेकिन अकेले कानून पर्याप्त नहीं हैं। 6–14 वर्ष की आयु के बीच की कुछ 60 लाख लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। लड़कियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और घर से दूरी या उनकी 'बेहतर उपयोगिता' जैसे कारणों से स्कूल नहीं जा सकती हैं।

• सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता

एक शिक्षित व्यक्ति को समझने में सक्षम होना चाहिए (समझ का अर्थ ज्ञान होना है), ज्ञान का पोषण करना, ज्ञान का पालन करना और उसे व्यवहार में बदलने के लिए

उपयुक्त रूप से निवेश करना– (अर्थात, करने की क्षमता), किसी के कार्य की आज्ञा देना, उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करना और इस प्रकार समझदारी और बेहतर प्रदर्शन पर जाएं, उत्कृष्टता के उच्च स्तर तक पहुंचें। इस प्रकार 'टू' सार्थक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और इसे शिक्षा के शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में लिया जाना चाहिए।

टिप्पणी

भाषाओं के मामले में निश्चित, अनिवार्य वेटेज के रूप में, कई विकल्पों की पेशकश, सभी के लिए एक विस्तृत श्रृंखला से चुनने के लिए निःशुल्क है जैसे कि दवा का अध्ययन करने वाला व्यक्ति हस्तशिल्प में एक कोर्स की पेशकश कर सकता है। यह एक अनोखा संयोजन हो सकता है लेकिन असाध्य नहीं है क्योंकि कई मामलों में डॉक्टरों, इंजीनियरों या वैज्ञानिकों ने संगीत और कला के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, वास्तव में लोग अलग–अलग संकायों में समान रूप से अच्छी तरह से अलग हो सकते हैं जो अलग–अलग दिखते हैं।

यह एक ही संकाय या समान रंगों के संकायों को विकसित करने की एकरसता जीने की तुलना में जीवन में अधिक संतोषजनक और पुरस्कृत है। वैकल्पिक रूप से या इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक और उद्यमशीलता की शिक्षा को विभिन्न मौजूदा संकायों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

एक देश में परिवर्तनों की छाप पहले से ही दुनिया और समय के माध्यम से महसूस की जा रही है। कोई भी देश दूसरों से अलग–थलग नहीं रहेगा। सीमाएं दुनिया को एक विशाल बाजार में बदलने के लिए भंग कर रही हैं, जिसमें राष्ट्रों की पकड़ के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। यह महसूस किया गया है कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ संवर्धित कार्यबल के कौशल और क्षमता आर्थिक विकास की सीमा और परिमाण को एक महत्वपूर्ण सीमा तक सीमित कर देते हैं और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए व्यक्तियों को अवसर प्रदान करते हैं।

इस तरह के परिदृश्य में, बेहतर कुशल मानव संसाधन और तकनीक शर्तों को तय करेगी, जिससे अच्छे संसाधन वाले प्रमुख देश सुपर पावर होंगे, यह प्रभावी रूप से, सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए मंच को सुदृढ़ करेगा।

1.5.3 जनसंख्या वृद्धि, मूल्य शिक्षा, मानवाधिकार, आरटीई –2009 आदि जैसी उभरती हुई चिंताएं और व्यावसायिक शिक्षा के साथ उनका संबंध

अकाल, दुर्घटनाओं, बीमारियों, संक्रमण और युद्ध के कारण मानव उच्च मृत्यु दर की स्थिति में विकसित हुआ और इसलिए प्रजातियों के अस्तित्व के लिए अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दर आवश्यक थी। अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दर के बावजूद, वैश्विक आबादी के लिए मानव जाति के विकास से लेकर 19 वीं शताब्दी के मध्य तक एक अरब तक पहुंचने में समय लगा। बीसवीं शताब्दी में स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों और दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में अभूतपूर्व तेजी से सुधार देखा गया। परिणामस्वरूप मृत्यु दर में भारी गिरावट आई और दीर्घायु में वृद्धि हुई। जनसंख्या ने इन परिवर्तनों को महसूस किया और उनकी प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए कदम उठाए लेकिन प्रजनन क्षमता में गिरावट इतनी अधिक नहीं थी। परिणामस्वरूप वैश्विक जनसंख्या सौ वर्षों में चार गुना बढ़ गई है और 6 बिलियन तक पहुंच गई है।

वैश्विक जनसंख्या परिदृश्य

टिप्पणी

1901 में विश्व की जनसंख्या 1.6 बिलियन थी। 1960 तक, यह 3 बिलियन और 1987 तक 5 बिलियन और 1999 में 6 बिलियन हो गई। वर्तमान में, हर 12–13 वर्षों में एक अरब लोगों को जोड़ा जाता है। पिछले दशक के दौरान जन्म दर में पर्याप्त गिरावट आई है। गिरावट के कारणों में समाज से समाज में भिन्नता है। शहरीकरण, बढ़ती शैक्षिक प्राप्ति, महिलाओं में बढ़ता रोजगार, कम शिशु मृत्यु दर कुछ प्रमुख कारक हैं जो छोटे परिवारों की बढ़ती इच्छा के लिए जिम्मेदार हैं; बढ़ती जागरूकता और गर्भनिरोधक की बेहतर पहुंच ने युगल के अधिकांश के लिए वांछित पारिवारिक आकार प्राप्त करना संभव बना दिया है।

कुछ देशों में जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से मृत्यु दर में वृद्धि के कारण हुई है (जैसे कि उप–सहारा अफ्रीका में एचआईवी संबंधित मृत्यु दर)। इन सभी के परिणामस्वरूप नब्बे के दशक के दौरान वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पहले की भविष्यवाणियों की तुलना में तेज है। वर्तमान में, वार्षिक वेतन वृद्धि लगभग 80 मिलियन है। इसके 2020–25 तक लगभग 64 मिलियन और 2045–50 तक 33 मिलियन तक घट जाने की उम्मीद है; विकासशील देशों में जनसंख्या का 95% विकास होता है। अधिकांश जनसांख्यिकी का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि में वर्तमान त्वरित गिरावट अगले कुछ दशकों तक जारी रहेगी और संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या प्रभाग के मध्यम अनुमानों के अनुसार, वैश्विक जनसंख्या 2050 तक बढ़कर 8.9 बिलियन हो जाएगी।

जनसंख्या, जो किसी भी आर्थिक गतिविधि (नियोजित व्यक्ति) और काम की मांग करने वाली आबादी में लगी हुई है। (बेरोजगार) लेबर फोर्स का गठन करती है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति है। उपलब्ध मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए श्रम शक्ति की प्रोजेक्शन पूर्व–आवश्यकता है।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास पर्याप्त श्रम शक्ति, उचित कौशल और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि तेजी से सामाजिक व आर्थिक विकास हो और आवश्यक कौशल और उपलब्ध कौशल के बीच कोई बेमेल न हो। नियोजन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन (स्व–रोजगार और वेतन रोजगार दोनों) के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है।

अतीत में, भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर युवा निर्भरता का पर्याप्त बोझ लाद दिया है। पिछले एक दशक के दौरान, राष्ट्रीय आर्थिक प्रदर्शन पर जनसांख्यिकी के प्रभाव के संबंध में दो महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। सबसे पहले आबादी को बदलती उम्र संरचना के प्रभाव के साथ करना है। दूसरा जनसंख्या स्वास्थ्य से संबंधित है।

जनसांख्यिकी 'जनसांख्यिकीय संक्रमण' का उपयोग इस प्रभाव को समझाने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में करते हैं। जनांकिकीय परिवर्तन लगभग सर्वव्यापी परिवर्तन वाले देशों को संदर्भित करता है जो उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर और कम मृत्यु दर के एक शासन से गुजरता है। जैसा कि यह घटना एक अतुल्यकालिक फैशन में घटित होती है, मृत्यु दर में पहले और जन्म की दर में बाद में गिरावट आती है, देशों को अक्सर तीव्र जनसंख्या वृद्धि की एक संक्रमणकालीन

अवधि का अनुभव होता है। यह अवधि पारंपरिक रूप से जनसांख्यिकी में रुचि रखने वाले अर्थशास्त्रियों का मुख्य केंद्र बिंदु रही है।

माना जाता है कि स्वास्थ्य चार मुख्य कारणों से आर्थिक विकास को गति देता है–

- सबसे पहले, एक स्वस्थ कार्यबल एक अधिक उत्पादक कार्यबल है।
- दूसरा, स्वस्थ बच्चे स्कूल में उपस्थिति के बेहतर रिकॉर्ड रखते हैं, और लंबे समय तक स्कूल में रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक अधिक शिक्षित कर्मचारी होता है। स्वस्थ बच्चों में भी बेहतर संज्ञानात्मक कार्य होते हैं, और शारीरिक और मानसिक विकलांगता से बचते हैं जो बचपन की बीमारी से जुड़ा हो सकता है।
- तीसरा, स्वस्थ आबादी में उच्च बचत दर होती है, क्योंकि लोग सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की प्रत्याशा में अधिक बचत करते हैं।
- और अंत में, स्वस्थ आबादी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करती है।

टिप्पणी

- **जनसंख्या वृद्धि परिणाम**

1. कई विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि जारी रहने के कारण भूमि पर दबाव, भूमि धारण का विखंडन, मत्स्यपालन, सिकुड़ते जंगल, बढ़ते तापमान, पौधे और पशु प्रजातियों का नुकसान हुआ है।
2. जीवाश्म ईंधन (मुख्य रूप से विकसित देशों द्वारा) के बढ़ते उपयोग के कारण ग्लोबल वार्मिंग विकासशील देशों में आबादी वाले तटीय क्षेत्रों, उनके खाद्य उत्पादन और आवश्यक जल आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।
3. तेजी से जनसंख्या वृद्धि, विकास की गतिविधियां या तो बढ़ती जनसंख्या या जनसंख्या की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ बदलती जीवनशैली और उपभोग पैटर्न, भारत में पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़ी चुनौती है।
4. संसाधन के उपयोग की दर और उपयोग की प्रकृति दोनों के कारण जंगलों पर गंभीर दबाव है।
5. अविकसित देशों में, पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए जनसंख्या की संरचना निर्धारित की जाती है। इन देशों में जन्म दर और जीवन की कम उम्मीद के कारण आश्रितों का प्रतिशत बहुत अधिक है।
6. विकसित देशों के तहत, जनसंख्या का तेजी से विकास पूंजी की उपलब्धता को कम कर देता है जिससे इसकी श्रम शक्ति की उत्पादकता कम हो जाती है। परिणामस्वरूप उनकी आय कम हो जाती है, और बचत करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, जो बदले में, पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
7. आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में, निवेश की आवश्यकताएं इसकी निवेश क्षमता से परे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या जनसांख्यिकीय निवेश की आवश्यकताओं को बढ़ाती है जो एक ही समय में लोगों की बचत की क्षमता को कम कर देती है।
8. यह निवेश आवश्यकताओं और निवेश योग्य धन की उपलब्धता के बीच एक गंभीर असंतुलन पैदा करता है। इसलिए, ऐसे निवेश की मात्रा एक अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर से निर्धारित होती है।

9. जनसंख्या में तेजी से वृद्धि का मतलब श्रम बाजार में आने वाले व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या है जिनके लिए रोजगार प्रदान करना संभव नहीं हो सकता है।
10. वास्तव में, अविकसित देशों में, नौकरी चाहने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि योजनाबद्ध विकास की दिशा में सभी प्रयासों के बावजूद, सभी को रोजगार प्रदान करना संभव नहीं है।
11. तेजी से बढ़ती जनसंख्या आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के लिए बेरोजगारी की समस्या को हल करना लगभग असंभव बना देती है।
12. जनसंख्या वृद्धि खाद्य समस्या पैदा करती है।
13. श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को और कम कर देता है, दूसरा, खाद्यान्नों की कमी से खाद्यान्न आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उनके विदेशी मुद्रा संसाधनों पर अनावश्यक रूप से दबाव डालता है।
14. बढ़ती जनसंख्या वृद्धि से औद्योगीकरण के साथ बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों का प्रवास होता है। इससे बड़े शहरों और कस्बों में प्रदूषित हवा, पानी, शोर और आबादी होती है।
15. रोजगार तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
16. तेजी से बढ़ती जनसंख्या आय, बचत और कम कर देती है।
17. पूंजी निर्माण मंद हो गया है और रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है।

टिप्पणी

मूल्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के साथ उसका संबंध (Value education and their relationship with vocational education)

शब्द 'वैल्यू' एक लैटिन शब्द 'वेलेरे' से लिया गया है, जो किसी चीज के मूल्य या उपयोगिता को व्यक्त करता है। यह उन मूल्यों के प्रति व्यक्तियों की प्रतिबद्धता है जो मानव समाज के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। मूल्य हमारे वैश्विक दृष्टिकोण और आचरण को आकार देने वाले सिद्धांत हैं। डॉ. राधाकृष्णन ने ठीक ही कहा है कि, एक सभ्यता ईंटों, स्टील की गुणवत्ता और चरित्र से नहीं बनी है। इसलिए, एक व्यक्ति में सामाजिक और नैतिक मूल्यों, अखंडता, चरित्र, आध्यात्मिकता और बहुत कुछ प्रदान करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता होती है। मूल्य शिक्षा के पीछे मुख्य विचार छात्रों में आवश्यक मूल्यों की खेती करना है ताकि सभ्यता जो हमें जटिलताओं का प्रबंधन करना सिखाती है, उसे निरंतर और आगे विकसित किया जा सके।

प्राचीन शिक्षा प्रणाली और मूल्यों की शिक्षा प्राचीन भारत ने मानव जीवन में शिक्षा के सर्वोच्च मूल्य को मान्यता दी। प्राचीन विचारकों ने महसूस किया कि शिक्षित व्यक्तियों के बिना एक स्वस्थ समाज संभव नहीं है। उन्होंने छात्रों को इसके सभी पहलुओं का आनंद लेने के लिए उपयोगी जीवन के लिए तैयार करने के लिए बहुत उदार शैक्षिक योजना तैयार की। प्राचीन काल में, भारत ने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को स्पष्ट रूप से आत्म–साक्षात्कार के रूप में मान्यता दी थी। इसलिए, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कर्तव्यों को निभाने के लिए अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करना था।

टिप्पणी

• मूल्य–शिक्षा का अर्थ

शिक्षा का बहु उद्देश्य और मुख्य कार्य छात्रों के सर्वांगीण और अच्छी तरह से संतुलित व्यक्तित्व का विकास है, और मानव बुद्धि के सभी आयामों को विकसित करना है ताकि हमारे बच्चे हमारे राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक, सामंजस्यपूर्ण, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद कर सकें। लेकिन, आजकल ज्ञान–विज्ञान और सूचना–आधारित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें केवल बच्चे के बौद्धिक विकास का ध्यान रखा जाता है।

• मूल्य शिक्षा की आवश्यकता

21 वीं सदी की शुरुआत के साथ, दुनिया भर में मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, जिसने सामाजिक मूल्यों में कई बदलाव किए। औद्योगीकरण और वैश्वीकरण की घटना ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों आदि के मुद्दों को जन्म दिया है। आज का समाज अत्यधिक भौतिकवादी हो गया है। केवल मौद्रिक विचार संस्थान और छात्रों के दिमाग में हैं। मूल्यों के संबंध में, अपराध, हिंसा, लालच मानव जीवन के सभी पहलुओं में फैल गए हैं। अब एक दिन, भारत का राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक चरण से गुजर रहा है, जो लंबे समय से स्वीकृत मूल्यों के क्षरण का खतरा पैदा करता है। प्यार, सहकारिता, विश्वास, स्वीकृति, खुशी, गरिमा, व्यक्तिगत मतभेदों के लिए सम्मान, समझौता, सच्चाई, समझ और श्रद्धा जैसे मूल्य तनाव में वृद्धि कर रहे हैं।

• मूल्य शिक्षा के उद्देश्य

छात्रों/युवाओं में अच्छे जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए उन्हें सही जीवन पद्धति अपनाने में सक्षम बनाना बेहद आवश्यक है। इसलिए, मूल्य–उन्मुख शिक्षा का उद्देश्य निम्नानुसार होना चाहिए–

- छात्रों/युवाओं में नैतिकता, समय की पाबंदी, खुशी, समानता, बंधुत्व और वैज्ञानिक स्वभाव आदि के बुनियादी मूल्यों को विकसित करना।
- छात्रों को एक जिम्मेदार और प्रगतिशील नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित करना।
- विद्यार्थियों को लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीय एकीकरण और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों से परिचित कराना।
- स्वयं, समाज, राजनीति, मानवता, धर्म और पर्यावरण आदि के प्रति सही दृष्टिकोण का एहसास करने के लिए छात्र के कुल व्यक्तित्व का विकास करना।
- छात्रों/युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के लिए प्रेरित करना।

भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा लाए गए वर्ष, 1974–79 में शिक्षा पर ध्यान दिया गया है– 'शायद, शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। शिक्षकों और प्रशासकों को स्कूलों में मूल्य–उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए, मास मीडिया और विभिन्न प्रकार के स्कूल संगठनों के माध्यम से लोगों में पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न करना आवश्यक है। स्कूल निश्चित रूप से विभिन्न, पाठ्यक्रम और सह–पाठ्यक्रम कार्यक्रमों के प्रभावी संगठन के माध्यम से विद्यार्थियों में वांछनीय मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।'

शिक्षा की नीति (1986) ने मूल्य–उन्मुख शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है और टिप्पणी की है कि भारत, सांस्कृतिक रूप से बहुवचन समाज है, 'शिक्षा को सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसकी ओर उन्मुख होना चाहिए।' 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने निम्न कारणों से मूल्य–शिक्षा की आवश्यकता की बहुत दृढ़ता से सिफारिश की है।

टिप्पणी

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति के कारण लोगों की जीवनशैली में पूरी तरह से बदलाव आया है।
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव जीवन की बेहतरी के लिए उपयोग करने के बजाय मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले सामूहिक विनाश के हथियारों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है।
3. स्कूलों को उन मूल्यों का माहौल बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो विभिन्न गतिविधियों को चलाने चाहिए और छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षिक प्रशासकों के बीच मूल्यों के संवर्धन के लिए अनुकूल होंगे।
4. मूल्य–शिक्षा के कार्यक्रमों को अपने सभी आयामों – भौतिक, महत्वपूर्ण, बौद्धिक, सौंदर्य, नैतिक और आध्यात्मिक में अभिन्न व्यक्तित्व के मूल्यों को शामिल करना चाहिए।

मूल्य शिक्षा, इस प्रकार नैतिकता को छात्रों के लिए एक जीवित चिंता बनाने के लिए चिंतित है। इसलिए, जो आवश्यक है वह है मूल्य–शिक्षा। मूल्य–शिक्षा के संबंध में कई शिक्षकों और शिक्षाविदों के वर्णन के बावजूद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निरंतर अनुसंधान मूल्य–शिक्षा के विवरण को और अधिक पर्याप्त बनाते रहेंगे।

मानव मूल्य एक शैक्षणिक व्यवहार है जिसके माध्यम से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समझ की प्रगति होती है। शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास है, इसलिए व्यक्तिगत प्रगति के लिए संज्ञानात्मक, अभिसारी और प्रभावी डोमेन को सीखने के स्तर पर ले जाया जाता है। विषय की जानकारी के आदान–प्रदान से, संज्ञानात्मक डोमेन में विकास आसानी से संभव है।

मानवाधिकार और व्यावसायिक शिक्षा के साथ संबंध (Human rights and their relationship with vocational education)

मानवाधिकार शिक्षा को 'मानव अधिकारों के कानून, उसके इतिहास, सिद्धांत, आदि की शिक्षा' के रूप में परिभाषित किया गया है। मानव व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए शिक्षा आवश्यक है और यह मानव अधिकारों और व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता को मजबूत करने में सहायक है।

10 दिसंबर, 2004 को, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सभी क्षेत्रों में मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विश्व मानवाधिकार शिक्षा (2005–चल रही) कार्यक्रम की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के दौरान रखी गई नींव पर भवन निर्माण मानवाधिकार शिक्षा (1995–2004), विश्व कार्यक्रम, जिसे एक नए विशिष्ट मानक–सेटिंग प्रयास द्वारा पूरक किया गया है, अर्थात् मानव अधिकार शिक्षा और प्रशिक्षण पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का विकास, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है कि मानवाधिकार शिक्षा दूरगामी परिणाम दे सकती है।

मानवाधिकार शिक्षा शिक्षकों के साथ–साथ शिक्षार्थियों के लिए एक ज्वलंत विषय बन गया है। मानव अधिकार शिक्षा में कई किस्में हैं और लगातार क्षेत्र को बदलकर

टिप्पणी

विश्व समाज के विकास के लिए प्रतिक्रिया देता है। आजकल, कक्षा में मानवाधिकार शिक्षा विभिन्न नामों से चर्चा करती है जैसे संघर्ष संकल्प, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, विकास शिक्षा, विश्व व्यवस्था अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और एडीआर, पुनर्स्थापना न्याय शिक्षा इसके द्वारा हम सामाजिक अन्याय, संघर्ष और युद्ध के खतरों के कारणों का पता लगा सकते हैं, आदि। ये विषय सामाजिक अन्याय, संघर्ष, और युद्ध–खतरे, आदि जैसी समस्याओं के लिए रोकथाम के लिए निवारक शिक्षा से जुड़ते हैं।

मानव अधिकारों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग शिक्षण के लिए किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्र की जिम्मेदारी के बारे में पढ़ाने के लिए, माता–पिता, लोकतंत्र, आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उपयोग मानवाधिकार शिक्षा के लिए अध्ययन सामग्री के रूप में किया जा सकता है। ऐसे अधिकारों के बारे में शोधकर्ताओं के मानवाधिकारों और अनुभवों पर समाजों, सामाजिक और धार्मिक समूहों के विभिन्न विचार और यह उन सामाजिक परिवर्तनों और ऐतिहासिक घटनाओं का समर्थन करेगा जो एक महान राष्ट्र को विकसित करने के लिए आवश्यक हैं।

भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत में मानवाधिकार शिक्षा के लिए नीतियों की सिफारिश की है–

- **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग**– 1948 में, भारत सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न चरणों की सिफारिश की। इसने राष्ट्र के लिए कुशल दिमाग विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का वर्णन किया।
- **माध्यमिक शिक्षा आयोग**– भारत सरकार ने सितंबर 1952 में डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग के मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्वों का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा, विश्व नागरिकता की अवधारणा, समाजों और मानव से संबंधित बुनियादी ज्ञान की शुरुआत थे।
- **कोठारी आयोग**– भारतीय शिक्षा आयोग जिसे जुलाई 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग के रूप में जाना जाता था। आयोग ने 29 जून, 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रणाली में 22 प्रमुख सिफारिशों की सिफारिश की, जैसे कि समान शैक्षिक अवसर, शैक्षिक संरचना, शिक्षण के तरीकों में सुधार, पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता, शिक्षकों की शिक्षा आदि।

  भारत सरकार ने 1968 में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियों की शुरुआत की; जो शिक्षा आयोग (1964–1966) द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर था। इन नीतियों को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए बुलाया गया था और शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर प्रशिक्षण की बात की गई थी। ये नीतियां 'तीन भाषा सूत्र' पर केंद्रित हैं। फिर सरकार ने आगे 1986 में शिक्षा के लिए अन्य राष्ट्रीय नीतियों की शुरुआत की गई, जो बालिका परिवर्तन, पिछड़े वर्गों के उन्नयन, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष स्कूल, आदिवासी लोगों के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा में योग्यता सूची में प्रवेश आदि पर केंद्रित थी।

टिप्पणी

- भारतीय संसद ने नए आयोगों की स्थापना की। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में और आगे, एस. बी. चव्हाण की अध्यक्षता में चव्हाण समिति ने मूल्य आधारित शिक्षा की सिफारिश की जिसमें सत्य, धार्मिक आचरण, शांति, प्रेम और अहिंसा शामिल हैं; ये पांच सार्वभौमिक मूल्य हैं; सिफारिश के समान ये विचार कोठारी आयोग द्वारा दिए गए हैं।
- भारत के विधि आयोग की सिफारिश पर, भारतीय संसद ने 2002 में एक संशोधन विधेयक पारित किया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है और ऐसा अधिकार संविधान के भाग IIA में डाला गया है।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 1986 भारतीय संसद ने 1969 और 1986 में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियों की शुरुआत की, जो 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1964 में कोठारी आयोग और इतने ही के रूप में विभिन्न शिक्षा आयोग का परिणाम था। ये नीतियां शैक्षिक अवसर के समतुल्य थीं।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 1986 द्वारा सिफारिशें दी गईं–

- o ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना।
- o स्कूलों को सुझाव दिया गया था कि प्रवेश मेरिट सूची में होना चाहिए।
- o सामाजिक परिवर्तन में तेजी लाने के लिए बालिकाओं को शिक्षित करना।
- o आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा प्रदान करें।
- o मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष स्कूल।

• भारत में मानव अधिकारों की आवश्यकता

आजकल, भारत की शिक्षा प्रणाली में नैतिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। यह लोकतंत्र और व्यक्तियों की गरिमा के लिए बहुत हानिकारक है। जो मानव अधिकारों के साथ–साथ संवैधानिक अधिकारों से आच्छादित हैं। इसलिए, भारत में प्राथमिक स्तर के साथ–साथ उच्च शिक्षा में भी मानवाधिकार शिक्षा को एक विषय के रूप में जोड़ने की पुरजोर सिफारिश की जाती है।

ज्ञान मानव को अपने अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए सबसे अच्छा बचाव है। शिक्षा वह मूल स्रोत है जो मानव अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। एक के अधिकारों के बारे में सीखना जो दूसरों के अधिकारों के बारे में निर्माण करता है और जो एक शांतिपूर्ण और सहिष्णु समाज की स्थापना में मदद करता है।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय शांति, निरस्त्रीकरण और पर्यावरण संरक्षण संस्थान और कई एनजीओ ने देशव्यापी मानवाधिकार के लिए एक सार्वजनिक सूचना अभियान चलाया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के बारे में अधिक जागरूक बनाना और उनके लिए खड़े होने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित है। इसी समय, अभियान उन साधनों का ज्ञान फैलाता है जो मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद हैं।

टिप्पणी

आने वाले सालों में भारत ऐसा देश बन जाएगा जहां सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। लेकिन अगर यह युवा अशिक्षित, बेरोजगार, अपने अधिकारों के बारे में अनजान है, तो राजनेता बहुत आसानी से उनका उपयोग करते हैं। इसलिए वर्तमान अध्ययन में शोधकर्ता स्नातक छात्रों में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता के बारे में सर्वेक्षण करते हैं। साथ ही शोधकर्ता ने मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम लागू किया।

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य के पास हैं या उसकी मानवीय गरिमा के अधिकार सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार हैं। वे व्यक्तियों और शक्ति संरचनाओं के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं, विशेष रूप से राज्य। मानवाधिकार परिसीमन राज्य शक्ति और, एक ही समय में, राज्यों को एक ऐसे वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक उपाय करने की आवश्यकता होती है जो सभी लोगों को उनके मानव अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है।

इस प्रकार, यह संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों या हमारे संविधान से लिए गए मानवाधिकारों के सार सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मानवाधिकारों को एक शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ये जन्म के साथ शुरू होते हैं और मृत्यु तक खड़े रहते हैं और ये अधिकार जन्मे अधिकारों, पर्यावरण अधिकारों, शिक्षा के अधिकारों, जीने के अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, मरने के अधिकार आदि के सहयोग से, जिसे इंसान से जोड़ा जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र भी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर मानव अधिकारों के बारे में बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रों को मजबूर करते हैं। भारतीय संविधान भी व्यक्तियों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में सुरक्षित करता है और राज्य की नीतियों के निर्देश सिद्धांत के रूप में राज्य पर दायित्व प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र की मदद से भारत के मानवाधिकार आयोग द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आयोग का मकसद सभी के लिए बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित करना है। अंत में, मैं कह सकता हूं कि मानवाधिकार शिक्षा के अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इन शैक्षिक अधिकारों को राज्यों के बाद शैक्षिक प्रणाली में जोड़ा जाना चाहिए।

आरटीई–2009 और व्यावसायिक शिक्षा के साथ संबंध (RTE-2009 and their relationship with vocational education)

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लम्बी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि– राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया। आगे चलकर 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया जो इस प्रकार है–

"राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा।"

और इसी 86 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 (ट) जोड़ा गया जो इस प्रकार है–

''माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) पास किया गया। इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act, RTE) कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया है। इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं–

टिप्पणी

(1) **संक्षिप्त नाम**– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education Act, 2009) है।

(2) **परिभाषाएं**– इस अधिनियम में प्रयुक्त विशेष शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण आगे संदर्भवश कर दिया है।

(3) **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालक/बालिका का अधिकार**– 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक/बालिका को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(4) **प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबंध**– यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी।

(5) **अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार**– यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा।

(6) **राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य**– इस अधिनियम के लागू होने के तीन सालों के भीतर राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा, जिस क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है।

(7) **वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना**– केन्द्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

(8) **राज्य सरकारों के कर्तव्य**– राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। वे विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और बच्चों को उम्दा किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी।

(9) **स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य**– स्थानीय प्राधिकारी उपर्युक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ–साथ अपने क्षेत्र के बालकों का

टिप्पणी

अभिलेख रखेंगे, विद्यालय के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेंगे तथा शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार करेंगे।

(10) **माता–पिता और संरक्षक का कर्तव्य**– प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए।

(11) **राज्य सरकारों द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना**– तीन वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने और जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकारें एवं स्थानीय प्राधिकारी जरूरी इंतजाम करेंगे।

(12) **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा**– सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने होंगे।

(13) **प्रवेश के लिए किसी फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना**– कोई भी विद्यालय न तो दान या चंदा लेगा और न ही अभिभावक या बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा।

(14) **प्रवेश के लिए आयु का सबूत**– जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

(15) **प्रवेश से इनकार न करना**– स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

(16) **रोकने और निष्कासन का प्रतिशोध**– किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा।

(17) **शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न निषेध**– किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी।

(18) **मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना**– बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा और उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूरे करते हों।

(19) **विद्यालय के मान और मानक**– जो स्कूल अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे तथा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं, उन्हें अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष के अंदर समस्त मानक पूरे करने होंगे।

(20) **अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति**– केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी भाग या मानक को अनुसूची में परिवर्द्धन (Adding) या उसका लोप (Omitting) करके उसका संशोधन कर सकेगी।

(21) **विद्यालय प्रबंध समिति**– अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे जिसमें जन प्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति कामकाज का मानीटर करने जैसे कार्य करेगी।

(22) **विद्यालय विकास योजना**– धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति करने का कार्य करेगी।

(23) **शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें**– शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केन्द्र सरकार करेगी।

(24) **शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना**– शिक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे नियमित समय से स्कूल में उपस्थित हों, पाठ्यक्रम पूरा करें। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शिक्षण करें तथा अभिभावक बैठकें आयोजित करें।

टिप्पणी

(25) **छात्र शिक्षक अनुपात**– इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1 : 40 से अधिक न हो।

(26) **शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना**– राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक न हों।

(27) **गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने पर रोक**– शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य (सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर) नहीं कराए जाएंगे।

(28) **शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक**– कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगायेगा/लगायेगी।

(29) **पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया**– सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार (परिषद) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा और बच्चे के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ–साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। मूल्यांकन व्यापक और सतत् होगा।

(30) **परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र**– किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(31) **बालक के शिक्षा के अधिकार को मानीटर करना**– बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (Commission for Protection of Child Rights Act, 2005) के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग (Commission for Protection of Child Rights) इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे।

(32) **शिकायतों को दूर करना**– उपयुक्त धारा में वर्णित बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे।

(33) **राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन**– प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केन्द्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केन्द्र सरकार को परामर्श देना होगा।

(34) **राज्य सलाहकार परिषद का गठन**– प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकारें करेंगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा।

(35) **निर्देश जारी करने की शक्ति**– धारा 35 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकार को, राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी

स्कूल प्रबंधन समितियों को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे और निर्देश दे सकेंगे।

(36) **अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी**– अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13, 18 और 19 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन समुचित सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी

(37) **सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण**– इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाये गए नियमों और आदेशों के पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति या अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास (Good Faith) के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी।

(38) **राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति**– राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों (Provisions) के कार्यान्वयन के लिए नियमन, अधिसूचना (Notification) द्वारा नियम बना सकेगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) ने मौजूदा अवधारणाओं में क्रांति ला दी है और समावेशी शिक्षा समुदाय में भारत को मजबूती से स्थापित किया है। सामान्य कक्षा में सीखना अब सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसलिए स्कूल का मार्गदर्शक सिद्धांत पाठ्यक्रम को स्कूल में सभी बच्चों को शामिल करने और बनाए रखने के लिए आरटीई अधिनियम 2009 की थीम पर आधारित होना चाहिए। आरटीई 2009 में मौजूदा कक्षाओं में विविध शिक्षार्थियों का प्रवेश अनिवार्य है।

विशेष आवश्यकताओं के साथ और बिना सीखने वाले शिक्षार्थियों को अब समावेशी शिक्षण वातावरण तक पहुंचने का अधिकार है। इसलिए छात्र मूल्यांकन का लक्ष्य सीखने की जरूरतों और हस्तक्षेप की पहचान करना है और विकलांगता को लेबल नहीं करना है। आरटीई 2009 के साथ एक विविध छात्र आबादी को शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र बिंदु प्रभावी निर्देश बन जाता है जिसे पूरी आबादी के लिए सामान्य कक्षा में वितरित किया जाना है।

आरटीई द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार, बच्चों की अनूठी विशेषताओं, पृष्ठभूमि और सीखने की शैली नियमित कक्षा में नियमित शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अनंतर शिक्षण पद्धति की मांग करती है। यह एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है जो सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। शैक्षिक प्रणाली को अपने सामूहिक संसाधनों का उपयोग शीघ्र हस्तक्षेप करने के लिए करना चाहिए और सीखने और व्यवहार संबंधी समस्याओं को बड़े मुद्दों से रोकने के लिए उचित हस्तक्षेप और समर्थन प्रदान करना चाहिए।

आरटीआई के सिद्धांतों में शिक्षा के लिए एक सक्रिय और निवारक दृष्टिकोण, छात्र कौशल, पाठ्यक्रम और निर्देश के बीच एक निर्देशात्मक मैच, एक समस्या–समाधान अभिविन्यास और डेटा–आधारित निर्णय लेने और प्रभावी प्रथाओं का उपयोग शामिल है। आरटीआई की मुख्य विशेषताएं उच्च गुणवत्ता कक्षा निर्देश, अनुसंधान आधारित निर्देश, कक्षा प्रदर्शन और शिक्षाविदों और व्यवहार की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग हैं। आरटीआई के लक्षणों में एक मूल्यांकन प्रणाली के साथ अनुदेशात्मक प्रणाली का एकीकरण शामिल है जहां सिस्टम सभी छात्रों को यह निर्धारित करने के लिए स्क्रीन करता है कि खराब शैक्षणिक परिणामों के लिए कौन जोखिम में हो सकता है।

• आरटीई अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताएं

आरटीई अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

- यह अधिनियम पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है मुक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार का दायित्व और छह से चौदह आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना। 'मुक्त' का अर्थ है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के शुल्क या व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा का पीछा करने और पूरा करने से रोक सकता है।
- यह एक गैर–भर्ती बच्चे के लिए एक उपयुक्त आयु वर्ग में भर्ती होने का प्रावधान करता है।
- यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उपयुक्त सरकारों, स्थानीय प्राधिकरण और माता–पिता के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है, और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करता है।
- यह पुपिल शिक्षक अनुपात (पीटीआर), इमारतों और बुनियादी ढांचे, स्कूल–कार्य दिवसों, शिक्षक–काम के घंटों के लिए अंतर और मानकों से संबंधित है।
- यह सुनिश्चित करके शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती का प्रावधान करता है। यह गैर–शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती, निषेध जनगणना के अलावा, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों और आपदा राहत के लिए भी प्रदान करता है।
- यह पाठ्यक्रम में निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रदान करता है, और जो बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा, बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करेगा और बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करेगा।

टिप्पणी

माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिक प्रायोजित योजना शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण के लिए प्रदान करता है ताकि व्यक्तिगत रोजगार में वृद्धि हो, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम किया जा सके और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान किया जा सके। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि, मूल्य शिक्षा, मानवाधिकार, आरटीई–2009 आदि जैसी उभरती हुई चिंताएं और व्यावसायिक शिक्षा के साथ उनका संबंध मजबूती से स्थापित है।

1.5.4 सामुदायिक कॉलेजों के माध्यम से कौशल सीखने की अवधारणा

भारत में जूनियर कॉलेजों की एक प्रणाली विकसित करने का विचार 1930 के दशक (ओडर्स, 1933) से मिलता है, लेकिन इन्हें अनिवार्य माध्यमिक विद्यालय से पहले के वर्षों में निम्न माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच एक पुल के रूप में सेवा करने की कल्पना की गई थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यावसायिक अध्ययन में 1978 में विंगस्प्रेड सम्मेलन और सामुदायिक कॉलेज में भाग लिया था कि शिक्षा सुधारकों ने भारत में सामुदायिक

टिप्पणी

कॉलेज मॉडल (यारिंगटन, 1978) के अनुकूलन पर विचार करना शुरू किया था। विचार के पनपने से पहले यह एक दशक से भी अधिक होगा। 1995 में, पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने देश का पहला सामुदायिक कॉलेज (सिंह, 2012) स्थापित किया।

2009 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने एक सामुदायिक कॉलेज की स्थापना की, जिसने ICC (IGNOU, 2011, पृष्ठ 14) के रूप में पंजीकरण करने के लिए संगठनों को 'समुदाय आधारित गतिविधियों में निहित' की अनुमति दी। IGNOU नीति ने IGNOU डिग्री प्रोग्राम (IGNOU, 2011) में स्थानांतरण की संभावना के साथ स्टैकेबल क्रेडेंशियल्स के एक पाठ्यक्रम को रेखांकित किया। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग ने एक सिद्ध कॉलेज समुदाय जैसी योजना तैयार की है, जो सिद्ध अमेरिकी सामुदायिक कॉलेज मॉडल पर आधारित है।

वर्तमान में, तीन मॉडल या रूपरेखाएं हैं जिनके आधार पर देश भर में सामुदायिक कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं, और इन्हें अपनाने के लिए उपलब्ध हैं–

1. **यूजीसी–मान्यता प्राप्त सामुदायिक कॉलेज** (UGC Recognized Community College)– देश में पायलट सामुदायिक कॉलेज (पीसीसी) स्थापित करने के विचार को 22 फरवरी, 2012 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने शुरू करने का फैसला किया 2013 में मौजूदा कॉलेजों / पॉलिटेक्निक से 200 सामुदायिक कॉलेजों को राज्य सरकारों द्वारा चुना जाना है। इन कॉलेजों को स्थानीयता की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वह कला, शिल्प, हस्तकला, संगीत, वास्तुकला या ऐसी कोई भी चीज हो, उचित रूप से डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम के माध्यम से जिसमें स्वरोजगार और उद्यमिता विकास सहित रोजगार का उचित आश्वासन हो।
2. **उद्योग–आधारित सामुदायिक कॉलेज** (Industry-based Community Colleges)– उद्योग महिंद्रा समूह, अंबुजा समूह और जिंदल समूह जैसे दिग्गज अपने कार्यबल को प्रशिक्षित करने और अपने विस्तार व्यवसायों के लिए कुशल श्रमिकों की एक स्थिर–धारा बनाने के लिए देख रहे हैं। ये उद्योग आधारित मॉडल यूजीसी द्वारा लागू किए गए मॉडल से कुछ अलग हैं कि वे केवल एक प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं और कोई डिप्लोमा नहीं। यह कार्यक्रम अपने 'सकाम' पहल के माध्यम से छोटे व्यवसाय को विकसित करने और उद्यमी कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह 'अपराजिता' पहल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र की महिलाओं को नौकरी के लिए पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें महिलाएं अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए कई चुनौतियों का सामना करती हैं।
3. **एनजीओ / सोसायटी / स्थानीय निकाय द्वारा संचालित सामुदायिक कॉलेज** (NGO/Society/Local Body/run Community Colleges)– ये भारत में शुरू किए गए एक सामुदायिक कॉलेज के पहले प्रोटोटाइप थे। चेन्नाएब्ड इंडियन सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन (ICRDCE) के तत्वावधान में, फादर जेवियर अल्फोंस ने 1995 में देश में कम्युनिटी कॉलेज पहल की शुरुआत की। यह कम्युनिटी कॉलेज में सहायता के लिए तमिलनाडु प्रांत के जेसुइट्स का एक उपक्रम है। यह भारत में सामुदायिक कॉलेजों के लिए

एक सुविधा और समन्वय एजेंसी है। यह भारत के 18 राज्यों में 232 सामुदायिक कॉलेजों की तैयारी, स्थापना, निगरानी और मूल्यांकन में शामिल रहा है।

• सामुदायिक कॉलेज के प्रमुख उद्देश्य

सामुदायिक कालेज के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो वर्तमान में कम–क्षमता वाले ज्ञान श्रमिकों को सामर्थ्य, पहुंच और रोजगार की बाधाओं से पार पाने के मिशन को ध्यान में रखे हुए हैं–

टिप्पणी

1. वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कैरियर उन्मुख कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए,
2. हाई स्कूल पास–आउट के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षा के साथ रोजगार योग्य और प्रमाणित कौशल के अवसर प्रदान करने के लिए पारंपरिक कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा के लिए भविष्य में स्थानांतरित करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है,
3. उसके/उसकी योग्यता या उम्र के बावजूद शिक्षार्थियों के पारंपरिक/अधिगृहीत कौशल के उन्नयन और प्रमाणन के अवसर प्रदान करना,
4. व्यक्तिगत विकास के लिए समुदाय को सामान्य पाठ्यक्रम की पेशकश करके समुदाय–आधारित जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करना।

सामुदायिक कॉलेज कार्यक्रम आम तौर पर दो साल के कार्यक्रम होते हैं और पूरा होने पर एसोसिएट डिग्री प्रदान करते हैं; वे गैर–डिग्री, लघु अवधि के प्रमाणपत्र कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं। अन्य कॉलेज और विश्वविद्यालय चार साल के स्नातक कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं और पूरा होने पर स्नातक की डिग्री प्रदान करते हैं।

सामुदायिक कॉलेजों में एक ओपन–डोर प्रवेश नीति है और चार साल के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की तुलना में प्रवेश मानदंड आमतौर पर कम कठोर हैं। साथ ही, ट्यूशन की लागत चार साल के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की तुलना में बहुत कम है।

• सामुदायिक कॉलेज में अध्ययन के लाभ

सामुदायिक कॉलेजों को स्थानीय श्रम बाजार की स्थितियों से मेल खाने के लिए अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात किया गया है, जो उन्हें आज की अर्थव्यवस्था और नौकरी बाजार के लिए लचीला और प्रासंगिक बनाता है। वे छात्रों की व्यापक आबादी को नौकरी से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कुछ सामुदायिक कॉलेज लाभों में शामिल हैं–

- कम मूल्य,
- चार साल के विश्वविद्यालय या कॉलेज में स्थानांतरण का अवसर,
- लचीली अंग्रेजी प्रवीणता आवश्यकताएं,
- छोटे वर्ग का आकार,
- व्यावहारिक प्रशिक्षण,

- कार्यक्रम की विविधता,
- छात्र सहायता सेवाएं

• आर्थिक विकास में सामुदायिक कॉलेजों और व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका–

टिप्पणी

आर्थिक विकास में सामुदायिक कॉलेजों और व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है–

1. सामुदायिक कॉलेज आश्चर्यजनक रूप से विविध देशों और सांस्कृतिक संदर्भों में उभरे। उदाहरण के लिए, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, हंगरी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम। इन देशों की विविधताएं और वे संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामुदायिक कॉलेज मॉडल के लचीलेपन के लिए वसीयतनामा है, जिसमें यह राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संदर्भों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए खुद को अनुकूलित करने में सक्षम है।
2. उच्च शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र।
3. सामुदायिक कॉलेज कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करके व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बना रहे हैं जो रोजगार और गरीबी से बाहर का रास्ता बनाते हैं।
4. कौशल विकास न केवल उन्हें आजीविका कमाने में सक्षम बनाता है बल्कि परिवार/समाज के उत्पादक सदस्य बनने में भी उनकी मदद करता है।
5. वे स्कूल छोड़ने वालों और वंचितों की बड़ी आबादी को शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए दरवाजे खोलने वाली शिक्षा प्राप्त करने का दूसरा मौका देते हैं।
6. यह उच्च शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करके रोजगार के अवसरों और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को बढ़ाकर क्षैतिज गतिशीलता के साथ सहायता करता है।
7. सामुदायिक कॉलेजों में एक क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में योगदान दिया जा रहा है जो स्थानीय संगठनों, व्यापार और उद्योग की मजबूत साझेदारी के नेतृत्व में देश भर के समुदायों में मानव संसाधनों का निर्माण कर रहा है।

अपनी प्रगति जांचिए

7. व्यक्ति के जीवन की संक्षिप्त गुणवत्ता का सीधा संबंध किस शिक्षा से है?
   (क) बुनियादी (ख) सामान्य
   (ग) आजीवन (घ) व्यावसायिक
8. 'प्रत्येक समाज के प्रत्येक नागरिक' को शिक्षा का लाभ देना कब शुरू किया गया था?
   (क) 1975 (ख) 1990
   (ग) 1950 (घ) 1970

1.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)

3. (ग)
4. (ख)
5. (क)
6. (ख)
7. (ग)
8. (ख)

टिप्पणी

1.7 सारांश

व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को बिना कौशल वाले कार्य से हटाकर बौद्धिक स्तर पर पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति के स्वयं या समाज के लिए आवश्यक है के लिए दी जाने वाली शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा है। यह एक विशिष्ट शिक्षा है जो सामान्य शिक्षा से भिन्न है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वह व्यक्ति उस व्यवसाय द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यार्थियों को किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए तैयार करती है।

शिक्षा के साथ काम की अवधारणा भारत में आजादी से पहले से पाई जाती है। हालांकि, शब्द, शिक्षा पर विभिन्न आयोग और समितियों के अनुसार काम बदल दिया गया है। कार्य को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में पेश किया गया है, जैसे– कार्य अनुभव (WE), कमाते समय आप सीखें, स्वस्थ और उत्पादक जीवन की कला (APHL), SUPW, पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा और जेनेरिक व्यावसायिक शिक्षा (GVE)। वास्तव में, कार्य शिक्षा मैनुअल और बौद्धिक कार्यों के बीच की खाई को पाटने का एक सचेत प्रयास है।

कार्य शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन और रोजगार के बीच एक संबंध बनाती है, फिर भी यह पाया गया कि शैक्षणिक विषयों को कार्य शिक्षा गतिविधियों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया था। कार्य शिक्षा की कार्यान्वयन की स्थिति बहुत खराब पाई गई और बड़े पैमाने पर उपेक्षा की गई। इस पत्र ने केंद्रीय विद्यालय और निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों में कार्य शिक्षा गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रधानाध्यापकों, कार्य शिक्षा के शिक्षकों और छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली कार्य शिक्षा और समस्याओं की कार्यान्वयन स्थिति पर एक तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एक जानकार और कुशल कार्यबल को देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानव पूंजी के रूप में देखा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास दोनों व्यक्तियों की उत्पादकता, नियोक्ताओं की लाभप्रदता और राष्ट्रीय विकास को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। यह देखते हुए विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों के विचारों और धारणाओं और विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों ने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार दिया, बल्कि व्यक्तिगत रोजगार और राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में शिक्षा की व्यावसायिकता की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला।

व्यावसायिक शिक्षा कुशल श्रमशक्ति का निर्माण, औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण

टिप्पणी

भूमिका निभाती है। व्यावसायिक शिक्षा व्यवसाय और रोजगार पर आधारित है और हर देश के लिए मजबूत व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। यह छात्रों को कुशल बनाने में मदद करता है और बदले में, रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है। व्यावसायिक या कौशल आधारित शिक्षा आज अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि कई नियोक्ता नए कर्मचारियों से सभी व्यावहारिक कौशल की अपेक्षा करते हैं।

यह किसी भी देश के रोजगार को मजबूत कर सकता है और इसी तरह उसकी अर्थव्यवस्था को भी। भारत ने एक विकासशील देश होने के नाते व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने और लागू करने का एक लंबा सफर तय किया है। सरकार व्यावसायिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ है और इस क्षेत्र में पहले ही कई महत्वपूर्ण पहल कर चुकी है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए बदलते राष्ट्रीय संदर्भ में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए और भारत के लिए तकनीकी क्षेत्रों के फलों का आनंद लेने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्वपूर्ण तत्वों को लचीला, समकालीन बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

ग्रामीण/शहरों के कई इच्छुक युवा अपने शहरी समकक्षों के समान संसाधनों और शैक्षिक अवसरों तक पहुंच नहीं रखते हैं और रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। साक्षरता की समस्या पूरे भारत में फैली हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं और इस तरह अक्सर पीछे रह जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, स्किल इंडिया का एक उप–समूह, भारत ग्रामीण कौशल (इंडिया रूरल स्किल) एक कार्यक्रम है, जो शहरी और ग्रामीण युवाओं में प्रशिक्षण विधियों को मानकीकृत करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब यह भी है कि प्रशिक्षण विभिन्न भाषाओं में आयोजित किए जाते हैं, अक्सर स्थानीय प्रशिक्षकों के साथ जो तत्काल, स्थानीय आवश्यकताओं को समझते हैं।

1.8 मुख्य शब्दावली

- **बुनियादी** : मूलभूत, आधारभूत, मूल।
- **संकल्पना** : अवधारणा, धारणा, विचार।
- **शिल्प** : हस्तकला।
- **अभिविन्यास** : दिशानिर्देश, अभिमुखता।
- **प्रमाणीकरण** : मानकीकरण।
- **अनुसंधान** : अन्वेषण, खोज।
- **फ्रेमवर्क** : ढांचा।

1.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. गांधीजी की बुनियादी शिक्षा के बारे में 8–10 पंक्तियां लिखिए।
2. व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता, अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए।

3. स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में आयोगों और समितियों की सिफारिशें लिखिए।
4. जनसंख्या वृद्धि और व्यावसायिक शिक्षा के साथ कौनसा संबंध है? वर्णन कीजिए।
5. मूल्य शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए।
6. आरटीई अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताएं बताइए।

टिप्पणी

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका और विकास के बारे में आपकी राय स्पष्ट कीजिए।
2. व्यावसायिक शिक्षा के बारे में स्वतंत्र भारत में आयोगों और समितियों की सिफारिशों पर टिप्पणियां कीजिए।
3. व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विशेष समूहों की रोजगार से संबंधित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए।
4. भारत में माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यावसायिक शिक्षा का स्थान उल्लिखित कीजिए।
5. व्यावसायिक शिक्षा के मॉडल स्पष्ट कीजिए।
6. विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है?
7. व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे और समस्याएं कौन–सी हैं?
8. भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत में मानवाधिकार शिक्षा के लिए किन नीतियों की सिफारिशें की? उल्लेख कीजिए।
9. आरटीई–2009 और व्यावसायिक शिक्षा के साथ कौन–सा संबंध है? स्पष्ट कीजिए।
10. आर्थिक विकास में सामुदायिक कॉलेजों और व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

1.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Advant, S-B- (1985) : "An Evaluation of Vocational Courses Introduced at the +2 stage in Marathwada" submitted to Swami Ramanand Teerth Research Institute, Aurangabad, pp- 1-10.
2. Aggarwal, J.C. (1983) : 'Educational Research –An Introduction', Arya Book Depot. New Delhi.
3. Agrawal. J.C. (1981) : 'Philosophical and Sociological Bases of Education', Vikas Publishing House, New Delhi.
4. Agrawal, J.C. and Agrawala. S.P. (1989) : 'National Policy on Education', Concept Publishing Company, New Delhi, pp- 5-100.

टिप्पणी

5. Balkishanji, A.J. (2007) : 'Quality up Gradation in Vocation Education and Training' paper presented in National Conference on Vocational Education : Trends and Issues, at Pune, pp- QU 22 -25.
6. Bhatnatgar, S. (1984) : 'Kothari Commission Recommendations and Evalulation with a Text on National Policy Education', Mcerat Loyal Book Depot.
7. CABE Committee (1992) : 'Report of the CABE Committee on policy', Department of Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi.
8. Concept of Basic Education, Ministry of Education, GOI, New Delhi.
9. Guidelines Orientation Guide on Vocational Education Programme (1995) : Published by The Joint Director, Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education (PSSIVE) M-P- Nagar, Bhopal.
10. Guru, G. (2000) : 'Vocational Education for Sustainable Development', paper published in Quarterly Bulletin, Vol- 6, No- 3-4, pp- 19-21.
11. Guidelines (1987), Work Ecperience in School Education, New Delhi.
12. Gupta, Y.K. (1996), Teaching–Learning Strategies with Reference to Competencies in Work Experience, The Primary Teacher, July, pp-31&34] New Delhi, NCERT.
13. Indian Education Commission (1882-83) : 'Report of Indian Education Commission, 1882-83', Government Printing Press, Calcutta.
14. Koshe, G.S. (1989) : 'Vocationalisation of Education', Pune Vidhyarthi Griha Prakashan, Pune.
15. Kothari Commission (1966) : 'Report of Kothari Commission (1964-66), Government of India, New Delhi-pp- 369 & 388.
16. National Policy of Education (NPE) 1986, MHRD, 1986
17. Programme of Action of NPE, 1992, MHRD, GOI, New Delhi.
18- Sehgal, G.S. (1994), A Status Study of Work Experience Programme at Secondary Schools of Delhi- SCERT, New Delhi.
19. Sharma, R.C. (2002) : 'National Policy on Education and Programme of Implementation' Published by Mangal Deep Publication, Jaipur, pp- 1&355.
20. Singh Y. and Nath R, (2002) : 'History of Indian Education System', APH Publishing Corporation, New Delhi, p- 153&166
21. Report of the working group on vocationalisation, (1978) Ministry of Education & Social Welfare, New Delhi.
22. The Committee on 10+2+3 Educational Structure (1972) : 'Report of the Committee on 10+2+3 Educational Structure', The Manager of Publications, New Delhi.
23. Zakir Hussion Committee (1937) : Report of Zakir Hussion Committee the detailed syllabus, 'Hindustani Talim Sangh' Wardha.

इकाई 2 व्यावसायिक शिक्षा : पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन, प्रबंधन और अभिकरण (एजेंसियां)

टिप्पणी

संरचना

2.0 परिचय

2.1 उद्देश्य

2.2 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और कार्यान्वयन

- 2.2.1 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना और रूप (क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम)
- 2.2.2 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन लिए रणनीतियां

2.3 संगठन और प्रबंधन

- 2.3.1 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत स्तरों पर प्रबंधन संरचना
- 2.3.2 विद्यालय संगठन और प्रबंधन योजना, निष्पादन और निर्देशन, कक्षा, शॉप फ्लोर और नौकरी प्रशिक्षण प्रबंधन
- 2.3.3 खरीद, भंडारण, अभिलेख (रिकॉर्डिंग), सामग्री और उपकरण का रखरखाव

2.4 पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान

- 2.4.1 पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान : कई क्षेत्रों के कार्य कौशल के संयोजन की संभावना
- 2.4.2 वास्तविक जीवन में ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका

2.5 व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अभिकरण (एजेंसियां)

- 2.5.1 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के विशेष संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका
- 2.5.2 गैर–औपचारिक क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थानों की भूमिका
- 2.5.3 व्यावसायिक संस्थानों के शिक्षक और प्रमुख की भूमिका, कर्तव्य और गुण
- 2.5.4 भोपाल में केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की भूमिका

2.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

2.7 सारांश

2.8 मुख्य शब्दावली

2.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

2.10 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय

भारत में स्कूलों में बच्चों के बीच, महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा की गुणवत्ता का है। क्या भारत के शिक्षा क्षेत्र की क्षमता, निर्माण, अभ्यास का शिक्षा के उच्च मानकों की स्थापना के बाद पर्याप्त रूप से पालन किया गया है? भारत जैसे देश में, इसकी विशाल जनसंख्या के साथ, नीति–निर्माताओं को अकसर साक्षरता के मुद्दे के समाधान की मात्रा और पैमाने के साथ देखा जा सकता है।

पाठ्यक्रम के मानकीकरण से व्यक्तिपरक अनुभवों के साथ कम जुड़ाव और छात्रों के जीवन का एक निश्चित विखंडन हुआ है। रॉट (Rote) अधिगम (लर्निंग) की संस्कृति और संसाधनों और अवधारणाओं के लिए एक परीक्षा–उन्मुख दृष्टिकोण के

टिप्पणी

कारण विषयों और उनके अनुप्रयोगों की एक पारलौकिक और तिरछी समझ पैदा हुई है। भारत में, आजादी के बाद, दो राष्ट्रीय आयोगों – माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952 – 1953) और शिक्षा आयोग (1964 – 1966) द्वारा नागरिकों की शिक्षा के विषय पर विचार–विमर्श किया गया था। भारतीय संविधान में 1976 में शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था, और पहली बार भारत के रूप में 1986 में शिक्षा पर एक समान राष्ट्रीय नीति थी। लेकिन यह सहस्राब्दी के मोड़ तक नहीं था जिस तरह से हम भारत में शिक्षा को देखते हैं, उसमें बड़ा बदलाव हुआ।

शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के लिए सामान्य योजना और नीतियां तैयार करने से संबंधित है। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के अध्ययन के भीतर एक अनुशासन है जो सामान्य रूप से शिक्षा और प्रशासनिक संस्थानों और शिक्षकों में शिक्षा के प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार की जांच करता है। यह क्षेत्र आदर्श रूप से शैक्षिक दर्शन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के पालन के माध्यम से प्रशासन और प्रबंधन से अलग है। शैक्षिक प्रशासन एक स्कूल चलाने में शामिल संसाधनों, कार्यों और संचार के प्रबंधन का अध्ययन और अभ्यास है।

व्यावसायिक शिक्षा में मानव आवश्यकताओं के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता, भोजन, कपड़े, मनोरंजन और सामाजिक सेवा के साथ–साथ मानसिक क्षमताओं और शिक्षा के विभिन्न चरणों में बच्चों की मानसिक दक्षता और उपलब्धता के अनुसार सामाजिक विकास की गतिविधियां शामिल हैं। नीति ने एक वैकल्पिक आधार पर जरूरतमंद छात्रों के लिए 'अर्जित करते समय आप सीखते हैं' आयाम के साथ–साथ मध्य और निचले–माध्यमिक चरणों के लिए उत्पादन और सेवा–उन्मुख परियोजनाओं में गहन भागीदारी की कल्पना की। इसने बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय या समाज के कल्याण/विकास के लिए सामाजिक जागरूकता और चिंता पैदा करने के लिए सामुदायिक कार्य/सामाजिक सेवा को समान महत्व दिया।

भारत सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरुआत की है। सरकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी के लिए समान गुणवत्ता की शिक्षा देश की मानव संसाधन क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए। सामान्य उद्देश्य गुणवत्ता वाले स्कूल शिक्षा के विस्तार के माध्यम से पहुंच को बढ़ाना है। वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के समावेश के माध्यम से समानता (इक्विटी) को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर एजेंसियां हैं।

प्रस्तुत इकाई में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और कार्यान्वयन, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संगठन व प्रबंधन संरचना, पाठ्यक्रम में कार्य की भूमिका तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित एजेंसियों का विस्तार से अध्ययन किया गया है।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना को समझ पाएंगे;
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत स्तर पर प्रबंधन संरचना से अवगत हो पाएंगे;

- पाठ्यक्रम में कार्य कौशल के संयोजन को समझ पाएंगे;
- व्यावसायिक संस्थानों में शिक्षक की प्रमुख भूमिका, कर्तव्य व गुणों से परिचित हो पाएंगे।

टिप्पणी

2.2 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और कार्यान्वयन

ज्ञान शक्ति है और शिक्षा सतत प्रगति की नींव है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, 'ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज का भुगतान करता है'। भारत इतिहास में एक अनूठे बिंदु पर पहुंच गया है, जहां इसकी आबादी के मानव संसाधन मापदंडों की आनुपातिक प्रगति के साथ इसकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति को निरंतर और टिकाऊ बनाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा मानव प्रगति और विकास का एक तत्व है जिसे और अधिक बारीकी से देखने की आवश्यकता है। भारत दुनिया के स्कूल से बाहर (आउट–ऑफ–स्कूल) बच्चों की एक बड़ी संख्या का घर है, हालांकि हाल ही में स्कूली भागीदारी में उत्साहजनक संकेत मिले हैं।

स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए NCERT भारत में आधिकारिक एजेंसी है। भारत में 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF–2005) के दौरान नई नीति का प्रारूप तैयार किया गया था (NCF–2005, 2012)। NCF राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक अलग स्तर पर एक सामान्य शिक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य राष्ट्र के सभी स्कूलों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना, सभी स्तरों पर न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्रदान करना है ताकि बच्चों को शिक्षा की विशिष्ट गुणवत्ता प्रदान की जा सके। यह बच्चों के बीच प्रांतीय असमानताओं को कम करने के लिए एक दृष्टिकोण है।

शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत है क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम, क्योंकि यह स्कूल नेतृत्व में पूर्वाग्रह को समझने और हटाने का उद्देश्य रखता है। छात्रों को उनकी व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों के आधार पर पढ़ाया और समर्थित किया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सफलता के समान अवसर मिलते हैं। इस प्रकार, संस्कृति, सामाजिक वर्ग, घरेलू आय या भाषा के आधार पर उपलब्धि की भविष्यवाणी पूरी तरह से दूर हो जाती है। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीतियां आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षमता/योग्यता आधारित शिक्षा एक समावेशी संस्कृति बनाने में भी मदद करती है जहां सभी छात्र सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं।

2.2.1 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना और रूप (क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम)

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना को समझने के लिए पहले पाठ्यक्रम के अर्थ एवं परिभाषा को समझना आवश्यक है।

• पाठ्यक्रम : अर्थ एवं परिभाषा

निश्चित रूप से, शब्द 'पाठ्यक्रम' लैटिन शब्द 'करियर' से लिया गया है जिसका अर्थ है रन या रन–वे या रनिंग कोर्स। इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ है एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलाया जाने वाला कोर्स।

टिप्पणी

आर्थर जे. लेविस और मिड एलिस (1972) ने पाठ्यक्रम को 'समय की कुछ व्यवस्थाओं में अन्य व्यक्तियों के साथ और चीजों के साथ शिक्षित करने के अवसरों के बारे में, (अन्य लोगों के साथ सूचना प्रक्रिया, तकनीक और मूल्यों के सभी के लिए) शिक्षित होने के अवसरों के बारे में' के रूप में परिभाषित किया।

एक पाठ्यक्रम का अर्थ है, संस्था द्वारा चयनित और संगठित कुल स्थिति (सभी स्थितियों) को संचालित करने और वास्तविकता में शिक्षा के अंतिम उद्देश्य का अनुवाद करने के लिए शिक्षक को उपलब्ध कराया गया।

कनिंघम के शब्दों में, पाठ्यक्रम अपने स्टूडियो (स्कूल) में अपने आदर्श (उद्देश्य) के अनुसार अपनी सामग्री (शिष्य) को ढालने के लिए कलाकार (शिक्षक) के हाथों में एक उपकरण है। सामग्री अत्यधिक आत्म सक्रिय, आत्मनिर्भर मानव है जो सचेत रूप से प्रतिक्रिया करता है।

पाठ्यक्रम को 'गति में सामाजिक पर्यावरण' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी गतिविधियों और अनुभवों का कुल योग है।

पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एक दस्तावेज है जो पाठ्यक्रम के लिए मानक निर्धारित करता है और शिक्षकों के संदर्भ (उपलब्ध संसाधन) में क्षमताओं और सिस्टम समर्थन प्रदान करता है जिसमें विषय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम विकसित करते हैं। यह आम तौर पर एक एकल दस्तावेज होता है जिसे फ्रेमवर्क के विशिष्ट भागों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए अन्य सामग्रियों द्वारा पूरक किया जाता है। ये स्कूल प्रणाली, व्यक्तिगत स्कूलों और कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए व्यक्तिगत वर्ष, विषय या शिक्षण क्षेत्र द्वारा अधिक विस्तृत विनिर्देश या मार्गदर्शन दे सकते हैं।

दस्तावेजों में पाठ्यक्रम, अध्ययन के कार्यक्रम, वर्ष की योजना और पाठ योजनाएं शामिल हो सकती हैं। एक पाठ्यक्रम ढांचा शैक्षिक वातावरण का वर्णन करता है जिसमें पाठ्यक्रम (या उद्देश्यों, परिणामों, सामग्री और उपयुक्त मूल्यांकन और शिक्षण विधियों की विशिष्ट रूपरेखा) को विकसित किया जा सकता है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा पाठ्यक्रम के एक सेट को परिभाषित करती है जो पाठ्यक्रम की एक सीमा को सह–अस्तित्व में सक्षम बनाता है। इस प्रावधान पर कि प्रत्येक पाठ्यक्रम विशिष्ट मानदंडों के साथ है।

इसलिए पाठ्यक्रम रूपरेखा एक एकल राज्य के भीतर या जातीय समूहों की संबद्धता के भीतर देशों के बीच लचीलेपन और विविधता की अनुमति देने के लिए एक बहुत ही उपयोगी तंत्र है, प्रत्येक व्यक्तिगत प्रणाली अनुपालन के माध्यम से स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए अपने स्वयं के पाठ्यक्रम की पहचान बनाए रख सकती है।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

पाठ्यक्रम की रूपरेखा को निम्न बिंदुओं के अनुसार समझा जा सकता है–

- ऐसे गुणों को विकसित करना जो एक बच्चे को विभिन्न सामाजिक सेटिंग्स जैसे मित्रता, सहयोग, आत्म–अनुशासन, आत्म–साक्षात्कार, सामाजिक न्याय के लिए प्रेम आदि में सामाजिक रूप से प्रभावी और खुशहाल बनाते हैं।

टिप्पणी

- पूर्व–व्यावसायिक / व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए, कड़ी मेहनत करने की इच्छा, मैनुअल काम की गरिमा और नौकरी से संतुष्टि।
- पर्यावरण और इसके सीमित संसाधनों की समझ और प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता के लिए।
- विभिन्न जीवन स्थितियों में सुंदरता की सराहना और खोज करने की क्षमता विकसित करना और इसे स्वयं के व्यक्तित्व में एकीकृत करना।
- जांच के वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान विकसित करना और समस्याओं को हल करने में इसका उपयोग करना।
- स्कूल स्तर पर सामग्री, शिक्षाशास्त्र, शिक्षण और शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन आदि की पसंद के बारे में निर्णय लेने के लिए स्कूलों और शिक्षकों को सुविधा प्रदान करना।
- स्कूलों और शिक्षकों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम मोड की योजना बनाने और विकसित करने के लिए लचीलापन और स्वामित्व देना।
- स्कूल पाठ्यक्रम, शिक्षण और शिक्षण रणनीतियों की समीक्षा करने और स्कूल मूल्यांकन नीति विकसित करने में मदद करना।
- अपने स्वयं के अनुभव से सीखने वाले चिंतनशील व्यवसायी बनने में शिक्षक की मदद करना।
- सीखने और सीखने के साथ सीखने पर जोर देना, और बच्चों को उनके जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी समझ विकसित करने में मदद करता है।
- यह निर्धारित करने के लिए कि छात्रों को स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व

पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है–

- शिक्षा की आवश्यकता पाठ्यक्रम के महत्व को निर्धारित करती है। इसमें साहित्य की समीक्षा से पता चलता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन पर जोर दिया गया है।
- मानसिक पहलुओं को प्रशिक्षित और विकसित किया जाता है, इस प्रकार विभिन्न स्कूली विषयों को पढ़ाकर मानसिक सुविधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा छात्रों को तैयार करती है।
- रुचियों और दृष्टिकोण का विकास छात्र के अनुसार किया जाता है।
- अच्छे नागरिक जीवन के विकासशील लोकतांत्रिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। इससे शिक्षकों की योग्यता और क्षमता भी विकसित होती है।
- स्व–बोध की क्षमता भी शिक्षा द्वारा विकसित की गई है और अच्छा आदमी बनाने के लिए भी।
- यह वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी विकास के लिए भी तैयार है।

- यह सर्वांगीण विकास में मदद करता है।
- यह सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली साधन है।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा के कार्य

टिप्पणी

पाठ्यक्रम ढांचा (फ्रेमवर्क) के कुछ कार्य इस प्रकार हैं–

- यह पाठ्यक्रम मानकों के एक सेट को परिभाषित करता है जो पाठ्यक्रम के एक हिस्से को पाठ्यक्रम के लिए सक्षम बनाता है, जो प्रत्येक पाठ्यक्रम को विशिष्ट मानदंडों के साथ संकलित करता है।
- यह एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो शिक्षक को शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने में मदद कर सकता है–हमारे भविष्य को व्यवहार में लाने के लिए।
- यह पाठ्यक्रम के लिए कुछ गुणवत्ता मानकों को विकसित करता है, मूल्यांकन की भी आवश्यकता है।
- पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक लेखकों को मार्गदर्शन देता है।
- एक बार एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर सहमति हो जाने के बाद, अन्य दस्तावेजों को सबसे महत्वपूर्ण विषय या सीखने के क्षेत्र, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों सहित विकसित किया जा सकता है। यह अन्य नीति और वित्त पोषण प्राथमिकताओं की एक सीमा का विस्तार निर्धारित करता है।

अंत में, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए परिचालन परिभाषाएं भी विचार के लिए रखी गई हैं। हम देखते हैं कि, पाठ्यक्रम रूपरेखा एक परिणाम–आधारित शिक्षा या मानकों पर आधारित शिक्षा सुधार डिजाइन का हिस्सा है। फ्रेमवर्क का दूसरा चरण है– स्पष्ट, उच्च मानकों को परिभाषित करना, जो सभी छात्रों को प्राप्त होगा।

• क्षमता की अवधारणा

क्षमता की अवधारणा को निम्नांकित बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है–

1. इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ स्टेंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग एंड परफॉरमेंस इंस्ट्रक्शन (IBSTPI) क्षमता/योग्यता को 'ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण जो किसी को रोजगार में अपेक्षित मानकों के लिए किसी दिए गए व्यवसाय या कार्य की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है' के रूप में परिभाषित करता है।
2. बल्गेरियाई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा क्षमता मूल्यांकन सूचना प्रणाली मेरी क्षमता में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली क्षमता, परिणाम (प्रदर्शन स्तर) प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार का एक सेट मानती है।
3. कौशल और ज्ञान के विभिन्न तत्वों, पेशेवर और व्यक्तिगत गुणों के अतीत के अनुभव के संयोजन और एकीकृत करने की क्षमता के रूप में क्षमता/योग्यता को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, दक्षताओं में व्यक्ति के काम पर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता की अभिव्यक्ति है।

टिप्पणी

4. यूरोपीय योग्यता ढांचे के संदर्भ में, 'क्षमता का अर्थ है, ज्ञान, कौशल और व्यक्तिगत, सामाजिक और कार्यप्रणाली क्षमताओं का उपयोग करने की सिद्ध क्षमता। यूरोप में ट्यूनिंग शैक्षिक संरचनाएं ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमताओं के एक गतिशील संयोजन के रूप में सक्षमताओं को परिभाषित करती हैं। छात्र द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रतियोगिताएं प्राप्त या विकसित की जाती हैं।

क्षमता की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं–

- स्थायी विशिष्ट लक्षण और विशेषताएं जो प्रदर्शन निर्धारित करती हैं;
- विशिष्ट विशेषताएं जो बाकी से सफल कलाकार को अलग करती हैं;
- लक्ष्यों तक पहुंचने की क्षमता;
- भूमिका या स्थिति के साथ बेहतर सामना करने की अनुमति देता है;
- ज्ञान, कौशल, योग्यता और अन्य विशेषताओं को काम पर प्रदर्शित किया जाता है।

हालांकि, शब्द क्षमता के लिए कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। क्षमता और योग्यता के अंतर पर बहस अभी भी जारी है।

क्षमता/योग्यता आधारित शिक्षा

निर्देश, मूल्यांकन, ग्रेडिंग और शैक्षणिक रिपोर्टिंग की प्रणालियों को संदर्भित करती है जो छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होती हैं और यह बताती हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से जिस ज्ञान और कौशल को सीखने की उम्मीद की है, उसे वे सीख चुके हैं।

मूल रूप से, क्षमता/योग्यता आधारित शिक्षा का अर्थ है, ग्रेड और वार्षिक पाठ्यक्रम अनुसूची पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मुख्य ध्यान इस बात पर रखा जाता है कि प्रत्येक छात्र किस विषय में कितना सक्षम है। क्षमता आधारित शिक्षा (CBE), किसी भी दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जिसका उद्देश्य छात्रों को विशेष दक्षता विकसित करने में सक्षम बनाना है।

क्षमता/योग्यता आधारित शिक्षण या योग्यता आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण का उपयोग अमूर्त सीखने की तुलना में ठोस कौशल सीखने में किया जाता है।

क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम

आइए हम पहले यह समझें कि क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम क्या है। यह एक पाठ्यक्रम है जो सीखने की प्रक्रिया के जटिल परिणामों पर जोर देता है (यानी, शिक्षार्थियों द्वारा लागू किए जाने वाले ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण)। मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि शिक्षार्थियों को पारंपरिक रूप से परिभाषित विषय सामग्री के बारे में क्या सीखने की उम्मीद है। सिद्धांत रूप में इस तरह का पाठ्यक्रम छात्रों, शिक्षकों और समाज की बदलती जरूरतों के लिए सीखने पर केंद्रित और अनुकूल है। इसका तात्पर्य यह है कि सीखने की गतिविधियों और वातावरण को चुना जाता है ताकि शिक्षार्थी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परिस्थितियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकें और लागू कर सकें।

टिप्पणी

क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के दृष्टिकोण का वर्णन करता है जो कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप शिक्षार्थी में दक्षताओं के विकास पर केंद्रित है। एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो इस बात पर जोर देता है कि शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्य रूप से उन बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो उन्हें जानने की उम्मीद है। सिद्धांत रूप में, ऐसा पाठ्यक्रम छात्रों, शिक्षकों और समाज की बदलती जरूरतों के लिए सीखने पर केंद्रित और अनुकूल है।

क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं

क्षमता/योग्यता आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं निम्न हैं–

1. **लचीला** : क्षमता/योग्यता आधारित कार्यक्रम बहुत लचीले होते हैं क्योंकि उनकी संरचना व्यक्तिगत शिक्षार्थी पर निर्भर करती है। इन कार्यक्रमों में कोई कठोर कार्यक्रम नहीं है, कोई वर्ग नहीं है। इसके बजाय, छात्र अपने सीखने और नियंत्रण का मार्गदर्शन करते हैं कि वे कब और कहां परियोजनाओं और आकलन को पूरा करते हैं।
2. **स्व–गति** : यह छात्रों को उनकी पेसिंग को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है क्योंकि वे एक सीखने की प्रक्रिया द्वारा सीमित नहीं हैं। जैसे ही एक छात्र को लगता है कि वे महारत हासिल कर सकते हैं, वे मूल्यांकन कर सकते हैं, क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और अगली सामग्री पर शुरुआत कर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार धीमी या तेज गति से आगे बढ़ते हुए, छात्र तैयार होने पर एक डिग्री पूरी करने में सक्षम होते हैं।
3. **संलग्न करना** : क्षमता/योग्यता आधारित शिक्षा व्यक्तिगत सीखने को बढ़ावा देती है और विभिन्न प्रकार की सीखने की शैली को समायोजित करती है, जिससे यह वास्तव में व्यक्तिगत अनुभव होता है। यह अनुभव जुड़ाव बढ़ाता है क्योंकि सामग्री प्रत्येक छात्र और अधिक प्रासंगिक के अनुरूप होती है।
4. **कौशल–आधारित** : योग्यता–आधारित पाठ्यक्रम शिक्षा वास्तविक–विश्व कौशल और योग्यता विकास पर केंद्रित है।
5. **आलोचनात्मक और स्वतंत्र सोच** : शिक्षार्थियों की अपनी योग्यता, सीखने की क्षमता को पहचानने, प्रबंधित करने और बनाने की क्षमता में सुधार हुआ है।
6. **वैयक्तिकृत समर्थन** : छात्रों को अपने गुरु या प्रशिक्षकों से व्यक्तिगत सहायता मिलती है जो अपने कौशल के आधार पर अनुकूलित सेवाएं प्रदान करते हैं।
7. **नियंत्रित अनुसूची** : पारंपरिक कॉलेज डिग्री कार्यक्रमों में अकसर आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों को रखने की आवश्यकता होती है ताकि आप एक कक्षा में बैठ सकें।
8. **मौजूदा ज्ञान पर बनाता है** : योग्यता–आधारित पाठ्यक्रम में, पहले से अर्जित ज्ञान का लाभ उठाया जाता है।
9. **व्यस्तता** : प्रतिस्पर्धा–आधारित पाठ्यक्रम के सबसे मजबूत परिणामों में से एक छात्र की व्यस्तता में वृद्धि है।
10. **वास्तविक दुनिया का अनुभव** : पारंपरिक डिग्री के विपरीत, सीबीसी दक्षता व्यावहारिक कौशल नियोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

टिप्पणी

11. **नौकरी प्रतिधारण :** नियोक्ताओं की योग्यता और सीखने की उपलब्धियों को समझने के लिए नियोक्ता की बेहतर क्षमता।

इस प्रकार, छात्र लगातार नए ज्ञान को मौजूदा ज्ञान में एकीकृत करते हैं, जिससे संदर्भ प्रदान करते हैं और संसाधनों का एक व्यक्तिगत 'भंडारण कक्ष' बनाते हैं जो भविष्य की समस्या को सुलझाने की जरूरतों के लिए उपलब्ध होगा। छात्र विषयवस्तु को अपने जीवन के अनुभव से जोड़कर संबंध और जुड़ाव बनाना भी सीखते हैं। छात्र साक्ष्य और तार्किक तर्कों के साथ अपने निष्कर्षों का समर्थन करना सीखते हैं। छात्र निष्कर्ष निकालने के लिए सूचना और संदर्भ के कई स्रोतों को संश्लेषित करना सीखते हैं

क्षमता–आधारित शिक्षा (CBE), किसी भी दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जिसका उद्देश्य छात्रों को विशेष दक्षता विकसित करने में सक्षम बनाना है। सभी क्षमता–आधारित दृष्टिकोण सामग्री–या अनुशासन–आधारित दृष्टिकोण से खुद को अलग करते हैं, इसके बजाय यह ध्यान केंद्रित करते हैं कि छात्र ज्ञान के बजाय ज्ञान के साथ क्या करना चाहते हैं।

पाठ्यचर्या सुधार

पाठ्यचर्या सुधारों को भारत सरकार ने NCERT और विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क– 2005 के माध्यम से लिया है। स्कूल शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है अर्थात, सूचना भरी हुई पाठ्यपुस्तकें, और स्मृति आधारित परीक्षाएं सुस्त दिनचर्या और बोर्ड शिक्षण और शिक्षण की रट प्रणाली। और चिंताओं, उद्देश्य और पाठ्यक्रम के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। ज्ञान और दृष्टिकोण भी कुछ हद तक अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। निम्नलिखित पाठ्यचर्या सुधारों और पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए NCF 2005 दस्तावेज में परिलक्षित मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं और राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सुधार और पाठ्यपुस्तक विकास के लिए विचार किया जाएगा–

- स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना।
- यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण को रटने के तरीकों से अलग कर दिया जाए।
- पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना।
- परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन में एकीकृत करना।
- देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखना।

स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान, यह महसूस किया गया था कि मैकाले के मिनट 1835 के परिणामस्वरूप भारत में पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, यह भारत की जरूरतों और प्रेरणा के अनुरूप नहीं था। शिक्षा और पाठ्यक्रम के सुधारों की दिशा में एक बड़ा प्रयास गांधीजी द्वारा किया गया था जब उन्होंने शिक्षा की मूल प्रणाली को प्रस्तावित किया था। शिल्प के अलावा, शारीरिक और सामाजिक वातावरण को भी स्कूली पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था।

टिप्पणी

शिक्षा के विभिन्न निकायों/एजेंसियों द्वारा अनुशंसित कुछ सुधार निम्नलिखित हैं–

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1952–53 ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुछ मुख्य विषयों के साथ विविध पाठ्यक्रम की परिकल्पना की थी।
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1964–66 पर विचार किया, देश में शिक्षा की पूरी प्रणाली का काम किया और ज्ञान के विस्फोट के प्रकाश में पाठ्यक्रम के पुनर्गठन के लिए सुझाव दिया।
3. राष्ट्रीय नीति, 1968 माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के कारण शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का गठन, 1968 जिसने पूरे देश के लिए शिक्षा के 10 + 2 + 3 पैटर्न की परिकल्पना की थी।
4. 1975 में, 10 + 2 + 3 प्रणाली के पैटर्न के लिए एक नया पाठ्यक्रम था।
5. 1977 में, सरकार द्वारा नियुक्त ईश्वरबाई पटेल समिति भारत के, समाज उपयोगी निर्माण कार्य के समावेश का सुझाव दिया।
6. डॉ. मैल्कम एस. अदिशैया की अध्यक्षता में 1977–78 समिति ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर +2 चरण में, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा की और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बदलाव लाने के लिए दिशानिर्देशों का सुझाव दिया।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ने एक नई दिशा प्रदान की। पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण निर्देश के रूप में पाठ्यक्रम की परिकल्पना करता है, संविधान में निहित समाज के आदर्शों को साकार करना।
8. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (NCF 2005)–कला, कार्य, शांति, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के क्षेत्र में लाना, उन्हें सीखने के सभी क्षेत्रों में प्रभावित करता है, जबकि उन्हें प्रासंगिक चरणों में स्वयं की पहचान देता है। शिक्षार्थियों को अपनी आवाज खोजने में सक्षम करें, सोचने की जिज्ञासा को पोषित करें, प्रश्न पूछें, पाठ ज्ञान को पुनः उत्पन्न करने के बजाय अपने अनुभव को स्कूली ज्ञान के साथ एकीकृत करें।

• क्षमता–आधारित पाठ्यक्रम संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना और रूप

क्षमता–आधारित पाठ्यक्रम की अवधारणाओं की बहुलता उपलब्ध है क्योंकि शिक्षाविद् पाठ्यक्रम की सामग्री और कार्यों की अपनी अलग व्याख्या देते हैं। आइए हम तीन अलग–अलग विचारकों द्वारा तीन ऐसी अवधारणाओं पर चर्चा करें, जो पाठ्यक्रम पर ज्ञान के तीन प्रमुख योगदानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- अल्बर्ट ओलिवर द्वारा बताई गई पहली अवधारणा, पाठ्यक्रम को केवल तीन महत्वपूर्ण तत्वों जैसे कि अध्ययन, गतिविधियों और मार्गदर्शन से युक्त शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में संदर्भित करती है।
- फिलिप फेनिक्स द्वारा वर्णित दूसरी अवधारणा, मूल्यों की सावधानीपूर्वक सोची गई योजना पर आधारित है जो उद्देश्य और शिक्षा के उद्देश्यों का गठन करते हैं।
- तीसरी अवधारणा, हिल्डा टेबा द्वारा दी गई। यह पब्लिक स्कूल के कार्य के रूप में पाठ्यक्रम को देखती है, यह सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संचार के

टिप्पणी

रूप में तीन कार्यों को सूचीबद्ध करती है, संस्कृति के परिवर्तन के लिए एक साधन के रूप में सेवा करती है, और व्यक्तिगत विकास के लिए एक साधन के रूप में काम करती है।

एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ–2005) के गठन ने देश भर में प्राथमिकताओं और समस्याओं पर एक विशाल बहस की शुरुआत की कि कैसे ज्ञान को चुना जाता है और स्कूल के पाठ्यक्रम में इसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है और इसे कक्षा में शिक्षकों द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है। 2006 से NCERT द्वारा लाए गए नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों ने इस बहस को गहरा कर दिया है, और कई अन्य पहलों ने राज्यों में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर बहस को अवशोषित और आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है। कई राज्यों ने नई पाठ्यपुस्तकों को अपनाने का फैसला किया है। एनसीईआरटी की अनुकरणीय सामग्री की मदद से एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हुए कई अन्य लोगों ने अपना स्वयं का बनाया है।

यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और NCERT द्वारा की गई पांच राज्यों की हालिया समीक्षा से पता चलता है कि यद्यपि पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन तस्वीर मिश्रित बनी हुई है। कुछ समस्याएं संस्थागत संरचनाओं से सीधे तौर पर पाठ्यक्रम सुधारों, उनकी शैक्षणिक स्थिति और क्षमताओं, और अन्य संस्थानों में उपलब्ध बौद्धिक और रचनात्मक संसाधनों तक उनकी पहुंच से उत्पन्न होती हैं।

वर्तमान में शिक्षक शिक्षा भारत में पाठ्यक्रम सुधारों की एक प्रमुख प्राथमिकता है। NCF–2005 का शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFTE, 2009) द्वारा अनुसरण किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE), शिक्षक शिक्षा के लिए वैधानिक रूप से जिम्मेदार संगठन, ने विभिन्न राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम की समीक्षा शुरू कर दी है।

इस अभ्यास को NCF–2005 और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कानूनी ढांचे में व्यक्त शैक्षणिक दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। साथ में, इन 2 दस्तावेजों में शिक्षक को एक सामाजिक वास्तुकार की भूमिका में रखा गया है, जिनकी पेशेवर जागरूकता और तीक्ष्णता को NCF–2005 गूंजती गहरी चिंताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित करने की उम्मीद है। ये कक्षा में भेदभाव की स्थानिक समस्याओं से संबंधित हैं। पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र एक समावेशी कक्षा के वातावरण में सभी सामाजिक समूहों के बीच लैंगिक समानता और समानता सुनिश्चित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता प्राप्त करने के आरटीई के लक्ष्यों के केंद्र में हैं।

इन लक्ष्यों को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में अकेले परिवर्तन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों के विश्वास और इन परिवर्तनों के प्रति प्रतिबद्धता NCF पहल को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। एनसीईआरटी ने बदलाव के लिए अनुकूल आचरण बनाने के लिए पाठ्यक्रम सुधारों का दायरा बढ़ाया है।

उपग्रह संचार के माध्यम से विषय विशेषज्ञों के साथ परस्पर संवादात्मक (इंटरएक्टिव) सत्रों ने विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम के डिजाइन में किए गए परिवर्तनों के आधार को समझने के लिए कार्यकारियों के एक विशाल निकाय को सक्षम किया

टिप्पणी

है। व्यक्तिगत शिक्षकों और संस्थानों द्वारा स्वदेशी नवाचारों की मान्यता – एनसीईआरटी की योजना का एक और आयाम है।

इसने नवाचार की विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्कूलों को सहायक अनुदान और अकादमिक सलाह दी है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम सुधार के दृष्टिकोण का एक अन्य प्रमुख पहलू दो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम क्षेत्रों की पहचान है, जिस पर सीखने की प्रकृति और गुणवत्ता निर्भर करती है। प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड पर ध्यान केंद्रित करने से, एनसीईआरटी के अनुसंधान और प्रशिक्षण इन दो प्रमुख क्षेत्रों में एक लंबी अवधि के शैक्षणिक घाटे को दूर करने के लिए बड़ी प्रणाली को सक्षम करेगा।

अंत में, मूल्यांकन और मूल्यांकन में सुधार पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षण के एक पहलू का मूल्यांकन और रिकॉर्ड रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पाठ्यक्रम संरचना

o **उच्च प्राथमिक चरण (3 वर्ष)**

- तीन भाषाएं – मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी
- गणित
- विज्ञान और तकनीक
- सामाजिक विज्ञान
- काम की शिक्षा
- कला शिक्षा (ललित कला– दृश्य और प्रदर्शन)
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (खेल और खेल, योग सहित)
- एनसीसी और स्काउटिंग और गाइडिंग

o **माध्यमिक चरण (2 वर्ष)**

- तीन भाषाएं – मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी।
- गणित
- विज्ञान और तकनीक
- सामाजिक विज्ञान
- काम की शिक्षा
- कला शिक्षा (ललित कला– दृश्य और प्रदर्शन)
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (खेल और खेल, योग सहित)
- एनसीसी और स्काउटिंग और गाइडिंग

क्षमता–आधारित पाठ्यक्रम संरचना

क्षमता–आधारित पाठ्यक्रम चुनौतीपूर्ण और आकर्षक सीखने के अनुभव प्रदान करके उच्च स्तर तक ले जाता है, जिसे केवल याद रखने के बजाय गहरी सोच की आवश्यकता होती है। इसका ध्यान इस बात पर है कि युवा क्या जानते हैं, इसके बजाय क्या कर सकते हैं। क्षमता–आधारित पाठ्यक्रम में दो श्रेणियां हैं– बुनियादी

टिप्पणी

प्रतिस्पर्धा और सामान्य प्रतिस्पर्धा। इन दो घटकों को विषय पाठ्यक्रम में बनाया गया है।

1. बुनियादी प्रतिस्पर्धा

बुनियादी नीतियां राष्ट्रीय नीतियों के दस्तावेजों में परिलक्षित उम्मीदों और आकांक्षाओं के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाएं हैं। यह इन दक्षताओं के विवरणकर्ताओं के आधार पर है कि शिक्षार्थियों की शिक्षा के प्रत्येक स्तर में प्रोफाइल, पढ़ाए जाने वाले विषय और सीखने के क्षेत्र, व्यापक विषयवस्तु और प्रमुख प्रतिस्पर्धाओं का निर्माण किया जाता है।

बुनियादी दक्षताओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है–

- साक्षरता,
- संख्यात्मकता,
- आईसीटी,
- नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान,
- उद्यमिता और व्यवसाय विकास,
- विज्ञान और तकनीक,
- आधिकारिक भाषाओं में संचार।

2. सामान्य प्रतिस्पर्धा

सामान्य दक्षताओं में उच्च कौशल के विकास को बढ़ावा मिलता है। वे अपने आप में अत्यधिक मूल्यवान होने के साथ–साथ विषय सीखने को बढ़ावा देते हैं। उन्हें सामान्य दक्षताओं के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे पाठ्यक्रम में लागू होते हैं, और अध्ययन किए गए सभी विषयों में विकसित किए जा सकते हैं।

सभी विषयों के भीतर विकसित की जाने वाली सामान्य प्रतिस्पर्धाएं नीचे सूचीबद्ध हैं–

- गहन सोच
- रचनात्मक और नवरीति
- अनुसंधान और समस्या समाधान
- संचार
- सहयोग, पारस्परिक संबंध और जीवन कौशल
- उम्र भर सीखना

ये सामान्य योग्यता छात्रों को विषयों की उनकी समझ को गहरा करने में मदद करती हैं और कई स्थितियों में उनके विषय को सीखने में लगाती हैं। इसलिए वे विषय क्षमता के विकास में योगदान करते हैं। जब छात्र इन सामान्य दक्षताओं को विकसित करते हैं, तो वे उन कौशलों के समुच्चय को भी हासिल कर लेते हैं, जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों में खोजते हैं, इसलिए यह कार्य छात्रों को काम की दुनिया के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। छात्रों को जीवन भर सीखने के लिए सक्षम बनाने के लिए सामान्य दक्षताओं का भी महत्व है जो हमारी तेजी से बदलती दुनिया और अनिश्चित भविष्य के लिए अनुकूल हो सकते हैं।

टिप्पणी

पाठ्यक्रम के उद्देश्य, योजना और परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और नौकरी–प्रशिक्षण साइटों की सूची दी गई है। अन्य जानकारी में उपकरण, रसायन आदि की सूची शामिल है। सहयोगी संस्थानों की सूची के साथ। शिक्षकों की विचारोत्तेजक योग्यता, संदर्भ पुस्तकों और कैरियर मार्ग की एक सूची भी प्रदान की जाती है।

PSSCIVE भोपाल (Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education) ने कृषि, गृह विज्ञान में विभिन्न व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया है–

- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी,
- वाणिज्य,
- स्वास्थ्य और पैरामेडिकल और मानविकी।
- संकलक की सूची PSSCIVE द्वारा विकसित नीचे दी गई है–

01. कृषि	:	28
02. व्यापार और वाणिज्य	:	11
03. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी	:	17
04. स्वास्थ्य और पैरामेडिकल	:	09
05. गृह विज्ञान	:	09
06. मानविकी और अन्य	:	08
कुल	:	82

राष्ट्रीय स्तर पर PSSCIVE द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम डिजाइन में, प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित घटक होते हैं–

घटक भार

1. भाषा – 15–20%
2. सामान्य आधार पाठ्यक्रम (जनरल फाउंडेशन कोर्स) (GFC) 15–20%
   - पर्यावरण शिक्षा
   - ग्रामीण विकास
   - उद्यमिता विकास
3. व्यावसायिक सिद्धांत और अभ्यास 70% = कुल 100%

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2019 के प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज के अनुसार क्षमता–आधारित पाठ्यक्रम संरचना प्राथमिकताएं।

दस्तावेज की धारा 4 स्कूलों में पाठ्यक्रम के मुद्दों से संबंधित है।

- **समस्या–समाधान और तार्किक तर्क**– जिस तरह शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मन का भी व्यायाम करना जरूरी है। रणनीति, तर्क और शब्द पहेली, और मनोरंजक गणित के खेल बच्चों को गणित के बारे में उत्साहित करने के लिए और तार्किक कौशल

टिप्पणी

विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो उनके स्कूल के वर्षों में और वास्तव में जीवन भर में महत्वपूर्ण है।

- **व्यावसायिक प्रदर्शन और कौशल**– हमारे देश के लिए कुशलतापूर्वक और सही तरीके से चलने के लिए व्यावसायिक शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार बच्चों को इसकी उपयोगिता और कला के रूप में इसके मूल्य के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के तत्वों को शामिल करना बहुत ही फायदेमंद है।
- **डिजिटल साक्षरता और कम्प्यूटेशनल सोच**– डिजिटल साक्षरता का एकीकरण का यह नया पाठ्यक्रम बुनियादी स्तर पर सभी शिक्षार्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता को एकीकृत करेगा।
- **नैतिकता और नैतिक तर्क**– स्कूल के वर्षों के दौरान और जल्दी–जल्दी पाठ्यक्रम के लिए एक 'नैतिकता' घटक का परिचय छात्रों को चरित्र निर्माण, नैतिक और अच्छे इंसानों में विकसित होने, उत्पादक और खुशहाल जीवन जीने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

क्षमता आधारित पाठ्यक्रम विकास के लिए पद्धति

क्षमता आधारित पाठ्यक्रम विकास के लिए प्रस्तावित व्यवस्थित कार्यप्रणाली में छह चरण शामिल हैं–

(1) संकल्पना,

(२) योजना,

(3) डेटा संग्रह,

(4) डेटा विश्लेषण और दक्षताओं की सूची बनाना,

(5) क्षमता आधारित पाठ्यक्रम विकसित करना और

(6) एप्लीकेशन और पायलट टेस्ट विकसित करना।

पाठ्यक्रम में सुधारों के दिखने वाले चेहरे में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन शामिल हैं, लेकिन अदृश्य चेहरा कहीं अधिक जटिल है। यहां तक कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के सीमित संदर्भ में, पाठ्यक्रम सुधार की लोकप्रिय धारणा 'संशोधन', अद्यतन या सुधार पर केंद्रित है। उम्मीद है कि पाठयक्रम सुधारों को शैक्षणिक संबंधों के गहन पुनः डिजाइन की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए, उनके प्रभाव को महसूस करने से पहले लंबी अवधि की आवश्यकता होती है।

2.2.2 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतियां

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन और रणनीतियों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

- विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (VEP) का कार्यान्वयन शिक्षा निदेशालयों की जिम्मेदारी है। कुछ राज्यों में व्यावसायिक शिक्षा का एक अलग निदेशालय बनाया गया है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम या तो प्राथमिक और

टिप्पणी

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, या उच्च शिक्षा निदेशालय, या स्कूल शिक्षा निदेशालय, या औद्योगिक निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- एमएचआरडी का एक व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो है, जो व्यावसायिक शिक्षा के पूरे कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।
- विभिन्न संगठनों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जो व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त परिषद का समर्थन करता है
- काफी संख्या में राज्यों में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (SCVE) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण तक SCVE का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और राज्य स्तर पर इसके समानांतर निकायों का निर्माण किया जाता है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण आयोजित करता है, इन–सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन करता है।
- अधिकांश राज्यों ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारी शिक्षा निदेशालय को दे दी है। उनमें से कुछ ने औद्योगिक निदेशालय को जिम्मेदारी सौंपी।
- बहुत कम राज्यों ने जिला व्यावसायिक शिक्षा कार्यालयों (DVEO) की स्थापना की है। जिला स्तर पर, जिला शिक्षा अधिकारी या जिला व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी देखरेख करते हैं। कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन और समन्वय के लिए नोडल एजेंट के रूप में काम करता है।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त अनुदेशात्मक समय का प्रावधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जो रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, वे नीचे दी गई हैं–

स्कूल–उद्योग लिंकेज (School-Industry Linkage)

अक्टूबर 1987 में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए 'विकास योजनाओं के लिए मार्गदर्शिकाएं', तत्काल पर्यावरण (सरकारी/गैर सरकारी) के साथ संबंध में, विशेष रूप से, बड़े पैमाने पर निवेश गतिविधियों में भाग लेने के अवसरों की तलाश के संदर्भ में। ग्रामीण आवास, जल विभाजन प्रबंधन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि बंजर भूमि विकास, फूलों की खेती, खाद्य प्रसंस्करण, घरेलू उपकरण, संचार आदि के क्षेत्रों में होने जा रहे हैं, पीटीसी के लिए स्कूल उद्योग लिंकेज भूमिका की परिकल्पना की गई है।

अनिवार्य संस्थानों और माध्यमिक स्कूल प्रदाताओं को भी कार्य अनुभव के रूप में कार्यस्थल प्रशिक्षण के प्रावधान में उद्योग के साथ लिंक किया। छात्रों ने विभिन्न प्रकार के उद्योग कार्यक्रम शुरू करने के लिए, स्कूलों को एक साथ जोड़ा है। पूल और

संसाधनों को साझा करने के लिए समूह (क्लस्टर) ने इन संसाधनों का उपयोग किया है। कार्यस्थापन समन्वयक (वर्क प्लेसमेंट को–ऑर्डिनेटर) के पास उद्योग स्थापित करने की जिम्मेदारी है। लिंकेज और प्लेसमेंट स्थापित करने के लिए नियमित स्थापन प्रदान करने के लिए विशिष्ट उद्योगों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए।

टिप्पणी

• **प्रमुख लाभ** : माध्यमिक प्रदाताओं के लिए उद्योग लिंकेज के विकास से कई लाभ प्राप्त होते हैं, जो निम्न हैं–

1. प्रशिक्षण पैकेज जो योग्यता की मान्यता और पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करते हैं।
2. ऑफ–द–जॉब प्रशिक्षण के लिए उद्योग इनपुट की सुविधा देना।
3. कार्य स्थानों के लिए व्यवस्था को सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत करना।
4. छात्र कौशल विकसित करना और उपयुक्त व्यवसायों और संगठनों के बारे में जागरूकता लाना।
5. सार्वजनिक छवि में सुधार करना।
6. उद्योग के विकास के बारे में जागरूकता लाना।

सहयोगात्मक व्यवस्था (Collaborative Arrangement)

तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालियों के सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशें व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण और श्रम बाजार के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की आवश्यकता को संदर्भित करती हैं। तकनीकी प्रगति की दर और मानव हस्तक्षेप की गुणवत्ता के बीच सहयोग तेजी से स्पष्ट हो गया है क्योंकि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए अर्थव्यवस्था में सक्रिय लोगों को नवाचार करने के लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। नए कौशल की आवश्यकता है और शैक्षिक संस्थानों को न केवल न्यूनतम स्कूली शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, बल्कि वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

विश्व बैंक के अनुसार, टीवीई संस्थानों की प्रतिष्ठा योग्य युवा लोगों के उत्पादन की उनकी क्षमता पर निर्भर है, जो कार्य स्थल में तुरंत चालू हो जाएंगे। तकनीकी संस्थानों को काम की दुनिया के साथ काम करना बंद करना चाहिए ताकि उपकरणों, कर्मचारी विनिमय कार्यक्रमों और छात्रों के प्लेसमेंट के दान के रूप में इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण में वृद्धि हो सके। कुछ समय के लिए, TVET शिक्षाविदों द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग करता है जिसमें उद्योग की आवश्यकताओं या स्थानीय आवश्यकताओं की कोई समझ नहीं होती है।

TVET और उद्योग के बीच सफल सहयोग कई विशेषताएं साझा करते हैं।

- पहले, संस्थान उद्यमों की मांगों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों को संशोधित करते हैं जबकि उद्यम प्रशिक्षुओं को उनके कार्यक्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- दूसरी विशेषता संयुक्त रूप से विकसित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम है।

टिप्पणी

- तीसरी विशेषता साझा प्रबंधन संरचना है जो इन स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में उद्यम को शामिल करती है।
- चौथा, प्रशिक्षकों को उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए उद्यम आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण का उद्यम है।

हाल ही में, उद्योग संगठनों और संघों ने टीवीईटी को विकासशील नीतियों से प्रशिक्षण देने में अधिक सक्रिय रूप से भाग लिया है क्योंकि वे अब स्वीकार करते हैं कि औद्योगिक उत्पादन को प्रशिक्षण के साथ जोड़ना उत्पादकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। उद्यम के अनुसार, प्रदाता अब इस सहयोग को भविष्य के रोजगार के लिए अपने प्रशिक्षुओं को तैयार करने के सर्वोत्तम तरीके के रूप में देखते हैं। कई कारक इन संबंधित सहयोगों की सफलता में योगदान करते हैं।

संस्थागत ढांचे के आधार पर सहयोग को औपचारिक बनाना महत्वपूर्ण है जो विभिन्न परिचालन मुद्दों को नियंत्रित करता है– स्कूल प्रशासन का विकास, बोर्ड के सदस्यों का चयन, संयुक्त रूप से शिक्षण सामग्री विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को स्थापित करना, और मौजूदा तंत्र जो दोनों प्रशिक्षण में उद्योग को शामिल करेंगे।

सहयोग की एक प्रमुख विशेषता प्रशिक्षुओं के रोजगार की तैयारी पर अपना जोर है। पूर्व–रोजगार कौशल–विकास शिक्षा के सभी स्तरों पर मुख्य सहयोग उद्देश्य बनाता है जबकि अनुसंधान और नवाचार उच्चतर टीवी क्षेत्रों में दूसरे मुख्य उद्देश्य के रूप में कार्य करते हैं। लाभ दोनों पक्षों पर देखे जाते हैं, हालांकि विभिन्न रूपों के साथ संघर्ष करने के लिए मुद्दे हैं। सहयोग पहल की स्थिरता से संबंधित मुद्दे मुख्य रूप से शासन की निरंतरता हैं, कई सहयोगियों की आवश्यकताओं की बेहतर समझ और सहयोगी कार्यक्रमों में प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना। सहयोग के प्रयासों के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद, काम करने में सफल सहयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण (On-the-job Training)

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य काम की दुनिया के अनुभव को दिखाना है ताकि युवा लोगों के पास उपलब्ध विकल्पों की सीमा को समझें और प्रस्ताव पर कैरियर के रास्तों के बारे में सही विकल्प बनाने में उनकी सहायता करें।

- चूंकि ऑन–जॉब प्रशिक्षण में फील्ड वर्क शामिल होता है, इसलिए आपके कौशल और कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण उसे कॉर्पोरेट जगत की बारीकियों के अनुकूल बनाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण एक नौकरी के लिए आकांक्षी आत्मविश्वास देगा और उसे नौकरी के लिए तैयार करेगा।
- नए कौशल को अपनाने के अलावा, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी व्यक्ति के लिए नए कौशल के उन्नयन में सहायक होता है, इस प्रकार यह प्रशिक्षण पुराने कौशल और उपयोग को दूर करता है। दूसरों के विपरीत, यह पहले से ही कार्यरत लोगों द्वारा अपने नौकरी से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी लिया जाता है।

टिप्पणी

- समाज में हाशिए पर रहने वाले कुछ समूहों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की आसान पहुंच है जो उन्हें जीवनयापन करने में मदद करती है। यहां तक कि एक छात्र जो शिक्षाविदों में उत्कृष्ट नहीं था, वह व्यावसायिक प्रशिक्षण की मदद से एक आकर्षक नौकरी हासिल कर सकता है।
- लगभग सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से एक को व्यावहारिक प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता होती है। सीखने की यह पूरी प्रक्रिया अधिक सुखद हो जाती है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यक्ति की उत्पादकता को कौशल के साथ उन्नत बनाकर बढ़ाता है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति की संभावना अधिक है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण एक शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से एक नया अनुभव हो सकता है। शिक्षकों को एक ऐसा वातावरण बनाने पर ध्यान देना चाहिए जहां छात्र दूसरों के साथ बातचीत करने की क्षमता बढ़ा सकें।
- सीखने के दौरान व्यावहारिक प्रक्रिया अवलोकन, प्रतिबिंब, अनुभव और आवेदन का एक अनुमान है। व्यवसाय प्रशिक्षण एक छात्र की आउट–ऑफ–द–बॉक्स सोच क्षमता को बढ़ावा दे सकता है।

आज व्यावसायिक दुनिया तेजी से युवा स्नातकों को काम पर रखना चाहती है, जिनके पास संचार कौशल, टीम, काम करने और कार्यस्थल में कामयाब होने के लिए व्यावहारिक कौशल जैसे ज्ञान हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण युवाओं को कार्यस्थल पर सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद कर रहा है।

व्यावसायिक योग्यता वाले युवा स्नातक प्रशासन, बिक्री और ग्राहक सेवा, आतिथ्य, तकनीकी रोजगार, देखभाल और अवकाश, और कुशल ट्रेडों सहित व्यावसायिक क्षेत्रों की एक सरणी में अपने कौशल का उपयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC) लास ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को देश की शिक्षा पहल का एक महत्वपूर्ण तत्व माना। इसे लचीला, समावेशी और अधिक रोजगार उन्मुख बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण तत्वों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति भी जबरदस्त उत्साह दिखाया है और महत्वपूर्ण पहल का सुझाव दिया है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC) ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित लंबी और छोटी अवधि की रणनीति की सिफारिश की है।

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के तहत व्यावसायिक शिक्षा को रखा जाना चाहिए।
2. निम्नलिखित चरणों के माध्यम से मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर VET के लचीलेपन को बढ़ाएं।
3. सामान्य शिक्षा के पहलुओं (जैसे संख्यात्मक कौशल, आदि) को वीईटी में जहां तक संभव हो, अनुमति दी जानी चाहिए ताकि छात्रों को बाद की अवस्था में मुख्यधारा की शिक्षा पर वापस लौटाया जा सके।
4. प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के कार्यक्रमों में अलग–अलग शैक्षिक प्राप्ति के छात्रों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए।

टिप्पणी

5. व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को कई प्रवेश और निकास विकल्प रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
6. व्यावसायिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा के बीच उचित लिंक बनाए जाने चाहिए।
7. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कुछ कौशल प्रशिक्षण के लिए समर्पित कार्यक्रम सभी स्कूलों में शुरू किए जाने चाहिए।
8. विभिन्न साक्षरता और वयस्क शिक्षा योजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
9. लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आजीवन कौशल उन्नयन के लिए योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।
10. बहु–कुशल व्यक्तियों का संवर्ग (कैडर) बनाने की सुविधा होनी चाहिए।

समूह प्रशिक्षण कंपनियों को पहले प्रशिक्षुओं के रोजगार में सहायता के लिए स्थापित किया गया था और ये वे निकाय हैं जो अकसर एक विशेष उद्योग द्वारा प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रायोजित होते हैं, और ऑफ और ऑन जॉब का एक कार्यक्रम स्थापित करने के लिए इन प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कंपनी उनके वेतन, वर्कओवर लागत, बीमारी, छुट्टी आदि के लिए जिम्मेदार है और उन उद्यमों का पता लगाने के लिए जो प्रशिक्षु की मेजबानी करेंगे और उन्हें कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करेंगे।

हाल ही में, समूह प्रशिक्षण कंपनियों ने भी छात्रों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण और शिक्षुता में शामिल होने के अवसर प्रदान करने के लिए स्कूलों के साथ मिलकर काम किया है। इसका मतलब है कि वे ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण घटकों को स्थापित करने की जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि स्कूल ऑफ–द–जॉब प्रशिक्षण घटकों की जिम्मेदारी लेते हैं। कई बार कंपनियां कुछ ऑफ–द–जॉब घटकों को भी प्रदान कर सकती हैं।

शासन संरचनाओं और कार्यक्रम सलाहकार समूहों पर उद्योग प्रतिनिधित्व यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रदाता उद्योग जागरूकता बनाए रखें और अपने व्यावहारिक कौशल और ज्ञान को चालू रखें।

प्रशिक्षुता या प्रशिक्षुता नियोक्ताओं और प्रशिक्षुओं या प्रशिक्षुओं (या उनके अभिभावकों) के बीच एक कानूनी अनुबंध द्वारा कवर एक प्रशिक्षण व्यवस्था को संदर्भित करता है जहां व्यक्तियों को समय की एक विशिष्ट राशि के लिए नियोक्ताओं के लिए प्रेरित किया जाता है।

एक प्रशिक्षुता ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण का एक रूप है जो निरंतर श्रम की अवधि के बदले में नियोक्ता के तहत प्रशिक्षण द्वारा विशेषता है। प्रशिक्षु अकसर प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अपने व्यापार या पेशे का अभ्यास करने के लिए अपना लाइसेंस या मान्यता प्राप्त करते हैं। कुछ मामलों में, ऑन–द–जॉब लेबर अधिक औपचारिक शोध या अध्ययन के साथ होता है।

उत्पादन–सह–प्रशिक्षण केंद्र (Production-cum-training Centre–PTC)

उत्पादन–सह–प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना को काम की दुनिया के साथ शिक्षण प्रक्रिया को जोड़ने के लिए एक सीखने का अनुभव प्रदान करने की एक पद्धति के रूप में

टिप्पणी

कल्पना की जाती है, ताकि छात्रों को न केवल प्रासंगिक कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त हो, बल्कि उत्पादन में कौशल का उपयोग करने के लिए अनुभव पर आवश्यक हाथ भी मिलें और विपणन वस्तुओं और सेवाओं, स्कूलों में पीटीसी की स्थापना से शिक्षा और काम के बीच की द्वंद्वात्मकता को कम किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रियाएं सीखने के वाहन बनते हैं, जो सामान और सेवाओं के लिए समाज की जरूरतों से संबंधित हैं। पीटीसी के माध्यम से कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन छात्रों के बीच वितरित किया जाता है जो प्रोत्साहन के रूप में आते हैं और उनका समर्थन करते हैं।

पीटीसी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(1) बाजार के लिए प्रासंगिक शैक्षिक अनुभव प्रदान करना।

(2) आवश्यकता आधारित उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से आत्म–समर्थन करना।

(3) छात्रों को लाभकारी स्व–वेतन रोजगार के लिए तैयार करना।

इसलिए, स्कूल में पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के दायरे को देखते हुए प्रत्येक स्कूल में एक पीटीसी का गठन किया जा सकता है। जन शिक्षण जैसे संस्थानों के साथ सहयोग के लिए उपयुक्त संपर्क स्थापित किया जा सकता है। PSSCIVE स्कूलों में PTC को स्थापित करने और चलाने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करेगा और PTC की स्थापना के लिए प्रमुख कार्यकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

स्कूल अपनी माध्यमिक स्कूल योग्यता के लिए छात्रों को तैयार करते हैं और छात्रों को सामान्य कार्य अनुभव के माध्यम से व्यावसायिक स्थापन के माध्यम से काम की दुनिया का अनुभव करने के अवसर प्रदान करते हैं जो विशिष्ट वीईटी पाठ्यक्रमों से जुड़े होते हैं।

उत्पादन–सह–प्रशिक्षण के प्रमुख केंद्र

1. **सेवा उत्पादन केंद्र, पाबल, पुणे में विज्ञान आश्रम**– पाबल, पुणे में सेवा उत्पादन केंद्र, एक व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय से जुड़ी एक शिक्षा–सह–उत्पादन इकाई है। माध्यमिक व्यावसायिक स्कूल में उद्यम को शामिल करने के प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा की प्रासंगिकता में सुधार कर रहे हैं, स्कूल को एक व्यवहार्य आर्थिक इकाई बना रहे हैं और अपने छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करके उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहे हैं कि वे एक लाभदायक उद्यम चला सकें।

   विज्ञान आश्रम द्वारा उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत विविधता प्रदान की जाती है। इनमें डेयरी और कृषि उत्पाद (पोल्ट्री, अंडे, ब्रॉयलर) और प्रजनन शामिल हैं। तकनीकी सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, ईआरएम उपकरणों का उत्पादन, कार्यशाला निर्माण, जल संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण प्रयोगशाला, यांत्रिक बैल, प्रकाशन और ग्रामीण व्यापार केंद्र शामिल हैं।

2. **शांतिकुंज आश्रम, हरिद्वार में उत्पादन केंद्र**– शांतिकुंज की स्थापना 1969 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने की थी, जो महात्मा गांधी के एक सक्रिय सहयोगी स्वतंत्रता सेनानी थे। शांतिकुंज गांधीवादी दर्शन का अनुसरण करते हैं और अनुशासित मामूली जीवन जीने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करते हैं, और समाज के कमजोर वर्गों को आध्यात्मिक, नैतिक और वित्तीय मदद प्रदान करते हैं।

टिप्पणी

उत्पादन केंद्र मूल रूप से आश्रम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें निम्नलिखित ट्रेडों में कई छोटे उद्यम शामिल हैं। मोमबत्ती बनाना, धागा और रेशम का तार, मधुमक्खी का मोम और शहद का उत्पादन, बेकरी, अगरबत्ती, चाक बनाने, बुकबाइंडिंग, रबरस्टैंप, फोटो फाड़ना, बाइलेन रिफिल, सिलाई, धार्मिक धागा (जनेऊ), प्रिंटिंग प्रेस तरल, फोटोग्राफी, तेल निष्कर्षण, हथकरघा कपड़ा, पापड़ बनाना (बिन रोटी)। 1986 में शांतिकुंज में लघु उद्योग स्थापित किए गए थे। ये उद्यम बहुत मामूली, कम लागत वाले पैमाने पर काम करते हैं और स्वैच्छिक श्रमिकों की सेवाओं को रोजगार देते हैं।

शांतिकुंज में इस तरह के उत्पादन केंद्र व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित किए गए हैं। ऐसे उत्पादन केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को कौशल प्रशिक्षण और कुछ आकस्मिक उत्पादन और लाभ प्रदान करना है। किसी भी उत्पाद के लिए छोटे ऑर्डर स्कूलों के कर्मचारियों से खरीदे जाते हैं। इन आदेशों का निष्पादन छात्रों को पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, उनके व्यावहारिक कौशल को परिष्कृत करने और व्यावहारिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक कक्षाओं के दौरान सामानों की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

3. **डॉन बॉस्को तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली**– डॉन बॉस्को तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली को मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में मोटर यांत्रिकी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मशीन कार्यशाला स्थापित करने का विचार किया गया। 1977 में ट्रेड्स टर्नर और फिटर को मंजूरी दी गई। 1983 तक ट्रेड्स ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) और मशीनिस्ट (ग्राइंडर) को जोड़ दिया गया। संस्थान को शुरू में आधुनिक उद्योग के लिए स्थानीय ईसाइयों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था।

   लेकिन, जैसा कि इस स्तर पर प्रशिक्षण वास्तव में सम्मानजनक नहीं माना जाता था, संस्थान अपनी इष्टतम क्षमता पर काम नहीं कर रहा था। कैलिबर वाले कॉलेज जाना पसंद करते थे या उच्च स्तर पर प्रवेश चाहते थे। जो लोग आए थे, उन्होंने अपनी दसवीं कक्षा पूरी नहीं की थी, जिसका मतलब था कि उन्हें अंग्रेजी और गणित की बुनियादी दक्षताओं में ड्रिल करना था। अन्य कठिनाई स्थानीय उद्योगों में से कुछ के साथ काम कर रहे रिश्तों में आने की थी।

   निजी केंद्रों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण निदेशालय के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, एक कंप्यूटर विभाग स्थापित किया गया है जिसमें एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। जबकि दिल्ली के अधिकांश कंप्यूटर सेंटर केवल उच्च वर्ग के लिए ही काम करते हैं, डॉन बॉस्को एक ऐसी जगह है जहां कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को सीखने का मौका मिलता है।

4. **डॉन बॉस्को स्वरोजगार अनुसंधान संस्थान, हावड़ा**– भारत में वास्तविक स्थिति यह है कि युवाओं के मेजबान हैं जो स्कूल ड्रॉप–आउट हैं या कौशल

टिप्पणी

की पाठ्यपुस्तक से निपटने की कमी है, हालांकि व्यावहारिक बुद्धि से पूरी तरह से नहीं। डॉन बॉस्को केवल इन स्थानीय लड़कों और युवाओं की एक बहुत ही सीमित संख्या को पूरा करने में सक्षम रहा है, जो पाते हैं कि वे शिक्षा की औपचारिक प्रणाली का सामना नहीं कर सकते हैं।

इसलिए यह महसूस किया गया कि एक नए प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए– कम परिष्कृत, अल्पकालिक और रोजगार–उन्मुख। लाभार्थियों में स्कूल ड्रॉप आउट, गरीब अनाथ, शारीरिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जनजाति या जाति और गरीबी रेखा से नीचे के लोग होंगे। जर्मनी के मिसरे की आर्थिक सहायता और दिल्ली के इंडो–जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी ने एक शुरुआत की थी।

प्रशिक्षण को स्कूल छोड़ने वाले और सामाजिक रूप से वंचित युवाओं के लिए सुलभ बनाया गया है। जैसा कि उद्यमों की स्थापना इस प्रशिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है, यह वंचितों को कम करने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, 15 से 20 प्रशिक्षुओं को तीन महीने से एक वर्ष तक की अवधि के गैर–औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिए जाते हैं। गैर–औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी को एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है।

5. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलोर**– 1988 में, विश्व बैंक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और आधुनिकीकरण में भारत सरकार की सहायता करने के लिए सहमत हुआ। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना में उच्च प्रौद्योगिकी और स्वरोजगार प्रशिक्षण और समर्थन में व्यावसायिक प्रशिक्षण के विविधीकरण शामिल थे। प्रमुख प्रेरणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र कारीगरों, प्रशिक्षुओं और तकनीशियनों के बीच उच्च बेरोजगारी का स्तर था, और इन स्नातकों को स्व–रोजगार के लिए डायवर्ट किया जाना चाहिए। परियोजना का स्वरोजगार घटक निम्नलिखित मानदंडों के साथ डिजाइन किया गया था–
   - यह उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।
   - यह प्रशिक्षण चरण के दौरान व्यावहारिक उत्पादन कार्य पर जोर देगा।
   - यह मौजूदा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (VTI) द्वारा लागू किया जाएगा।
   - यह स्कूटर और मोटर यांत्रिकी, स्प्रे पेंटिंग और टायर के प्रसार जैसे मांग आधारित ट्रेडों को कवर करेगा।
   - इसमें उद्योग से अंशकालिक प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में केवल तीन प्रशिक्षुओं के लिए तीन से छह महीने के लिए गहन अंशकालिक प्रशिक्षण शामिल होगा।
   - इसमें उद्यमिता प्रशिक्षण का एक अनुखंड (मॉड्यूल) शामिल होगा।

टिप्पणी

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (Apprenticeship Training)

अतीत में प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) मुख्य रूप से विनिर्माण, आतिथ्य, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग, हेयरड्रेसिंग, भवन निर्माण और मोटर वाहन उद्योगों से जुड़े पारंपरिक व्यवसायों में थे। हालांकि आज नए अप्रेंटिसशिप उभरते हुए उद्योगों के साथ–साथ सेवा और व्यावसायिक उद्योगों में भी किए जा सकते हैं। अतीत में प्रशिक्षु एक पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगे हुए थे। अब नए अप्रेंटिसशिप के तहत व्यक्ति अंशकालिक आधार पर नए अप्रेंटिसशिप में शामिल हो सकते हैं, और जब वे अभी भी स्कूल में हैं। प्रशिक्षण के अनुबंध विशेष रूप से प्रासंगिक प्रशिक्षण पैकेज की योग्यता को संदर्भित करते हैं।

यह लगातार महसूस किया गया है कि व्यावसायिक स्तर के छात्रों को +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। 1986 में, +2 स्तर (तकनीशियन वोकेशनल अपरेंटिस) के व्यावसायिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपरेंटिस अधिनियम में संशोधन किया गया था। यह योजना मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर में चार क्षेत्रीय बोर्ड ऑफ अपरेंटिसशिप ट्रेनिंग (BOAT) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

वर्तमान में प्रशिक्षुता (अपरेंटिस) अधिनियम, 1961 के तहत परिशिष्ट–ए (पृष्ठ 77 से 79) के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। प्रशिक्षुता (अपरेंटिस) अधिनियम के तहत अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय और जिला व्यावसायिक शिक्षा कार्यालय को छात्रों के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए BOATS के साथ संपर्क करना चाहिए।

यह योजना औद्योगिक उद्यमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ITI पास आउट, व्यावसायिक छात्रों, डिप्लोमा धारकों, इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए प्रदान करती है और साथ ही वजीफा भी प्राप्त करती है। शिक्षार्थी का प्रशिक्षण शिक्षार्थी की ओर से वैकल्पिक है। छात्रों को सीधे काम की दुनिया में शामिल होने या उन्नत पाठ्यक्रमों के लिए जाने का विकल्प है, या शिक्षुता कार्यक्रम का विकल्प चुनना है।

शिक्षुता, हालांकि, उम्मीदवार को कौशल को और अधिक परिष्कृत करने या अधिक अभ्यास करने का अवसर प्रदान करती है और इस प्रकार, काम की वास्तविक दुनिया में शामिल होने से पहले छिपकर प्रदर्शन करने की क्षमता में अधिक आत्मविश्वास विकसित करती है। वजीफे का प्रावधान एक अतिरिक्त लाभ है।

वर्तमान में, PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NCEBT द्वारा विकसित व्यावसायिक पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत कोवेक्सज के प्रयोजन के लिए पहचाने गए हैं।

शिक्षुता प्रशिक्षण के प्रमुख लाभ

माध्यमिक और बाद के माध्यमिक प्रदाताओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें शामिल हैं–

1. प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) पैकेज जो योग्यता की मान्यता और संवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) की सुविधा प्रदान करते हैं।

2. काम के स्थानों के लिए व्यवस्थित और केंद्रीकृत व्यवस्था।
3. अविकसित छात्र कौशल और उपयुक्त व्यवसायों और संगठनों के बारे में जागरूकता।
4. नियोक्ताओं की सार्वजनिक छवि को सुधारना।
5. उद्योग के विकास के बारे में शिक्षक जागरूकता बढ़ाना।

टिप्पणी

छात्र सहायता प्रणाली (Student support system)

तेजी से बदलती तकनीक के मद्देनजर, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को आवश्यक मूल्यांकन, सह–विकास का समर्थन, अनुदेशात्मक सामग्रियों का विकास, छात्रों के लिए समर्थन, शिक्षक तैयारी समर्थन, बुनियादी ढांचे का समर्थन, व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श समर्थन, आर एंड डी (अनुसंधान) में सहयोग की आवश्यकता होगी और विकास समर्थन, परियोजना की तैयारी में सहायता, वित्तीय सहायता, गैर प्रिंट सामग्री और ई–लर्निंग आईसीटी समर्थन की तैयारी, तकनीकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग और समर्थन, मूल्यांकन और प्रमाणन, सामुदायिक समर्थन। औपचारिक और गैर–औपचारिक प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का वितरण एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल उद्यम है।

जब व्यावसायिक शिक्षा को बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग तौर–तरीकों के माध्यम से दिया जाना है, तो पूरे सिस्टम को पाठ्यक्रमों के चयन और डिजाइन, प्रशिक्षण स्थानों और विशेषज्ञों की पहचान, सुविधाओं को संक्रमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के समर्थन की आवश्यकता होती है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेने वाले छात्र काफी युवा हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे इतनी कम उम्र में काम की दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए, उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जिसमें ये शामिल होते हैं– कार्य की दुनिया में उनके निर्बाध संक्रमण और निर्वाह के लिए सही पाठ्यक्रम का चयन। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।

छात्रों को कैरियर विकल्प बनाने और उनकी रुचि क्षमता और आकांक्षा के लिए उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन करने की आवश्यकता है। उन्हें बाजार के रुझानों के बारे में भी निर्देशित किया जाना चाहिए।

विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अलग–अलग अवधि के पाठ्यक्रम आईटीआई के विज्ञापन पॉलिटेक्निक, एनआईओएस और गैर–औपचारिक प्रणाली में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा भी पेश किए जाते हैं। सही चुनाव के लिए सावधानी और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

यह आवश्यक माना जाता है कि इस तरह की सेवाएं शिक्षा के सभी चरणों के दौरान प्रदान की जाती हैं और विभिन्न समूहों के बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। व्यावसायिक मार्गदर्शन जो शिक्षार्थियों की मदद करता है।

कार्यक्षेत्र बनाने में उद्योग की सहायता

यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (NCF2005) में परिकल्पित है कि 'कार्य क्षेत्र' ('वर्क बेंच') ग्रामीण शिल्प, कृषि या वन के सहयोग से स्थापित किए जा सकते हैं।

टिप्पणी

आधारित उत्पादन प्रणाली, उद्योग और सेवाएं– इनसे तिहरा (ट्रिपल) फायदा होगा। सबसे पहले, इसे न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ स्थापित किया जा सकता है। दूसरे, यह नवीनतम तकनीकों तक पहुंच प्रदान करेगा और तकनीक उस क्षेत्र में उपलब्ध है, और तीसरा, छात्रों को अनुभव और डिजाइनिंग और बाजार की वास्तविक समस्याओं के बारे में जानने को मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए, एनसीएफ 2005 ने सुझाव दिया है कि इसे आवश्यक 'कार्य क्षेत्र' के अलावा प्रारूप प्रशिक्षण और निगरानी सहायता प्रदान करके क्षेत्र के स्कूलों के साथ सहयोग करने के लिए उत्पादन और सेवाओं में लगी सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

मुक्त अधिगम प्रणाली (ओपन लर्निंग सिस्टम)– मुक्त अधिगम प्रणाली उन लोगों के बीच अधिगम को सहायक बनाने के लिए एक शिक्षा प्रणाली के रूप में उभर रही है, जो देश के भीतर शिक्षा संचालन की औपचारिक प्रणाली का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। यह प्रणाली एक लचीली और सीखने के अनुकूल तरीके से तुलनीय मानकों की शिक्षा प्रदान करती है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, मुक्त विद्यालयी प्रणाली का उपयोग शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों के लिए पूरी तरह से किया जा सकता है। यह कल्पना की जाती है कि कई छात्र खुले शिक्षण प्रणाली के माध्यम से इस स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जाना चाहते हैं क्योंकि यह इसमें स्वतंत्रता प्रदान करती है।

तकनीकी सहायता

तकनीकी उन्नति, छात्रों के समर्थन में सीखने, फिर से शिक्षित करने, बहु कौशल (मल्टीस्किलिंग) में बड़े पैमाने पर आ सकती है। यदि कोई दैनिक जीवन में कंप्यूटर के उपयोग को देखता है, तो यह देख सकता है कि वह समय आ गया है जब संचार, टिकटिंग और आरक्षण (वायु और रेलगाड़ी), ऑनलाइन बैंकिंग, ई–मेल का उपयोग करके शिक्षण सामग्री, ई–लर्निंग का उपयोग करना सब कंप्यूटर के माध्यम से किया। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ कंप्यूटर, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, इंटरनेट की उपलब्धता की लागत आम आदमी के लिए सुलभ हो गई है।

भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उपग्रह 'एडुसेट' लॉन्च किया गया है। व्यावसायिक कार्यक्रमों को किसी भी शिक्षार्थी को उपग्रह के माध्यम से व्यावसायिक कार्यक्रमों के माध्यम से देखा जा सकता है। यह विशेष रूप से कुछ व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त है।

डिजिटल लाइब्रेरी सहायता

पहले जब कोई छात्र किसी पुस्तक, लेख या अन्य संसाधन सामग्री को संदर्भित करना चाहता था, तो हेल्शे को एक पुस्तकालय में जाना पड़ता था। अब इंटरनेट सुविधा वाला कंप्यूटर कई वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करता है जहां नवीनतम सामग्री, रिपोर्ट, पुस्तकें और पत्रिकाएं संदर्भ उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हैं और आवश्यकतानुसार इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। डिक्शनरी और इनसाइक्लोपीडिया भी लाइन पर उपलब्ध हैं।

टेलीकांफ्रेंसिंग सहायता

टेलीकांफ्रेंसिंग का उपयोग ऑडियो वीडियो और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक या एक से अधिक स्थानों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक स्थान से एक विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, प्रदर्शन आदि विभिन्न स्थानों पर छात्रों द्वारा सुना जा सकता है। चर्चा के दौरान, विशेषज्ञ के साथ उनकी कठिनाइयों को भी हल किया जा सकता

है। टेली–कॉन्फ्रेंसिंग में एक स्टूडियो है जहां से शिक्षक व्याख्यान देते हैं और छात्रों को केंद्रों पर इकट्ठा किया जाता है, जो दूर हो सकता है, जहां नीचे लिंकिंग की सुविधा उपलब्ध है।

ई–लर्निंग सहायता

ई–लर्निंग से गति में एक प्रक्रिया निर्धारित करने की उम्मीद की जाती है जो वर्तमान समाज को सीखने वाले समाजों में बदल सकती है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के प्रावधान में वृद्धि होगी, जो विस्तृत होगी। निर्देशित पाठ्यक्रम जो अन्तरक्रियाशीलता, असाइनमेंट और (सेल्फ टेस्ट) के साथ पाठ को सुदृढ़ करते हैं। यदि अनुशिक्षक (ट्यूटर) और शिक्षार्थी एक ही समय में एक ही आभासी स्थान साझा करते हैं और एकीकृत और पाठ आधारित संचार उपकरणों का उपयोग करके वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं, तो यह विशेष रूप से प्रभावी होगा जो उपयोगकर्ता बातचीत, सुनना, देखना और पूछताछ करके सबसे अच्छा सीखते हैं।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

1. "गति में सामाजिक पर्यावरण" के रूप में किसको परिभाषित किया जा सकता है?

   (क) रूपरेखा (ख) पाठ्यक्रम

   (ग) क्षमता (घ) वैज्ञानिक आविष्कार

2. किस पर आधारित पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के दृष्टिकोण का वर्णन करता है?

   (क) ज्ञान (ख) अनुशासन

   (ग) क्षमता/योग्यता (घ) कौशल

2.3 संगठन और प्रबंधन

परंपरागत रूप से, व्यावसायिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का हिस्सा रही है, जो विभिन्न कारणों से अत्यधिक केंद्रीकृत है। मंत्रालयों, नियोक्ताओं और कभी–कभी, शिक्षाविदों के व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ राष्ट्रीय वीईटी परिषदों और बोर्डों की स्थापना के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लिए विकेंद्रीकरण की एक निश्चित डिग्री पेश की गई है। व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन को अधिकारियों (संघीय और क्षेत्रीय स्तर) और शिक्षा अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारियों, व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों, उद्यमों, व्यावसायिक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों के साथ उत्पादक बातचीत के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य इष्टतम कामकाज और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने और बढ़ावा देने के साथ–साथ समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। प्रत्येक मनुष्य एक सकारात्मक संपत्ति है और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे कोमलता और देखभाल के साथ पोषित और विकसित किया जाना है।

टिप्पणी

प्रशासक का लक्ष्य विद्यालय की समग्र प्रक्रिया को सुचारू रूप से प्रवाहित रखना है, जिससे निर्णय सफल शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रशासक एक विद्यालय के मिशन और लक्ष्यों की पहचान करता है और उन्हें लागू करता है और उन्हें कार्यक्रमों को लागू करने, कार्यों को प्रस्तुत करने और संसाधनों को आवंटित करने से होता है। स्कूल के भौतिक संसाधन प्रबंधन का सीखने के वातावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यह शैक्षिक परिणामों का एक प्रमुख निर्धारक है।

इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि स्कूल भौतिक संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को स्कूल की संपत्ति को बुनियादी शिक्षा सेवा वितरण मानकों और रणनीतियों से जोड़कर स्कूल सुधार योजना के साथ संरेखित करें। यह सुविधा, रखरखाव, शिक्षण और सीखने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। इसमें शिक्षण और सीखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल है।

2.3.1 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत स्तरों पर प्रबंधन संरचना

आधुनिक समाज में प्रबंधन कोई नवीन अवधारणा नहीं है। जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग आवश्यक बन गया है। व्यावसायिक शिक्षा में प्रबंधन का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है ताकि संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत स्तरों पर प्रबंधन का बहुत महत्व है। विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना अलग–अलग होती है।

प्रबंधन की सफलता यह निर्धारित करती है कि वे इन कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। ये कार्य संख्या में तीन हैं, समान रूप से महत्वपूर्ण और अनिवार्य रूप से भिन्न हैं, जो संगठन को अपने प्रभार में संगठन को कुशलतापूर्वक कार्य करने और समाज में अपना योगदान देने के लिए सक्षम करना है। (i) संगठन के विशिष्ट उद्देश्य और मिशन को संतुष्ट करने के लिए, (ii) संगठन को काम करने के लिए उत्पादक और कार्यबल को परिणामों की उपलब्धि के लिए कुशल और प्रभावी बनाना है, और (iii) सामाजिक प्रभावों का प्रबंधन करने और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। संगठन की निरंतरता एक केंद्रीय उद्यमशीलता का काम है और इतनी अच्छी तरह से करने की क्षमता प्रबंधन का सबसे अधिक इंगित और निश्चित कार्य है।

संगठन समाज संरचना का हिस्सा हैं। वे उस समुदाय का हिस्सा हैं जिसमें वे कार्य करते हैं। वे समाज की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ कुछ सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि संगठन सफलतापूर्वक कार्य करें ताकि वे उन कार्यों को पूरा कर सकें जिनके लिए वे स्थापित हैं। वे प्रभावी रूप से और कुशलता से समाज की उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं जिनके लिए वे अस्तित्व में आए हैं। प्रबंधन, बदले में, संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अपने आप में कोई कार्य नहीं है, वास्तव में, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रबंधन जिस संगठन से कार्य करता है, उससे अलग प्रबंधन नहीं है।

जब यह नौकरशाही बन जाती है, या जब यह समाज में कुछ विशेष हितों की सेवा शुरू कर देता है या संगठन को सफलतापूर्वक कार्य करने में विफल रहता है, तो यह कुशलता से और प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है, ताकि यह उन कार्यों को पूरा

कर सके जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है। संगठन में प्रबंधन का अस्तित्व तब से है जब इसके लिए कुछ कार्यों को पूरा करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना को क्रमशः इस प्रकार समझा जा सकता है–

विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना

टिप्पणी

तालिका : व्यावसायिक शिक्षा प्रबंधन संरचना

कार्य/स्तर (Function/ Level)	नीति और समन्वय मूल्यांकन और निगरानी (Policy & Coordination Evaluation & Monitoring)	अनुसंधान विकास और कार्यान्वयन (Research Development & Implementation)	प्रशासन/पर्यवेक्षण (Administration/ Supervision)	परीक्षा और प्रमाणन (Examination & Certification)
राष्ट्रीय (National)	संयुक्त शिक्षा परिषद (JCVE) (Joint Council of Vocational Education) (JCVE)	केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) (Pundit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education)	व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो (बीवीई), एमएचआरडी (Bureau of Vocational Education (BVE),MHRD)	अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड (All India Board of Vocational Education)
क्षेत्रीय (Regional)	------	------	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड - (Board of Apprenticeship Trainings (BOATs)	------
राज्य- (State)	राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद (State Council of Vocational Education) (SCVE)	राज्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में व्यावसायिक विंग (Vocational Wing in SCERT/State Institute of Vocational Education)(SIVE)	शिक्षा निदेशालय में व्यावसायिक विंग (Vocational Wing in Directorate of Education)	राज्य बोर्ड (State Boards)
जिला (Districts)	जिला व्यावसायिक शिक्षा समिति (District Vocational Education Committee) (DVEC)	------	जिला शिक्षा कार्यालय / जिला व्यावसायिक शिक्षा कार्यालय में व्यावसायिक विंग- (Vocational Wing in District Education Office/District Vocational Education Office) (DVEO)	------
विद्यालय (School)	------	------	------	प्रधान अध्यापक (Principal)

(क) राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना

राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना को इस प्रकार समझा जा सकता है–

(1) संयुक्त व्यावसायिक परिषद [Joint Council of Vocational Education (JCVE)] की स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में की गई है और इसमें सभी मौजूदा व्यावसायिक प्राधिकरणों / परिषदों और कुछ राज्य सरकारों से प्रतिनिधित्व शामिल है।

टिप्पणी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री निम्नलिखित कार्य करता है–

- विभिन्न संगठनों/मंत्रालयों द्वारा संचालित व्यावसायिक कार्यक्रमों की योजना और समन्वय,
- जनशक्ति आवश्यकताओं का आकलन,
- सभी स्तरों पर व्यावसायिक कार्यक्रमों का विकास,
- पुल/स्थानांतरण पाठ्यक्रमों का विकास,
- शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण,
- पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विकास,
- गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन और प्रमाणन,
- विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक सुविधाएं बनाने के लिए योजनाएं विकसित करना,
- व्यावसायिक शिक्षा में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उद्योग की भागीदारी के लिए योजना का विकास करना,
- श्रमिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम शुरू करने और गैर–औपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करना,
- समय–समय पर व्यावसायिक कार्यक्रमों की समीक्षा करना,
- विशेष वंचित समूहों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में लगे गैर–सरकारी संगठन की पहचान करना और उसका समर्थन करना।

शिक्षा विभाग के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की जाती है–

- विशेष रूप से नियोजन, कार्यक्रम के विकास, दिशानिर्देशों और समन्वय को निर्धारित करने के संबंध में जेसीडब्ल्यू को सचिवालयीय सहायता प्रदान करना;
- जेसीवीई की सिफारिशों/निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम के कार्यान्वयन को लागू करना और उसकी देखरेख करना;
- राष्ट्रीय स्तर पर जनशक्ति आवश्यकताओं का समन्वय, व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक रोजगार/भर्ती योग्यता में संशोधन की दिशा में काम करना;
- व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखना;
- व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए कदम उठाना, निगरानीय कार्यक्रम और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का कार्य करना।

(ii) NCERT का एक घटक, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, शीर्ष स्तर के अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसके विशिष्ट कार्य निम्नलिखित हैं–

टिप्पणी

- देश के माध्यम से औपचारिक और गैर–औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम दोनों में गुणवत्ता और मानकों (शिक्षण पेशे के लोगों सहित) में तुलना सुनिश्चित करना।
- राज्य सरकार और अन्य संस्थानों को पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और निगरानी और मूल्यांकन आदि में दिशा–निर्देश देना और प्रदान करना।
- विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों जैसे कि स्कूल के प्राचार्यों, राज्य अधिकारियों, सर्वेक्षण श्रमिकों आदि के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।
- अल्पकालिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- SIVE / SCERT कर्मियों के लिए इन–सर्विस कोर्स की पेशकश करना।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक सूचना प्रणाली विकसित करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए सूचना के समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना।
- शिक्षण सामग्री के मल्टी–मीडिया पैकेज विकसित करना।
- शिक्षा की उपयुक्त एजेंसियों और अन्य मंत्रालयों/विभागों, गैर–औपचारिक, नव–साक्षर युवाओं, स्कूल ड्रॉप–आउट, काम में लगे व्यक्तियों और बेरोजगारों के लिए आंशिक रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों के साथ सहयोग करना।
- संयुक्त शिक्षा परिषद और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अकादमिक/तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(ख) क्षेत्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना

राष्ट्रीय स्तर पर छह क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं (आर ई ए) के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मॉड्यूलों का समूह तैयार करता है और अध्यापकों तथा शिक्षक शिक्षकों के प्रशिक्षण के विशिष्ट कार्यक्रम भी शुरू करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा संस्थानिक सहायता भी दी जाती है। एन सी ई आर टी और एन यू ई पी ए दोनों राष्ट्रीय स्तर के स्वायत्तशासी निकाय हैं। राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें (एस सी ई आर टी), शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल तैयार करती हैं और शिक्षक शिक्षकों और स्कूल शिक्षकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संचालन करती हैं। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सी टी ई) और उन्नत शिक्षा विद्या संस्थान (आई ए एस ई), माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अध्यापकों और शिक्षक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जिला स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डी आई ई टी) द्वारा प्रदान किया जाता है। स्कूल अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रखंड संसाधन केन्द्र (बी आर सी) और समूह संसाधन केन्द्र (सी आर सी) रैखिक सोपान में सबसे निचले सोपान के संस्थान हैं। इनके अलावा सिविल सोसायटी, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और अन्य स्थापनाओं की सक्रिय भूमिका के साथ भी सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) देश की शिक्षा पहल का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में

टिप्पणी

अच्छी तरह से अवगत होने से पहले ही इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। हाल ही में, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है, जिसका लक्ष्य सभी कार्यबल कौशल विकास कार्यक्रमों को विनियमित और समन्वयित करना है। इसके अलावा, सरकार ने उदान, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मॉड्यूलर नियोजित कौशल, आजीविका मिशन ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार ने कई पॉलिटेक्निक भी खोले हैं, जो तीन साल का डिप्लोमा कोर्स प्रदान करते हैं। ग्रास अकैडमी के पुरी बताते है , "भारत सरकार ने पिछले 2–3 वर्षों में क्वांटम लीप लेने के लिए कौशल विकास को सक्षम बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। सरकारी वित्त पोषण कौशल विकास कार्यक्रम न केवल निजी क्षेत्र को स्किलिंग और रोजगार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित होने और आने वाले समय में लाभप्रद रूप से नियोजित करने में मदद करेगा।"

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण राष्ट्र के शिक्षा संबंधी प्रयास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र के बदलते परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा, और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सके तथा भारत की बड़ी जनसंख्या/विशाल जन समूह इसका लाभ उठा सके, उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण तत्वों को पुनः परिभाषित करने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे वह इसे और अधिक सुविधापूर्ण, समकालीन, प्रासंगिक सम्मिलित और सृजनात्मक बन सकें। सरकार व्यावसायिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका से भली भांति अवगत है, इसीलिए सरकार इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। इस समय भारत स्कूल पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना में शामिल है जिस पर 1988 में विचार विमर्श किया गया और जिसका उद्देश्य उच्चतर शैक्षिक शिक्षा का विकल्प प्रदान करना था। एनआईओएस के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास के लिए व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों क्षेत्रों के लिए कुशल और मध्यमवर्गीय जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है। बाजार की मांग और शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का क्षेत्र पिछले वर्षों में बढ़ता रहा है। एनआईओएस के वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से संबन्धित है।

विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं से बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, मात्र 10 से 50 प्रतिशत बच्चे माध्यमिक शिक्षा पूरी करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों में उन विद्यार्थियों के लिए विकल्प के रूप में लगती है जो नियमित महाविद्यालयों में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। ऐसे भी बहुत से वयस्क सीखने वाले हैं जिन्हें अपने कुशलताओं में सुधार लाने अथवा नई कुशलताएं सीखने के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसे वे अपने जीवन के लिए कमाने में उपयोग कर सके। लड़कियों, महिलाओं तथा हाशिए पर खड़े समूहों जिसमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सम्मिलित हैं, को सशक्त बनाने के लिए बाजार योग्य कुशलताओं का विकास करने की आवश्यकता है। संक्षेप में लक्षित समूह जिसे व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, में सम्मिलित हैं–

टिप्पणी

- 14 से 25 वर्ष की आयु समूह के मध्य युवा जो सामान्य शिखा जारी नहीं रख पाते,
- युवा/विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने के योग्य नहीं,
- लड़कियां, महिलाएं, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां तथा अल्पसंख्यक,
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी,
- वयस्क अधिगमार्थी, जो अपनी कुशलताओं में सुधार चाहते हैं।

विद्यालय छोड़ने वालों की घटना बहुत से देशों में देखी जाती है विशेष रूप से विकासशील देशों में। उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता का समथ्रन किया जाता है। यूनेस्को की आख्या बताती है, "युवा लोगों की जॉब के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण एक व्यंजन विधि के रूप में शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित करने की प्रवृत्ति है।"

यूनेस्को की संस्तुतियां, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सुझाव देती हैं–

- सामान्य शिक्षा का एक आंतिरिक भाग।
- व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए युवा वर्ग को तैयार करने का एक माध्यम तथा कार्य के संसार में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए तैयार करने का एक माध्यम।
- पर्यावरण के लिए उपयुक्त संपोषणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपकरण तथा
- निर्भरता दूर करने को सुविधाजनक बनाने का एक मापन।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा द्वारा कई लक्ष्यों की पूर्ति होगी जैसे–

- युवाओं का सर्वांगीण विकास तथा उनकी रोजगार योग्यता को बहुसंख्यक कुशलताओं को सशक्त करके बढ़ाना।
- राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सहायता।
- आर्थिक तथा तकनीकी नवप्रवर्त्तन जो हो रहे हैं उनकी सहायता से विर्निर्माण तथा सेवा क्षेत्र की मांगों को पूरा करना।
- शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी तथा अल्प–बेरोजगारी के स्तर को कम करना।
- कलाकारों तथा शिल्पकारों जो कि पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं उनकी कुशलताओं में सुधार को सुविधाजनक बनाना।
- व्यावसायिक शिक्षा की सर्वांगीण वृद्धि के लिए देश के प्राकृतिक भौतिक तथा मानव संसाधनों के संपोषणीय तथा उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण तथा हाशिए के वर्गों की स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर स्थितियों को सुधारने में सहायता करना।
- उद्यमिता उत्पन्न करने वाले पारंपरिक रोजगारों को विज्ञान तथा तकनीकी आगतें उपलब्ध करा कर आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।

- ज्ञान व्यवस्था, ज्ञान समाज तथा ज्ञान कर्मियों का विकास।
- रोजगार बाजार की चरित्र बदलने के लिए उपयुक्त कुशलताओं को प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना।

व्यावसायिक पाठ्य के क्षेत्र

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को छः व्यापक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत प्रसिद्ध पाठ्यक्रम नीचे दिए गए हैं–

1. कृषि
    - डेयरी प्रौद्योगिकी
    - फसल उत्पादन
    - बागवानी
    - अंतर्देशीय मत्स्य
    - कुक्कुट उत्पादन
2. व्यापार तथा वाणिज्य
    - एकाउंटेंसी एवं ऑडिटिंग
    - बैंकिंग
    - एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और प्रलेखन
    - बीमा
    - खरीद और बिक्री
3. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी
    - एकयर कंडीशनिंग और प्रशीतन
    - इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रख–रखाव और मरम्मत
    - घरेलू उपयोग
    - भवन निर्माण
    - ग्रामीण इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी
    - सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन
4. स्वास्थ्य और पैरामेडिकल
    - हॉस्पिटल हाउस कीपिंग
    - चिकित्सा प्रयोगशला तकनीशियन
    - नेत्र संबंधी तकनीशियन
    - एक्स–रे तकनीशियन
    - स्वास्थ्य/स्वच्छता निरीक्षक
5. गृह विज्ञान
    - बेकरी और कन्फेक्शनरी

- खानपान और भोजनालय प्रबंधन
- वाणिज्यिक परिधान डिजाइनिंग और बनाना
- खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण
- पूर्व–विद्यालय और बालबाड़ी प्रबंधन

6. मानविकी, शिक्षा और अन्य
   - आंतरिक सज्जा
   - पर्यटन और यात्रा प्रबंधन
   - वाद्य संगीत – तबला
   - वाणिज्यिक कला
   - पुस्तकालय और सूचना विज्ञान

टिप्पणी

क्षेत्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना इस प्रकार है–

- दो चरण में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण के बोर्डों को व्यावसायिक छात्रों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संवर्धित किया जाता है।
- क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आरआईई) एनसीईआरटी के तहत अनुसंधान और विकास कार्य करने के अलावा क्षेत्रीय व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में कार्य करता है।

(ख) राज्य स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना

स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (SCVE) JCVE का एक हिस्सा है और राज्य स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए समग्र नीति बनाने और समन्वय के रूप में कार्य करता है। SCVE द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य JCVE के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार हैं–

- संस्थानों के चयन और सहयोग के लिए मानदंड तैयार करना।
- संस्थानों और पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के के संदर्भ में मानदंड तैयार करना।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड विकसित करना।
- जिले के संविधान के बारे में राज्य सरकार को सलाह देना।
- समय–समय पर कार्यक्रम की समीक्षा करना।
- रोजगार के बीच सहसंबंध स्थापित करने के लिए उपाय करना।
- अवसर (स्वयं और मजदूरी) और व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करना।
- व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने और छात्रों के प्लेसमेंट का समन्वय करने के लिए – व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की देखरेख करना।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।

टिप्पणी

- रोजगार/भर्ती में संशोधन की दिशा में काम करना।
- व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता, व्यावसायिक छात्रों के शिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना।
- स्वरोजगार चाहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद (State Council of Vocational Education–(SCVE)

SCVE एक उच्च स्तरीय निकाय है और इसकी सदस्यता में सरकार के संबंधित विभागों, निजी क्षेत्र के संगठन/संघों, अन्य निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, रोजगार और स्व–रोजगार और प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधित हैं जो कार्यक्रम को लागू करने में प्रभावी हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित तदर्थ समितियों के माध्यम से SCVE कार्य करता है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षा निदेशालय व्यावसायिक शिक्षा

कार्यक्रमों को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है। स्कूल स्तर पर नियंत्रण के द्वंद्व से बचने के लिए, एक पूरी तरह से नया संगठन बनाने के बजाय शिक्षा निदेशालय के भीतर एक अलग व्यावसायिक विंग की स्थापना की जाती है। शिक्षा निदेशालय की व्यावसायिक शिक्षा विंग को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों और शैक्षिक प्रशासकों के विशेषज्ञों के मिश्रण से तैयार किया जाता है।

पूर्णकालिक आधार या विभिन्न विभागों/संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त उनकी सेवाएं। निदेशालय के इस व्यावसायिक विंग का आकार राज्य और अन्य स्थानीय विचारों में शामिल छात्रों की आबादी पर निर्भर करता है।

इस विंग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं–

- राज्य और जिला स्तर की समितियों का समन्वय करना।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए संस्थानों का चयन करना।
- सेवाकालीन (इन–सर्विस) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था करना।
- व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की देखरेख करना।
- शिक्षकों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करना।
- व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने और समन्वय करने के लिए छात्रों की नियुक्ति करना।
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।
- राज्य निदेशालय द्वारा प्रदर्शन किए जाने वाले कार्यों को करने के लिए व्यवस्था करना।

तालिका : व्यावसायिक शिक्षा विंग के लिए एमजीएम पैटर्न

पोस्ट (Posts)	संख्या (Number)
टपर निदेशक (Additional Director)	1
संयुक्त निदेशक (Joint Directors)	2
उप. निदेशक (Dy. Director)	1
सहा. निदेशक (Asst. Directors)	2
अनुसंधान सहायक (Research Assistant)	1
अनुभाग अधिकारी (Section Officer)	1
सहायकों (Assistants)	4
लेखाकार मुनीम (Accountant)	1
आशुलिपिक जीआर. सी (Stenographers Gr. C)	3
आशुलिपिक जीआर. डी (Stenographers Gr. D)	3
एलडीसी (LDC's)	3
चपरासी (Peons)	5

तालिका : व्यावसायिक शिक्षा विंग के लिए स्टाफिंग पैटर्न

पोस्ट (Posts)	संख्या (Number)
टपर निदेशक (Additional Director)	1
संयुक्त निदेशक (Joint Directors)	2
उप. निदेशक (Dy. Director)	1
सहा. निदेशक (Asst. Directors)	2
अनुसंधान सहायक (Research Assistant)	1
अनुभाग अधिकारी (Section Officer)	1
सहायकों (Assistants)	4
लेखाकार मुनीम (Accountant)	1
आशुलिपिक जीआर. सी (Stenographers Gr. C)	3
आशुलिपिक जीआर. डी (Stenographers Gr. D)	3
एलडीसी (LDC's)	3
चपरासी (Peons)	5

टिप्पणी

तालिका : व्यावसायिक शिक्षा विंग के लिए स्टाफिंग पैटर्न

पोस्ट (Posts)	संख्या (Number)
उप. निदेशक (Dy. Director)	1
सहा. निदेशक (Asst. Directors)	3
अनुसंधान सहायक (Research Assistant)	2
अधीक्षक (Superintendent)	1
सहायकों (Assistants)	2
लेखाकार मुनीम (Accountant)	1
स्टेनोग्राफर जीआर. सी (Stenographers Gr. C)	2
यूडीसी (UDC's)	3
चपरासी (Peons)	2

SCERT / SIE में राज्य स्तर पर कार्यक्रम को अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग विंग स्थापित किया जाना है। इस व्यावसायिक विंग से निम्नलिखित विशिष्ट कार्य करने की अपेक्षा की जाती है–

- माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / जूनियर कॉलेज शिक्षा बोर्ड के साथ समन्वय में पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री विकसित करना।
- जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण करने के लिए– व्यावसायिक शिक्षा के लोकप्रियकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम विकसित करना।
- पाठ्यक्रम विकसित करना।
- अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से इन–सर्विस शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- आरसीई, कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए,माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विकास के सहायता प्रदान करना।
- विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित राज्य विभाग– प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्लेसमेंट गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के मामलों पर व्यावसायिक शिक्षा की राज्य परिषद को अकादमिक सहायता प्रदान करना।

SCERT की/SIE की तालिका आगे इंगित की गई है–

तालिका : व्यावसायिक विंग के लिए स्टाफिंग पैटर्न

पोस्ट (Posts)	संख्या (Number)
प्रोफेसर (प्रमुख विंग के प्रमुख) (Professor Head of the Vocational Wing)	1
व्याख्याता (शैक्षिक योजना) (Lecturer Educational Plainning)	1
प्रपाठक (Readers)	5
व्याख्याता (Lectureres)	5
कंसल्टेंट्स (Consultants) –सहायक कर्मचारी (Supporting Staff)	5
स्टेनोग्राफर जीआर.सी (Stenographers Gr. C)	5
कार्यालय अधीक्षक (Office Superintendent)	1
लेखाकार मुनीम (Accountant)	1
स्हायक (Assistants)	2
एलडीसी (LDC's)	2
चपरासी (Peons)	4

टिप्पणी

(घ) जिला स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना

जिला व्यावसायिक शिक्षा समिति (DVEC) का गठन किया जाता है जिसे जिला शिक्षा बोर्ड (DBE) की उप–समिति के रूप में समामेलित किया जाता है। DVEC सभी संबंधित जिला स्तर के अधिकारियों या उनके नुमाइंदों और नियोक्ताओं संगठनों, व्यावसायिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों और माता–पिता शिक्षक संघ के प्रतिनिधि के साथ–साथ व्यावसायिक प्रमुखों से बना है।

DVEC जिला सचिवालय के व्यावसायिक शिक्षा विभाग में स्थित अपने सचिवालय के साथ निम्नलिखित कार्य करता है–

- जिले में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना।
- जिले में शिक्षा निदेशालय, राज्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ संबंध बनाए रखता है।
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान करता है।
- व्यावसायिक स्कूलों के लिए स्थानों की पहचान करता है।
- व्यावसायिक छात्रों के नौकरी प्रशिक्षण और शिक्षुता पर सुविधा संस्थानों को उद्योग से जोड़ता है।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान और इसके बाद व्यावसायिक उत्पादों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है।
- गुणवत्ता और निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की समीक्षा करता है।

टिप्पणी

तालिका : जिला शिक्षा कार्यालय का स्टाफिंग पैटर्न

पोस्ट (Posts)	संख्या (Number)
अतिरिक्त डी.ई.ओ. (Additional DEO)	1
उप. निदेशक (Asst. DEO)	2
अधीक्षक (Superintendent)	1
अनुसंधान सहायक (Research Assistant)	2
स्टेट. सहायक (Stat. Assistant)	1
लेखाकार मुनीम (Accountant)	1
यूडीसी (UDC)	1
एलडीसी (LDC)	2
स्टेनोग्राफर जीआर. डी (Stenographer Gr. D)	1
चपरासी (Peons)	1

पाठ्यक्रम (Curriculum)

पाठ्यक्रम सामाजिक रूप से प्रासंगिक आधारित है और इसका अर्थ स्व या वेतन रोजगार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित पाठ्यक्रम डिजाइन में निम्नलिखित घटक होते हैं–

1. भाषाएं 15%
2. सामान्य फाउंडेशन 15%
3. व्यावसायिक सिद्धांत और 70%

   अभ्यास (पर–सहित नौकरी प्रशिक्षण)

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में नौकरी प्रशिक्षण पर है। कौशल और दक्षताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक है। NCERT द्वारा विकसित GFC पाठ्यक्रम को 2 चरण में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अनिवार्य घटक के रूप में अनुशंसित किया गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है–

1. कृषि
2. व्यापार और वाणिज्य
3. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी
4. स्वास्थ्य और पैरा–चिकित्सा सेवाएं
5. गृह विज्ञान
6. सेवाएं।

एनसीईआरटी ने न्यूनतम व्यावसायिक दक्षताओं का विकास किया है।

ये पाठ्यक्रम सूची नौकरी के अवसर, नौकरी विवरण, नौकरी विश्लेषण, अंकन योजना, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, सामग्री–सिद्धांत और अभ्यास, उपकरणों की सूची और संदर्भ पुस्तकों के आधार पर विशिष्ट दक्षताएं हैं।

(ङ) संस्थागत स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की प्रबंधन संरचना

टिप्पणी

विद्यालय स्तर पर एक वरिष्ठ स्टाफ सदस्य प्रबंधन का प्रभारी होता है।

मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य : माध्यमिक स्कूलों के प्रशासन के लिए संस्थानों के प्रमुख के रूप में मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य होते हैं। हाई स्कूलों के लिए मुख्य अध्यापक, मुख्य अध्यापिका होते हैं और उन्हें दूसरे मुख्य अध्यापक का पूरा सहयोग मिलता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रमुख को प्रधान कहा जाता है और उन्हें उप–प्राचार्य द्वारा सहयोग किया जाता है।

मुख्य अध्यापक : मुख्य अध्यापक को स्कूल में सात प्रमुख भूमिकाएं निभानी होती हैं– (1) योजना में भूमिका (2) स्कूल संगठन में भूमिका (3) शिक्षण भूमिका (4) पर्यवेक्षण में भूमिका (5) मार्गदर्शन में भूमिका (6) संबंध बनाए रखने में भूमिका (7) सामान्य प्रशासन में भूमिका।

संस्थागत प्रमुख निम्नलिखित कार्य करता है–

प्रधानाचार्य सीधे स्कूल से जुड़ा होता है, इसलिए स्कूल के कार्यक्रमों की सफलता उस पर निर्भर करती है। वर्ष के दौरान उनके कार्यों का अध्ययन इन शीर्षकों के तहत किया जा सकता है–

(अ) सत्र की शुरुआत से पहले

(ब) सत्र के दौरान, और

(स) सत्र के अंत में।

(अ) **सत्र की शुरुआत से पहले**– यह वह समय है जब मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य अपने शिक्षकों की मदद से पूरे सत्र के कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं। वह शैक्षणिक वर्ष के लिए योजना बनाता है, वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रवेश और अन्य कार्यों को अधिकतम करने के लिए।

(ब) **सत्र के दौरान**– सत्र के दौरान मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य नियमित कार्यों, अनुशासन कार्यों और अन्य कार्यक्रमों को करने में व्यस्त हैं।

(स) **सत्र के अंत में**– छात्रों को अगली उच्च कक्षाओं में पदोन्नत करने के लिए वह बोर्ड परीक्षा और अन्य स्कूल परीक्षाओं के उचित संचालन के लिए व्यस्त हैं।

- परिणामों की घोषणा और वार्षिक रिपोर्ट को प्रतिबिंबित करने के लिए, उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं।
- नए विषय शिक्षकों के शामिल होने की व्यवस्था करना।
- उच्च अधिकारियों के आदेश, निर्देशों और निर्णय को लागू करना।
- विभिन्न सहकारी गतिविधियों की व्यवस्था करना।
- खेल और खेल गतिविधियों के लिए प्रावधान करना।
- दैनिक गतिविधियों को सफल बनाने के लिए।

टिप्पणी

- स्कूल की इमारत को बनाए रखने के लिए, स्कूल के फर्नीचर, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं उनके मुख्य कार्य हैं।
- कार्यालय के अभिलेखों का ध्यान रखना और इनका सूक्ष्म निरीक्षण करना।
- शिक्षकों का नेतृत्व करना और उन्हें कुछ कार्यों में मार्गदर्शन देना।
- परीक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था करना।

सार– 1947 में आजादी के बाद से, वृहद योजना (मैक्रो–प्लानिंग) से लेकर सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लानिंग) तक, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन की प्रक्रिया में 'केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण' की ओर एक बदलाव आया है। जबकि स्कूली शिक्षा राज्यों द्वारा ही नियोजित और क्रियान्वित की जाती है। जिले को नियोजन और शैक्षिक प्रशासन की सबसे उपयुक्त रूप में स्वीकार किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन के लिए जिला परियोजना समन्वयक द्वारा और अधिक समन्वित किया जाता है, जहां प्रत्येक जिले को छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है।

2.3.2 विद्यालय संगठन और प्रबंधन योजना, निष्पादन और निर्देशन, कक्षा, शॉप फ्लोर और नौकरी प्रशिक्षण प्रबंधन

विद्यालय संगठन और प्रबंधन योजना के अंतर्गत तथ्यों को क्रमशः इस प्रकार समझा जा सकता है–

विद्यालय संगठन और प्रबंधन नियोजन/योजना (School organization and management planning)

नियोजन/योजना, संगठन और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शिक्षक विकास से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए प्रमुख के संदर्भ में महत्व को मानता है। यह कुछ खास पहलुओं में महत्वपूर्ण है जहां निजी बनाम सरकारी संस्थान, इक्विटी और समानता, बुनियादी ढांचा, हस्तक्षेप, पाठ्यक्रम क्षेत्र, रचनात्मकता और नवाचार, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, बजट और व्यक्तिगत विकास को योजना और संगठन में उचित ध्यान दिया जाता है।

संगठन नियोजन/योजना को अस्तित्व में लाने का एक साधन है। संगठन लोगों की योजना और प्रयासों से सीधे जुड़ा हुआ है। यह एक माध्यम है, जिसके माध्यम से लक्ष्य और उद्देश्य प्रशासन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

स्टेनली वेंस के अनुसार 'प्रबंधन केवल पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए मानव की कार्रवाई पर निर्णय लेने और नियंत्रण की प्रक्रिया है।

प्रबंधन एक कला और एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें कौशल का अनुप्रयोग शामिल है और यह एक विज्ञान है क्योंकि यह प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से विकसित ज्ञान का एक व्यवस्थित शरीर है। स्कूल प्रबंधन मानव संसाधनों, भौतिक स्रोतों, सिद्धांतों और अवधारणाओं के इष्टतम उपयोग के माध्यम से विकास की दिशा में स्कूल का नेतृत्व करने की एक प्रक्रिया है जो स्कूल के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन उन सभी के बीच उचित समन्वय और समायोजन भी करता है।

स्कूल के भौतिक संसाधन प्रबंधन का सीखने के वातावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यह शैक्षिक परिणामों का एक प्रमुख निर्धारक है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि

स्कूल भौतिक संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को, स्कूल की संपत्ति को बुनियादी शिक्षा सेवा वितरण मानकों और रणनीतियों से जोड़कर स्कूल सुधार योजना के साथ संरेखित करें। सुविधा रखरखाव शिक्षण और सीखने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। इसमें शिक्षण और सीखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल है।

टिप्पणी

स्कूल प्रबंधन के उद्देश्य

स्कूल प्रबंधन के निम्न उद्देश्य हैं–

1. स्कूल संगठन में शामिल प्रक्रियाओं के उद्देश्यों को निर्धारित करना।
2. कक्षा प्रक्रियाओं के लिए समन्वित गतिविधियों की एक प्रणाली तैयार करना।
3. स्कूल में शामिल प्रक्रियाओं के लिए गुणवत्ता सूचकांक का निर्धारण करना।
4. स्कूल प्रबंधन को नेतृत्व, टीम निर्माण, सहयोग, लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता होती है।

नियोजन/योजना शैक्षिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आयोजन, स्टाफ, निर्देशन और नियंत्रण के साथ प्रभावी योजना की आवश्यकता होती है।

वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रियाओं पर विश्वास करने के लिए योजना एक प्रतिबद्धता है। टेरी के अनुसार, 'नियोजन वांछित तथ्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है और प्रस्तावित गतिविधियों के विजुअलाइजेशन और औपचारिकता में भविष्य के बारे में मान्यताओं के चयन और तथ्यों का निर्माण और उपयोग है।'

मैकफारलैंड नियोजन को 'कार्यकारी कार्रवाई की एक अवधारणा के रूप में परिभाषित करता है जो प्रकृति के परिवर्तन की दिशा और दिशा को प्रभावित करने, प्रत्याशित करने और नियंत्रित करने के कौशल का प्रतीक है।'

नियोजन/योजना शिक्षा के लिए आवश्यक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण गुण है। योजना एक नीति वक्तव्य है और समान रूप से आवश्यक है कि नीति बनाने में मदद मिले। नियोजन/योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य की कार्रवाई को निर्धारित करती है और प्रबंधन के सभी स्तरों पर की जाती है। यह निरंतर है और इसमें धारणा, विश्लेषण और वैचारिक मुद्दे की प्रक्रिया शामिल है।

संगठन नियोजन/योजना को अस्तित्व में लाने का एक साधन है। यह एक मीडिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों और प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रबंधन एक कला और एक विज्ञान है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया है और कार्रवाई पर नियंत्रण है।

नियोजन/योजना की विशेषताएं

नियोजन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. नियोजन किसी दिए गए बिंदु पर व्यवहार के बजाय एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करती है।

टिप्पणी

2. नियोजन मुख्य रूप से भविष्य को देखने से संबंधित है, जिसके लिए भविष्य की स्थिति का पूर्वानुमान आवश्यक है।
3. नियोजन में कार्रवाई के उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन शामिल है।
4. योजना प्रबंधन के सभी स्तरों पर की जाती है और भविष्य की कार्रवाई के साथ संबंधित है।
5. नियोजन लचीला है क्योंकि प्रतिबद्धता भविष्य की परिस्थितियों पर आधारित है जो हमेशा गतिशील होती हैं।
6. नियोजन एक सतत प्रबंधकीय कार्य है जिसमें धारणा, विश्लेषण, वैचारिक विचार, संचार, निर्णय और कार्रवाई की प्रक्रिया शामिल है।
7. एक अच्छी योजना का उद्देश्य भौतिक सुविधाओं, शिक्षकों, पुस्तकालय सेवाओं, पाठ्यचर्या, सह–पाठयक्रम गतिविधियों, सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी और इस तरह के सुधार का उद्देश्य शामिल है।

नियोजन/योजना सभी प्रबंधन की नींव है। शिक्षा में यह शिक्षकों को शामिल करता है, छात्रों को कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सीखने के अनुभवों के बारे में सीखने और शिक्षण संबंधी निर्णय लेने के बारे में पाठ्यक्रम संबंधी निर्णय लेना। सीखने की गतिविधियों का निर्धारण एक प्रमुख नियोजन कार्य है। नियोजन आमतौर पर छात्रों की उपस्थिति के बिना किया जाता है और यहां तक कि जब छात्र प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो शिक्षकों की ओर से पूर्व नियोजन आवश्यक है। जबकि नियोजन अप्रत्याशित घटनाओं को समाप्त नहीं कर सकता है, बिना घटनाओं के सभी अनपेक्षित हो जाते हैं।

निष्पादन और निर्देशन (Execution and Direction)

निष्पादन (Execution) में एक संस्था की नींव निहित है। निष्पादन न केवल बताता है कि संसाधनों की क्या आवश्यकता है, बल्कि खरीद के स्रोत भी बताता है। इन संसाधनों में भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कर्मियों जैसे गैर–भौतिक संसाधन, और छात्रों और माता–पिता जैसे अन्य हितधारकों और दृष्टि, मिशन वक्तव्य, विचारधारा और मूल्यों जैसे भौतिक संसाधन शामिल हो सकते हैं।

निर्देशन (Directing) लोगों को प्रभावित करने की कला या प्रक्रिया है कि वे स्वेच्छा से समूह लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह उत्साह और आत्मविश्वास के साथ काम करने की इच्छा के विकास पर केंद्रित है, कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करता है, और समन्वित तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करता है। यह जिम्मेदारी और जवाबदेही का निर्धारण करते हुए नेतृत्व अभ्यास करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

प्रशासनिक कार्यकारी निकाय व्यवस्थित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों की व्यवस्था करता है और उनका उपयोग करता है। निर्देशन संस्था का विजन और मिशन स्टेटमेंट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी खोज में संस्था को निर्देशित करने का कार्य करता है। शैक्षिक प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम निर्माण और अकादमिक नियोजन के दौरान निर्देशों को बरकरार रखा जाता है।

टिप्पणी

सफल रणनीति निष्पादन से प्राप्त मूल्य में औसत दर्जे की वृद्धि करते हैं। वे इस प्रणाली में छह चरणों को रेखांकित करते हैं–

1. रणनीति विकसित करें,
2. रणनीति की योजना बनाएं,
3. संगठन को संरेखित करें,
4. योजना संचालन,
5. मॉनिटर करें और जानें,
6. परीक्षण और अनुकूलन।

कक्षा प्रबंधन (Classroom)

कक्षा प्रबंधन, शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कक्षा में जो होता है वह स्कूली शिक्षा का प्रतिबिंब है। कक्षा प्रबंधन निस्संदेह शिक्षकों के प्रबंधकीय कौशल पर निर्भर करता है। कक्षा प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्य है जिसमें शिक्षकों को नियोजन जैसे विभिन्न कार्यों को करने की आवश्यकता होती है; आयोजन, समन्वयय निर्देशन; नियंत्रित, संवाद स्थापित; गृह व्यवस्था (हाउसकीपिंग) और पोषण।

कक्षाओं को अब बच्चों के बीच सीखने की सुविधा के लिए केंद्र माना जाता है। NCF–2005 शिक्षकों को सीखने के सूत्रधार मानता है। छात्रों को रचनात्मक शिक्षार्थियों के रूप में माना जाता है। यह शिक्षक के हिस्से पर रचनात्मक सोच, योजना, संगठन और कक्षा प्रक्रियाओं के प्रबंधन की मांग करता है। सीखने और इस तरह के लिए एक उत्साहजनक वातावरण पैदा करना। इसलिए, यह बहुत आवश्यक है, छात्र शिक्षकों को इन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे प्रभावी कक्षा प्रबंधक बन सकें।

कक्षा की तैयारी के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है–

- बैठने की पर्याप्त संख्या में सीटें होनी चाहिए और ठीक से व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षक शिक्षार्थियों की देखरेख कर सके।
- प्रकाश और वायु संचार (वेंटिलेशन) पूरे क्लास रूम की जगह के लिए उपयुक्त और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सीखने और इस तरह के लिए एक उत्साहजनक वातावरण पैदा करना। इसलिए, यह बहुत आवश्यक है, छात्र शिक्षकों को इन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे प्रभावी कक्षा प्रबंधक बन सकें।

शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि सार्थक सीखने की प्रक्रिया का आयोजन करना, छात्रों को उनकी क्षमताओं के साथ बाहर आने के लिए एक मंच बनाना, छात्रों को जानना, छात्रों को प्रेरित करना, प्रत्येक छात्र की उपलब्धियों के बारे में बताना होता है।

कक्षा प्रबंधन में तीन बुनियादी कार्य शामिल होते हैं–

1. नियोजन, जिसके द्वारा उद्देश्यों, प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है।
2. नियंत्रण, जिसके द्वारा योजनाओं के प्रदर्शन की अनुरूपता का आश्वासन दिया जाता है।

टिप्पणी

3. संचार, जिसके द्वारा सूचना को आंतरिक और बाह्य दोनों में स्थानांतरित किया जाता है।

स्कूल प्रबंधनों का उद्देश्य

- स्कूल संगठन और प्रबंधन में शामिल प्रक्रियाओं के उद्देश्यों का निर्धारण करना।
- कक्षा प्रक्रियाओं के लिए समन्वित गतिविधियों की एक प्रणाली तैयार करना।
- स्कूल में शामिल प्रक्रियाओं के लिए गुणवत्ता सूचकांक का निर्धारण करना।
- स्कूल प्रबंधन को नेतृत्व, टीम निर्माण, सहयोग, लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, कक्षा प्रबंधन–

- एक प्रक्रिया है।
- एक सामाजिक प्रक्रिया है।
- समूह के प्रयास को शामिल करता है।
- एक अलग इकाई है।
- अधिकार की प्रणाली है।

कक्षा प्रबंधन निस्संदेह शिक्षकों के प्रबंधकीय कौशल पर निर्भर करता है। शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है।

कार्यशाला (शॉप फ्लोर) (Shop Floor)

शॉप फ्लोर एक बड़े संगठन के भीतर एक छोटा संगठन है। यह व्यावसायिक उद्यम का एक सबसेट है जहां सभी मूर्त उत्पादन होता है। शॉप फ्लोर के भीतर विभिन्न छोटे विभाग, संचालन और जिम्मेदारियां हैं।

शॉप फ्लोर स्टाफ के सदस्य कई कर्मी हैं जो शॉप फ्लोर पर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। आइए अब समझते हैं कि इन कर्मियों में से प्रत्येक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं।

1. **शॉप फ्लोर मैनेजर**– प्रबंधक शॉप फ्लोर पर कर्मचारियों और संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। वह नए कर्मचारियों और अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने, उन्हें कार्य संस्कृति से परिचित कराने और उनकी कार्य–संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए भी जिम्मेदार है। शॉप फ्लोर प्रबंधक को उत्पादन प्रबंधक के साथ हाथ से काम करने की आवश्यकता होती है।
2. **पर्यवेक्षक**– पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है कि वह शॉप फ्लोर पर परिचालन का ट्रैक रखे और कुछ गलत होने पर संबंधित व्यक्ति के ध्यान में लाए। वह शॉप फ्लोर के सहायक के रूप में काम करता है और उसका मुख्य कर्तव्य चीजों को प्राप्त करना है।
3. **फोरमैन**– वे औपचारिक प्रशिक्षण के बजाय नौकरी में अनुभव के आधार पर अपना स्थान प्राप्त करते हैं। वे वही कार्य करते हैं जो पर्यवेक्षक शॉप फ्लोर प्रबंधक के तहत करते हैं। वे दूसरों को सिखाते हैं कि किसी कार्य को सही और कुशलता से कैसे किया जाए। वे डिजाइन या रेखाचित्र पढ़ते हैं और उनका

पालन करते हैं। यदि आवश्यक हो तो वे परिवर्तन का सुझाव दे सकते हैं। वे मशीनरी और उपकरणों के लिए निजी विक्रेताओं से संपर्क करते हैं। वे संगठन के बाहर अन्य विभागों या एजेंसियों के साथ काम करते समय संपर्क के बिंदु भी हैं।

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा सीखने वाले को न केवल अवधारणाओं को सीखने में मदद कर सकती है, बल्कि स्कूल और विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्हें लागू करने में भी मदद कर सकती है। क्या मायने रखता है जो उन्हें लागू करने और सीखने का मौका दे रहा है, न कि विफलता या सफलता दर। वास्तव में, विफलताएं छात्रों को और भी बेहतर बनाती हैं। एक शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से, यह उसे शॉप फ्लोर ज्ञान लागू करने का अवसर देता है और उसे उसकी क्षमताओं और रुचियों की खोज करने की अनुमति देता है। एक उद्योग के दृष्टिकोण से, यह प्रतिभा को जल्दी पहचानने में मदद करता है। कौशल प्रशिक्षण को स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में कैसे शामिल किया जा सकता है।

शॉप फ्लोर ट्रेनिंग से तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो इन–हाउस, प्लास्टिक निर्माण मशीनरी या प्लांट फ्लोर पर किया जाता है। यह स्थिति के प्रासंगिक जोखिम पर निर्भर करता है, साथ ही साथ अनुभवी लोग जो सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं।

चूंकि उनके खाके या नक्शे (लेआउट) बहुत भिन्न हो सकते हैं। शॉप फ्लोर प्रशिक्षण सीखने वालों को यह पहचानने में सक्षम बनाता है कि कौन से नियंत्रण कहां हैं, हालांकि इस तरह के नियंत्रण की आवश्यकता क्या है और क्यों होती है, इसे समझने के लिए पूर्व ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, और वे कैसे प्रभावित करते हैं। एक बार सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद काम करने के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक कौशल के बीच लिंक अपेक्षाकृत आसानी से बनाया जा सकता है।

शॉप फ्लोर प्रशिक्षण कार्यशाला नाम के रूप में ही बताती है कि यह एक ऐसी जगह है जहां व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जब हम व्यावहारिक कहते हैं तो यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षण दिया गया कौशल अधिक कौशल आधारित है। इसलिए जब हम किसी विशेष व्यापार के लिए मशीनरी और उपकरण प्राप्त करते हैं, तो यह एक संबंधित प्रशिक्षक के लिए एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। इसलिए ट्रेनर एक अच्छी हाउसकीपिंग के सिद्धांत को अपनाता है।

शॉप फ्लोर प्रबंधन कमजोर उत्पादन के संदर्भ से उभरता है, निश्चित रूप से इसके कई अन्य कमजोर तरीकों के लिंक हैं। उपर्युक्त घटक स्वयं आंशिक रूप से दृश्य प्रबंधन और प्रदर्शन प्रबंधन जैसे अन्य कमजोर सिद्धांतों के घटकों के रूप में जाने जाते हैं।

शॉप फ्लोर प्रबंधन के विश्लेषण के उद्देश्यों और घटकों के परिणाम, यह मानव संसाधन के विषयों में बहुत प्रभाव दिखाते हैं। फिर भी, अब तक इस क्षेत्र में, यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों के विशिष्ट प्रशिक्षण या योग्यता का क्या मतलब है। उद्योग के भीतर प्रशिक्षण जैसी तकनीक मुख्य रूप से श्रमिकों के त्वरित अनुकूलन के लिए नौकरी के निर्देशों की आपूर्ति पर केंद्रित है लेकिन श्रमिकों के निरंतर विकास की उपेक्षा करती है।

टिप्पणी

शॉप फ्लोर के क्षेत्र

इसमें छह मुख्य क्षेत्र शामिल हैं–

- हर एक कर्मचारी को सशक्त बनाना और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना,
- शॉप फ्लोर पर अग्रणी कर्मियों की उपस्थिति,
- विजुअलाइजेशन की विभिन्न अवधारणाओं का उपयोग करते हुए,
- मिनी कारखानों की तरह नए संगठनों को शुरू करना,
- सुधार और समस्या समाधान प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना,
- शॉप फ्लोर पर सक्षमता विकास को सुविधाजनक बनाना।

शॉप फ्लोर पर तकनीकी कौशल प्रशिक्षण की मांग के संबंध में एक दिलचस्प प्रवृत्ति विकसित हो रही है। यह प्रशिक्षण आमतौर पर नींव कौशल जैसे कि दुकान, गणित, ब्लू प्रिंट रीडिंग और व्याख्या, और माप विद्या (मेट्रोलॉजी) में प्रशिक्षण या सटीक माप उपकरणों के उपयोग पर केंद्रित है।

ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण (नौकरी का प्रशिक्षण) प्रबंधन (On-the-Job Training management)

व्यावसायिक शिक्षा एक शैक्षणिक प्रणाली है जो छात्रों को निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए तैयार करना चाहती है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का हिस्सा होने के नाते, व्यावसायिक उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ–साथ नौकरी हासिल करने के महान विचार के साथ कल्पना की गई थी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और विशेष रूप से व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना एक बढ़ती और बहुत सकारात्मक प्रवृत्ति है। विशेष व्यवसायों या ट्रेडों के लिए कौशल प्रशिक्षण के एक नियमित भाग के रूप में मान्यता और नियंत्रण का शिक्षण बाद में इस तरह के ज्ञान को लागू करने की कोशिश करने से कहीं अधिक प्रभावी है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधारणा महात्मा गांधी के विचारों से उत्पन्न हुई, जिनका आधुनिक युग में वास्तविक महत्व है। प्रत्येक मनुष्य में पर्यावरण के अनुसार एक जन्मजात प्रतिभा होती है जिसमें उसका समाजीकरण होता है या उसे ऊपर लाया जाता है। इसलिए जब कोई पढ़ाई के दौरान अपने जुनून और प्रतिभा के अनुसार पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो उसके जीवित रहने के लिए कमाई करने में कोई समस्या नहीं होगी। व्यावसायिक शिक्षा के लिए, किसी व्यक्ति के हितों और शक्तियों की पहचान करना, जबकि वह सीखने की अवधि में है, अधिक महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा जीवन कौशल प्रदान करती है जिसे युवाओं को काम की दुनिया में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण (OJT) कार्य वातावरण में विशिष्ट कार्य करने के लिए शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं को प्रदान करता है।

व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए, शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थिति में तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में काम करने के लिए व्यावसायिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक सेवा केंद्र या मरम्मत केंद्र या उत्पादन इकाई में लाया जाता

टिप्पणी

है। ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण एक प्रभावी शिक्षण विधि है जिसका उपयोग व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को विद्यालयों में सीखे गए विषयों पर सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ के माध्यम से कार्य अनुभव के साथ तैयार किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा में पाठ्यक्रम लेनदेन के तीन प्रमुख घटक हैं–

(1) स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी कौशल प्रशिक्षण

(2) सहयोगी संस्थानों में विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण और

(3) वास्तविक विदेशी परिस्थितियों में ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण

ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण में वास्तविक काम करने की स्थिति के तहत पहले ज्ञान और अनुभव प्रदान करने का लाभ है। प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का एक औपचारिक तरीका है जो नौकरी की शिक्षा के साथ नौकरी की शिक्षा पर निकट पर्यवेक्षण को जोड़ती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योजना पहले से बनाई गई है और हर दिन सावधानीपूर्वक कदम उठाए जाते हैं। ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण आमतौर पर स्कूल के इलाके के आसपास और आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों में किया जाता है। सरकार ने प्रत्येक स्कूल को ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण प्रोग्राम (स्कूल से छात्रों को ओजेटी सेंटर तक दैनिक भत्ते से संबंधित अनुरक्षण शिक्षक (एस्कॉर्टिंग टीचर्स)/व्यावसायिक शिक्षक (वोकेशनल टीचर्स) से संबंधित विभिन्न खर्चों को कवर करने के लिए एक निर्दिष्ट राशि आवंटित की है।

व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना (VHSE) का उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है, कौशल निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करके यह औद्योगिक वातावरण में काम करने और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरी प्रशिक्षण पर जोर देता है।

अग्रवाल (2005) ने कहा कि, उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जो लोग इस चरण को पूरा करते हैं और काम की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं उन्होंने व्यवसाय से संबंधित कुछ कौशल हासिल किए हैं और रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। हाथों पर यह प्रशिक्षण श्रमिकों को उनके विशिष्ट कार्य वातावरण के भीतर नए कौशल और ज्ञान को सीखने में मदद करने में और कक्षा में सीखने के कार्य को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। (लवे एंड वेन्जर, 1991)

ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण के लाभ

ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण के कुछ लाभ निम्न हैं–

1. यह सीधे काम से संबंधित है।
2. वे अकसर अनौपचारिक होते हैं।
3. यह सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि यह अनुभव से सीखता है।
4. पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है जो छात्रों को व्यावहारिक जटिलताओं को जानने और समझने में मदद करता है और उन्हें अच्छी तरह से सुसज्जित, आत्मविश्वास से भरपूर और प्रेरित बनाता है ताकि वे आसानी से किसी भी नौकरी पर ले जा सकें।

टिप्पणी

5. यह योजनाबद्ध और संगठित कार्य अनुभव की एक विधि है। शैक्षिक संस्थान एक ओजेटी कार्यक्रम की योजना बना रहा है और एक स्थापित या संगठित उद्योग या कार्यस्थल में प्रशिक्षण दिया जाता है।
6. यह छात्र को कक्षा में पढ़ाए गए सिद्धांत को आत्मसात करने देता है और प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होने के बाद, इसे वास्तविक कार्य स्थान पर लागू करता है।
7. यह छात्र को एक अनुभव प्रदान करता है जिसकी देखरेख की जाती है।
8. कक्षा और प्रयोगशाला के भीतर सिखाए गए सिद्धांत विषय आम तौर पर छात्र को वास्तविक कार्य स्थिति तक पहुंच के लिए बहुत कम जगह देते हैं। लेकिन छात्र को जो ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण मिला, उससे उसे काम के दौरान होने वाले परिणाम और पेचीदगियों को महसूस करने में मदद मिलती है।
9. यह छात्र को माल और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में भाग लेने का अवसर देता है जो कुछ लाभदायक नौकरियों की सुरक्षा की ओर जाता है।
10. सीखने या प्रशिक्षण के समय, छात्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक भागीदारी से प्रेरित होता है, और आत्मविश्वास हासिल करता है।
11. मनोवैज्ञानिक रूप से छात्र को उद्यमिता के गुणों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह स्व–रोजगार लेने की स्थिति में हो।
12. यह छात्र की नौकरी और समझ के निरंतर मूल्यांकन में मदद करता है क्योंकि यह एक अनुभवी कार्यकर्ता और कार्यस्थल पर एक शिक्षक के मार्गदर्शक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कौशल पाठ्यक्रम में जैसे, एग्रो मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन एंड टेक्नोलॉजी एयर कंडीशनिंग, पॉलिमर प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रौद्योगिकी, कृषि – फसल स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि विज्ञान और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय और कृषि सेवा, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, ईसीजी और ऑडियोमेट्रिक प्रौद्योगिकी, बुनियादी नर्सिंग और प्रशामक देखभाल, दंत चिकित्सा प्रौद्योगिकी, जैव–चिकित्सा प्रौद्योगिकी, फिजियोथेरेपी, शारीरिक शिक्षा, पशुधन प्रबंधन, डेयरी प्रौद्योगिकी, समुद्री मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, एक्वाकल्चर, समुद्री प्रौद्योगिकी, सौंदर्यशास्त्र और सौंदर्य चिकित्सा, फैशन और परिधान डिजाइनिंग, क्रेच और प्री स्कूल प्रबंधन, यात्रा और पर्यटन, लेखा और कराधान, ग्राहक संबंध बैंकिंग और बीमा सेवाएं, विपणन और वित्तीय सेवाएं। कम्प्यूटरीकृत कार्यालय प्रबंधन और खाद्य और रेस्तरां प्रबंधन शामिल है।

यह स्पष्ट है कि ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण, जो वास्तविक जीवन प्रशिक्षण के साथ व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को प्रदान करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है। ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं, बल्कि अधिकांश विकसित देशों, जैसे यूनाइटेड किंगडम, चीन, रूस, आदि में प्रशिक्षण का सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसकी प्रभावशीलता मौजूदा कार्यस्थल उपकरणों के उपयोग पर आधारित है। ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना और प्रबंधित

करना आसान है और यह नए कार्यस्थल के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया को सरल करता है। व्यावहारिक कार्यों के लिए ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। यह सस्ती है, और इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है जो आमतौर पर एक विशिष्ट नौकरी के लिए उपयोग किया जाता है।

टिप्पणी

2.3.3 खरीद, भंडारण, अभिलेख (रिकॉर्डिंग), सामग्री और उपकरण का रखरखाव

क्रय / खरीद (Procuring) एक व्यापक शब्द है। इसमें उत्पादन, भंडार, यातायात, प्राप्ति, निरीक्षण और निस्तारण के लिए आवश्यक उत्पादों की खरीद शामिल है।

एक विशिष्ट खरीद प्रक्रिया में शामिल हैं–

- वस्तुओं और सेवाओं की जरूरतों की पहचान करना।
- आपूर्तिकर्ता खोजना।
- अनुरोधों के प्रस्ताव / कोटेशन (RFP / RFQ)
- आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करना।
- आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत शर्तें।
- उत्पादों / सेवाओं की व्यवस्था करना और प्राप्त करना।
- गुणवत्ता आश्वासन प्रदर्शन करना।
- परिणामों और मार्जिन का विश्लेषण।

खरीद प्रबंधन का महत्व लागत प्रभावी उत्पादन के लिए क्रय आंतरिक आवश्यकताओं को जानने, आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने और उनका चयन करने के लिए जिम्मेदार है, जो किसी उत्पाद का उत्पादन करने या सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री, भागों, आपूर्ति और सेवाओं को प्राप्त करता है।

खरीद का महत्व केवल खरीदे गए सामान की लागत से अधिक है; अन्य महत्वपूर्ण कारकों में माल और सेवाओं की गुणवत्ता और माल या सेवाओं की डिलीवरी का समय शामिल है, दोनों का संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

यदि अधिकारी सौदेबाजी में कुशल हैं तो वे संगठनों के लिए बचत कर सकते हैं और इससे संगठनों को लागत में कटौती करने में मदद मिलेगी और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। खरीद की पहल से इन्वेंट्री को कम करने और विक्रेता चयन और आपूर्तिकर्ता विकास के माध्यम से आने वाले भागों और घटकों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। क्रय भी उत्पाद विकास में आपूर्तिकर्ता की भागीदारी को प्रोत्साहित करके नए उत्पाद विकास का समर्थन करता है।

इस प्रकार एक खरीद योजना तैयार करना एक आवश्यकता है। यह खरीद गतिविधियों की उचित निगरानी और निष्पादन के लिए एक उपकरण है। विश्व बैंक के प्रारूप में परियोजना के हर साल नागरिक कार्यों, उपकरणों की आपूर्ति, माल और संसाधन समर्थन को कवर करने वाली खरीद योजना तैयार की जाएगी। जिन अनुबंधों को वर्ष में सम्मानित किया जाना अपेक्षित है, उन्हें केवल उस वर्ष की खरीद योजना में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी

खरीद प्रक्रिया/दिशानिर्देश मोटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों से मिलकर बनते हैं–

1. आवश्यकता का आकलन
2. खरीद की रणनीति तय करना
3. खरीद का तरीका
4. निविदा दस्तावेज तैयार करना
5. निविदा का विज्ञापन
6. निविदा दस्तावेज जारी करना
7. निविदाओं का खोलना
8. निविदाओं का मूल्यांकन
9. अनुबंध का पुरस्कार, प्रकटीकरण
10. गुणवत्ता आश्वासन
11. खेप के लिए वितरण की अधिसूचना और खेप की प्राप्ति
12. संग्रहण
13. पेटेंट (एकस्व) अधिकार
14. शिकायत निवारण तंत्र
15. अधिप्राप्ति ऑडिट
16. रिकॉर्ड रखना

क्रय करने से खरीदने की प्रक्रिया का वर्णन होता है। यह एक आपूर्तिकर्ता, बातचीत की कीमत की पहचान और चयन, आवश्यकता की सीख है। खरीद, खरीद के व्यापक कार्य का एक तत्व है और इसमें कई गतिविधियां शामिल हैं जैसे कि ऑर्डर करना, शीघ्रता, प्राप्ति और भुगतान। क्रय किसी उत्पाद के उत्पादन या सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री, भागों, आपूर्ति और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। (जॉयस, 2006) खरीद को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, खरीदी गई उत्पाद की सात विशेषताओं के आधार पर बड़ी और छोटी खरीद – मात्रा, विशिष्टता, तकनीकी जटिलता, अनिवार्यता, नाजुकता, परिवर्तनशीलता और आर्थिक मूल्य। (पारिख, 2005)

प्रबंधन (प्रोक्योरमेंट) प्रक्रिया/दिशानिर्देश सामान्य चरणों का एक सेट है जिसमें खरीद लेनदेन को निष्कर्ष के माध्यम से इसके निष्कर्ष तक ले जाया जाता है। ये चरण एक साथ संगठन की खरीद नीति बनाते हैं।

भंडारण (Storing)

भंडारण से प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षक को उचित स्थान पर स्टोर करना होता है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए विस्फोटक और ज्वलनशील वस्तुओं को कुछ दूरी पर रखा जाना चाहिए। भंडारण इस तरह से होना चाहिए कि सामग्री सही समय पर उपयोग के लिए उपलब्ध हो। आपके उपकरण आपके व्यवसाय के सुचारू

रूप से चलने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास उन्हें रखने के लिए कहीं सुरक्षित स्थान आसानी से उपलब्ध हो।

भंडारण योजना

अपनी साइट पर सभी उपकरणों और सामग्रियों को संगृहीत करने के लिए एक योजना बनाएं।

टिप्पणी

- भंडारण से पहले ठीक से धोएं और सुखाएं।
- प्रत्येक आइटम के लिए एक विशिष्ट स्थान निर्दिष्ट करें और तदनुसार स्थान को लेबल करें।
- निश्चित करें कि कार्य क्षेत्र और पैदल मार्ग सभी संगृहीत वस्तुओं से स्पष्ट रखे गए हैं।
- प्रत्येक प्रकार के उपकरणों के लिए एक निर्दिष्ट स्थान हो।
- बड़े क्षेत्र के फर्श पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए टेप या पेंट का उपयोग करें, जैसे कि विनिर्माण सुविधा।
- एक कार्यालय, प्रयोगशाला या इसी तरह की छोटी सेटिंग में, दरवाजे के साथ अलमारियां का उपयोग करें जो सुरक्षित रूप से बंद हो।
- हमेशा संगृहीत वस्तुओं और आग बुझानेवाले के शीर्ष के बीच कम से कम 1.5 फीट जगह छोड़ दें, यदि मौजूद हो।
- सुनिश्चित करें कि सभी स्टैक ठोस हैं और जब भी संभव हो, उन्हें सुरक्षित करें।
- स्व–भंडारण काम में आ सकता है। अपने उपकरणों को सुरक्षित रखना, स्व–भंडारण अकसर आपकी वैन, गेराज या शेड की तुलना में अधिक सुरक्षित विकल्प होता है।
- यदि आप हॉल में या पिछले दरवाजे से अपने उपकरणों को हमेशा के लिए डंप कर रहे हैं तो एक स्व–भंडारण अधिक संतोषजनक समाधान है – घर में निशान, दाग या खरोंच को रोका जाता है।
- यदि आपको हर चीज के लिए एक उचित स्थान मिल गया है तो आपकी किट को दुर्घटनाओं का सामना करने और टिप–टॉप स्थिति में रखने की संभावना कम है। क्षति को रोका जाता है।
- धारदार औजार के साथ उपयोग में न होने पर जैसे चाकू को अच्छी तरह से स्टोर करें।
- आसानी से सुलभ स्थानों में अकसर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को रखें।
- उलझने या रोचकता को रोकने के लिए विद्युत डोरियों को इकट्ठा और सुरक्षित करें।
- नमी संग्रह से बचने के लिए कटिंग बोर्ड को लंबवत संगृहीत किया जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि आप जिन क्षेत्रों में उपकरण स्टोर कर रहे हैं वे साफ, सूखे और भीड़भाड़ वाले नहीं हैं।

टिप्पणी

औजारों और उपकरणों के उचित भंडारण का महत्व

- यह सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ अच्छे व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।
- सामान्य–दुकान और निर्माण क्षेत्रों की उपस्थिति में सुधार करता है।
- रखरखाव के माध्यम से समग्र उपकरण लागत को कम करता है।
- यह भी सुनिश्चित करता है कि उपकरण हाथ में अच्छी मरम्मत में हों।
- (उपकरण) जवाबदेही के श्रमिकों के सिद्धांतों को सिखाता है।

अभिलेख (Recording)

क्यों अभिलेख (रिकॉर्ड) महत्वपूर्ण हैं?

1. रिकॉर्ड उनकी सामग्री के लिए महत्वपूर्ण हैं और संचार, निर्णय, कार्यों और इतिहास के सबूत के रूप में संस्थान, स्कूल बोर्ड/प्राधिकरण जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह हैं।
2. रिकॉर्ड खुलेपन का समर्थन करते हैं और दस्तावेजीकरण और कार्य गतिविधियों के सबूत प्रदान करके और उन्हें जनता के लिए उपलब्ध कराकर पारदर्शिता रिकॉर्ड गुणवत्ता कार्यक्रम और सेवाओं का समर्थन करते हैं, निर्णय लेने की सूचना देते हैं, और संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं।
3. रिकॉर्ड में किसी भी जानकारी को शामिल किया गया है जो संगठन के मिशन और नियोजन उद्देश्यों को शामिल करता है।
4. महत्वपूर्ण दैनिक गतिविधियों के परिणाम जो हमारे संगठनों के मिशन और उद्देश्यों का समर्थन करते हैं।
5. रिकॉर्ड और जानकारी जिसे एक के हिस्से के रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए।
6. व्यक्तिगत जानकारी है कि रिकॉर्ड संगठन द्वारा उपयोग किया गया है जिसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
7. आधिकारिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संगृहीत किया जाना चाहिए ताकि वे उन लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हों जिन्हें उनकी आवश्यकता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए अधिकृत हैं। यह हमारे पेपर–आधारित और हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार्य वातावरण दोनों में लागू होता है।
8. स्टॉक रजिस्टर भी आवश्यक हैं। उपकरण और उपकरणों के भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उपयोग के बाद सब कुछ अपने स्वयं के और संबंधित स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
9. स्कूलों को छात्र सूचना प्रबंधन प्रणाली के संचालन के विवरण के लिए अपलोड किए गए 'छात्र सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए दिशानिर्देश' का उल्लेख करना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम की शिक्षा के लिए खरीदे गए उपकरणों की एक सूची तैयार करें और उन्हें कॉलम के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करें।

टिप्पणी

10. स्कूल अपने छात्रों का उचित रिकॉर्ड रखता हैं जिसे समय पर और आसानी से प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्य बातों के अलावा, ये रिकॉर्ड अन्य स्कूलों, तृतीयक संस्थानों या अपने पूर्व या वर्तमान छात्रों के प्रदर्शन, आचरण और उपलब्धि के बारे में नियोक्ताओं को जानकारी प्रदान करते हैं। डेटा संग्रह, डेटा का उपयोग, डेटा सुरक्षा और डेटा एक्सेस आदि सहित छात्रों के व्यक्तिगत डेटा को संभालते हैं। प्रत्येक स्कूल डेटा एक्सेस या सुधार के अनुरोधों के लिए किसी भी रिफ्यूजल को दर्ज करने के लिए एक लॉग बुक रखता है।

कोर्स रिकॉर्ड

प्रत्येक वीईटी पाठ्यक्रम के लिए एक हार्ड कॉपी फाइल बनाई जाती है। पाठ्यक्रम फाइल में शामिल हैं–

एक सीखने और मूल्यांकन रणनीति सहित–

- पाठ्यक्रम (नामकरण और कोड)
- ग्राहक/छात्र सूची
- छात्रों को दी गई जानकारी
- प्रवेश हेतु आवश्यक शर्तें
- पाठ्यक्रम की संरचना

छात्र के सीखने और मूल्यांकन संसाधनों की मास्टर प्रतियां – शिक्षार्थी और सुविधा मार्गदर्शक, कार्यपुस्तिका, मूल्यांकन उपकरण और मूल्यांकन/अंकन मार्गदर्शिका के लिए स्पष्ट मानदंड सहित (1 वर्ष के बाद के पाठ्यक्रम के लिए)

- वितरण व्यवस्था
- अवधि
- वितरण कार्यक्रम
- मूल्यांकन की व्यवस्था
- मूल्यांकन आव्यूह (मैट्रिक्स)
- मूल्यांकनकर्ताओं के लिए सूचना गाइड
- कर्मचारी आव्यूह (स्टाफ मैट्रिक्स)
- छात्र प्रतिक्रिया
- नियोक्ता/उद्योग प्रतिक्रिया
- प्रशिक्षक/मूल्यांकनकर्ता प्रतिक्रिया
- योग्यता/मापदंड (मॉड्यूल) पूर्णता

छात्र रिकॉर्ड शामिल हैं–

रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी डेटा शामिल हैं, जो समय–समय पर निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन आवश्यक रूप से सीमित नहीं हैं–

- परिवार और दिए गए नाम
- जन्म की तारीख

टिप्पणी

- विद्यार्थी आईडी नंबर
- नामांकन की तारीख
- विशेष जरूरतें
- क्रेडिट ट्रांसफर/आरपीएल
- उच्च प्रस्थिति (एडवांस्ड स्टैंडिंग)
- पाठ्यक्रम (कोड सहित) में नामांकित
- सक्षमता की इकाइयां
- कार्य स्थापन (प्लेसमेंट) का विवरण
- योग्यता की इकाइयों के खिलाफ आकलन
- पुरस्कार (योग्यता और जारी किए जाने के प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र संख्या)

छात्र मूल्यांकन और प्रशिक्षण संसाधनों की मास्टर प्रतियां (शिक्षार्थी और सुविधा मार्गदर्शक, कार्यपुस्तिका, मूल्यांकन उपकरण, मूल्यांकन/अंकन के स्पष्ट मापदंड सहित) प्रत्येक प्रशिक्षक/मूल्यांकनकर्ता के लिए कर्मचारियों के रिकॉर्ड में फाइल शामिल हैं–

- नाम और संपर्क विवरण
- स्थान का विवरण
- रोजगार अनुबंध/समझौता
- वर्तमान सीवी – प्रशिक्षक (ट्रेनर)/एसिस्टर द्वारा हस्ताक्षरित
- प्रशिक्षक कौशल आव्यूह (ट्रेनर स्किल मैट्रिक्स) – प्रशिक्षक (ट्रेनर)/मूल्यांकनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित
- मूल्यांकनकर्ता योग्यता – आरटीओ द्वारा सत्यापित या अन्यथा
- प्रमाणित
- व्यावसायिक विकास गतिविधियां – प्रशिक्षक (ट्रेनर)/मूल्यांकनकर्ता द्वारा
- सत्यापित या हस्ताक्षरित
- जिम्मेदारियां

एक रिकॉर्ड दर्ज की गई जानकारी है, चाहे वह मुद्रित रूप में दर्ज की गई हो, फाइल पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्यथा और पत्राचार, एक ज्ञापन, एक किताब, एक योजना, एक नक्शा, एक ड्राइंग, एक आरेख, एक सचित्र या ग्राफिक काम शामिल हैं। एक तस्वीर, एक फिल्म, एक माइक्रोफिल्म, एक साउंड रिकॉर्डिंग, एक वीडियो टेप, एक मशीन पठनीय रिकॉर्ड, कोई अन्य वृत्तचित्र सामग्री, भौतिक रूप या विशेषताओं की परवाह किए बिना, और इसकी कोई भी प्रति शामिल हैं।

सामग्री और उपकरण का रखरखाव (Maintenance of Materials, Tools and Equipment)

उपकरण संगृहीत करने से पहले, आपको उपकरणों की खरीद और देखभाल करते समय कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नीचे कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जो

आपको लंबे समय तक समय और पैसा बचा सकते हैं– समय बचाने के लिए, आगे बढ़ो और शिकंजा, टिका आदि पर भी तेल छिड़कें, जब भी आपको ब्लेड को तेज करने के लिए अलग मशीनों को लेने की आवश्यकता होती है।

उपकरण और सामग्री जो कक्षा के संचालन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हाथ से पहले व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यह शिक्षण सहायक सामग्री के तहत भी शामिल किया जाएगा। विचलित करने वाली वस्तुओं को हटाना जो आइटम विचलित कर रहे हैं, अर्थात् पाठ के लिए अप्रासंगिक, जैसे कि अवांछित चार्ट, चॉक बोर्ड रीडिंग, भविष्य के सबक के लिए उपकरण के टुकड़े कक्षा से हटा दिए जाने चाहिए अन्यथा, प्रशिक्षु का ध्यान हटा दिया जा सकता है।

टिप्पणी

सामग्री और उपकरणों का रखरखाव/देखभाल

- मूल्य अल्पकालिक और लंबे समय तक चलने वाले उपकरणों के बीच अंतर कर सकते हैं।
- स्टेनलेस स्टील के औजारों की तलाश करें क्योंकि वे जंग नहीं करते हैं। सस्ते पेंट नौकरियों के सामान, लेपित धातु और कार्बन स्टील नमी के संपर्क में होने पर समय के साथ जंग लगना सुनिश्चित करते हैं।
- तेल उपकरण नियमित रूप से आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करें कि तेल लगाने से पहले उपकरण साफ और सूखे हों।
- उपकरण पर एक तौलिया या चीर के साथ तेल लगाया जा सकता है जो तेल के साथ नम है जब तक कि यह अन्य रसायनों या पानी से नम नहीं होता है।
- लकड़ी के हैंडलों को रेत से ढका जाना चाहिए और तेल से घिसना चाहिए।
- जिन उपकरणों में जंग जमा हो गया है, उन्हें पानी के साथ नीचे उतारा जाना चाहिए और जंग खत्म होने तक तार ब्रश, स्टील वूल या सैंड पेपर से स्क्रब करना चाहिए। उपकरण पर तेल लगाने से पहले यह किया जाना चाहिए।
- तेज उपकरण के साथ काम करते समय सुरक्षा चश्मे और दस्ताने पहनना याद रखें।
- आपके उपकरण को संगृहीत करने के स्थान के बावजूद, आप उन्हें रेत– तेल के मिश्रण में संगृहीत करने पर विचार कर सकते हैं, जिसका उपयोग वर्षों तक किया जा सकता है। यह रेत से भरे पांच गैलन बाल्टी और खनिज (या मोटर) तेल के आधा गैलन का उपयोग करके किया जा सकता है।
- बालू/तेल के मिश्रण वाली बाल्टियों के अलावा, आपके औजारों को संरक्षित करने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- एक खाली प्लास्टिक कंटेनर में साफ उपकरण रखें, जैसे कि ट्रैशकेन। इसके अलावा, रैक पर लटकने वाले उपकरणों पर विचार करें या अपने उपकरणों को रखने और व्यवस्थित करने के लिए कोष्ठक स्थापित करें।
- दस्ताने हमेशा एक बंद कंटेनर में रखे जाने चाहिए ताकि जब आप उन्हें डालेंगे तो आपके हाथ उनके द्वारा खाए नहीं जाएंगे।

टिप्पणी

- उपकरण को एक ठंडी, सूखी जगह पर रखा जाना चाहिए, जैसे कि गेराज या भंडारण इकाई। यह आपके कीमती सामान को नमी से दूर रखने में मदद करेगा।
- अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री को विशेष हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों को उपयुक्त लेबल वाले दबाव–सुरक्षित कंटेनरों में रखा जाना चाहिए। ज्वलनशील गैसों को एक अलग, अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में रखा जाना है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन के अनुसार, ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे गैसोलीन और केरोसिन को अन्य ज्वलनशील पदार्थों से दूर स्थित अनुमोदित कंटेनरों में संगृहित किया जाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों को गर्मी या लौ के स्रोतों से 50 फीट दूर रखें।
- सफाई सामग्री सहित सभी रसायनों को उनके मूल कंटेनरों में या उचित प्रकार के लेबल वाले कंटेनरों में रखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग करने वाले प्रत्येक कार्यस्थल में सभी सामग्री डेटा सुरक्षा शीट्स वाली एक पुस्तक होनी चाहिए, और पुस्तक को वहां रखा जाना चाहिए जहां यह आसानी से सुलभ हो।
- जब उपकरण आउट–ऑफ–ऑर्डर हो जाता है, तो यह एक प्रशिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह इसे संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करे। उपकरण को ठीक करने के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया जाना चाहिए। उसी को ठीक करने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई को मशीन के साथ प्रदान की गई हिस्ट्री शीट में दर्ज किया जाना चाहिए।
- आवश्यकता के अनुसार सामग्री और औजारों की खरीद करना आसान बनाएं। साधनों की खरीद को आसान बनाने से, सामग्री और साधनों का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।
- भंडारण सामग्री और उपकरणों के लिए जगह का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। आप यह जानना चाहेंगे कि क्या वह स्थान– अलमीरा, बॉक्स, टेबल आदि जहां सामग्री या उपकरण रखे जाने हैं, साफ हैं या नहीं। धूल हटाना जरूरी है।
- कुछ कारणों से यदि साधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें समय–समय पर साफ करना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार इन्हें सूर्य के प्रकाश में रखना आवश्यक होगा।

कुल मिलाकर, उनकी दीर्घायु और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपने उपकरणों का ध्यान रखना सुनिश्चित करें। प्रत्येक मौसम में अपने औजारों का निरीक्षण करें और उचित कदम उठाएं, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर किया गया है, ताकि उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जा सके। उपकरण के निवारक रखरखाव के रूप में जाना जाता है। उपकरणों को नियमित रूप से जांचना चाहिए।

ऐसा करने से, व्यावहारिक प्रयोग के दौरान होने वाले कुछ मामूली दोषों को बिना किसी देरी के तुरंत ठीक किया जा सकता है। एक रखरखाव अनुसूची बनाई जानी चाहिए और प्रशिक्षक को यह देखना चाहिए कि इसका सही तरीके से पालन किया जा रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि आप साधारण टूट–फूट की मरम्मत करने और

अपने छात्रों में उसी कौशल को विकसित करने के लिए कौशल प्राप्त करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे उपकरणों की मरम्मत करने में सक्षम हों।

अपनी प्रगति जांचिए

3. निम्न में से किसकी स्थापना शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में की गई?

(क) SIVE (ख) JCVE

(ग) NCERT (घ) SCERT

4. कक्षा प्रबंधन शिक्षकों के प्रबंधकीय ..... पर निर्भर करता है?

(क) अधिकार (ख) संगठन

(ग) आश्वासन (घ) कौशल

टिप्पणी

2.4 पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान

बच्चे के सर्वांगीण विकास और देश की भलाई के लिए कार्य शिक्षा के अनूठे महत्व को देखते हुए, लगभग सभी महत्वपूर्ण योजनाओं, शिक्षा और रिपोर्ट पर दस्तावेजों में इसका महत्व दिया गया है जो अंतिम रूप में सामने आए हैं। उदा. गांधीजी की बेसिक शिक्षा की योजना, कोठारी आयोग की रिपोर्ट, एनसीईआरटी का दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम, ईश्वर भाई पटेल समिति की रिपोर्ट, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1986 और हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। नतीजतन, कार्य शिक्षा देखी जाने लगी है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में– शिक्षा को सांस्कृतिक पुनः जागरण के लिए शारीरिक श्रम से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र को अपने विशेष समुदाय के क्षेत्र से बाहर आकर मानव जाति की सेवा के कुछ कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। काम को शिक्षा के एक माध्यम के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि अनुभव हमारे मस्तिष्क की खिड़कियां हैं।

शिक्षा और उत्पादकता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, एक स्वावलंबी और उत्पादक नागरिक के रूप में और सामाजिक पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय विकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में बच्चे की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे अलग–अलग समय पर और देश के अलग–अलग हिस्सों में शिल्प शिक्षा (क्राफ्ट एजुकेशन) (1937), कार्यानुभव (वर्क एक्सपीरियंस) (1967), सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य (सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क) (1977) जैसे अलग–अलग नामों से पेश और लागू किया गया है।

हाल ही में, NCERT (2000) द्वारा विकसित स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने कार्य अनुभव के पहले नामकरण के स्थान पर एक अधिक व्यापक शब्द 'कार्य शिक्षा' का सुझाव दिया। कार्य शिक्षा की अवधारणा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक मैनुअल कार्य के रूप में माना है जिसके परिणामस्वरूप उन वस्तुओं या सेवाओं का परिणाम होता है जो समाज के लिए उपयोगी हैं।

वर्तमान में, छात्र केंद्रित कार्य विधियों, छात्रों की स्वयं की पहल और उद्यमशीलता के विकास, उनकी जिम्मेदारी की भावना और सीखने के लिए कार्य के महत्व पर जोर

दिया गया है। प्रमुख कारकों में लचीले शिक्षण व्यवस्था, काम करने के तरीकों की एक विस्तृत श्रृंखला और शिक्षण सिद्धांत और व्यवहार के एकीकरण के साथ–साथ निर्देश के नियोजन और कार्यान्वयन में संस्थानों के बीच सहयोग और बातचीत शामिल हैं।

2.4.1 पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान : कई क्षेत्रों के कार्य कौशल के संयोजन की संभावना

टिप्पणी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) ने सभी चरणों में स्कूली पाठ्यक्रम में शिक्षा का काम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया है। यह 'कार्य अनुभव' शब्द पर वापस आ गया है जो पहले कोठारी आयोग द्वारा कार्य शिक्षा के लिए उपयोग किया गया था। एनपीई कहता है– "कार्य अनुभव, जिसे उद्देश्यपूर्ण, सार्थक, मैनुअल कार्य के रूप में देखा जाता है, को सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में आयोजित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप समुदाय के लिए उपयोगी वस्तुओं या सेवाओं को आवश्यक पाठ्यक्रम के रूप में माना जाता है।" यह अच्छी तरह से बाधित और वर्गीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। कार्य अनुभव में छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं, शिक्षा के चरणों के साथ कौशल और ज्ञान के स्तर के अनुसार गतिविधियां शामिल होंगी। यह अनुभव एक छात्र को कार्यबल में उसके प्रवेश पर मददगार होगा। निचले माध्यमिक चरण में प्रदान किए गए पूर्व–व्यावसायिक कार्यक्रम भी उच्चतर माध्यमिक चरण में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन की सुविधा प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) में कार्य शिक्षा एनपीई में कार्य शिक्षा इस प्रकार वैचारिक रूप से SUPW के समान है। हालांकि, इसका जोर स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में अच्छी तरह से संरचित और वर्गीकृत कार्यक्रमों पर है, जिसमें विद्यालय के मध्य चरण में कार्यक्रम शामिल है, जो छात्रों के बीच सीधे या कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त मनोचिकित्सा कौशल और आत्मविश्वास विकसित करेगा। यह निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व–व्यावसायिक कार्यक्रमों की परिकल्पना करता है, जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कामकाजी जीवन या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पसंद में सीधे प्रवेश के लिए तैयारी के रूप में होता है।

पूरे स्कूल कार्यक्रम में कार्य शिक्षा एक ऐसा विषय है, जो स्कूल को प्रभावी ढंग से समाज के करीब लाता है– कार्य शिक्षा समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की प्रत्येक स्थिति का ध्यान रखती है। यह अपनी प्रतिभा और कला को प्रदर्शित करने के लिए कारीगरों को आमंत्रित करती है।

पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान

पाठ्यक्रम में कार्य के स्थान को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है–

- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (2000) ने भी वर्क एजुकेशन की अवधारणा और दर्शन पर जोर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि वर्क एजुकेशन से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वर्क एजुकेशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जैसे कि सम्मान के शिक्षार्थियों के बीच झुकाव, मैनुअल कार्य, आत्मनिर्भरता के लिए मूल्य, सहकारिता, दृढ़ता,

टिप्पणी

सहायकता, सहिष्णुता और कार्य नैतिकता के अलावा व्यवहार और मूल्य–उत्पादक कार्य से संबंधित और समुदाय के लिए चिंता।

- आजादी से पहले औपचारिक शिक्षा के आगमन से बहुत पहले शिक्षा के उपकरण के रूप में मैनुअल (हाथ द्वारा किया गया) काम को मान्यता दी गई थी। प्राचीन भारत में जब छात्र आश्रमों में रहते थे, तो उन्हें अपने रहन–सहन और सीखने के लिए हर तरह के मैनुअल काम करने पड़ते थे– 'गरुकुल प्रणाली' (Gurukul System) शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित थी, शिक्षा और कार्य के बीच सह–अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए यह जीवन के माध्यम से जीवन के लिए शिक्षा थी। शिक्षा की औपनिवेशिक प्रणाली की शुरुआत के साथ स्थिति बदल गई, जो काफी हद तक सैद्धांतिक थी। सामान्य शिक्षा में मैनुअल गतिविधि का प्रावधान नहीं होने की कमी को शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच (1854) में इंगित किया गया था, जिसने माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत पर विचार किया था। वुड एंड एबट रिपोर्ट (1937) ने व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए शिक्षा में मैनुअल गतिविधियों को शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
- रवींद्रनाथ टैगोर ने चौतरफा शिक्षा प्रदान करने में मैनुअल काम की भूमिका पर भी जोर दिया। अक्टूबर 1937 में आयोजित वर्धा राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन किया कि शिक्षा की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में मैनुअल और उत्पादक कार्यों के बीच होनी चाहिए। अन्य सभी क्षमताओं को विकसित किया जाना चाहिए या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जहां तक संभव हो, बच्चे के पर्यावरण के संबंध में, चुने गए केंद्रीय हस्तकला से अभिन्न रूप से संबंधित होना चाहिए। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को जाकिर हुसैन समिति द्वारा व्यावहारिक रूप दिया गया था और बेसिक शिक्षा को 1938 में प्रारंभिक चरण के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न के रूप में स्वीकार किया गया था।
- आजादी के बाद स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय शिक्षा प्रणाली ने कार्य अनुभव के अन्य वैचारिक संस्करणों को देखा, अर्थात् कार्य अनुभव, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और स्वस्थ और उत्पादक जीवन की कला। ये वर्षों से एक कालानुक्रमिक क्रम में दिखाई दिए, जिससे यह पता चलता है कि इन कार्यक्रमों की उपस्थिति पृथक या अचानक नहीं है। वास्तव में, ऐसा करने से सीखने की अवधारणा में क्रमिक सुधार और शोधन की दिशा में प्रगतिशील प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है।
- शिक्षा आयोग (1964–66) ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि शैक्षिक परिवर्तन राष्ट्रीय विकास के लिए अग्रणी है। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़कर और इस लिंक को सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव को पेश करके उत्तम बनाया जा सकता है।
- दस वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम – एक रूपरेखा (1976) में कोठारी आयोग द्वारा कल्पना के रूप में स्कूल पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव शामिल था। इसके बाद ईश्वर भाई पटेल समिति (1977) की समीक्षा की गई,

टिप्पणी

जिसने सामाजिक रूप से उत्पादक कार्यों की गांधीवादी अवधारणा की फिर से पुष्टि की।

- शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) ने माल और सेवाओं के परिणामस्वरूप उद्देश्यपूर्ण और सार्थक मैनुअल काम के रूप में कार्य अनुभव की कल्पना की है, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता, भोजन, कपड़े, आश्रय, मनोरंजन और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में समाज के लिए उपयोगी हैं। डेलर्स कमीशन की रिपोर्ट (1996) 'लर्निंग द ट्रेजर विद' ने रेखांकित किया कि 'लर्निंग टू डू' के सिद्धांत को शिक्षा के स्तंभों में से एक बनाना चाहिए और कामकाजी जीवन के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए करीब से ध्यान देना चाहिए।
- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCERT, 2000) ने स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में स्वस्थ और उत्पादक जीवन और कार्य शिक्षा की कला (आर्ट ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लिविंग एंड वर्क एजुकेशन) के लिए अध्ययन की योजना का सुझाव दिया। आर्ट ऑफ हेल्दी और प्रोडक्टिव लिविंग का लक्ष्य स्कूली शिक्षा के शुरुआती दौर में बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर होगा। इस स्तर पर, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन गतिविधियों, सौंदर्य विकास, रचनात्मक गतिविधियों और मूल्य वृद्धि घटकों पर जोर दिया गया। प्राथमिक चरणों के लिए, कक्षा I से V तक, स्वस्थ और उत्पादक रहने की कला, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक चरणों के लिए, कार्य शिक्षा (वर्क एजुकेशन) का सुझाव दिया गया है और उच्चतर माध्यमिक चरणों के लिए, शिक्षात्मक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण बच्चों को काम की वास्तविक दुनिया में लाता है। व्यावसायिक विषयों को पेश करने के लिए स्कूलों को प्रशिक्षित शिक्षकों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। वर्तमान और भविष्य की नौकरियों के संदर्भ में व्यावसायिक विषयों की आवश्यकता को बताने के लिए माता–पिता का परामर्श महत्वपूर्ण है। और, बच्चों को व्यावसायिक विषयों का चुनाव करना चाहिए जो उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर चुने जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर छात्र इंजीनियर या प्रबंधक नहीं बन सकता है।
- हाई स्कूल स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शुरुआत करने में मदद करता है और सभी नौकरियों के लिए सम्मान की भावना पैदा करता है। पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य या एक वैकल्पिक विषय के रूप में, छात्रों को एक नया व्यापार या एक कौशल सीखने को मिलता है जो वास्तव में उनकी जन्मजात प्रतिभा और एक निश्चित नौकरी के लिए एक स्वाभाविक झुकाव की खोज में मदद कर सकता है। छात्रों को श्रम की गरिमा के बारे में जानने के लिए भी मिलेगा क्योंकि उन्हें हमारे हाथ से काम करने की कोशिश करनी चाहिए और चीजों को सीखना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर के सुधार और पाठ्यक्रम का पुनर्गठन एक समयबद्ध अभ्यास है जिसे उद्योग की गतिशील मांगों के साथ नहीं रखा जा सकता है। व्यावसायिक विषयों, उद्योग के साथ गठबंधन किए जाने के गुण के साथ, शिक्षा को ज्ञान

टिप्पणी

और कौशल के माध्यम से रोजगार से जोड़ने में मदद करते हैं जो रोजगार को योग्य बना सकते हैं। इसके अलावा, इस तरह के हस्तक्षेप सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल रखते हैं, क्योंकि शिक्षा समय के साथ विकसित होती है।

- CBSE ने निम्नलिखित उद्योग क्षेत्र को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल किया है– कृषि, पर्यटन और आतिथ्य, सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, खुदरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, हेल्थकेयर, प्लम्बर, निर्माण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और कल्याण।

उच्च प्राथमिक स्तर पर, कार्य शिक्षा की निरंतरता सार्थक कार्यों के लिए सम्मान को मजबूत करेगी। माध्यमिक स्तर पर छात्रों की परिपक्वता के स्तर को देखते हुए, गतिविधियां अधिक विविध और जटिल बन जानी चाहिए।

उच्च प्राथमिक चरण (कक्षा छठी से आठवीं तक) पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान

अध्ययन की योजना में तीन भाषाएं, प्रौद्योगिकी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा शामिल हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर, बच्चों में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यह 'बचपन से किशोरावस्था' तक जैविक संक्रमण की अवधि है। संज्ञानात्मक स्तर पर, बच्चे धीरे–धीरे किसी विशेष समस्या से संबंधित सभी काल्पनिक स्थितियों के संदर्भ में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थी जोरदार गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व होते हैं, उच्च कौशल को शामिल करते हुए काम करते हैं और न्यूरो–पेशी–समन्वय की आवश्यकता होती है।

इस स्तर पर कार्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को काम की ओर उन्मुख करना और उनमें विकास करना है। मैनुअल श्रम के लिए व्यावसायिक शिक्षा सम्मान फाउंडेशन के रूप में कार्य केंद्रित शिक्षा ने बच्चों को अच्छी तरह से डिजाइन की गई परियोजनाओं को समझने और निष्पादित करके उत्पादन प्रक्रियाओं में अधिक तीव्रता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

द्वितीय चरण (कक्षा IX से X तक) पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान

अध्ययन की योजना में भाषा, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा शामिल हैं। द्वितीयक स्तर पर, उच्च प्राथमिक चरण के दौरान होने वाले चारित्रिक विकास को बल मिलता है। अमूर्त अवधारणाओं के साथ सोचना, सामाजिक पहचान स्थापित करना और सहकर्मी समूहों को महत्व देना काफी बढ़ जाता है। इसलिए, इस महत्वपूर्ण चरण में बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। गतिविधियों की जटिलता और उद्यमशीलता कौशल को आवश्यक गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संवर्धित करने की आवश्यकता है।

कार्य शिक्षा (वर्क एजुकेशन) के अलावा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा (प्री–वोकेशनल एजुकेशन) का इस स्तर पर प्रमुख स्थान है। यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन की सुविधा प्रदान करेगा और फिर काम की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करेगा।

टिप्पणी

उच्चतर माध्यमिक चरण (कक्षा XI और XII) पाठ्यक्रम में कार्य का स्थान

पढ़ाई के दस साल के आम कार्यक्रम के बाद, जहां छात्रों को मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, वाणिज्य जैसे विषयों का ज्ञान विशिष्ट–गहन पाठ्यक्रमों में छात्रों को कराया जाता है। वहीं दूसरी विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार, कोठारी आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक के अनुसार, इस स्तर पर पाठ्यक्रम को दो धाराओं, शैक्षणिक धारा और व्यावसायिक धारा के तहत आयोजित किया जाना है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दोनों के बीच उचित संबंध न केवल बनाए रखा जाए बल्कि व्यवस्थित रूप से मजबूत किया जाए।

तकनीकी प्रगति की प्रकृति और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्ञान और कौशल के निरंतर उन्नयन की मांग करती है। जबकि संगठित क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार के अवसर अब कम हो रहे हैं, वे सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों को प्रदान किया जाना है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम (वोकेशनल कोर्स) को स्व–निहित मॉड्यूल के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सैद्धांतिक पहलुओं या बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यावहारिक परिचालन का विवरण निर्दिष्ट करता है। स्कूली छात्रों को देने से पहले पाठ्यक्रमों की आवश्यकता, प्रासंगिकता और क्षमता का आकलन करेंगे। औपचारिक स्कूल प्रणाली में ये पाठ्यक्रम काम की दुनिया में शामिल होने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा की धारा को विशेष रूप से खुली शिक्षा में वैकल्पिक स्कूली शिक्षा और ड्रॉपआउट, नव–साक्षर और वंचित समूहों के लिए गैर–औपचारिक प्रणाली में अपना उचित स्थान खोजना होगा। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अलग–अलग अवधि के बहु–प्रवेश और बहु–निकास मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होगी।

मुख्य क्षेत्र (कोर क्षेत्र) (Core Area)

मुख्य क्षेत्र को मोटे तौर पर दो विषयों अर्थात व्यक्तित्व और सामुदायिक विकास (कोर एरिया और एंटरप्राइज एजुकेशन) में वर्गीकृत किया गया है। विषयों को तत्वों में और वर्गीकृत किया गया है, एक व्यक्ति, परिवार और समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण और शांतिप्रिय समाज को विकसित करने के लिए एक व्यक्ति की भूमिका निभानी होती है। तत्वों को उप–तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। उप–तत्वों को शिक्षा के चरण के अनुसार सुझाव दिया गया है, यह ध्यान में रखते हुए कि दक्षता का सहज संक्रमण और अंतर्निहित आंतरिक निरंतरता हो सकती है।

मुख्य घटक में उन गतिविधियों को शामिल किया गया है, जो जीवन–समर्थक गतिविधियों को करने के लिए एक व्यक्ति को प्रासंगिक जीवन कौशल और अनुभव प्रदान करेंगे। यह व्यवसाय–विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए ज्ञान का आधार भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह परिकल्पना की गई है कि शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ सामान्य दक्षताओं को विकसित किया जाएगा। इनमें से कुछ हैं– निर्णय लेने, महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच, संचार, वर्तमान और उभरती हुई

तकनीकों का अनुप्रयोग, विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन, पारस्परिक संबंध, सहानुभूति, भावनाओं और तनाव का सामना करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंधन करना।

टिप्पणी

NCERT ने स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। 'कार्य और शिक्षा' पर एक राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था। विभिन्न फोकस समूहों के परिणाम और सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) को अंतिम रूप दिया गया और जारी किया गया।

कार्य और शिक्षा पर राष्ट्रीय फोकस समूह ने सुझाव दिया है–

(अ) पूर्व–प्राथमिक चरण से बारहवीं कक्षा तक कार्य–केंद्रित शिक्षा तथा

(ब) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) उन लोगों के लिए जो शिक्षा पूरी करने से पहले अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने या पुश–आउट 'या–वॉक–आउट' करने के बाद अपने व्यवसाय/आजीविका के लिए सम्मानजनक विकल्प चाहते हैं।

यह प्रस्तावित किया है कि काम–केंद्रित शिक्षाशास्त्र बारहवीं कक्षा तक के पूर्व–विद्यालय के चरण से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय आयोजन विषय हो। उद्देश्य के लिए कार्य पाठ्यक्रम में अंतर होगा–

- ज्ञान प्राप्त करना जो न तो किसी बच्चे को उसके सामाजिक लोकाचार से अलग करता है और न ही उसे सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाने से रोकता है;
- मूल्यों और उनके द्वारा खड़े होने के लिए आवश्यक ताकत, विशेष रूप से संकट के दौरान, सहकर्मी टीमों में सहकारी कामकाज के माध्यम से और उन्हें सामुदायिक कार्य और सामाजिक कार्रवाई से संबंधित; तथा
- एक सामान्य ढांचे के भीतर कई कौशल गठन को बढ़ावा देना और बच्चों के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ से उभरने वाले व्यवसायों से संबंधित है, तेजी से बदलावों को ध्यान में रखते हुए कि यह संदर्भ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चल रहा है।

स्कूल प्रणाली किसानों, कारीगरों (जो शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं), स्वास्थ्य चिकित्सकों (गांव वाले सहित), पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पकड़ने और औषधीय जड़ी–बूटियों, यांत्रिकी में अनुभवी व्यक्तियों के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाएंगी।

पाठ्यक्रम में कार्य की सक्रिय भूमिका और महत्व

1. यह हाथ और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित करता है।
2. शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक रूप से उपयोगी शारीरिक श्रम निहित है।
3. यह सीखने की प्रक्रियाओं में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कारक है।
4. यह समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं और उत्पादक कार्यों के रूप में दिखाई देता है।
5. यह बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के सभी पहलुओं के साथ एक आवश्यक कारक के रूप में जुड़ा हुआ है।

टिप्पणी

6. यह करने के द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है।
7. समस्या को सुलझाने, महत्वपूर्ण सोच और निर्णय लेने जैसे कौशल विकसित करता है।
8. छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर आधारित है।
9. शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुसार छात्रों की क्षमताओं का विकास करता है।
10. व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है।
11. उत्पादन में व्यावसायिक तत्परता और दक्षता को विकसित करता और बढ़ाता है।
12. विभिन्न सिद्धांत, तकनीकों, विधियों, सामग्रियों और वस्तुओं से परिचय का अवसर प्रदान करता है।
13. सामुदायिक सेवाओं से संबंधित परिस्थितियों का अनुभव करने के अवसर प्रदान करता है।
14. काम की दुनिया से परिचय कराता है।
15. श्रम और सकारात्मक अभिवृत्ति की गरिमा से परिचय कराता है।
16. कल्पनाशील और रचनात्मक अभिवृत्ति बढ़ाता है।
17. यह उनके शरीर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से तैयार रहता है।
18. आदतें और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है।
19. अपने परिवेश के प्रति जागरूकता लाने और मानवता व पर्यावरण के अंतर प्रतिशोध की समझ विकसित करता है।
20. शारीरिक कार्य और श्रम के महत्व के प्रति गर्व भावना विकसित करता है।
21. यह सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है।
22. कार्य पोषण, भोजन, संक्रमण रोगों और स्वच्छता से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वे कार्य शिक्षा के माध्यम से सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए सतर्क और जागरूक हो जाते हैं।
23. आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के गुणों का पोषण करना। प्रत्येक बच्चे को एक प्राकृतिक संकेत के रूप में रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति की संभावना है।
24. कार्य कलात्मक गतिविधियों के आयोजन के बाद व्यक्तिगत आधार पर आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है।
25. यह स्थानीय और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की भावनाओं की सराहना करने की क्षमता का पोषण करता है।
26. यह नेतृत्व और नेतृत्व कौशल की भावनाओं को शुरू करने में मदद करता है।
27. कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होते हैं और पहल करने में संकोच करते हैं। कार्य ऐसे अनुभव प्रदान करता है ताकि नेतृत्व को आसान गतिविधियों के माध्यम से विकसित और पोषित किया जा सके।

टिप्पणी

28. आवश्यक जीवन कौशल का विकास–शिक्षा की वास्तविक और आदर्श जिम्मेदारी बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है।
29. कार्य समस्या निवारण, निर्णय लेने, रचनात्मक सोच, महत्वपूर्ण सोच, सहानुभूति, प्रभावी संचार जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने में मदद करती है और बच्चों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाती है।
30. काम का संबंध स्थापित करना–कार्य शिक्षा विभिन्न कार्य स्थितियों को जानने और उनमें भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। यह श्रमिकों के काम और दिनचर्या को जानने के लिए प्रेरित करती है।

स्कूल को निर्धारित कक्षाओं और अवधियों में विभाजित करने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय, स्कूल को बच्चों के बहु–स्तरीय, लचीले और गतिशील समूहों के संदर्भ में पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें बातचीत के समय–सीमा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों के समूह का गठन उनके सामान्य ज्ञान अभिविन्यास और तुलनीय कौशल स्तरों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें से कुछ को समूह में रखा जाएगा ताकि वे सीखने की प्रक्रिया में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकें।

2.4.3 वास्तविक जीवन में ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका

शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चों को वयस्कों के रूप में जीवन के लिए तैयार करना और ज्ञान, कौशल, गुण और दृष्टिकोण प्रदान करना है जो उन्हें आत्म–सहायक व्यक्ति और उत्पादक नागरिक बनाते हैं। एनपीई में कल्पना के अनुसार, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक (केवल शैक्षणिक स्ट्रीम) चरणों में पूर्ववर्ती कार्यक्रम, विशेष रूप से अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कौशल के विकास के उद्देश्य से किए जाते हैं ताकि उच्च/उच्चतर माध्यमिक चरणों के बाद पढ़ाई बंद न हो जाए।

शिक्षा क्षेत्र में पेशेवरों के रूप में, हम मानते हैं कि शिक्षण तेजी से अधिक जटिल हो गया है। शैक्षिक पुनर्गठन की काफी मात्रा के कारण, कई नवाचार सामने आए हैं, जिसमें एकीकृत पाठ्यक्रम भी शामिल है। शिक्षण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि जब थीम या प्रोजेक्ट संयुक्त होते हैं, तो छात्र विभिन्न विषयों के बीच सार्थक और प्रासंगिक संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। सामग्री की अधिक गहन समझ बनाने के अलावा, विषयों के बीच पुनरावृत्ति कम हो जाती है। एकीकृत पाठ्यक्रम इस विश्वास का समर्थन करता है कि व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, एक एकीकृत पाठ्यक्रम एक व्यावहारिक तरीका है जो सार्थक शिक्षा को एक वास्तविकता बनने में सक्षम बनाता है।

वास्तविक जीवन में ज्ञान को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका

ज्ञान एक परिचित, जागरूकता या किसी की समझ है, जैसे तथ्य, सूचना, विवरण, जो अनुभव, शिक्षा या विचार, खोज, या सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा–2005 (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क–2005) के अनुभव को केंद्र में रखते हुए, ज्ञान को भी परिभाषित करता है। इसके अनुसार, ज्ञान को भाषा

के माध्यम से आयोजित अनुभव के रूप में सोचा जा सकता है, इस प्रकार अर्थ का निर्माण होता है, जो बदले में हमें उस दुनिया को समझने में मदद करता है जिसमें हम रहते हैं। इसे गतिविधि के पैटर्न या भौतिक निपुणता के रूप में भी माना जा सकता है।

टिप्पणी

समय के साथ मनुष्यों ने ज्ञान के कई निकायों को विकसित किया है, जिसमें सोचने के तरीके, महसूस करने और चीजों को करने, और अधिक ज्ञान का निर्माण करने का एक प्रदर्शन शामिल है। ज्ञान अधिग्रहण में जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं– धारणा, संचार और तर्क, जबकि ज्ञान को मानव में पावती की क्षमता से संबंधित भी कहा जाता है।

'कार्य–केंद्रित शिक्षा' के सार्वभौमिक कार्यक्रम का परिचय निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है–

- ज्ञान प्राप्त करने, मूल्यों के निर्माण, कौशल निर्माण और महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और अन्य सामान्य दक्षताओं को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए सन्निकट परिस्थितियों में उत्पादक कार्यों में भाग लेना।
- जबकि काम और विषय–विशिष्ट ज्ञान के बीच संबंध को अनुकूलित किया जाएगा, बच्चों के मूल्य–ढांचे के लिए उभरती चुनौती हमेशा एक केंद्रीय चिंता का विषय रहेगी।

किसी संगठन का सबसे मूल्यवान संसाधन उसके लोगों का ज्ञान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका व्यवसाय विचार कितना खास है, जो आपकी कंपनी को विशिष्ट बनाता है, जो लोग ऐसा करते हैं। जब कर्मचारी अपना ज्ञान साझा करते हैं, तो आपका संगठन हर किसी की बुद्धिमत्ता के लाभों को पढ़ता है। यही कारण है कि ज्ञान प्रबंधन व्यवसाय की सफलता में एक मौलिक भूमिका निभाता है।

एक आसान जगह में विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को इकट्ठा करके, ज्ञान साझा करने की रणनीतियों से समय बचता है। ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक समझ है। यह वह है जो आपने शिक्षा या कार्य अनुभव के माध्यम से सीखा है। उदाहरण के लिए, भवन और निर्माण में, आपको सामग्री, विधियों और घरों, भवनों, या राजमार्गों और सड़कों जैसे अन्य संरचनाओं के निर्माण या मरम्मत में शामिल उपकरणों की जानकारी की आवश्यकता होगी।

ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों के एक व्यापक सेट की आवश्यकता है जो छात्र भविष्य के लिए सबसे अच्छे रूप से तैयार हैं वे परिवर्तन एजेंट हैं। वे अपने परिवेश पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों के इरादों, कार्यों और भावनाओं को समझ सकते हैं, और जो वे करते हैं उसके छोटे और दीर्घकालिक परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं।

योग्यता की अवधारणा का तात्पर्य केवल ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण से अधिक है; इसमें जटिल मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को जुटाना शामिल है। छात्रों को अपने ज्ञान को अज्ञात और विकसित परिस्थितियों में लागू करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए, उन्हें संज्ञानात्मक और मेटा–संज्ञानात्मक कौशल (जैसे महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक सोच, सीखना सीखना और आत्म–नियमन) सहित कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होगी।

सामाजिक और भावनात्मक कौशल (जैसे सहानुभूति, आत्म–प्रभावकारिता और सहयोग); और व्यावहारिक और शारीरिक कौशल (जैसे नई जानकारी और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करना)।

ज्ञान और कौशल की इस व्यापक श्रेणी का उपयोग दृष्टिकोण और मूल्यों (जैसे कि प्रेरणा, विश्वास, विविधता और सद्‌गुण के लिए सम्मान) द्वारा मध्यस्थता की जाएगी। दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्तिगत, स्थानीय, सामाजिक और वैश्विक स्तरों पर देखा जा सकता है। जबकि मानव जीवन विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों और व्यक्तित्व लक्षणों से उत्पन्न मूल्यों और दृष्टिकोणों की विविधता से समृद्ध है, कुछ मानवीय मूल्य हैं। उदाहरण के लिए, जीवन और मानव गरिमा के लिए सम्मान, और पर्यावरण के लिए सम्मान।

टिप्पणी

हमारे समाज को बदलने और हमारे भविष्य को आकार देने की क्षमताएं यदि छात्रों को जीवन के सभी आयामों में एक सक्रिय भूमिका निभानी है, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के संदर्भों में अनिश्चितता के माध्यम से नेविगेट करने की आवश्यकता होगी। नए मूल्य बनाना विकास के नए स्रोतों को मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक टिकाऊ विकास प्राप्त करने के लिए तत्काल आवश्यक है। नवीन अर्थव्यवस्थाएं, अधिक उत्पादक, अधिक लचीला, अधिक अनुकूलनीय और बेहतर जीवन स्तर का समर्थन करने में पाठ्यचर्या की भूमिका सक्षम है।

वास्तविक जीवन में कौशल को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका

21 वीं सदी के कौशल को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है–

1. सीखने का कौशल
2. साक्षरता कौशल
3. जीवन कौशल

- **सीखने का कौशल**– छात्रों को आधुनिक कार्य परिवेश में अनुकूलन और सुधार के लिए आवश्यक मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में सिखाता है।
- **साक्षरता कौशल**– यह इस बात पर केंद्रित है कि छात्र तथ्यों को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, प्रकाशन के आउटलेट, और उनके पीछे की तकनीक। भरोसेमंद स्रोतों और तथ्यात्मक जानकारी को निर्धारित करने पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित है जो इसे इंटरनेट पर बाढ़ से होने वाली गलत सूचना से अलग करता है।
- **जीवन कौशल**– एक छात्र के रोजमर्रा के जीवन के अमूर्त तत्वों पर एक नजर डालते हैं। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कुछ व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) स्कूल में सिखाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर आप रोजमर्रा की जिंदगी में सीखते हैं और किसी भी समय सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए–

- अच्छा संचार कौशल
- गहन सोच
- एक टीम में अच्छा काम करना

टिप्पणी

- स्व प्रेरणा
- लचीला होना
- दृढ़ संकल्प और दृढ़ता
- अच्छा समय प्रबंधन
- ईमानदारी और अखंडता
- अनुकूलन
- समस्या–समाधान
- निर्भरता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी
- वफादारी
- सकारात्मक दृष्टिकोण / प्रेरणा / ऊर्जा / जुनून
- आत्म–विश्वास
- टीमवर्क
- नियोजन और आयोजन
- नेतृत्व और प्रबंधन कौशल
- बहुसांस्कृतिक संवेदनशीलता और जागरूकता
- सीखने की इच्छा
- विश्लेषणात्मक कौशल
- तकनीकी साक्षरता
- मजबूत काम की नैतिकता
- पारस्परिक क्षमता

ज्ञान और कौशल को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका

ज्ञान और कौशल को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है–

1. पाठ्यक्रम में सीखे गए ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करके और अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ ज्ञान और कौशल के एकीकरण पर, छात्र अपने सीखने और पाठ्यक्रम की सामग्री से अधिक जुड़े हुए हैं। एकीकरण और सामान्यीकरण कौशल पर जोर देने से छात्रों को पाठ्यक्रम के बीच और कोर्सवर्क और अन्य प्रकार के ज्ञान के बीच संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे छात्रों का जुड़ाव बढ़ता है।
2. छात्र अपने मूल्यांकन की शर्तों और लक्ष्यों को समझते हैं।
3. सीखने के परिणामों को विकसित करने की प्रक्रिया अपने संभावित अनुप्रयोगों के संदर्भ में पाठ्यक्रम की सामग्री पर प्रतिबिंब के लिए एक अवसर प्रदान करती है।
4. सीखने के परिणामों को विकसित करने का मतलब है कि सीखने के संदर्भ पर हमेशा जोर दिया जाएगा, और पाठ्यक्रम उन ज्ञान और कौशल पर ध्यान

टिप्पणी

केंद्रित करते हैं जो अब और भविष्य में छात्र के लिए सबसे अधिक मूल्यवान होंगे।

5. सीखने के परिणामों से प्रशिक्षकों को उन मानकों को निर्धारित करने की अनुमति मिलती है जिनके द्वारा पाठ्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन किया जाएगा।
6. शैक्षणिक सामग्री ज्ञान सामग्री और शिक्षाशास्त्र का एक विशिष्ट संयोजन है जो शिक्षकों द्वारा विशिष्ट रूप से निर्मित किया जाता है और इस प्रकार एक शिक्षक के पेशेवर जानने और समझने का 'विशेष' रूप है।
7. शैक्षणिक सामग्री ज्ञान को शिल्प ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें शिक्षकों के संचित ज्ञान का उनके शिक्षण अभ्यास के संबंध में एकीकृत ज्ञान शामिल है।
8. शैक्षणिक सामग्री ज्ञान को एक विविध शिक्षण के संदर्भ में संबोधित किया जाना चाहिए।
9. शैक्षणिक सामग्री का ज्ञान शिक्षक के रोजमर्रा के काम में गहराई से निहित है। हालांकि, यह सैद्धांतिक ज्ञान के विपरीत नहीं है। यह शिक्षक की तैयारी के दौरान सीखे गए सिद्धांत के साथ–साथ चल रही स्कूली गतिविधियों से प्राप्त अनुभवों को शामिल करता है।
10. शैक्षणिक सामग्री ज्ञान का विकास शिक्षक की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से संबंधित कारकों और उस संदर्भ से प्रभावित होता है जिसमें वह काम करता है।
11. शैक्षणिक सामग्री ज्ञान छात्रों, उनके परिवारों और समुदायों के अनुभवों और संपत्ति में गहराई से निहित है।
12. शैक्षणिक सामग्री ज्ञान अनुसंधान शिक्षण के बारे में ज्ञान के साथ शिक्षण पर ज्ञान को जोड़ता है, एक शक्तिशाली ज्ञान आधार है जिस पर शिक्षण विशेषज्ञता का निर्माण करना है।

मूल्य को एकीकृत करने में पाठ्यचर्या की भूमिका

मानव जाति का संपूर्ण विकास स्मारक समय से एक भविष्य कहनेवाला मिशन रहा है, और यह सामाजिक परिवर्तन संस्थानों के लिए एजेंटों द्वारा विरासत में मिला है, उनमें से एक स्कूल है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों में नैतिक मूल्यों के एकीकरण को मजबूत करके, छात्रों को विचार करने के लिए विकल्प के रूप में मूल्यों में एक आधार प्रदान करता है।

स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों को एकीकृत करने के लिए तर्क इस तथ्य से देखा जा सकता है क्योंकि वे सभी प्राणियों के लिए फायदेमंद हैं, उन्हें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि मानव व्यवहार को आकार देने के लिए मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम के रूप में जाना जा सके। एकीकृत नैतिक मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम का सार यह है कि यह व्यक्तियों को ताकत के अपने सकारात्मक क्षेत्रों का निर्माण करने और नकारात्मक लोगों को दबाने में मदद करता है।

समाज में अनैतिक प्रथाओं को कैसे संबोधित किया जाए, इस सवाल को स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को एकीकृत करने के दृष्टिकोण से माना जाता है ताकि धीरे–धीरे एक मजबूत नैतिक नींव का निर्माण किया जा सके जो युवाओं को अब और

टिप्पणी

भविष्य में अनैतिक व्यवहार का अपमान करने और उनका विरोध करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह तर्क दिया जाता है कि छात्रों को विचार करने के लिए विकल्प के रूप में मूल्यों में एक आधार प्रदान करने के लिए मूल्यों के शिक्षण को मजबूत करने से, स्कूल में और बाद में वयस्कों और नेताओं के रूप में उनके लिए सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों का विरोध करने के लिए, जहां पाया गया, उनके फैसले प्रभावित कर सकते हैं।

लोग मूल्यों की अवधारणाओं को अलग–अलग रूप से देखते हैं, आंतरिक विचारों, विश्वासों या समझ के रूप में जो मार्गदर्शन करते हैं और किसी के व्यवहार में दिखाई देते हैं (लिंडा, 1997), आदर्शों, मानकों या जीवन के सिद्धांतों के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार के सामान्य मार्गदर्शक या निर्णय लेने के संदर्भ बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं। विद्वान (जैसे– तेज, 1984; रोवे और न्यूटन, 1994; लिपमैन, 1987; फिशर, 1994; कोह्लबर्ग, 1980) यह मानते हैं कि शिक्षा से पता चलता है कि शिक्षार्थियों द्वारा नैतिक मूल्यों की वकालत करना अच्छा है और जिन्हें टाला जाना और बदला जाना बुरा है। और सामाजिक–संवैधानिक–धार्मिक मानदंडों के रूप में नैतिक मूल्य लोगों को जिम्मेदारी से व्यवहार करने में मदद करने वाले हैं।

राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों के एकीकरण के लिए एकीकृत मॉडल में शब्दांकन से पहले शब्दावली 'एकीकृत पाठ्यक्रम' का क्या अर्थ है, यह चित्रित करना महत्वपूर्ण है। विगिंस (2001: 272) 'संज्ञानात्मक शिक्षुता' का उपयोग करता है, जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्कूली संदर्भ में सीखना एकीकृत पाठ्यक्रम को परिभाषित करने के लिए 'जीवन' सीखना पसंद है।

मूल्यों की योजना के रूप में पाठ्यक्रम

- हमारे सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य का संरक्षण और प्रसारण शिक्षा में, पाठ्यक्रम के माध्यम से, छात्रों को सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराया जाएगा और शिक्षक उन्हें विभिन्न गतिविधियों, खेलों, कहानी आदि के माध्यम से मूल्यों और आदर्शों से परिचित कराते हैं। शिक्षा उन्हें नागरिकों के संविधान, नियमों और विनियमों आदि से परिचित कराती है।
- शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति एकता, प्रेम, बंधुत्व और अन्य मूल्यों के महत्व के बारे में जागरूक होते हैं। शिक्षा सभी लोगों को समाज का हिस्सा बनने के लिए जाग्रत करती है और वे समाज के रूप में दुनिया में योगदान दे सकते हैं।
- रीड के अनुसार, "शिक्षा जीवन का हिस्सा है, और स्पष्ट रूप से मूल्यों और शिक्षा के बारे में हमारे प्रश्न जीवन में मूल्यों के प्रश्नों से अपरिहार्य हैं। इस प्रकार शिक्षा अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव की भावना विकसित करती है। यह भेदभाव मूल्यों पर आधारित है। और इन मूल्यों को स्कूल में परखा जाता है।"
- डब्ल्यू. एच. किलपैट्रिक को उद्धृत करने के लिए, "शिक्षक के पास अपने पेशेवर उपकरणों का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, जिसे यहां मूल्यों का मानचित्र कहा जाता है।" इस तरह के मानचित्र में उनकी आशाएं, उद्देश्य, आदर्श, उन सभी पोषित मूल्यों का समावेश होता है, जिन्हें वह उन चीजों को निर्देशित करने के उद्देश्य से उपयोग करेगा।

टिप्पणी

- पाठ्यक्रम की एक दूसरी अवधारणा ने कहा कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, चयन के एक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए जिसे मूल्यों के पैमाने के रूप में, या मानदंडों के सेट के रूप में कहा जा सकता है। यहां, पाठ्यक्रम की अवधारणा मूल्यों का एक प्रश्न है (फिलिप एच. फेनिक्स)। कोई भी नेक विचार, भावना या कार्य जो समाज की रक्षा के लिए किया जाता है उसे मूल्य कहा जाता है।
- "पाठ्यक्रम छात्र के विकास की पसंदीदा दिशा को देखते हुए प्रस्तावित निर्माण का एक सेट है।" यह उन मूल्यों की एक योजना पर आधारित है जो शिक्षा के उद्देश्यों का गठन करते हैं।
- हम सभी के बहुत सारे हित हैं जैसे कि जैविक, अस्तित्व, शारीरिक और मानसिक आराम, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्म–अभिव्यक्ति, साहचर्य और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया की समझ, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतंत्रता, मित्रता और ज्ञान जैसे इन हितों की संतुष्टि के तहत पाठ्यक्रम के निर्माण के बारे में निर्णय लेने के आधार पर मूल्यों का सुझाव दिया गया है।
- समाज में प्रचलित शिष्टाचार और रीति–रिवाज, सामाजिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित व्यवसाय, आजीविका, रक्षा, धर्म, आदि, और जिन पर सामान्य मूल्य हैं।
- सांस्कृतिक मूल्य को व्यापक रूप से आयोजित मान्यताओं या भावनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि समुदाय की पहचान या कल्याण के लिए कुछ गतिविधियां, रिश्ते, भावनाएं, लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। इस तरह का मूल्य सांस्कृतिक परंपरा के दावों पर आधारित है। इसलिए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा सामग्री से युक्त होना चाहिए, जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और विस्तारित करने में मदद करता है।
- विचारों और विश्वास प्रणाली में एक एकीकृत पाठ्यक्रम शामिल है जो स्कूलों की पारंपरिक संरचना से हट जाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम का समर्थन करता है कि सार्वभौमिक सत्य एक संभावना नहीं है। इसके बजाय, कई अलग–अलग संभावनाएं मौजूद हैं और एक वांछित परिणाम तक पहुंचने के लिए कई तरह के तरीके हैं, इस तरह के दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण के बाद अपनाया जाता है।

एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था या एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, वास्तविक समाज से अलग हैं। स्कूल एक नई सामाजिक व्यवस्था को लाने के लिए वांछित सुधारों को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए, पाठ्यक्रम में एक संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृतियों के अध्ययन के लिए प्रावधान शामिल होना चाहिए– यह वर्तमान समाज और भविष्य के आदर्श समाज दोनों के व्यवसायों को पढ़ाकर व्यावसायिक संतुलन हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।

शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षक समस्या समाधान के दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया जाना चाहिए। उन्हें काम और सेवाओं के लिए सामग्री, उपकरण और तकनीकों पर चर्चा

करके और उचित कार्य करने के द्वारा इन समस्याओं के समाधान तक पहुंचने के लिए नेतृत्व किया जाना चाहिए। यदि कोई स्कूल ऐसी शिक्षा गतिविधि शुरू करने का इरादा रखता है जिसके लिए पाठ्यक्रम यहां नहीं दिया गया है, तो स्कूल पहले सूचीबद्ध मानदंडों को पूरा करने के लिए अपना पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकता है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

5. उद्योग क्षेत्र को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसने शामिल किया है?

(क) NCERT (ख) CBSE

(ग) NPE (घ) NCTE

6. निम्न में से किसके अनुसार "शिक्षा जीवन का हिस्सा" है?

(क) रीड (ख) लिपमैन

(ग) विगिंस (घ) कोह्लबर्ग

2.5 व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अभिकरण (एजेंसियां)

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण लीवर है। प्रासंगिक ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल से सुसज्जित एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी इक्कीसवीं सदी में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है और एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।

2.5.1 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के विशेष संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका

उच्चतर माध्यमिक चरण में शिक्षा जैसा कि पहले कहा गया था, 1988 में शिक्षा का सीएसएस +2 चरण में शिक्षा का सीएसएस NPE–1986 के कार्यान्वयन के बाद शुरू किया गया था। व्यावसायिक विकास की केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण को प्रदान करना है ताकि वृद्धि हो सके।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक रूप से प्रायोजित योजना के विशिष्ट उद्देश्य बहु–प्रवेश के प्रावधानों के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए मांग व योग्यता आधारित मॉड्यूलर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। शिक्षा के अवसरों और योग्यता में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता/विनिमय क्षमता से बाहर निकलें, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए शिक्षित और रोजगार के बीच अंतर को भरने के लिए।

'माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण' की केंद्र प्रायोजित योजना 1988 में शुरू की गई थी, जिसे शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक चरण (कक्षा XI–XII) में लागू किया जाना था। इस योजना में मानव संसाधन की जरूरतों के मूल्यांकन के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन की परिकल्पना की गई है। योजना के मुख्य उद्देश्य, जैसा कि शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय नीति 1986 में किया गया था, शैक्षिक अवसरों का

टिप्पणी

विविधीकरण प्रदान करना था ताकि व्यक्तिगत रोजगार में वृद्धि हो, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम किया जा सके और पीछा करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान किया जा सके।

कृषि, व्यवसाय और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, गृह विज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्रों में दो साल की अवधि के लगभग 150 व्यावसायिक पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक स्तर पर पेश किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई "माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण" की योजना की समीक्षा ने योजना की कई कमजोरियों को ध्यान में रखा।

सितम्बर 2011 में अनुमोदित "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण" की योजना को 2014 को कौशल विकास पर कैबिनेट समिति की मंजूरी के साथ संशोधित किया गया था। संशोधन की मुख्य वजह 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना का जारी रहना था, जिसमें हरियाणा के पायलट से NVEQF में उभरती हुई शिक्षाओं को शामिल किया गया और राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (RMSA) की छत्रछाया में इस योजना को शामिल किया गया। अब "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण" के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) एक योग्यता–आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं का आयोजन करता है। एक से दस तक वर्गीकृत इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जिन्हें सीखने वाले को इस बात की परवाह किए बिना होना चाहिए कि क्या उन्हें औपचारिक, गैर–औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया गया है। भारत में एनएसक्यूएफ को 27 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। एचआरडी मंत्रालय द्वारा जारी एनवीईक्यूएफ (राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क) सहित अन्य सभी ढांचे, एनएसक्यूएफ द्वारा अलग किए गए हैं।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क 10 स्तरों से बना है। प्रत्येक स्तर के लिए सक्षमता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक जटिलता, ज्ञान और स्वायत्तता के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेमवर्क का स्तर एक जटिलता के निम्नतम स्तर को प्रदर्शित करता है। स्तर सीखने के परिणामों के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं और वे सीधे अध्ययन के वर्षों की संख्या से संबंधित नहीं होते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NVEQF) के तहत एक व्यापक प्रणाली के रूप में सामान्य शैक्षणिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा को एकीकृत करने का प्रस्ताव करते हैं। NVEQF एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता–आधारित कौशल रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यावसायिक शिक्षा के भीतर और सामान्य दोनों के बीच कई मार्गों के लिए प्रदान करेगा और एक स्तर तक सीखने के एक स्तर को जोड़ने के लिए और शिक्षार्थियों को किसी भी शुरुआती स्तर तक प्रगति करने में सक्षम करेगा।

टिप्पणी

एनवीईक्यूएफ के प्रमुख तत्व

एनवीईक्यूएफ के प्रमुख तत्व निम्न हैं–

- व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता प्रदान करने के लिए हैं;
- व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा और नौकरी बाजार के बीच कई प्रवेश और निकास;
- व्यावसायिक शिक्षा के भीतर प्रगति;
- व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच स्थानांतरण;
- उद्योग–नियोक्ताओं के साथ साझेदारी।

केंद्र और राज्य सरकार की अन्य भूमिका

1. व्यक्तिगत रोजगार, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम करना और इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान करना।
2. व्यावसायिक शिक्षा एक अलग स्ट्रीम है और पाठ्यक्रम सामान्य शिक्षण संस्थानों यानी हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य को सहायता प्रदान करना।
3. उत्पादक कौशल के विकास के लिए प्रावधान करना।
4. व्यक्तिगत रोजगार बढ़ाने, कम करने के लिए अवसर प्रदान करना।
5. कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल और उच्च शिक्षा का पीछा करने वालों के लिए एक विकल्प प्रदान करना।
6. वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए प्रशासनिक ढांचा, क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण स्थापित करने के लिए राज्य पाठ्यक्रम की तैयारी, पाठ्यपुस्तक, कार्य पुस्तक पाठ्यक्रम गाइड, प्रशिक्षण मैनुअल, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शक्ति अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली लागू करना, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि।
7. व्यावसायिक शिक्षा उपयुक्त कौशल विकसित करके कृषि और उद्योग में आत्मनिर्भरता के समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करती है।
8. नौकरियों के लिए व्यक्तियों की तैयारी, व्यक्ति को उसके विकास की रूपरेखा के भीतर अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए तैयार करती है जिसमें व्यक्ति योगदान देता है।
9. शिक्षा नौकरियों का उत्पादन नहीं करती है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा किसी व्यक्ति के लिए नौकरी पाने या जीवन में बहुत जल्दी एक नई उत्पादक गतिविधि या ऐसी सेवा शुरू करने से आसान काम करती है, जो समुदाय की जरूरत को पूरा कर सकती है।
10. शिक्षा की व्यावसायिकता श्रम की गरिमा के विकास के लिए उपयोगी अनुभव प्रदान करती है।

टिप्पणी

11. मांग आधारित योग्यता, माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
12. उचित कार्यान्वयन के लिए योजना, एक अलग प्रबंधन संरचना की स्थापना करना है।
13. शिक्षित और रोजगार के बीच अंतर को भरना और माध्यमिक शिक्षा के ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
14. जमीनी स्तर पर काम करने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह योजना उन नियोक्ताओं के लिए भी सहायक है जो प्रशिक्षण लागत के निवेश को कम कर सकते हैं।

2.5.2 गैर–औपचारिक क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थानों की भूमिका

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन The International Labour Organisation (ILO) अनौपचारिक क्षेत्र को आर्थिक गतिविधि के उस हिस्से के रूप में परिभाषित करता है, जो प्रवेश में आसानी, स्वदेशी संसाधनों पर निर्भरता, परिवार के स्वामित्व, छोटे पैमाने पर संचालन, श्रम गहन तकनीक, औपचारिक स्कूल के बाहर हासिल किए गए कौशल जैसी कुछ विशेषताओं की विशेषता है। प्रणाली, अनियमित और प्रतिस्पर्धी भारतीय संदर्भ में, इस क्षेत्र में उद्योग, परिवहन और कृषि के क्षेत्र में पड़ने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है।

गैर–औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक क्षेत्र

गैर–औपचारिक शिक्षा लचीली है, शिक्षार्थी उन्मुख, गैर–अधिनायकवादी (प्राधिकरण के लिए सख्त आज्ञाकारिता की मांग) और शिक्षार्थी भागीदारी पर बनाया गया है। गैर–औपचारिक कार्यक्रम साझाकरण, खोज (विस्तार से चर्चा), विश्लेषण और पूर्ण सीखने की भागीदारी के साथ न्याय करने की एक प्रक्रिया है। गैर औपचारिक शिक्षा का ग्राहक औपचारिक स्कूलों के ग्राहकों से बहुत अलग है। इनमें से ज्यादातर बच्चे गरीब वर्ग, एससी/एसटी महिलाओं और श्रमिक वर्ग के हैं।

हमारे देश के इतिहास से पता चलता है कि वहां (मुख्य मान्यताप्राप्त शाखा) एजेंसियों यानी आश्रमों, मंदिरों, मस्जिदों, शिक्षा के जैन केंद्रों आदि ने शिक्षा में सक्रिय भाग लिया है, लेकिन उनके पास कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं था। विभिन्न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद, उनकी ध्वनि विकास नीतियों को अपनाने के माध्यम से, अशिक्षा के उन्मूलन के उद्देश्य से योजना और कार्यक्रम, लोगों के जीवन पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं, इस बिंदु पर (ए बिंदु) गैर–सरकारी संगठन (NGO), स्वैच्छिक संगठन Voluntary Organizations (VO) और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व Corporate Social Responsibility (CSR) ग्राहक की साक्षरता स्तर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यहां गैर–औपचारिक शिक्षा का मतलब स्व–रोजगार और छोटे व्यवसाय निर्माण के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में अनौपचारिक क्षेत्र की मदद करना है। इसे मोटे तौर पर परिभाषित किया जा सकता है।

बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में जो साक्षरता, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, बचपन विकास और मातृ शिक्षा, कृषि विस्तार और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यक्रमों में होती है। (शेफर, 1992) 1979–80 के दौरान, गैर–औपचारिक शिक्षा को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में पेश किया गया था, जो विभिन्न कारणों से औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सके।

टिप्पणी

गैर–औपचारिक क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका (NGO)

एक गैर सरकारी संगठन क्या है? गैर सरकारी संगठन शब्द एनजीओवर्जेसल संगठन के लिए है, और इसमें 'निजी स्वैच्छिक संगठन', 'नागरिक समाज संगठन', और 'गैर–लाभकारी संगठन' जैसे कई संगठन शामिल हैं।

गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) का जन्म और पोषण किसी व्यक्ति या समूह की जरूरत के बारे में, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए संरचना के उनके बाद के संगठन के उत्पाद के रूप में हुआ है। श्री पेर्टर बोडेन ने विभिन्न प्रकार के गैर–सरकारी संगठनों जैसे विकास गैर–सरकारी संगठनों, वकालत करने वाले गैर–सरकारी संगठनों, महिला गैर–सरकारी संगठनों, धार्मिक गैर–सरकारी संगठनों, एनवायरोवायरल एनजीओ आदि का उदाहरण दिया है। विश्व बैंक ने गैर–सरकारी संगठनों के लिए एक व्यापक मापदंड बनाया है।

एनजीओ को इस प्रकार परिभाषित किया गया है–

1. यह एक गैर–लाभकारी, स्वैच्छिक, सेवा उन्मुख संगठन है, जो या तो सदस्यों (एक जमीनी स्तर पर संगठन) या लोकलुभावी (एक एजेंसी) के अन्य सदस्यों के लाभ के लिए है।
2. यह निजी व्यक्तियों का एक संगठन है, जो कुछ बुनियादी सामाजिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और जो अपनी गतिविधियों की संरचना करते हैं और लोगों के सशक्तीकरण में सहायता करने वाला एक सामाजिक विकास संगठन है।
3. यह विशिष्ट उद्देश्यों के साथ किसी भी बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है और उन कार्यों को पूरा करता है जो एक संबंधित समुदाय में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए उन्मुख हैं या क्षेत्र या स्थिति यह आर्थिक या सामाजिक रूप से हाशिए के समूहों के सशक्तीकरण के लिए काम करने वाले एक आश्रित, लोकतांत्रिक, गैर–संप्रदाय के लोगों के संगठन में है।
4. यह राजनीतिक दलों से संबद्ध संगठन नहीं है, जो आमतौर पर समुदाय की सहायता, विकास और कल्याण के लिए काम करता है।
5. यह एक ऐसा संगठन है जो विशेष रूप से गरीबों, शोषितों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा या बिना समुदाय के लिए सरकार की ओर से थोड़ा हस्तक्षेप; वे केवल एक चौरिटी संगठन नहीं हैं, बल्कि सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक गतिविधियों पर काम करते हैं।
6. यह एक ऐसा संगठन है जो अपने संगठन में लचीला और लोकतांत्रिक है और स्वयं के लिए लाभ के बिना लोगों की सेवा करने का प्रयास करता है।

टिप्पणी

विश्व बैंक ने अपने मिशनों के संदर्भ में NGOS को भी वर्गीकृत किया है। गैर सरकारी संगठनों के प्रकार हैं– (1) चौरिटेबल एनजीओ (2) सर्विस ओरिएंटेड एनजीओ (3) पार्टिसिपेटरी एनजीओ और (क्लास ऑर्गनाइजेशन) (4) एम्पावरिंग एनजीओ।

अनौपचारिक क्षेत्र के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

- राज्य को सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के पूरक और इसकी प्रभावशीलता में सुधार लाने में राज्य की सहायता करने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
- विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि स्कूली शिक्षा में गैर–सरकारी संगठनों के प्रायोगिक दृष्टिकोण ने सफलतापूर्वक (कठिन समस्याओं से निपटने के लिए) कई कमियों (दोष या कमजोरी) से निपट लिया है।
- शिक्षा में गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी से लाभार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली की जवाबदेही बढ़ जाती है। एनजीओ उत्कृष्टता के द्वीप बनाने के बजाय अपने मॉडल साझा करने के लिए सरकार के साथ साझेदारी स्थापित करते हैं।
- गैर–सरकारी संगठन कार्रवाई की प्रभावशीलता सबसे कम वंचित बच्चों की सफल स्कूली शिक्षा, दूरदराज के स्थानों में समुदायों को निर्धारित करने में सबसे स्पष्ट है।
- गैर–सरकारी संगठन पता लगा सकते हैं और तदनुसार संबंधित प्राधिकारी को सुझाव दे सकते हैं कि विशिष्ट वंचित समूहों के लिए लक्षित क्रियाएं आवश्यक हैं। जैसे शहरी गरीब, बाल श्रमिक या सड़क पर रहने वाले बच्चे गैर–सरकारी संगठन अग्रणी (कुछ के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण है) स्वैच्छिक शिक्षक और वैकल्पिक स्कूल की अवधारणाओं को शिक्षक की अनुपस्थिति का मुकाबला करने और स्कूली बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए करते हैं।
- सरकार और गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग एक व्यापक नीति के रूप में, भारत में राज्य शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी में प्रवेश करता है, जिसमें भागीदारी के विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य और इसके प्रशासनिक विभागों से कार्यान्वयन का कुछ बोझ उठाना पड़ता है। इस प्रकार राज्य की प्रकृति राज्य और गैर सरकारी संगठनों के बीच संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- राज्य को विकास के एजेंडे को प्रभावित करने के लिए तैनात किया गया था और इसलिए न केवल विकास के लिए रूपरेखा निर्धारित की बल्कि इस ढांचे (सेन 1999) के भीतर एनजीओ की भूमिका को भी परिभाषित किया।
- भारत में गैर–सरकारी संगठनों की वास्तविक संख्या विशेष रूप से रोजगार सृजन और रोजगार से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकासात्मक कार्यों में लगी हुई है।
- ग्रामीणों और संस्था के बीच संबंध (NGO) उन संस्थानों के संबंध में सबसे मजबूत है जो प्रौद्योगिकी, डिजाइन, वित्त और सामान्य इनपुट प्रदान करते हैं।
- समाज के वंचित वर्गों की कर्तव्यनिष्ठा और गतिशीलता के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।

टिप्पणी

गैर–औपचारिक क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

सीमित संसाधनों के साथ समस्या की सघनता, ज्ञान और कौशल की खाई को भरने के लिए औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए बेहद कठिन है। इसके अलावा, भारत में औपचारिक शिक्षा अप्रभावी होने के लिए जानी जाती है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती है, अकसर उन्हें अपने पारंपरिक व्यवसायों से दूर कर देती है। यही कारण है कि गैर–औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण तेजी से एक अधिक प्रभावी विकल्प माना जा रहा है और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका अहम है।

1. **गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड**– भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक, गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य उन समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है, जो इसके साथ काम करते हैं और सतत विकास सुनिश्चित करते हैं। फाउंडेशन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, महिलाओं के विकास, आजीविका, बंजर भूमि विकास, कृषि विकास, एड्स जागरूकता, स्कूलों को गोद लेने और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना के क्षेत्रों में काम करता है।
2. **अजीम प्रेमजी फाउंडेशन**– यह फाउंडेशन विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी द्वारा चलाया जाता है, जो हजारों कम उम्र के बच्चों को प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। इसने सरकार के साथ साझेदारी की है और संरचना और प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी संगठनों में शिक्षा वितरण प्रणाली और निर्माण क्षमता को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नींव 2001 में चालू हो गई, और वर्तमान में 14,000 से अधिक स्कूलों के साथ 15 भारतीय राज्यों की सरकारों के साथ साझेदारी में लगी हुई है।
3. **माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (भारत)**– माइक्रोसॉफ्ट कॉपोरेशन इंडिया ने सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को किफायती सॉफ्टवेयर समाधान, व्यापक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक केंद्रित कार्यक्रम, प्रोजेक्ट शिक्षा, तैयार किया है। कार्यक्रम के तहत अधिक स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिए आईटी साक्षरता में काम करता है।
4. **सिटी बैंक**– यह जरूरतमंदों को आवास सहायता प्रदान करने, वित्तीय रूप से निरक्षर लोगों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके सीएसआर प्रयासों को सिटीग्रुप फाउंडेशन के माध्यम से रूट किया जाता है जहां यह सालाना अपने लाभ का 1 प्रतिशत दान करता है। उसका अधिकांश प्रयास शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है।
5. **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)**– एचपीसीएल समाज और पड़ोसी समुदायों की भलाई के लिए एक साथ वर्षों से सक्रिय है। HPCl द्वारा ली गई परियोजनाएं हैं–

   उन्नाव : विशाखापट्टनम और मुंबई के अर्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 स्कूली छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना। समाज की कमजोर, सीमांत

टिप्पणी

(मुख्य धारा में नहीं) वर्ग की 500 छात्राओं का समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना कि वे शिक्षा को बीच में न छोड़ें; इसके बजाय यह सुनिश्चित करना कि वे पदार्थ की सशक्त महिलाओं में विकसित हों।

विकास : यह सुनिश्चित करने के लिए कि 5,500 बच्चे उपचारात्मक कक्षाओं, पुस्तकालय तक पहुंच और बाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।

मुस्कान : समय की अवधि के लिए (अपने कानूनी माता–पिता के बिना किसी और के बच्चे को अपने परिवार में लेने के लिए) पालक प्रदान करना, बोर्डिंग, लॉजिंग, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

गैर–औपचारिक क्षेत्र में अन्य संस्थानों की भूमिका

व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन में शामिल मुख्य एजेंसियों में शामिल हैं–

केंद्र सरकार

- राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में TVET कार्यक्रमों के लिए)
- उच्च शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा के लिए)
- श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए)
- कुछ अन्य 20 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग हैं जिनके पास कुछ छोटे टीवीईटी कार्यक्रम हैं।

राज्य सरकार

- तकनीकी शिक्षा निदेशालय
- निजी क्षेत्र
- गैर सरकारी संगठन
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसीएस)।

श्रम मंत्रालय में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी), भारत सरकार ने 1950 में देश के प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के लिए कुशल मानव शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में कौशल प्रदान करने के लिए लगभग 50 आईटीआई की स्थापना करके सीटीएस की शुरुआत की।

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र स्तर के शिल्प प्रशिक्षण को संदर्भित करता है और उन छात्रों के लिए खुला है, जिनकी आठवीं – बारहवीं कक्षा से कहीं भी पढ़ाई पूरी होने के बाद स्कूल छोड़ दिया जाता है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत प्रशासित कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आईटीसी) द्वारा संचालित किए जाते हैं।

टिप्पणी

जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों की भूमिका

1. **जिला स्तर की एजेंसियों की भूमिका**– जिला व्यावसायिक शिक्षा समिति (DVEC) का संयोजक जिला व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी (DVEO) है। जिला व्यावसायिक शिक्षा अधिकारी (संयोजक) स्कूल उद्योग लिंकेज की संस्था को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाता है। यह उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थिति पर चर्चा करने, पीटीसी की ताकत और कमजोरी का आकलन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक अकादमिक वर्ष में कम से कम तीन बार मिलते हैं।

2. **राज्य स्तरीय एजेंसियों की भूमिका**– ये व्यावसायिक शिक्षा विभाग (SDVE), व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय, बोर्ड/माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, S.I.V. या SCERT में व्यावसायिक विंग है। राज्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थान नीतियों और कार्यक्रम के मामलों पर DVEC को शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है।

   शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा राज्य में प्रशासनिक सेटअप के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है।

3. **राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों की भूमिका**– पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान +2 स्तर के वोकेशनल इंस्टीट्यूशन और संबंधित केंद्रों में उत्पादन–सेंटरिंग सेंटर की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद (JCVE) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करता है। व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ संबंध रखता है और कार्यक्रम की निगरानी करता है। JCVE समय–समय पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम और PTC की भी समीक्षा करता है।

मुख्य एजेंसियां जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देती हैं

वीईटी कार्यक्रमों को रोजगार के अवसर पैदा करने और स्व–रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्रदान करने पर लक्षित किया जाता है, विशेष रूप से ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र (अग्रवाल, 2013) में भारत में विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कई एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

1. स्कूल शिक्षा के एक भाग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली एजेंसियां।
2. स्कूली शिक्षा के बाहर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली एजेंसियां।

नीचे इन एजेंसियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

टिप्पणी

स्कूल शिक्षा के एक भाग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली एजेंसियां

माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 1988 में एमएचआरडी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा निर्देश प्रदान करती है और इसे स्कूलों में शिक्षा की सामान्य धारा का एक विकल्प माना जाता है। यह प्रबंधन संरचना, पाठ्यक्रम डिजाइन, बुनियादी ढांचे के विकास, व्यावसायिक सर्वेक्षण, अनुदेशात्मक सामग्री, शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण, स्कूल–उद्योग संपर्क, परीक्षा और प्रमाणन, और अन्य पहलुओं के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह योजना उच्च माध्यमिक स्तर यानी XI और XII में दो वर्ष की अवधि के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करती है। यह योजना केंद्र, राज्य और संघ के शिक्षा बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), इस योजना को एक विशिष्ट व्यावसायिक धारा के रूप में उच्च माध्यमिक स्तर पर लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, CBSE देश के लगभग 500 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 107 विषय वाले 34 व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है (MHRD, 2014b)। सीबीएसई प्रासंगिक उद्योग/संगठन के सहयोग से इस तरह के और पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास कर रहा है, और संयुक्त प्रमाणन के लिए सुविधाएं हैं। 12 वें योजना आयोग (2012–2017) के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिकता की योजना राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत शुरू की है।

व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली विद्यालयी शिक्षा के बाहर की एजेंसियां

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) स्कूली शिक्षा से बाहर व्यावसायिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक (DGET) की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह नोडल विभाग है जो नीतियों को तैयार करने, मानकों को पूरा करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यापार परीक्षण और प्रमाणन आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तर के निदेशक जनरल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं। प्रशिक्षण दो अलग–अलग योजनाओं– प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

अन्य लघु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली अन्य एजेंसियां

डीजीईटी के अलावा अन्य कई मंत्रालय और एजेंसियां हैं जो अपने विशिष्ट क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। उनमें से कुछ स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि मंत्रालय शामिल हैं। कपड़ा आदि और एजेंसियां हैं– राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS)।

- ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Open Schooling)– एनआईओएस प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक ओपन और डिस्टेंस मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें अपने अध्ययन–सह के एक नेटवर्क के माध्यम से सामान्य और प्राथमिकता वाले समूहों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, ग्रामीण लोगों,

टिप्पणी

नव–साहित्यकारों, विकलांग और वंचित समूहों आदि) को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का अधिकार है।

- जनशिक्षण संस्थान JAN SHIKSHAN SANSTHAN (JSS)– JSS को MHRD के एक वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यावसायिक कौशल और गुणवत्ता में सुधार करना है। जेएसएस ने व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला स्तर पर पुनर्जीवित होने का काम किया है।

गैर–औपचारिक शिक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार एजेंसियां

1. राष्ट्रीय संविधान के तहत, 1976 तक शिक्षा एक राज्य का मामला था। 1976 में समवर्ती (मौजूदा या एक ही समय में) सूची में शिक्षा को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था (मामूली बदलाव या सुधार करने के लिए)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डिजाइन के प्रारंभिक प्रयास 1968 में किए गए थे लेकिन 1986 में भारत में शिक्षा पर एक समान राष्ट्रीय नीति थी।
2. 1992 में संशोधित शिक्षा नीति 1986 में, 14 साल तक के बच्चों की सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण (कुछ धारण करने की क्षमता) और शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के रूप में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रमुख लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है।
3. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1994 में शुरू की गई जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) और 2001 के राष्ट्रीय शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) जैसे कई कार्यक्रमों के साथ चली गई है।
4. शिक्षा के अधिकार पर एक प्रस्तावित बिल (मसौदा, नवंबर 2005) 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के अधिकार पर जोर देता है जब तक कि उनका 15 वां जन्मदिन प्राथमिक शिक्षा या तो स्कूल या गैर–औपचारिक शिक्षा (एनएफई) प्राप्त करने के लिए नहीं होता है।
5. 1979–80 में, भारत सरकार, शिक्षा विभाग ने 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर–औपचारिक शिक्षा (एनएफई) का एक कार्यक्रम शुरू किया, जो नियमित स्कूलों में शामिल नहीं हो सकते – ड्रॉप–आउट, कामकाजी बच्चे, बच्चों से स्कूलों आदि के लिए आसान पहुंच के बिना क्षेत्र। योजना का प्रारंभिक फोकस शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर था। बाद में, इसे शहरी मलिन बस्तियों और अन्य राज्यों में पहाड़ी, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।

गैर–औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पेशेवर सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियां इस प्रकार हैं–

केंद्रीय स्तर की एजेंसियां

1. **नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (NCERT)**– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सर्वोच्च (उच्चतम बिंदु) संसाधन संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग के साथ है। स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक

टिप्पणी

मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह करना। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।

2. **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NIEPA)**– नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA), नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NUEPA), जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित है, क्षमता निर्माण और अनुसंधान से निपटने वाला एक प्रमुख (पहला महत्वपूर्ण) संगठन है। न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा की योजना और प्रबंधन। 1962 में नेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जब यूनेस्को ने 1965 में एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर की स्थापना की, जो 1965 में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। इसे 1979 में फिर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA) नाम दिया गया।)

3. **केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET)**– सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (CIET)– सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, NCERT की एक घटक इकाई है जो वर्ष 1984 में सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स के विलय के साथ अस्तित्व में आई। CIET शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। जैसे– रेडियो, टीवी, फिल्में, सैटेलाइट संचार और साइबर मीडिया आदि। यह संस्थान इक्विटी को बढ़ावा देने और स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गतिविधियों का संचालन करता है।

राज्य स्तर की एजेंसियां

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी के जिला संस्थान (DIETs)
- सतत शिक्षा के लिए केंद्र (CCE)

1. **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद** (State Council for Educational Research and Training–SCERT)– स्कूल शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने के लिए, हरियाणा शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2015 में राज्य के शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान को दो संस्थानों में विलय कर दिया। अनुसंधान और प्रशिक्षण (एससीईआरटी)। इस परिषद का मुख्य कार्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना है। हरियाणा शिक्षा विभाग का दृढ़ विश्वास है कि स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों के शैक्षिक मानकों में सुधार किया जाना चाहिए।

2. **शैक्षिक प्रौद्योगिकी के जिला संस्थान** (District Institutions of Educational Technology–DIET)– NCERT (1961 में स्थापित) और SCERT (1970 में स्थापित) जिले में प्रशिक्षण और संसाधन सहायता संरचना के तीसरे स्तर के संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारण DIAS की स्थापना

टिप्पणी

हुई। इसका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। परिणामस्वरूप देश के सभी राज्यों के लगभग सभी जिलों में DIET की स्थापना की गई।

3. **सतत शिक्षा के लिए केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान** (The Indian Institute of Science–IISc)– लंबे समय से उद्योगों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रतिष्ठानों में योग्य तकनीकी कर्मियों के लिए अपनी विशेषज्ञता और सुविधाएं उपलब्ध कराने के तरीकों से संबंधित था। छोटे पैमाने पर, संस्थान की सुविधाओं का उपयोग हमेशा अल्पकालिक / पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन इन गतिविधियों को एक एकल प्रविष्टि द्वारा समन्वित नहीं किया गया था। ऐसी सभी गतिविधियों के लिए और विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों की एक किस्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने के लिए 1975–76 में सतत शिक्षा केंद्र (The Centre for Continuing Education–CCE) की स्थापना की गई थी।

शिक्षा संबंधी नियमों का पालन शिक्षा की औपचारिक और गैर–औपचारिक धाराएं मूल रूप से सदियों पहले स्वेच्छा से शुरू की गई थीं। सरकार बहुत बाद में सामने आई। धार्मिक निकायों के अपने रुचि वाले क्षेत्रों– मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के माध्यम से हजारों पुरुषों और महिलाओं को ज्ञान प्रदान किया जाता है। साथ ही, औपचारिक और गैर–औपचारिक श्रेणी की शिक्षा में उनकी भूमिका काफी बड़ी है। राज्य ने एक सहायक या सह–समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य किया हो सकता है। यहां तक कि अच्छी तरह से प्रशासित राज्य सभी तक नहीं पहुंच सकते हैं और एक स्वैच्छिक समूह के रूप में प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। राज्य केवल इन प्रयासों का समन्वय कर सकते हैं जो इस तरह के गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संस्थानों द्वारा शुरू किए गए हैं।

2.5.3 व्यावसायिक संस्थानों के शिक्षक और प्रमुख की भूमिका, कर्तव्य और गुण

इक्कीसवीं सदी (21 वीं) एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था और समाज प्रस्तुत करती है, जिसका तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (Technical Vocational Education and Training–TVET) पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। TVET प्रणाली को इन प्रमुख विशेषताओं जैसे वैश्वीकरण, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT), और स्थिरता के अनुकूल होना चाहिए। यूनेस्को के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, अधिकांश अफ्रीकी देशों में, प्राथमिक नामांकन में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन सामान्य माध्यमिक शिक्षा में पर्याप्त स्थान नहीं है और न ही रोजगार की गारंटी के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए बढ़ती मांग का जवाब देने का एकमात्र तरीका युवाओं को काम की दुनिया तक पहुंचने के लिए नई टीवीईटी रणनीतियों को तैयार करना है।

इस तरह की रणनीतियों को बहुपक्षीय पहलुओं और शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न रूपों, औपचारिक, गैर–औपचारिक और अनौपचारिक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण एक अद्भुत पेशा है जो मानव जाति के ज्ञान की खोज के बाद से आज तक है। शिक्षक प्रशिक्षण बहुत आसान है जितना कि कई लोग सोच सकते हैं कि एक शिक्षक को न केवल पढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है,

बल्कि शिक्षण द्वारा एक जलती हुई इच्छा और एक जुनून भी होना चाहिए। इस लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षक और प्रमुख की भूमिका, कर्तव्य और गुण जानना आवश्यक है।

शिक्षक और प्रमुख के पास प्रशिक्षण संस्थान में कार्य के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं–

टिप्पणी

- **प्रबंधक**– शिक्षक मानव संसाधन यानी छात्रों के साथ–साथ भौतिक संसाधनों यानी उपकरण, सुविधाओं आदि का प्रबंधन करता है। छात्रों के साथ व्यवहार करते समय शिक्षकों को सहज रहना चाहिए, अपने ज्ञान को साझा करना चाहिए, यथार्थवादी लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए और असफलता का सामना करना चाहिए।
- **फैसिलिटेटर डेवलपिंग लाइफ**– तेजी से बढ़ते ज्ञान विस्फोट के साथ निर्णय लेने, समस्या हल करने, महत्वपूर्ण सोच आदि के लिए जैसे कौशल, विषय विशेषज्ञता विकसित करना।
- **मूल्यांकनकर्ता**– शिक्षक न केवल छात्रों (सतत और व्यापक) का मूल्यांकन करता है, बल्कि वह स्वयं भी कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री और खुद का मूल्यांकन करता है।
- **गाइड और काउंसलर**– शिक्षक में मित्र, विश्वासपात्र, सलाहकार,व्यावसायिक अनुसंधान की मानसिकता, प्रस्तुतिकरण का संचार (संचार, यांत्रिकी, वितरण, अनुकरण और शिक्षण के कौशल) अनुशासन बनाए रखने की क्षमता, तकनीकों का मूल्यांकन करने की क्षमता, प्रतिक्रिया से निपटने की योग्यता होनी चाहिए।
- **नियोजन–प्रक्रिया**– जिसके द्वारा एक प्रबंधक भविष्य की ओर देखता है और उसके लिए खुले वैकल्पिक क्रियाकलापों की खोज करता है।
- **नियंत्रण**– वह प्रक्रिया जो वर्तमान प्रदर्शन को मापती है और इसे कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है।
- **निर्देशन**–वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वास्तविक प्रदर्शन के द्वारा अधीनस्थों को सामान्य लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया जाता है।

एक आयोजक के रूप में (As an Organizer)

- **एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन**– प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर, प्रशिक्षक को आगे का विश्लेषण करके संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना होगा।
- **प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना**– पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले प्रशिक्षक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक जैसे पाठ योजना, सूचना पत्र, प्रशिक्षण सहायक, प्रदर्शन योजना आदि तैयार करने होते हैं, इसके लिए बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है।
- **एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन**– एक व्यावसायिक प्रशिक्षक का मुख्य काम प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना है, जिसमें योजना, तैयारी, प्रस्तुति, परीक्षण और मूल्यांकन शामिल हैं।

टिप्पणी

- **कार्यशाला में प्रदर्शन**– विशेष कौशल प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित कदम होंगे जिनका पालन किया जाना है। उदाहरण के लिए, एक कपड़े की सिलाई, एक प्रशिक्षक को चाकबोर्ड पर शैली की विशेषता खींचनी है। फिर इंस्ट्रक्टर को बोर्ड या पेपर पर उसी की ड्राफ्टिंग करनी होती है। पेपर पैटर्न को कपड़े पर चिह्नित किया जाता है और फिर कटिंग का प्रदर्शन किया जाता है। कटे हुए कपड़े को सिलाई मशीन की मदद से सिल दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में भाग लेने से प्रशिक्षु पूरी कटाई और सिलाई प्रक्रिया सीखेंगे।
- **अभिवृत्ति निर्माण को सक्षम करना**– एक प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के प्रति प्रशिक्षुओं के दृष्टिकोण को सुधारने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करना होगा जिसके बिना वे उस कौशल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे जो सिखाया गया है।
- **मूल्यांकन और ग्रेडिंग का प्रदर्शन**– कोई भी प्रशिक्षण पूरा नहीं होता है अगर उसका सही तरीके से मूल्यांकन और वर्गीकरण नहीं किया जाता है। प्राप्त किए गए अनुदेशात्मक उद्देश्यों की सीमा को परीक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से जाना जाएगा। ग्रेडिंग से शिक्षार्थियों को पिछले परीक्षण की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। शिक्षण में प्रशिक्षक की दक्षता मूल्यांकन और ग्रेडिंग के माध्यम से भी की जा सकती है।

एक प्रबंधक के रूप में (As a Manager)

- **उपकरणों का रखरखाव**– प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक प्रशिक्षक को पाठ्यक्रम के अनुसार सभी उपकरणों की खरीद करनी होगी और उन्हें ठीक से बनाए रखना होगा।
- **व्यावहारिक प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण**– व्यावहारिक अभ्यास के दौरान प्रशिक्षक के साथ प्रशिक्षक का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। बस प्रशिक्षुओं को सैद्धांतिक ज्ञान देकर और फिर उन्हें व्यावहारिक काम करने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है। लेकिन प्रशिक्षुओं की देखरेख और मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षक शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए।
- **संस्था के साथ संपर्क**– प्रशिक्षक प्रशासन और प्रशिक्षुओं के बीच की कड़ी है। तो प्रशिक्षक को प्रशासन को व्यापार की प्रशिक्षण गतिविधि के बारे में सूचित करना होगा, साथ ही प्रशिक्षक को छात्र को प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बारे में भी सूचित करना होगा। एक छात्र के रूप में वोकेशनल इंस्ट्रक्टर को हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहिए, और नवीनतम तकनीकों में बदलाव के आधार पर नई तकनीकों के साथ स्किल करना चाहिए।

शिक्षार्थियों प्रशिक्षुओं के प्रति जिम्मेदारी

- प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए संस्थान में आते हैं और उद्देश्य एक सक्षम शिल्पकार बनना है।
- प्रशिक्षुओं के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन और निर्देश देना चाहिए और अनुसूची के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना चाहिए।

- प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और आवश्यक स्तर से औसत स्तर से नीचे आने वाले प्रशिक्षु को लाता है।
- प्रशिक्षुओं के लिए व्यवहारिक और सुरक्षित कामकाजी आदतों को विकसित करता है जो कच्चे माल का आर्थिक रूप से उपयोग करने के लिए दिया जाता है जो सीखने के उद्देश्य से दिया जाता है।
- कार्यशाला की सुरक्षा, समय की पाबंदी, समय प्रबंधन आदि जैसी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए।

प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी

प्रशिक्षक के रूप में वह प्रशिक्षुओं और प्रशासन के बीच की कड़ी हैं, उन्हें होना चाहिए–

- प्रशासन के प्रति वफादार और ईमानदार।
- प्रशिक्षुओं की कामकाजी नीतियों का व्याख्याकार और संचारक और प्रशासन का सहायक।
- एक व्यक्ति जो अतिरिक्त निपटान द्वारा सामग्री को बर्बाद नहीं करता है।
- अनुशासन बनाए रखने में सक्षम है और प्रशासन को किसी भी घटना के होने की सूचना भी देता है।

उद्योगों के प्रति जिम्मेदारी

चूंकि औद्योगिक प्रतिष्ठान लाभार्थी हैं, प्रशिक्षक को चाहिए–

- शिक्षार्थी के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव का सुझाव दें। उद्योगों में नवीनतम तकनीक, उपकरण, सामग्री के बारे में खुद को अपडेट रखें।
- क्षेत्र के दौरे और प्लेसमेंट आदि द्वारा उद्योगों के साथ संपर्क रखना।

समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी

- समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।
- उन्हें यह एहसास कराना कि जब उन्हें समाज से कुछ मिलता है तो उन्हें भी समाज में योगदान देना होगा।
- एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो अंततः एक राष्ट्र के निर्माण में मदद करे।
- प्रशिक्षुओं को एक राष्ट्र के निर्माण की इस भावना को विकसित करना चाहिए।

खुद के प्रति जिम्मेदारी– प्रशिक्षक का काम एक नेक काम है और नौकरी करने के दौरान बहुत सी जिम्मेदारियां हैं।

- पेशे के प्रति वह ईमानदार होता है।
- उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करता है।
- सुखद शिष्टाचार को बढ़ावा देता है।
- पेशे की गरिमा को बनाए रखता है।
- अच्छा स्वास्थ्य रखता है और ज्ञान को अद्यतन करता है।
- शिक्षण में रुचि लेता है।

टिप्पणी

पेशे के प्रति जिम्मेदारी

- नवीन तरीकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना।
- शोध निष्कर्षों के मूल आधार और आवेदन को समझना।
- बेहतर और परीक्षणित नई रणनीतियों और तकनीकों का पालन करना।
- आत्म सुधार के लिए स्व अध्ययन सामग्री का उपयोग करना।

शिक्षक और प्रमुख के कर्तव्य

शिक्षक और प्रमुख कर्तव्य निम्न हैं–

1. **ज्ञान प्रदान करना**– एक व्यावसायिक शिक्षक का प्राथमिक कार्य विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। यद्यपि अधिकांश व्यावसायिक शिक्षक कक्षा निर्देश प्रदान करते हैं, लेकिन उनके अधिकांश शिक्षण में उनके छात्रों को कौशल का प्रदर्शन करना शामिल है। उदाहरण के लिए, वे उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुरक्षित और उचित उपयोग पर छात्रों को निर्देश दे सकते हैं।
2. **परीक्षा**– सभी शिक्षकों की तरह, व्यावसायिक शिक्षकों को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या व्यक्तिगत छात्र पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षक आमतौर पर किसी छात्र की प्रगति का अनुमान लगाने के लिए लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षाएं देते हैं। छात्रों को भी एक परियोजना को पूरा करने या किसी विशेष कौशल का प्रदर्शन करके अपनी प्रवीणता साबित करनी पड़ सकती है।
3. **संबंध स्थापित करना**– कुछ व्यावसायिक विषयों में एक प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप या अन्य हाथों से अनुभव शामिल हो सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षकों को कभी–कभी नौकरी के अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने छात्रों के लिए स्थान खोजने के लिए स्थानीय व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों या ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करनी चाहिए। शिक्षकों को भी कैरियर के रुझानों पर अप–टू–डेट रहना चाहिए, कौशल नियोक्ताओं की आवश्यकता है और लाइसेंस प्राप्त छात्रों को अपने चुने हुए व्यवसायों पर काम करने की आवश्यकता होगी।
4. **रिकॉर्ड बनाए रखें**– व्यावसायिक शिक्षकों को छात्र असाइनमेंट, ग्रेड और उपस्थिति के रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहिए। जब छात्र एक नियोक्ता के साथ नौकरी पर प्रशिक्षण शुरू करते हैं, तो व्यावसायिक शिक्षक भी प्रारंभ दिनांक, नियोक्ता मूल्यांकन और संबंधित पत्राचार के रिकॉर्ड रखता है। अपने छात्रों की उम्र के आधार पर, व्यावसायिक शिक्षकों को अगले स्तर पर पाठ्यक्रमों पर फाइलें बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है।
5. **जागरूक**– छात्रों को समझने के लिए और स्कूल और काम के बीच के संबंध के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से संक्रमण योजना के परिणामों को उचित रूप से निर्धारित करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए एक व्यापक व्यावसायिक मूल्यांकन योजना डिजाइन करें।
6. **अनुभव**– छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल और सामुदायिक वातावरण में कार्यशाला के

भीतर स्थितिजन्य व्यावसायिक आकलन के लिए मूल्यांकन डिजाइन विकसित करना और प्रदान करना।

7. **सहयोग**– सहयोग और योजना के उद्देश्य के लिए छात्रों, कर्मचारियों, अभिभावकों और प्रशासन के साथ प्रभावी संचार बनाए रखें।
8. **व्यावसायिक मूल्यांकन**– छात्र व्यावसायिक मूल्यांकन परिणामों के बारे में माता–पिता से संवाद करने और संक्रमण योजनाओं की दिशा में प्रगति के लिए प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक माता–पिता के सम्मेलन आयोजित करें।
9. **अतिरिक्त रोजगार**– अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने, नौकरी के डिब्बों की देखरेख करने और छात्र प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एनएसएसईओ को नौकरी के कार्य स्थानों या आश्रय कार्य स्थलों को विकसित करना।
11. **अन्य कर्तव्य**–
    - पाठ्यक्रम को रोचक बनाना चाहिए।
    - ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना चाहिए।
    - प्रशिक्षुओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
    - प्रशिक्षुओं के हित को मानना चाहिए।
    - बड़े करीने से कपड़े पहनने चाहिए।
    - सामाजिक रूप से लचीला होना चाहिए।
    - विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने चाहिए।
    - एक मिलनसार व्यक्तित्व होना चाहिए।
    - विषय का सही ज्ञान होना चाहिए।
    - दृष्टिकोण के समान (संतुलित) और व्यवसाय होना चाहिए।
    - बहुत उत्साह दिखाना चाहिए।
    - कई दृष्टांतों का उपयोग करना चाहिए।
    - मधुर आवाज होनी चाहिए।
    - आसानी से जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।
    - एक उदार माननीय दृष्टिकोण होना चाहिए।
    - हस्तांतरण और आवेदन के लिए ज्ञान कौशल का उपयोग करना चाहिए।
    - उचित रूप से सख्त होना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए।
    - शिक्षण सामग्री को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
    - मूल्यांकन में निष्पक्ष होना चाहिए।
    - उचित प्रशिक्षण रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
    - समय का पाबंद होना चाहिए।
    - आर्थिक रूप से उपकरण, सामग्री और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।

टिप्पणी

टिप्पणी

शिक्षक और प्रमुख के गुण

शिक्षक और प्रमुख में निम्न गुण होने आवश्यक हैं–

1. **संचार कौशल** (Communication)– प्रभावी संचार व्यवसाय और अंतरंग वातावरण दोनों में अधिग्रहण करने के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। यह सफल और यादगार रिश्तों की जड़ है। शिक्षण के मामले में, शिक्षक के रूप में मजबूत संचार कौशल का होना शिक्षक–छात्र के तालमेल के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है, और वास्तव में छात्रों के लिए एक भरोसेमंद वातावरण बनाना है।
2. **सुनना** (Listening)– एक अच्छा शिक्षक और प्रमुख होने का मतलब है कि आपके छात्र आपकी बात सुनते हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप सुनें और अपने छात्रों को उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ध्यान दें जो उन्हें चाहिए। आपको सुनने के पीछे की कहानी आपको अपने छात्रों को बेहतर समझने की अनुमति देती है। सुनने के कौशल के माध्यम से, शिक्षक एक मजबूत, स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण वातावरण बनाने में सक्षम हैं।
3. **दोस्ताना रवैया** (Friendly)– एक दोस्ताना रवैया सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। अपने छात्रों के प्रति एक दोस्ताना रवैया व्यक्त करना आपको अधिक स्वीकार्य बनाता है, और छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने की अधिक संभावना है। अधिक अनुमानित होने के कारण, छात्र प्रश्न पूछने में अधिक सहज महसूस करेंगे। यह बदले में छात्र–शिक्षक संचार को बढ़ाएगा और सीखने के अधिक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेगा।
4. **मजबूत नैतिक कार्य** (Moral)– नैतिक होना एक महत्वपूर्ण गुण है। एक मजबूत नैतिकता हमेशा आपके छात्रों और उनके काम को वितरित करने पर प्रतिबिंबित करेगी। एक रोल मॉडल के रूप में, एक मजबूत कार्य नीति होने से आपके छात्रों को मजबूत कार्य नीति विकसित करने में मदद मिलेगी, अच्छे काम के साथ नैतिकता में व्यावसायिकता, जिम्मेदारी और तैयारी आती है।
5. **संगठनात्मक कौशल** (Organizational)– संगठनात्मक कौशल के बिना, एक शिक्षक वास्तव में समय सीमा, अपेक्षाओं और कार्यों की समझ खो सकता है। अधिकांश शिक्षक अपनी कक्षा पूरी होने के बाद, अपनी अगली कक्षा के लिए ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ नोट्स लेते हैं। इस तरह, एक शिक्षक आसानी से अगली कक्षा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार कर सकता है, और यह भी जान सकेगा कि उसने कहां छोड़ा था।
6. **अनुशासन कौशल** (Discipline)– मजबूत और प्रभावी अनुशासन कौशल कक्षा के भीतर सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने में सक्षम होगा। एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए कक्षा अनुशासन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जो सीखने को बढ़ावा देता है।
7. **सम्मानजनक मनोवृत्ति** (Respect)– सम्मान सब कुछ है, काम के हर क्षेत्र में और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में। एक व्यक्ति के रूप में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षक के रूप में अपने कार्यों के लिए सम्मानजनक और जिम्मेदार होना महत्वपूर्ण है।

टिप्पणी

8. **सहानुभूति** (Sympathy)– सहानुभूति एक महत्वपूर्ण गुण है। बच्चों और युवाओं में बड़ी भावनाएं हैं और अकसर हम कक्षा के बाहर जितना जानते हैं उससे अधिक व्यवहार करते हैं। एक शिक्षक के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि वे जो महसूस कर रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रखने में सक्षम हों, भले ही यह एक बड़ी बात न लगे।
9. **सहयोग कौशल** (Collaboration)– स्कूल के प्रमुख मानदंड में से एक के रूप में, आप अपने कर्मचारियों और छात्रों की टीम को सफल बनाने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप विकसित हुए हैं और यह प्रदर्शित करने में सक्षम हैं कि आप कैसे एक के रूप में स्कूल को एकजुट करने और संकट या परिवर्तन के समय में नेतृत्व करने में सक्षम हैं।
10. **समन्वय** (Co-ordination)– छात्रों और कर्मचारियों के संबंध में संभावना से अधिक आपका विशेष विद्यालय एक बहुसांस्कृतिक मेल्टिंग पॉट है। यह आवश्यक है कि आप सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, चाहे लिंग, जाति, आयु, पंथ, सामाजिक–आर्थिक स्तर आदि। आपको कई अलग–अलग व्यक्तित्वों के साथ काम करना सीखना होगा – कुछ के साथ में काम करना बहुत आसान होगा। अपने कर्मचारियों को व्यक्तियों के रूप में जानने के लिए समय निकालें, जानें कि उनमें से कौन किस व्यक्तित्व प्रकार में आते हैं, और यह पता लगाते हैं कि उनके अनुसार कैसे समन्वय किया जाए।
11. **सकारात्मक सुदृढ़ीकरण** (Positivity)– सकारात्मकता एक महान प्रेरणा शक्ति हो सकती है। छात्रों और कर्मचारियों को सकारात्मक प्रोत्साहन प्रदान करने से, जैसे कि उन्हें यह बताना कि आप उन पर गर्व कर रहे हैं या अच्छी तरह से किए गए काम के लिए उन्हें पुरस्कृत करना।
12. **सर्वश्रेष्ठ व्यवहार** (Best Practice)– अनुभवी और नए स्कूल प्रशासकों के साथ सर्वश्रेष्ठ व्यवहार साझा करें जैसा कि पुरानी कहावत है, दो सिर एक से बेहतर हैं। एक ही क्षेत्र में अन्य पेशेवरों के साथ काम करके, आप विभिन्न विषयों पर अलग–अलग दृष्टिकोण सुन पाएंगे। यदि यह पहले से ही नहीं है, तो जिले भर के शिक्षकों और प्रशासकों के साथ मासिक बैठक आयोजित करने का प्रयास करें।
13. **शारीरिक / भौतिक गुणवत्ता** (Physical Quality)– पहनावे की शैली, व्यक्तिगत सौंदर्य की आदतें, और समग्र रूप से सभी एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। यदि आप एक गंभीर पेशेवर के रूप में लिया जाना चाहते हैं, तो आपको एक की तरह कपड़े पहनने होंगे। अपने कपड़ों के अलावा, यह सुनिश्चित करें कि आप व्यक्तिगत रूप से तैयार रहें – बौछार, कंघी या स्टाइल किए हुए बाल, ताजा सांस, साफ नाखून आदि।
14. **भाषा और भाषण** (Language – Speech)– एक प्रशिक्षक की भाषा सरल और स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए। यह सजावटी और व्याकरणिक रूप से गलत नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षक को एक अच्छा संचालक बनने के लिए खुद को विकसित करना चाहिए।

टिप्पणी

2.5.4 भोपाल में केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की भूमिका

पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (PSSCIVE–1993), भोपाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की एक घटक इकाई है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

यह संस्थान केंद्र और राज्य सरकारों को नीतिगत योजना और शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के व्यावसायिक विकास के कार्यान्वयन की सलाह देता है और सहायता करता है। यह स्कूलों में शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और ई–शिक्षण सामग्री विकसित करता है।

संस्थान के छह विभाग हैं–

(1) कृषि और पशुपालन,

(2) व्यापार और वाणिज्य,

(3) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी,

(4) स्वास्थ्य और पैरामेडिकल,

(5) गृह विज्ञान और आतिथ्य प्रबंधन,

(6) मानविकी, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान।

केंद्र/सेल में निम्नलिखित शामिल हैं–

(1) पाठ्यचर्या विकास और मूल्यांकन केंद्र,

(2) अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र,

(3) कार्यक्रम योजना और निगरानी केंद्र,

(4) राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) सेल

(5) आईसीटी केंद्र

यह संस्थान भारत में UNEVOC नेटवर्क केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।

मिशन– वर्तमान और भविष्य के कार्यबल की कौशल जरूरतों को पूरा करने के लिए वीईटी संस्थानों की क्षमता का निर्माण करना।

उद्देश्य

- देश के सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए वीईटी और कौशल विकास को बढ़ावा देना।
- प्रणालीगत नीति हस्तक्षेपों के माध्यम से वीईटी प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाना।
- व्यावसायिक स्कूलों के व्यावसायिक विकास के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन और स्कूलों में वीईटी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक आवश्यक कदम उठाना।
- रोजगार और 21 वीं सदी के कौशल के वितरण के माध्यम से आजीवन सीखने को बढ़ावा देना।
- वीईटी उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए संगठनों, संस्थानों और एजेंसियों के साथ तालमेल, साझेदारी और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।

नियमित कार्य

सलाह– स्कूलों में शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एमएचआरडी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह और सहायता।

अनुसंधान– शिक्षा के व्यावसायीकरण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना।

प्रशिक्षण– राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ प्रमुख पदाधिकारियों और व्यावसायिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

विस्तार– समाचार और पत्रिका के प्रकाशन सहित विस्तार गतिविधियों के माध्यम से अनुभव और विचार साझा करना।

विकास– स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, छात्र, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक पुस्तिकाओं का विकास करना।

टिप्पणी

भूमिका

- व्यावसायिक शिक्षा (VE) में अनुसंधान का संचालन और प्रचार करना।
- व्यावसायिक शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए तंत्र स्थापित करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, NVEQF और VET की समकक्षता और मानकीकरण प्रदान करना।
- NVEQF और VET के मानकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम डिजाइन और विकसित करना।
- रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए छात्र सहायता प्रणाली का विकास और स्थापना।
- व्यावसायिक शिक्षा में विश्व स्तर के संसाधनों का संगठन करना।
- नीति निर्माण, शिक्षण–शिक्षण और रोजगार से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में शोध करना।
- अनुसंधान केंद्रों का विकास और स्थापना करना।
- एनवीईक्यूएफ पाठ्यक्रम के लिए सामग्री, तकनीक और कार्यक्रम विकसित करना।
- स्टेक होल्डर्स के साथ लिंकेज और नेटवर्किंग विकसित और स्थापित करना।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलन, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और कैरियर मेलों का संचालन करना।
- प्रिंट और नॉन–प्रिंट सामग्री को विकसित और प्रकाशित करना।
- निर्देशों और समर्थन सेवाओं की वितरण प्रणाली को दिशा प्रदान करना।
- प्रमाणपत्र जैसे संपर्क/दूरी मोड द्वारा मॉड्यूलर व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करना।
- नीति निर्माण, शिक्षा–शिक्षण और रोजगार से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में शोध करना।

टिप्पणी

- वेबसाइट और EDUSAT केंद्र के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मीडिया अनुसंधान केंद्रों का विकास और स्थापना करना।

अपनी प्रगति जांचिए

7. "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण" की योजना को कब कैबिनेट समिति की मंजूरी के साथ संशोधित किया गया था?

   (क) 2016 (ख) 2015

   (ग) 2014 (घ) 2013

8. SDVE किस स्तर की एजेंसी है?

   (क) जिला (ख) केंद्रीय

   (ग) राष्ट्रीय (घ) राज्य

2.6 अपनी प्रगति जांचिए प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (ग)
3. (ख)
4. (घ)
5. (ख)
6. (क)
7. (ग)
8. (घ)

2.7 सारांश

व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम डिजाइन का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न घटक शामिल हैं, विशेष रूप से ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण, योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और कार्यान्वयन रणनीति। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को जरूरत के अनुसार, सामाजिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए और सार्थक रोजगार की ओर ले जाना चाहिए। योग्यता आधारित पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों की जानकारी होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विभिन्न पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार एकरूप अनुदेशात्मक समय का प्रावधान है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल–आधारित योग्यता शैक्षणिक शिक्षण का एक वास्तविक विकल्प है। इस प्रकार की नौकरी उन्मुख युवाओं को एक विशिष्ट शिल्प, व्यवसाय या व्यापार में व्यावहारिक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाती है, जो कि हाथों से काम पर आधारित शिक्षण प्रदान करके किया जाता है जो सिद्धांत और व्यवहार का एक आदर्श है।

टिप्पणी

इस तरह के नवाचार को देश के विकास, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना, आर्थिक क्षमता, इतिहास और सांस्कृतिक प्रणाली (OECD, 2004) के चरण में फिट किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सीबीटी एक प्रमुख शिक्षण और शिक्षण दृष्टिकोण है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें कौशल के स्तर को बढ़ाने, बेरोजगारी दर को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा (2005 और स्मिथ) को प्राप्त करने की एक मजबूत क्षमता है।

भारतीय राज्यों में शिक्षा के सभी स्तरों पर एक बहुत मजबूत और व्यवहार्य प्रशासनिक सेटअप काम कर रहा है। शिक्षा संगठन के जिम्मेदार प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक है जो विशेष रूप से शिक्षार्थियों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है (अर्थात, यह विशेष रूप से भवन, परिसर, जिला और राज्य में शिक्षा प्रशासकों और कर्मचारियों के लिए लिखा जाता है) प्रभावी रखरखाव कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं पर बल देता है।

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत स्तरों पर प्रबंधन संरचना, स्कूल संगठन और प्रबंधन योजना,निष्पादन और दिशा, कक्षा, शॉप फ्लोर और नौकरी प्रशिक्षण, खरीद, भंडारण, रिकॉर्डिंग और सामग्री का रखरखाव, और उपकरण व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख तत्व हैं।

हमारी दुनिया में समाज और शिक्षा दो अविभाज्य तत्व हैं। यह हमेशा चर्चा में रहा है कि शिक्षा समाज को कैसे प्रभावित करती है। हमें जो चीजें सिखाई जाती हैं और जो हम अपने स्कूली शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं, वह उस तरह के व्यक्ति को प्रभावित करती है जो हम हैं और परिणामस्वरूप समाज को समग्र रूप से प्रभावित करता है। लेकिन शायद ही कभी हम शिक्षा पर समाज के प्रभाव से निपटते हैं। समाज एक विशिष्ट सामाजिक समूह है जिसका एक विशिष्ट सांस्कृतिक और आर्थिक संगठन है। समाज के निर्माण खंड में हम इंसान हैं। लोग बातचीत के द्वारा व्यक्तियों के बीच संबंधों के पैटर्न को बनाते हैं और इस प्रकार समाज को रीति–रिवाजों, मूल्यों और कानूनों के अनुसार चरित्रवान बनाते हैं।

सभी बच्चों की शिक्षा में काम का शैक्षिक महत्व है, जो किसी भी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक आधार पर हो सकता है। जिस शिक्षा प्रणाली में काम और ज्ञान अलग–अलग रास्ते अपनाने की कोशिश करते हैं, उसे समाज के साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता है। स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक श्रम और उत्पादक कार्यों को एक उच्च पद पर रखकर शिक्षा का अर्थ जीवन को सार्थक, तार्किक और उपयोगी बनाना है।

वास्तविक जीवन स्थितियों में उत्पादन से संबंधित कार्य न केवल छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखने, बल्कि ज्ञान प्रदान करने, और स्वाभाविक रूप से जीवन कौशल विकसित करने में शैक्षिक महत्व रखते हैं। शिक्षा और काम की संयोजकता के साथ–साथ, आपको कार्य शिक्षा में ज्ञान, जीवन कौशल और मूल्यों के उद्देश्यों का एहसास हुआ। कार्य शिक्षा का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार है। यह छात्रों को खुशी प्रदान करता है। मात्र किताबी ज्ञान बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा करता है, जबकि सीखने से उनका कायाकल्प हो जाता है। कार्य बच्चों को स्वयं, उनके परिवार और समाज की जरूरतों को जानने के लिए उत्साहित करते हैं। शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य श्रमिकों के लिए सम्मान की भावना विकसित करना और छात्रों में श्रम की गरिमा है।

टिप्पणी

सरकार के प्रयासों के बावजूद, अनौपचारिक क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण कई लोगों के लिए सुलभ नहीं है। स्थान की समस्याओं के अलावा, नियमित रूप से काम करने का विघटन और अन्य सामान्य कठिनाइयों, औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच आसान नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोगों के लिए, शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रासंगिक लागत मौद्रिक लागत नहीं है, बल्कि अस्थायी रूप से, यहां तक कि रोजी–रोटी कमाने के अपने पेशे का अवसर नहीं है। जब तक वे कार्यक्रमों और अपनी स्वयं की आय–उत्पादक क्षमताओं के बीच सीधा संबंध नहीं देखते हैं, यह दुर्लभ है कि वे शिक्षा प्राप्त करने में दृढ़ रहेंगे। उत्पादक ज्ञान, कौशल और क्षमता का विकास इसलिए शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के उपयुक्त कार्यक्रमों पर निर्भर करता है।

2.8 मुख्य शब्दावली

- **आजीविका** : कमाई, आमदनी का साधन।
- **मानदंड** : पैमाना, किसी चीज का मूल्यांकन करना, जांच करने का तरीका।
- **परिधि** : घेरा, दायरा।
- **व्यवसाय** : रोजगार, कार्य।
- **सर्वांगीण** : हर क्षेत्र में, चारों तरफ से।
- **वोकेशनल** : व्यावसायिक, रोजगारपरक।
- **अवधारणा** : विचारधारा।
- **अधिगम** : अध्ययन, सीखना।

2.9 स्व–मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. स्कूल–उद्योग लिंकेज से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए।
2. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना को परिभाषित कीजिए।
3. उच्चतर माध्यमिक चरण पाठ्यक्रम में कार्य का क्या स्थान है? वर्णित कीजिए।
4. 21वीं सदी के कौशलों का उल्लेख कीजिए।
5. गैर सरकारी संगठनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
6. पाठ्यचर्या में मूल्यों का क्या महत्व है?

दीर्घ–उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की विवेचना कीजिए।
2. भारत में पाठ्यचर्या सुधारों का वर्णन कीजिए।
3. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीतियों की समीक्षा कीजिए।

टिप्पणी

4. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के विस्तृत प्रबंधन ढांचे की व्याख्या कीजिए।
5. विभिन्न चरणों में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित एजेंसियों का वर्णन कीजिए।
6. माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिक रूप से प्रायोजित योजना के विशेष संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका को समझाइए।
7. व्यावसायिक शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख की भूमिका, कर्तव्यों और गुणों का वर्णन कीजिए।
8. भोपाल के केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

2.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1 Arulsamy S., (2010), Curriculum Development, Neelkamal Publications Pvt-- Ltd, Hyderabad.

2 Australian Chamber of Commerce and Industry & Business Council of Australia (2002).

3 Barrera-Osorio, F., & Filmer, D., (2013), Incentivizing schooling for learning: Evidence on the impact of alternative targeting approaches (Working Paper No, 6541).

4 Boahin, P. & Hofman, W.H.A. (2012), Implementation of Innovation in higher education: the case of competency-based training in Ghana-Innovations in Education Teaching International,49(3),313-323.

5 British Council, Indian School Education System: An Overview- Report (2014).

6 Brown, P., Lauder, H. & Ashton, D. (2008), Education, Globalisation and the Future of the Knowledge Economy- Europeans Educational Research Journal, 7 (2), 131-156.

7 Competence based curriculum, (2015). Summary of curriculum framework pre-primary to upper secondary.

8 Framework on Vocational Pedagogy, for Vocational Educator, (2020), PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal (MP).

9 GOI (1985), Report of national working group on vocationalization of education, New Delhi.

10 Kelly, A.V., (2009), The Curriculum – Theory and Practice- Chapman Sage Publication, New Delhi.

11 Kalyanpur. Maya, "Equality, Quality and Quantity: Challenges in Inclusive Education Policy and Service Provision in India", International Journal of Inclusive Education 12-3 (2008): 243-262

12 Kingdon, Geeta Gandhi, "The progress of school education in India", Oxford Review of Economic Policy 23-2 (2007): 168-195.

13 Kodiappan, R. (2011), Challenges affecting the integration of competency-based training at the higher levels of the Singapore Workforce Skills

टिप्पणी

Qualifications-National Qualification Framework- https://www-ial-ed-edu-sg/files/documents/319/challenges.

14 Kouwenhoven, W. (2011), Competence-based curriculum development in Higher Education: some African experiences, Technology, Education and Development, pp- 125-146.

15 MHRD (2011), Working Group Report on Secondary and Vocational Education, 12th Five Year Plan 2012–2017, Government of India, New Delhi.

16 Mridula and Palanivel (2003), Vocational educational programme in Kamataka : success stories- Bhopal: PSSCIVE (NCERT).

17 National Council of Educational Research and Training (2011), Education for Values in Schools – A Framework- New Delhi: NCERT.

18 NCERT (1999)- PSSCIVE: Vocationalisation of education: perspective for the new millenniunr-New Delhi: NCERT.

19 NCERT (2000) National curriculum framework for school education, New Delhi.

20 NCERT (2004), Global educational change- New Delhi: NCERT.

21 NCERT (2005), National curriculum framework, New Delhi: NCERT.

22 NC'ERT (1990). On-the-job training guidelines, New Delhi: NCERT.

23 NEP Draft, (2019), Published by MHRD, New Delhi.

24 New Straits Times (2012), Honing job skills of vocational students, 6 Nov-2012, page 11 column 5.

25 Report of the Secretary-General, Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals, Report (2019).

26 Sharif Khan, M., (2004), School Curriculum- Ashish Publishing House, New Delhi.

27 Sharma, R.A. (2005), Curriculum Development and Instruction, Meerut, R. Laal Book Depot

28 Sharda Kumari (2005) Principles of Teaching Work Education, New Delhi.

29 Shoikova E., M, Krumova, Technology-Enhanced Social Learning and SECI 2.0", International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue No 3 (Vol- 5), 2013

30 Wesselink, R., M. A. Dekker-Greon, J,A, Biemans, & M, Mulder, (2010), Using an instrument to analyse competence-based study programmes: experiences of teachers in Dutch vocational education and training- Journal of Curriculum Studies. 42(6), 813-829.